राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं
प्रशासन विश्वविद्यालय

2013-14

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

वार्षिक रिपोर्ट

jk"Vªh; 'kSf{kd ;kstuk ,oa
iz'kklu fo'ofo|ky;

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (200 प्रतियाँ), 2014

(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के लिए कुलसचिव, न्यूपा द्वारा प्रकाशित तथा डिजिटल एक्सप्रेशन, नई दिल्ली द्वारा डिजायन एवं विभा प्रैस प्रा. लि., ओखला में न्यूपा के प्रकाशन एकक द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

अध्याय

1. विहंगावलोकन 1
2. अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम 21
3. अनुसंधान एवं मूल्यांकन 39
4. सहचर्या और सहभागिता 71
5. न्यूपा में नई पहल 75
6. पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं 81
7. कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं 87
8. प्रकाशन कार्यक्रम 91
9. न्यूपा में सहायता अनुदान योजना 97
10. प्रशासन एवं वित्त 103

अनुलग्नक

I. संकाय का अकादमिक योगदान 109

परिशिष्ट

I. न्यूपा परिषद् के सदस्य 165
II. प्रबंधन बोर्ड के सदस्य 167
III. वित्त समिति के सदस्य 168
IV. अकादमिक परिषद के सदस्य 169
V. अध्ययन बोर्ड के सदस्य 171
VI. संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ 173
VII. वार्षिक लेखा 175

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

223

1

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) देश के शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क के बीच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अपने महत्वपूर्ण और व्यापक शैक्षणिक कार्यकलापों के कारण विशेष स्थान रखता है।

इसकी स्थापना आरंभिक रूप से फरवरी 1962 में यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र के रूप से हुई थी। इस केंद्र का मुख्य कार्य एशिया के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा विद्यालय पर्यवेक्षण से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था।

1 अप्रैल 1965 से शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र का नाम बदलकर एशिया शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान कर दिया गया। यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच दस वर्ष के समझौते के समाप्त होने के बाद, एशिया संस्थान को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और तत्पश्चात 1970 में शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिये राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना की गई। पुनः इस कालेज का पुनर्गठन किया गया और 31 मई 1979 को इसका विस्तार करते हुये इसको राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया।

शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीपा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यो को देखते हुये संस्थान को वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इसे 'मानद विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत इसे डिग्री प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई और पुनः नाम परिवर्तन के बाद इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) कहा जाने लगा। इसे आगे 'राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' के नाम से संबोधित किया जायेगा। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

न्यूपा का मिशन और विज़न

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय 'ज्ञान के विकास के माध्यम से एक मानवीय अधिगम समाज के निर्माण का अभिकल्पना करता है'। इस विज़न के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य मिशन शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करना रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय 'ज्ञान के विकास के माध्यम से एक मानवीय अधिगम समाज के निर्माण का अभिकल्पना करता है'। इस विज़न के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य मिशन शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करना रहा है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी नीतियों, योजना तथा कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तथा संघ क्षेत्रों के स्तर पर सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण तथा स्कूल, समुदाय, जिला, राज्य/संघ प्रदेशों तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक त्वरित, सहभागिता और जवाबदेह शैक्षिक अभिशासन तथा प्रबंधन प्रणाली का सांस्थनीकरण;
- शैक्षिक सुधारों का अनुसमर्थन करने और शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की प्रभावी योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सुसज्जित शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में युवा पेशेवरों सहित और शिक्षाविदों सहित विशेषीकृत मानव संसाधनों के समूह का विस्तार करना;
- शैक्षिक क्षेत्र में उभरती तथा वर्तमान चुनौतियों का सामना करने हेतु तथ्य आधारित जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन एवं संबंधित विषयों के ज्ञान आधार में वृद्धि;
- शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार तथा बेहतर शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार, अनुसंधान परिणामों, नवाचारों तथा सर्वोत्तम व्यवहार समेत सूचना तथा ज्ञान की साझेदारी एवं पहुंच में सुधार;
- अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन देते हुये शैक्षिक नीति निर्माण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार/तकनीक शिक्षा के सभी चरणों तथा व्यवस्था में, तथा रणनीतिक उपागम शैक्षिक योजना प्रक्रियाओं, अभिशासन तथा प्रबंधन में सुधार हेतु तथा अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं में नेतृत्वकारी भूमिका जो शैक्षिक नीति–निर्माण तथा देश में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन व्यवहार का निर्माण करती है।

मुख्य कार्य

अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निम्नांकित मुख्य कार्यों में संलग्न है :

- शिक्षा के सभी चरणों में शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना;
- सर्वोत्तम प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के कैडर के गठन हेतु प्री–डाक्टरल, डॉक्टरल तथा पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों सहित अध्यापन के विकसित अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों का विकास तथा आयोजन और साथ में शैक्षिक नीतियों योजना तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु सतत् सांस्थानिक क्षमता का निर्माण करना;
- शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान एजेंडा तथा वचनबद्धता को स्वरूप देना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिये आवश्यक समर्थन हेतु नये ज्ञान का सृजन तथा तथ्य आधारित नीति निर्माण और बेहतर शैक्षिक योजना और प्रबंधन व्यवहार/तकनीक का प्रयोग करना;
- केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों को उनकी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तकनीकी समर्थन प्रदान करना और उन्हें शैक्षिक नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में सुधार हेतु मदद करना;
- शैक्षिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा निर्माण हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को परामर्श सेवायें प्रदान करना;
- शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान तथा नवीन ज्ञान के सृजन हेतु सूचना तथा विचारों के समाशोधन गृह के रूप में कार्य, शैक्षिक नीतियों, योजना तथा प्रशासन में विशेष रूप से, विचारों/अनुभवों के आदान–प्रदान तथा नीति–निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के बीच नीतिगत चर्चा हेतु विचार मंच प्रदान करना, प्रभावी नीतियों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन तकनीक/व्यवहार को शिक्षा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों को सामना करने हेतु चिह्नित करना तथा शिक्षा क्षेत्र संबंधी विकास लक्ष्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करना;
- शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में सुधार हेतु संयुक्त प्रयासों/कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रमों, निधि एवं एजेंसियों समेत राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा सहयोग;

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास में उभरती हुई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में उभरती हुई चुनौतियों की पहचान तथा शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त नीति निर्माण तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रगति का मूल्यांकन।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपरोक्त कार्य राज्य तथा संघशासित प्रदेश एवं केंद्रीय स्तर पर सरकारों तथा संस्थानों के साथ निकटतम संपर्क तथा सहयोग द्वारा आयोजित किये जाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं शिक्षा व्यवस्था की योजना तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। विश्वविद्यालय का एक मुख्य पहलू जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संबंध द्वि–रूप कार्य प्रणाली है। विश्वविद्यालय अपने ज्ञान आधार में वृद्धि वास्तविकता क्षेत्र में अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल, कालेज, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभागों के साथ संपर्क द्वारा करता रहा है। राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राज्यों/संघशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण को पूर्ण करने हेतु संसाधन व्यवक्तियों को प्रशिक्षण, राज्य सरकारों तथा राज्य संस्थानों के साथ निकटवर्ती संपर्क, उनकी शैक्षिक व्यवस्था का समालोचनात्मक अध्ययन, नीतियां तथा कार्यक्रम एवं उन्हें व्यावसायिक परामर्श तथा तकनीकी समर्थन हेतु प्रयासरत है। विश्वविद्यालय अपने ऐसे कार्यक्रमों की शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक थिंक टैंक (प्रसार केन्द्र) बना हुआ है। विश्वविद्यालय अपने अधिकांश क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और अन्तर्दृष्टि जमीनी स्तर के शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं को हस्तान्तरित कर रहा है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय की इस दोहरी भूमिका ने उसके अपने अध्यापन तथा अनुसंधान के अकादमिक कार्य को व्यापक प्रामाणिकता प्रदान की है।

अकादमिक ढांचा तथा समर्थन सेवाएं

संस्थान के अकादमिक ढांचे में विभाग, केंद्र, विशेष पीठ हैं जो शिक्षा के विशिष्ट पक्षों को संबोधित करते हैं तथा तकनीकी समर्थन एकक/समूह तथा अकादमिक समर्थन प्रणाली अपने संबंधित विषयगत क्षेत्रों से जुड़ी विकास तथा क्रियान्वयनकारी गविधियों के प्रति उत्तरदायी हैं। विश्वविद्यालय के संकाय में प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा राष्ट्रीय अध्येता सम्मिलित हैं जो शिक्षा नीति, योजना तथा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक विभाग अंतरशास्त्रीय विषयों के आधार पर संयोजित है और ज्ञान, विद्वता तथा अन्य अध्ययन कार्यक्रमों और अनुसंधान क्षेत्रों, सामान्यतः शिक्षा, और विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में विशेष तौर पर संसाधन प्रदान करते हैं। प्रत्येक विभाग के पास अनुसंधान/परियोजना सहायकों तथा अनुसचिवीय स्टाफ के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ के रूप में संकाय सदस्य हैं। अकादमिक विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर होता है। विभाग विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधन कार्यक्रमों के निष्पादन और विकास तथा उनको प्रदान किये गये क्षेत्रों में परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत, विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन आठ अकादमिक विभागों तथा विशेष पीठ द्वारा तथा दो केंद्रों द्वारा किया गया जिन्हें अकादमिक तथा प्रशासनिक सेवा एककों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया।

vdknfed lxBu

foHkkx

- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त
- शैक्षिक नीति
- विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा
- उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा
- शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली

dsUnz

- राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
- उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र

leFkZu lsok,

- पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र
- कंप्यूटर केन्द्र
- प्रकाशन एकक

ihB rFkk v/;srk

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ
- अध्यापक प्रबंधन एवं विकास पर राजीव गांधी स्थापना पीठ

- न्यूपा राष्ट्रीय अध्येता
- भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

अकादमिक विभाग

'kf{kd ;kstuk foHkkx % केंद्रीकृत नियोजन से हटकर विकेंद्रीकृत योजनाओं पर बल के साथ, न्यूपा के प्रमुख विभागों में से एक यह विभाग, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजना के आगतों, प्रक्रियाओं, और उत्पादों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पारंपरिक अर्थों में व्यापक योजना से हटकर आज, आर्थिक उदारीकरण की पृष्ठभूमि में, केन्द्रबिंदु रणनीतिक योजना पर स्थानांतरित हो गया है। हाल के दिनों में, गरीबी कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म नियोजन और स्कूल सुधार योजना के रूप में स्थानीय स्तर की योजना तकनीकों का प्रयोग करना भी है। यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों को परामर्श उलब्ध कराने के साथ–साथ शिक्षण और प्रशिक्षण, शैक्षिक योजनाकारों के पेशेवर विकास, अनुसंधान और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। यह विभाग शैक्षिक विकास में पहल का निदान और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण डेटा विश्लेषण और संकेतकों के प्रयोग हेतु शिक्षा पदाधिकारियों की क्षमताओं में सुधार करने में लगा हुआ है। विभाग एम.फिल. और पी–एच.डी. के विभिन्न केंद्रिक और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संचालन, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डेपा) और अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में योगदान देता है।

'kf{kd i'kklu foHkkx % शैक्षिक प्रशासन विभाग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों में प्रशासन और प्रबंधन के विविध आयामों अनुसंधान, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा परामर्शकारी सेवाओं में सक्रिय रूप से बौद्धिक और अकादमिक संलग्नता है। विभाग का एक मुख्य सरोकार शैक्षिक क्षेत्र में समृद्ध ज्ञान आधार का विकास करना और शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन के विविध आयामों पर शैक्षिक प्रशासकों तथा शोधार्थियों के लिए एक मजबूत पेशेवर अनुसमर्थन का निर्माण करना है। अतः यह विभाग शैक्षिक प्रशासन और शासन की गतिशीलता को समझने और उसका विश्लेषण करने हेतु इसकी ठोस अवधारणा और ढांचा के विकास के लिए प्रयासरत है। यह विभाग विभिन्न स्तर के शिक्षाकर्मियों के लिये शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के विविध पक्षों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करता है।

'kf{kd foÙk foHkkx % इस विभाग का दोहरा उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों –राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा विश्वस्तर पर आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष पर अनुसंधान करना तथा उसे प्रोत्साहित करना है तथा विकासशील देशों और भारत में शिक्षा क्षेत्र की वित्तीय योजना तथा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों के क्षमता निर्माण का सृजन करना है। विभाग के कार्यक्रम/गतिविधियां– अनुसंधान, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परामर्श पर केंद्रित हैं जो नीति, योजना तथा विकास, शिक्षा के सार्वजनिक तथा निजी वित्त पोषण, सरकारी तथा निजी संसाधनों की लामबंदी, शिक्षा के सभी स्तरों पर संसाधनों का आवंटन तथा उपयोग, प्राथमिक से उच्च, तथा संसाधन आवश्यकताओं के आकलन से जुड़े मुद्दों के इर्द–गिर्द केंद्रित हैं। अधिकांशतः शोध के क्षेत्र शिक्षा के वित्त पोषण, कार्यक्रम और नीतिगत मुद्दों से संबंधित हैं। परामर्शकारी सेवाएँ नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित हैं। अध्यापन के विषय में शिक्षा का अर्थशास्त्र और शैक्षिक वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम के विषय योजना तकनीक और प्रबंधन प्रणाली पर आधारित हैं।

'kf{kd uhfr foHkkx % यह विभाग नीतियों से संबंधित विभिन्न मसलों पर जिन दिशाओं की ओर शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, उन्हें ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नीति संबंधी अध्ययन करता है। यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति–निर्माताओं के बीच नीति निर्माण के प्रति मूलभूत समझ विकसित करने का प्रयास भी करता है। यह विभाग नीति निर्माताओं, कार्यकर्त्ताओं और शैक्षिक नीति तथा सार्वजनिक नीति से जुड़े अन्य लाभार्थियों/व्यक्तियों के लिए नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों पर परिसंवाद और प्रशिक्षण कार्य आयोजित करता है।

विभाग की प्रमुख गतिविधियों में प्रशिक्षण, अध्यापन, शोध और अकादमिक अनुसमर्थन शमिल हैं। यह विभाग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक प्रशासकों और योजनाकारों के लिये अल्पावधि और दीर्घकालीन प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा यह विमर्श के लिये अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। और पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी संबंधी मुद्दों पर सूचना आधार तैयार करता है। विभाग के प्रमुख शोध केन्द्र प्रायोजित शैक्षिक योजनाओं के मूल्यांकन और नीति तथा कार्य व्यवहार की समझ पर केंद्रित होता है।

यह विभाग राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिये नीतिगत मुद्दों पर क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह नीति के बहुस्तरीय अभिशासन को बल देता है जिसमें आधारभूत स्तर पर सहभागिता पूर्ण ढांचे पर फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पर शिक्षा की विकेंद्रीकृत योजना और स्कूली शिक्षा में समुदाय की भूमिका इसके शोध अध्ययनों में से प्रकट होता है। यह विभाग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एम.फिल., पी–एच.डी., डेपा और आईडेपा कार्यक्रमों के कुछ पाठ्यक्रमों सहित अध्यापन संबंधी सभी कार्यक्रमों में योगदान करता है। यह (क) सांस्थानिक निर्माण और (ख) क्षमता संवर्द्धन संबंधी कार्यक्रमों में राज्य सरकारों को परामर्शकारी सेवा भी प्रदान करता है।

fo|ky; vkj vukSipkfjd f'k{kk foHkkx % विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग व्यापक रूप से अधिकार–आधारित और समेकित ढांचे के अंतर्गत पूर्व–स्कूल शिक्षा, समग्र स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक और प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष बल देता है। यह गुणवत्ता, समता, सामाजिक न्याय और समेकन की सैद्धांतिक समझ विकसित करने का प्रयास करता है। यह विभाग संस्थान के रूप में स्कूलों और स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा में हो रहे बदलावों पर है। नीतियों तथा व्यावहारिक हस्तक्षेपों हेतु अनुभवजन्य आधार प्रदान करने के उद्देश्य से शोध अध्ययन करता है।

यह विभाग शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम एवं एम.फिल, पी–एच.डी. के कुछ पाठ्यक्रमों के अध्यापन सहित राज्य, जिला तथा उप–जिला स्तर के अधिकारियों के लिये कार्यशालाएं और क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करता है। यह विभाग सह–क्रियात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ अनुभव और विशेष क्षमता साझा करता है। वर्तमान में व्यावहारिक ज्ञान के मद्देनजर यह विभाग कमोबेस सीमित चार क्षेत्रों– अधिकार आधारित ढांचे के अंदर स्कूली शिक्षा में समता गुणवत्ता और समावेशन, अध्यापक विकास और प्रबंधन, स्कूल नेतृत्व एवं स्कूली मानकों के मूल्यांकन पर विशेष बल दे रहा है। संकाय के दो सदस्य राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र में भी कार्य करते हैं और एक सदस्य विद्यालय मानक और मूल्यांकन एकक में संबद्ध है।

mPprj vkj 0;kolkf;d f'k{kk foHkkx% यह विभाग वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लगातार अनुसंधानात्मक अनुसमर्थन और नीतिगत सुझाव प्रदान करता रहा है। विभाग के विश्व व्यापार संगठन कक्ष ने गेट्स के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों के विश्लेषण और भारत की सहमति की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विभाग ने उच्चतर शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के विविध आयामों पर अध्ययन किया और उन पर विमर्श हेतु संगोष्ठियां आयोजित की तथा उनके निष्कर्षों का प्रसारण किया। यह विभाग उच्चतर शिक्षा के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहयोग करता रहा है। यह विभाग विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संकायाध्यक्षों और कुलसचिवों के सम्मेलन और संगोष्ठियां के आयोजन में यू.जी.सी. का सहयोग करता रहा है।

इस विभाग ने कार्य निष्पादन आधारित उच्चतर षिक्षा पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने हेतु यूनेस्को क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन और भारतीय उच्चतर शिक्षा में कार्य निष्पादन आधारित वित्त पोषण पर योजना आयोग – विश्व बैंक प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन में भी सहयोग किया है। विभाग के नियमित वार्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न श्रेणी के कालेजों के प्राचार्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। वार्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत यह विभाग विभिन्न श्रेणियों के कॉलेज प्राचार्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विभाग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के विभिन्न आयामों तथा अकादमिक सुधार पर संगोष्ठियां आयोजित करने में अकादमिक समर्थन प्रदान करता है। विभाग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम– एम.फिल तथा पी. एच.डी. कार्यक्रमों के केंद्रिक तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और शोधार्थियों का अतिरिक्त शोधनिर्देशन कर रहा है।

'kf{kd if'k{k.k vkj {kerk fodkl foHkkx % यह विभाग विशेष रूप से नवनियुक्त एंव प्रोन्नत शैक्षिक प्रशासकों की क्षमता में सुधार के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सहसंबंध विकसित करने पर विशेष बल देता है। शिक्षा प्रणाली और संस्थानिक स्तर के अधिकारियों के लिये विषयगत और संवर्ग आधारित पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षा तथा विभागों के कार्य दल के विकास से स्थाई और समर्पित संस्थानिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से इस विभाग ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है।

इसके अलावा यह विभाग लंबी अवधि के दो डिप्लोमा कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कर्मियों के लिये आयोजित करता है। वर्ष 2013 में शैक्षिक योजना और प्रशासन में 34वां राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भारत के 12 राज्यों के 25 शिक्षा अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। शैक्षिक योजना और प्रशासन में 29वां अतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम फरवरी 2013 से आयोजित किया गया। इसमें 22 देशों के 35 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया और भूटान के अनुरोध पर इन देशों के लिए क्षमता विकास पर दो क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस विभाग ने विशेष फोकस समूह जैसे अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षा संस्थानों (विद्यालय और उच्चतर शिक्षा) के प्रमुखों, जनजातीय क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों के प्राचार्यों और डाइट के योजना एवं प्रबंधन विभाग के संकाय के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किये।

'kf{kd icèku lpuk i.kkyh foHkkx % शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग शोध और क्षमता विकास संबंधित कार्य करता है और भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा का आंकड़ा आधार और प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी परामर्श देता है। यह विभाग भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) और आंकड़ा आधार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनीसेफ के सहयोग से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाइस) का प्रबंधन करता है। इसके अलावा यह विभाग शैक्षिक सांख्यिकी के मुद्दों और शिक्षा के समकालीन मुद्दों पर सम्मेलन/संगोष्ठियां और शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधियों पर कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और सांख्यिकी तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली पर परामर्श प्रदान करता है। विभाग के संकाय सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली के निर्माण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में सक्रिय रूप से शामिल हैं। एकीकृत प्रणाली की दिशा में वर्ष 2012–13 से देशभर में समान आंकड़ा प्रपत्र में पहले कदम के रूप में डाइस और सेमीस का समेकन एकत्र किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे 15 मिलियन स्कूलों से आंकड़ा एकत्र किए गए।

इस विभाग द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के विषय निम्नलिखित हैं : शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग, एजुसेट द्वारा डाइस पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, शैक्षिक शोध में डाइस आंकड़ों का उपयोग और स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली आदि। यह विभाग तीसरी दुनिया के देशों के लिए ईएमआईएस पर सुनियोजित पाठ्यक्रम के साथ–साथ डेपा और आईडेपा में शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधि पर पाठ्यक्रम का अध्यापन करता है। विभाग का संकाय ईएमआईएस और स्कूली शिक्षा से संबंधित पक्षों पर भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करता है।

विशेष पीठ

ek|ykuk vCk|y dyke vktkn ihB % स्वतंत्र भारत के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के पहले मंत्री मौलाना आज़ाद के योगदानों को स्मरण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। पीठ का मुख्य अनुसंधान क्षेत्र 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान मौलाना आजाद के योगदानों की खोज करते हुए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास पर अध्ययन करना है। यह पीठ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। यह पीठ मौलाना आज़ाद के दर्शन और वैश्विक विचारों व अन्य संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है।

v/;kid ic/ku ,o fodkl ij jktho xk/kh LFkkiuk ihB% अध्यापक प्रबंधन एवं विकास पर राजीव गांधी स्थापना पीठ ने जून 2013 में प्रोफेसर और पीठ की नियुक्ति के साथ अपना कार्य आरंभ कर दिया। इस पीठ की स्थापना अध्यापक प्रबंधन एवं विकास पर केंद्रित कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तीन साल की अवधि (2012–15) हेतु की गई है। इसकी एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसमें विख्यात शिक्षाविद् और प्रशासक इसके सदस्य है। यह समिति पीठ की गतिविधियों का अनुमोदन करती है। इसकी पहली प्रमुख गतिविधि बहुराज्यीय अध्ययन– भारत के 9 राज्यों में प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की दशाओं का अध्ययन करना है। यह शोध अध्ययन झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में चल रहा है। न्यूपा नीति दस्तावेज़ों की व्यापक समीक्षा करने हेतु एससीईआरटी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ कार्य कर रहा है। और मुख्य हितधारकों के साथ परिचर्चा और साक्षात्कार कार्य भी किया जा रहा है। शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत किस प्रकार से अध्यापकों का प्रबंधन किया जाता है और इनका पदस्थापन किया जाता है, इसके बारे में अध्यापकों के विचार जानने के लिए रायशुमारी का प्रस्ताव हें इसके बाद इसका तीसरा चरण आरंभ होगा, जिसमें न्यूपा कुछ राज्य सरकारों और अध्यापकों के साथ कार्य करके शिक्षा प्रणाली में सुधार की संभावनाओं की रूपरेखा बनाएगा।

केन्द्र

jk"Vªh; fo|ky; usr`Ro dsanz ¼,u lh ,l ,y½ राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र भारत में विद्यालयों के रूपांतरण के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये यह चार घटकों– पाठ्यचर्या और सामग्री विकास, क्षमता विकास, नेटवर्क और संस्थानिक निर्माण और अंत में शोध एवं विकास पर कार्य कर रहा है। यह केंद्र व्यापक परिप्रेक्ष्य में बदलाव और विकास के लिये विद्यालय प्रमुखों के साथ–साथ प्रशासकों के नेतृत्व क्षमता विकास की परिकल्पना करता है। वर्तमान में यह केंद्र मौजूदा विद्यालय प्रमुखों तथा नवनियुक्त विद्यालय प्रमुखों, प्रारम्भिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के भावी एवं वरिष्ठ अध्यापकों जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हैं, के क्षमता विकास कार्य पर विशेष बल दे रहा है।

यह केंद्र अपने मिशन को पूरा करने के लिए विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से नेतृत्व क्षमता निर्माण के कार्य से संलग्न है जिसमें विद्यालय रूपांतरण के रूप में विद्यालय आधारित बदलाव लाने के लिए विद्यालय प्रमुखों के साथ सतत रूप से जुड़ाव भी शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर के दो दस्तावेज़– राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या ढांचा एवं विद्यालय नेतृत्व विकास पर हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इसके साथ–साथ अनेक कार्यशालाएँ और बैठकें आयोजित की गईं। समीक्षाधीन वर्ष में 10 राज्यों– आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिज़ोरम, राज़स्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस कार्य का शुभारंभ किया गया। राज्य विशिष्ट नेतृत्व जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने के लिये प्रत्येक राज्य की वास्तविक स्थितियों और विद्यालयों के संदर्भों के मद्देनज़र राज्य विशिष्ट कार्यवाही योजनाएँ तैयार की गईं। इस मिशन हेतु राज्यों तथा केंद्र के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की गई। यूकेरी के अंतर्गत भारत में विद्यालय नेतृत्व पर नेशनल कालेज फार टीचिंग एंड लीडरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

mPprj f'k{kk uhfr vuqla/kku dsanz राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति तथा योजना का अनुसमर्थन करने के लिये एक विशिष्ट संस्थान के रूप में उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआरएचई) की स्थापना की है। सीपीआरएचई शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और योजना आयोग के निकट सहयोग से कार्य कर रहा है। यह केंद्र उच्च शिक्षा के प्रावधानों के विस्तार और सुधार की मौजूदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, समता और समावेशन की सुनिश्चितता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रासंगिकता और स्नातकों के रोजगार और इसके अभिविन्यास और प्रबंधन को अंतरराष्ट्रीयकरण तथा सुधार कार्य पर विशेष बल दे रहा है। यह केंद्र शोध को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों का नेटवर्क विकसित कर रहा है। राज्य स्तरीय निकायों जैसे– राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के साथ राज्य तथा संस्था स्तर पर उच्च शिक्षा की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न है।

भारत अफ्रीका संस्थान

भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (आई.ए.आई.ई.पी.ए) भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान अप्रैल 2008 में आयोजित भारत–अफ्रीका मंच सम्मेलन के संकल्पों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई कार्यवाई योजना के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अखिल अफ्रीकी संस्था है। यह संस्थान बुरूण्डी गणराज्य की राजधानी बुजुम्बुरा में स्थित है।

आईएआईईपीए की स्थापना, संचालन और प्रबंध से संबंधित कार्य भारत सरकार की ओर से न्यूपा द्वारा किए जा रहे हैं। भारत सरकार, अफ्रीकी संघ और बुरंडी सरकार के बीच सहयोग के कार्यक्षेत्र, हैं : (i) अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की शैक्षिक योजना और प्रबंधन संबंधी क्षमता विकास और शोध की जरूरतों को पूरा करने के लिये आईएआईईपीए को एक प्रायद्वीपीय महत्व और उत्कृष्टता का केंद्र बनाना (ii) शैक्षिक नीति शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मज़बूत बनाने के लिए प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के समूह का संबंर्धन (iii) अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णयों के लिये अपेक्षित ज्ञान के विस्तार हेतु अफ्रीका आधारित शोध और विश्लेषण को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना (iv) शैक्षिक नीतियों और शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन तकनीकों से संबंधित नवाचार, सूचनाओं/प्रसार ज्ञान, शोध निष्कर्षों और प्रभावकारी कार्यव्यवहारों को साझा करने के लिये सांस्थानिक कार्य प्रणाली का विस्तार करना (v) अफ्रीकी संघ सदस्य देशों और अन्य हितधारकों के बीच सामान्य तौर पर शैक्षिक विकास संबंधी मुद्दों और विशेषतया अफ्रकी संघ सदस्य देशों में शैक्षिक योजना और प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नीतिगत परिसंवाद को सुगम बनाना, (v) अफ्रीकी संघ सदस्य देशों में शैक्षिक विकास के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शैक्षिक योजना और प्रबंधन की तकनीकों/कार्य व्यवहारों के प्रभावी अनुभवों को साझा करना और उपयुक्त कार्य नीतियों का विकास करना।

उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय, बुरुंडी सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली आईएआईईपीए की स्थापना से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये सयुक्त रूप से कार्यरत है। बुरूंडी सरकार द्वारा एआईईपीए की स्थापना से संबंधी कार्यों/गतिविधियों को देखने के लिये एक राष्ट्रीय परियोजना समन्वय दल का गठन किया गया है।

एआईएआईईपीए की स्थापना के लिये बुरूण्डी सरकार बुरुण्डी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान और शिक्षा संकाय के परिसर में 36,972 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड आवंटित किया है। इस संस्थान की स्थापना के लिये उपलब्ध कराए गए भवन में नवीकरण का कार्य प्रगति पर है और 2014 के अंत तक नवीकरण कार्य पूरा होने की संभावना है।

आईएआईईपीए का मुख्य कार्यकलाप क्षमता विकास / निर्माण करना है। अफ्रीका प्रायद्वीप की विविधता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक एवं लचीला शैक्षणिक कार्यक्रम के ढांचे की संकल्पना की गई है। शैक्षिक नीति योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान के रूप में आईएआईईपीए को अभिकल्पित किया गया है

जिसके कार्यक्रमों में शिक्षा के सभी पक्ष और उप–क्षेत्र समाहित होंगे। इसके शैक्षिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का पहला चरण संस्थान के भवन के नीवकरण और अन्य अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं संबंधी कार्यों के पूरा होने के तीन/चार महीनों के भीतर शुरू करने का प्रस्ताव है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रथम चरण में ये कार्य शामिल होंगेः (i) अफ्रीका संघ सदस्य देशों की शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षित मानव संसाधन के अंतराल को भरने के लिए शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों को प्रशिक्षित करना और शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में मानव संसाधन एवं सांस्थानिक क्षमता विकास का संबर्धन करना एवं शैक्षिक विकास के विविध पक्षों पर नीतिगत विश्लेषण और शोध कार्य आरंभ करना (ii) अफ्रीका संघ सदस्य देशों में शिक्षा सुधार से संबंधित निर्णयों के समर्थन मे अपेक्षित सूचना और ज्ञान के सृजन और विस्तार के लिये अफ्रीका संघ सदस्य देशों की स्थितियों/जरूरतों से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर आधारित शोध और केस अध्ययन करना (iii) देश, क्षेत्रीय/प्रायद्वीपीय स्तरों पर शैक्षिक विकास के रुझानों का आकलन/विश्लेषण और प्रकाशन एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों तथा परामर्श बैठकों के द्वारा उनका प्रसारण करना (iv) अफ्रीका संघ सदस्य देशों को उनकी शैक्षिक योजना और प्रबंधन संबंधी विशिष्ट क्षमता विकास और शोध की जरूरतों को पूरा करने में उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करना। (v) शैक्षिक विकास के विविध पहलूओं से संबंधित शोध और नवाचार, सीख, केस अध्ययनों संबंधी ज्ञान और सूचनाओं एवं शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन के प्रभावकारी कार्य व्यवहारों का प्रकाशन एवं अफ्रीकी देशों, क्षेत्रों और प्रायद्वीप स्तरों पर हितधारकों के बीच प्रसारण। (vi) सामान्यतः शैक्षिक विभाग और विशेषकर अफ्रीका संघ सदस्य देशों में शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नीतिगत परिसंवाद।

इसके प्रथम चरण के दौरान आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों के विस्तार के साथ दूसरे चरण के दौरान संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन पर लम्बी अवधि का उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें अफ्रीका संघ सदस्य देशों के प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों में बढ़ोतरी के लिये समिश्रित उपागम पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।

अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एकक

iLrdky; vkj iy[ku dUn % राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक अतिआधुनिक पुस्तकालय है जिसमें शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन और अन्य सहायक विषयों से संबंधित पुस्तकों और अन्य सामग्री का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र अपने पाठकों को विभिन्न सेवाएं जैसे–सीएएस, एसडीआई, संदर्भ सेवाएं वेब ओपैक, प्रसारण और फोटोकापी की सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेलनेट का सदस्य भी है। वर्तमान में पुस्तकालय में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे–यूएनओ, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ, यूनीसेफ, विश्व बैंक, ओईसीडी आदि द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों की रिपोर्टों के अलावा 55000 से अधिक पुस्तकों/दस्तावेज़ों तथा 6,435 जर्नलों का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय में शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन तथा अन्य सहायक क्षेत्रों से संबंधित 240 जर्नल मंगाए जाते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय पाठकों के लिए ऑन लाइन जर्नल डाटाबेस, जैसे–जेएसटीओआर, एलसेवियर और सेज भी मंगाता है। न्यूपा के प्रलेखन केंद्र में अधिकारिक रिपोर्टों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रकाशनों, शैक्षिक सर्वेक्षणों, पंचवर्षीय योजनाओं और जनगणना रिपोर्टों आदि सहित लगभग 18,500 दस्तावेज हैं। प्रलेखन केंद्र के पास महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हैं जो शैक्षिक शोध अैर नीति निर्माण के लिए जरूरी हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक डिजीटल अभिलेखागार बनाया गया है ताकि भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों, स्तरों और पक्षों पर शोध और संदर्भ के स्रोत के रूप में एक स्थान पर सभी दस्तावेजों की साफ्ट कापी सुलभ कारवाई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोक्ता समुदाय का निर्माण करना है जो कि विश्वविद्यालय के कार्यों का एक विस्तार है। नवीनतम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में उच्च स्तरीय स्वचालित डिजीटल स्कैन का उपयोग डिजाइन, संग्रह और डिजीटल दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस डिजीटल अभिलेखागार में प्रयोक्ता सुलभ बहुखोजी विकल्पों के साथ अंतनिर्हित उपयोगों सहित साफ्टवेयर उपलब्ध है।

dI;wVj dsUnz % कंप्यूटर केंद्र विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतें पूरा करता है। यह केंद्र विश्वविद्यालय के सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करता है। नेटवर्क संसाधन को पहुंचाने के लिए सभी संकाय और स्टाक को नेटवर्क प्वांइट सुलभ किए गए हैं। न्यूपा डोमेन से सभी संकाय और स्टाफ सदस्यों के व्यक्तिगत ई–मेल खाता खोले गए हैं। सभी संकाय सदस्यों को 1 जीबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। सभी स्टाफ सदस्यों को डेस्कटॉप और संकाय सदस्यों को लैपटाप आवंटित किए गए हैं। विश्वविद्यालय में समुचित नेटवर्क सुरक्षा का रखरखाव किया जा रहा है। क्रेंद्र में

आधुनिकतम सुविधाएं हैं, जैसे–आईबीएम–ई सिरीज सर्वर जो तीव्र अर्थनेट से जुड़ा है। वर्तमान में निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं हैं–उन्नत कैट–6 केबल, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा, जिसमें उच्च कार्यनिष्पादन वाले सर्वर्स, क्लाइंट पी सी, इंटरनेट से अपलिंक और अन्य सेवाएं और अति सक्षम बहुकल्पिक यू पी एस के जरिए पर्याप्त रूप में अनवरत पावर आपूर्ति उपलब्ध है।

izdk'ku ,dd % न्यूपा में शिक्षा के शोध और विकास के प्रसार– प्रचार हेतु प्रकाशन कार्यक्रम है। न्यूपा प्रकाशन एकक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य संबंधित सामग्री का रिपोर्टों, पुस्तकों, जर्नलों न्यूज़लेटर, अनुसंधान आलेखों, तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास की सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु महत्वपूर्ण

भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं: जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 'परिप्रेक्ष्य' हिन्दी जर्नल तथा एंट्रीप न्यूज़लेटर इत्यादि। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रकाशन एकक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है।

fgUnh d{k % यह कक्ष शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में व्यावसायिक प्रकाशनों के अनुवाद के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी प्रशासन और संकाय को सहयोग देता है।

ekufp=.k d{k % यह कक्ष राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रकाशनों/दस्तावेज़ों के लिये कम्प्यूटरीकृत मानचित्रण तथा अन्य मानचित्रण सेवाएं उपलब्ध कराता है।

अभिशासन और प्रबंधन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत घोषित एक मानद विश्वविद्यालय है जो सोसायटी अधिनियम पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में शामिल हैं : अध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, परिषद, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति और अध्ययन बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा घोषित ऐसे अन्य प्राधिकरण। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।

U;ik ifj"kn % न्यूपा परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। परिषद का मुख्य कार्य कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को कार्यान्वित करना है। न्यूपा परिषद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण का उत्तरदायी है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार न्यूपा परिषद के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति इसके उपाध्यक्ष हैं। परिषद के पदेन सदस्य हैं : सचिव, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और वित्त सलाहकार, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार। परिषद के अन्य सदस्य हैं– अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विख्यात शिक्षाविद्, अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य/संघ क्षेत्र प्रतिनिधि (5 प्रभागों में से प्रत्येक प्रभाग से एक–एक प्रतिनिधि) और अध्यक्ष द्वारा नामित न्यूपा संकाय का एक सदस्य। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव परिषद के सचिव हैं। दिनांक 31 मार्च 2014 के अनुसार न्यूपा परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट I में प्रस्तुत है।

izca/ku cksMZ % प्रबंधन बोर्ड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। राष्ट्रीय विश्वद्यािलय के कुलपति प्रबंध बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्य हैं : राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन सदस्य मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामिती, वि.अ.आ. के अध्यक्ष का एक नामिती, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय डीन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दो संकाय सदस्य (एक प्रोफेसर और एक सह–प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर), कुलसचिव, न्यूपा, प्रबंधन बोर्ड का सचिव होता है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

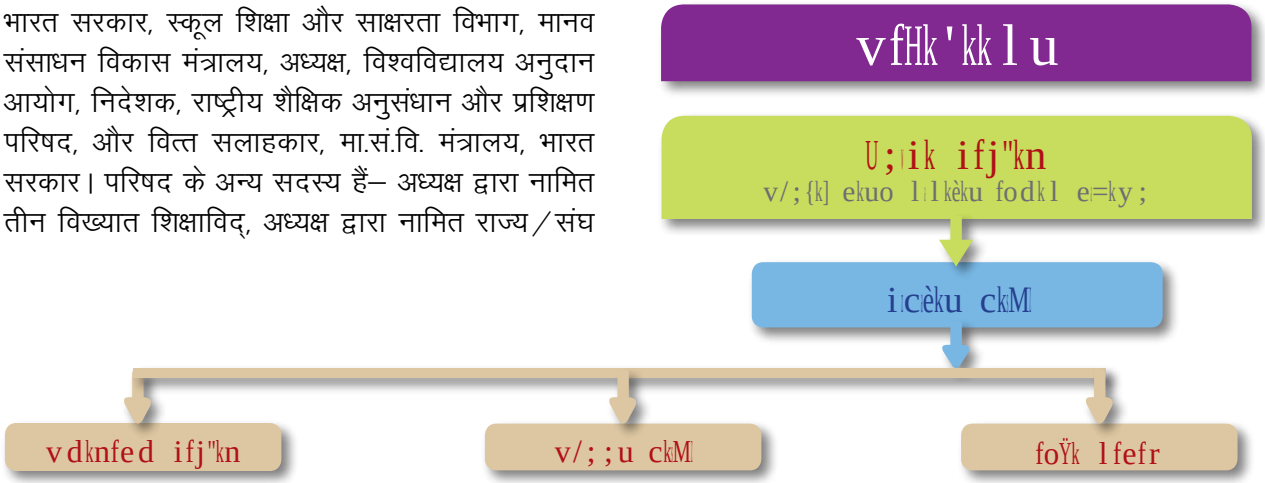

foÙk lfefr % वित्त समिति की मुख्य भूमिका विश्वविद्यालय की लेखा की जांच करना और व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करना है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा और वित्तीय आकलनों को वित्त समिति के सम्मुख रखा जाता है और समिति की टिप्पणियों के साथ इसे अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वार्षिक आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय की सीमाऐं तय करती हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं; इसके अतिरिक्त न्यूपा परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, वित्तीय सलाहकार, मा.सं.वि. मंत्रालय और वि.अ.आ. का एक–एक प्रतिनिधि होता है। वित्त अधिकारी, वित्त समिति के सचिव का कार्य करता है। 31 मार्च 2014 के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट III में दी गई है।

vdknfed ifj"kn % न्यूपा अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय का शीर्षस्थ अकादमिक निकाय है। अकादमिक परिषद शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श के स्तर में सतत सुधार और अंतर–विभागीय सहयोग, परीक्षा और परीक्षण आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका पदेन अध्यक्ष कुलपति होता है। अकादमिक परिषद में शामिल हैं: विश्वविद्यालय के संकाय डीन, अकादमिक विभागों के अध्यक्ष, और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन शिक्षाशास्त्री जो विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित हों और विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा चक्रानुसार नामित एक सहायक प्रोफेसर और तीन सहयोजित सदस्य जो शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य न हों और अकादमिक परिषद द्वारा विषय विशेषज्ञ के आधार पर सहयोजित किए गए हों। न्यूपा का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है। 31 मार्च 2013 के अनुसार सदस्यों की सूची IV में दी गई है।

vè;;u cksM % न्यूपा के कुलपति अध्ययन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्य हैं: संकाय–डीन, विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा नामित एक सह–प्रोफेसर, और एक सहायक प्रोफेसर और कुलपति द्वारा सहयोजित अधिकतम दो विषय विशेषज्ञ। अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की सूची 31 मार्च, 2014 के अनुसार परिशिष्ट V में दी गई है।

dk;lcy vkj lfefr;k %

कुलपति द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समय–समय पर विशेष कार्यबलों और समितियों का गठन किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों को शामिल करके परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। कुलपति की अध्यक्षता में शोध अध्ययन सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। इसमें अन्य विशेषज्ञों के साथ–साथ सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुलसिचव इस समिति के सदस्य सचिव हैं जो सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करता है।

प्रशासन और वित्त

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में तीन अनुभाग–अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन और दो कक्ष–प्रशिक्षण कक्ष और समन्वय कक्ष हैं। कुलसचिव सभी अनुभागों के प्रभारी हैं। कुल सचिव न्यूपा परिषद, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सचित भी हैं। कुल सचिव को प्रशासनिक कामकाज में प्रशासनिक अधिकारी और अनेक अनुभाग अधिकारी अनुसमर्थन प्रदान करते हैं।

कुलसचिव अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एककों, जैसे–पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, प्रकाशन एकक, मानचित्रण और हिंदी कक्ष के कार्य कलापों के प्रति उत्तरदायी हैं। वित्त अधिकारी वित्त और लेखा अनुभाग के प्रभारी हैं। अनुभाग अधिकारी (लेखा) वित्त अधिकारी का अनुसमर्थन करता है।

LVkQ dh l¡[;k ¼2013&14½

31 मार्च, 2014 के अनुसार विश्वविद्यालय की कुल स्टाफ संख्या 162 थी।

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय को कुल 2600.00 लाख रुपये का अनुदान मिला (गैर–योजना मद में 1415.00 लाख रुपये और योजना मद में रु. 1185.00 लाख) प्राप्त हुए। वर्ष के आरंभ में विश्वविद्यालय के पास योजना और गैर–योजना, दोनों मदों में 154.51 लाख रुपये शेष थे। वर्ष के दौरान कार्यालय और छात्रावास से 28.98 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। योजना और गैर–योजना मदों में इस वर्ष का व्यय 2714.83 लाख रुपये था।

दूसरे संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों के मद में इस वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के पास 205.38 लाख रुपये थे और 415.00 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्ति हुई। प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों पर वर्ष में कुल 352.36 लाख रुपये खर्च किए गए। (परिशिष्ट–VII)

परिसर और भवन
आधारभूत सुविधा

विश्वविद्यालय के पास एक चार–मंजिला कार्यालय, सुसज्जित स्नानघरयुक्त 60 कमरों वाला एक सात मंजिला छात्रावास और एक आवास–क्षेत्र है। इस आवास क्षेत्र में टाइप I के 16, टाइप II से V तक के 8–8 क्वार्टर और एक कुलपति आवास हैं।

विश्वविद्यालय के पास बिंदापुर, द्वारका में टाइप–III के 25 क्वार्टर हैं।

विश्वविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण कक्ष, कंप्यूटर केंद्र, अंतरराष्ट्रीय डायनिंग हाल, जिम और क्लास रूम हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में हाल ही में अर्जित 2100 वर्ग मीटर के भूखंड में नया अकादमिक भवन निर्माण के लिये अपेक्षित कदम उठाए गए हैं।

2 अध्यापन और व्यावसायिक विकास

कार्यक्रम

अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

एम.फिल. और पी-एच.डी

'kf{kd i'kklu d fy, fo}ku r;kj djuk

एम.फिल और पी–एच.डी. कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्मियों की शोध क्षमता के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शैक्षिक नीति, योजना प्रशासन तथा वित्त के संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक फीडर संस्थान है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जरूरत के अनुसार शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में विशेषज्ञता से युक्त मानव संसाधनों का विकास करता है। ऐसे विशेषज्ञ जो अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों/एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियों के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा तैयार किये जाते हैं, वे व्यापक एवं गतिशील संदर्भों में समुचित योजनाओं और कार्यनीतियों के निर्माण या सांस्थानिक प्रबंधन के सीमित भूमिकाओं से जुड़े मामलों के समाधान हेतु पूर्णतः सक्षम होते हैं।

वस्तुतः विश्वविद्यालय की एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियाँ विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन पर केंद्रित हैं। इसके द्वारा विश्वविद्यालय युवा शोधकर्त्ताओं को सशक्त और सक्षम बनाता है और शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उनका करियर तैयार करता है। न्यूपा यह कार्य कर रहा है और इसके माध्यम से यह शैक्षिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण करने हेतु विशेषज्ञ और सक्षम मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रमों का महत्व इसमें अंतर्निहित गतिशील और लचीले उपागम के द्वारा है जिसमें यह शिक्षा और सामाजिक विकास की अन्य सहायक क्षेत्रों से जुड़कर नवाचारी बहुशास्त्रीय पाठ्यक्रमों का विस्तार करता है।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रम में शामिल हैं: (i) पूर्णकालिक एम.फिल. कार्यक्रम (ii) पूर्णकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम और (iii) अंशकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वर्ष 2007–08 में आरंभ किए गए थे। एम.फिल और पी–एच.डी. कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्मियों की शोध क्षमता के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शैक्षिक नीति, योजना प्रशासन तथा वित्त के संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। एम.फिल और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे किए गए शोध अध्ययनों से अपेक्षा की जाती है कि ये नीति

निर्माण, शिक्षा सुधार कार्यक्रमों तथा क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ–साथ ज्ञान आधार को समृद्ध करने में भारी योगदान करेंगे। एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत शोध के व्यापक क्षेत्रों में शामिल हैं–शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा में समता और समावेशन, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, अल्पसंख्यक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा और शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण।

एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष की है। इस दो वर्षीय एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष का पाठ्यक्रम कार्य (30 क्रेडिट) है। इसके बाद एक वर्ष लघु शोध प्रबंध (30 क्रेडिट) के लिए है। दो वर्ष के एम.फिल. पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत और निर्धारित आर्हता (वर्तमान में 10 प्वाइंट स्केल पर) 6 एफ जी पी ए या इससे अधिक का ग्रेड पाने वाले शोधार्थी पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि के दो वर्ष बाद ही शोधार्थी अपने शोध प्रबंध जमा कर सकते हैं।

पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को दाखिला की पुष्टि हेतु एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। इसके बाद वे दो वर्ष के शोध कार्य के उपरांत ही वे उपाधि हेतु शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं।

अंशकालिक पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को पी–एच.डी. में दाखिला की पुष्टि से पहले एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। अंशकालिक पी–एच.डी. के शोधार्थी दाखिला की पुष्टि के कम से कम चार वर्ष बाद अपना शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं।

fooj.k	,e-fQy-	ih&,p-Mh-i.kdkfyd	ih&,p-Mh-vi'kdkfyd	;kx
वर्ष 2013–14 में नामांकित विद्यार्थी	16	06	&	22
वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की संख्या	18 (वर्ष 2012–13 में नामांकित 10 विद्यार्थियों सहित)	29 (वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक नामांकित विद्यार्थियों सहित)	9 (वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक नामांकित विद्यार्थी)	56
वर्ष 2013–14 के दौरान स्नातक विद्यार्थी	10	02	&	12

डिप्लोमा कार्यक्रम

डिप्लोमा कार्यक्रम के तीन घटक हैं : (i) न्यूपा में तीन महीने का सघन पाठ्यचर्या कार्य, (ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के शोध निर्देशन में पदस्थापित जिले में तीन माह का परियोजना अध्ययन कार्य और अंत में (iii) प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों पर 5 दिवसीय कार्यशाला शामिल हैं।

'kSf{kd ;kstuk vkSj iz'kklu esa fMIyksek ¼Mhik½

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्ष 1982–83 से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में विशेष रूप से डिजाइन, डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आरंभ में यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया था। वर्षों से इस कार्यक्रम में सतत रूप से बदलाव किया जाता रहा है ताकि जिला स्तर के शैक्षिक प्रशासकों एवं एससीईआरटी/एसआईई में शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत संकाय सदस्यों की पेशेवर आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कार्यरत अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों के संकाय सदस्यों को भी प्रवेश दिया जाता है।

डिप्लोमा कार्यक्रम के तीन घटक हैं। इनमें न्यूपा में तीन महीने का सघन पाठ्यचर्या कार्य, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के शोध निर्देशन में पदस्थापित जिले में तीन माह का परियोजना अध्ययन कार्य और अंत में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों पर 5 दिवसीय कार्यशाला शामिल हैं। इसकी पाठ्यचर्या में शामिल हैं– शिक्षा और समाज से जुड़े अध्ययन, शैक्षिक योजना और प्रशासन, वित्तीय योजना और प्रबंधन, शोध कार्य, मात्रात्मक तकनीक और संगणक अनुप्रयोग। डिप्लोमा पाठ्यक्रम 24 क्रेडिट का है जिसमें 17 क्रेडिट पाठ्यचर्चा कार्य का है और एक क्रेडिट प्रतिभाग संगोष्ठी आलेख के लिए और 6 क्रेडिट परियोजना कार्य (मौखिक परीक्षा सहित) के लिए निर्धारित है।

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय ने 33वें डिप्लोमा कार्यक्रम के तीसरे घटक का आयोजन 20–24 मई 2013 (5 दिन) को किया जिसका पहला घटक 1 सितंबर–30 नवंबर 2013 तक (91 दिन) आयोजित किया गया था। 33वें डिप्लोमा कार्यक्रम के तीसरे घटक को 25 प्रतिभागियों ने पूरा किया। 34वें डिप्लोमा कार्यक्रम में 12 राज्यों/संघ क्षेत्रों से कुल 25 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रथम घटक के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 नवंबर 2013 तक (91 दिन) अध्यापन–अधिगम कार्य किया गया और दूसरा घटक 1 दिसंबर 2013 से 28 फरवरी 2014 तक किया गया।

डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग ने किया। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राज्यवार भागीदारी का विवरण तालिका 2.1 में प्रदर्शित है :

वस्तुतः न्यूपा मौजूदा डिप्लोमा कार्यक्रम के ढांचे में बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसे पुनर्गठित करके लम्बी अवधि के पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम में उन्नत किया जा रहा है।

rkfydk 2-1% jk"Vªh; fMIyksek dk;Øe esa jkT;@la?k 'kkflr {ks=okj Hkkxhnkjh

jkT;@la?k {ks=	33oka Mik	34oka Mik	;ksx
अरुणाचल प्रदेश	2	3	3
बिहार	–	3	3
हरियाणा	4	–	4
हिमाचल प्रदेश	–	2	2
जम्मू और कश्मीर	2	2	4
कर्नाटक	1	–	1
केरल	1	–	1
मध्य प्रदेश	3	3	6
मणिपुर	4	3	7
मेघालय	–	2	2
मिजोरम	3	2	5
नागालैण्ड	–	1	1
राजस्थान	–	1	1
सिक्किम	–	2	2
उत्तराखंड	2	3	5
पश्चिम बंगाल	2	–	2
दिल्ली	1	–	1
;ksx	25	25	50

'kSf{kd ;kstuk vkSj iz'kklu esa varjjk"Vªh; fMIyksek ¼vkbZMsik½

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1985 से विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में 6 माह का अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के विद्यार्थी एशिया, अफ्रीका, मध्य एशियाई गण राज्यों, दक्षिणी अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों के देशों से आते हैं। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं– (i) सघन पाठ्यचर्या कार्यक्रम; (ii) अनुप्रयुक्त कार्य और (iii) लघु शोध प्रबंधन। आईडेपा की अवधि छः माह है और यह दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में तीन माह का सघन पाठ्यचर्या है जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह चरण आवासीय है और प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस चरण के दौरान परिसर में निवास करें। दूसरे चरण में प्रतिभागी को स्वदेश में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में क्षेत्र आधारित शोध परियोजना अध्ययन करना होता है।

आईडेपा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में केंद्रिक पाठ्यक्रम और वैकल्पिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक अभिविन्यास और अप्रयुक्त कार्य शामिल हैं। पाठ्यचर्या कार्य के विषय हैं : शिक्षा और विकास से संबंधित अध्ययन, विकासशील देशों में शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र, शैक्षिक योजना और प्रशासन परियोजना नियोजन, शिक्षा में व्यष्टि स्तरीय योजना, शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन, जनशक्ति योजना, शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकें,

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के विद्यार्थी एशिया, अफ्रीका, मध्य एशियाई गण राज्यों, दक्षिणी अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों के देशों से आते हैं। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं– (i) सघन पाठ्यचर्या कार्यक्रम; (ii) अनुप्रयुक्त कार्य और (iii) लघु शोध प्रबंधन।

शैक्षिक प्रबंधन, शोध प्रविधि और सांख्यिकी और शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली। अनुप्रयुक्त कार्य में शामिल हैं : विषयगत संगोष्ठियां डिप्लोमा कार्यक्रम के अभिन्न घटक हैं जो प्रत्येक प्रतिभागी या प्रतिभागियों के समूह को शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित विषयों से जुड़े वस्तुगत आंकड़ा और अनुभवों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने और उनका परस्पर आदान–प्रदान करने के अवसर प्रदान करती हैं। संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण के एक भाग के रूप में प्रतिभागियों को अपने देश की शिक्षा प्रणाली की विशिष्ट प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करने और परस्पर आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को स्वदेश में उनके कार्यों की प्रासंगिकता और जरूरतों के विशिष्ट क्षेत्र में शोध परियोजना की रूपरेखा बनाने में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशलों के बीच संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में चरण–II के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी के लिए एक शोध निर्देशक नियुक्त किया जाता है जो दूसरे चरण के कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी के परियोजना कार्य का निर्देशन करता है।

कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रतिभागी के स्वदेश में आयोजित होता है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रथम चरण के दौरान निर्धारित क्षेत्र कार्य आधारित शोधपरियोजना पर कार्य करना पड़ता है। शोध परियोजना कार्य (तीन माह की अवधि) पूरा करने के बाद प्रतिभागी को अपना लघुशोध प्रबंध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना पड़ता है। लघु शोध प्रबंध की प्राप्ति और तदुपरांत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा उसके मूल्यांकन के बाद प्रतिभागी को डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय ने 29वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा का दूसरा चरण पूरा किया जिसका प्रथम चरण 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2013 को आयोजित किया गया था। उसमें 22 देशों के 35 प्रतिभागी शामिल हुए। 29वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2013 के दौरान आयोजित किया गया।

30वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रथम चरण 1 फरवरी 2014 को शुरु हुआ और इसके प्रथम घटक की अध्यापन–अधिगम गतिविधियां 30 अप्रैल 2014 तक पूरी की गईं। 30वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में 17 देशों से कुल 27 प्रतिभागी शामिल हुए। इसका दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2014 के दौरान प्रतिभागियों के स्वदेश में नियत किया गया जो परियोजना कार्य पर आधारित था।

अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग करता है।

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों की देशवार भागीदारी का विवरण तालिका 2.2 में प्रदर्शित है।

rkfydk 2-2 % vrjjk"Vªh; fMIykek dk;Øeksa esa ns'kokj Hkkxhnkjh			
ns'k dk uke	29oka fMIykek	30oka fMIykek	;ksx
बांग्लादेश	–	3	3
भूटान	3	3	6
बोत्सवाना	1	–	1
चिली	1	–	1
कनाडा	–	–	0
कंबोडिया	2	–	2
जीबौती	1	–	1
इथियोपिया	2	–	2
घाना	2	1	3
गिनी	1	–	1
लाइबेरिया	–	1	1
मेडागास्कर	2	–	2
मलावी	2	–	2
मलेशिया	–	1	1
मालदीव	–	1	1
नेपाल	1	–	1
नाइजीरिया	2	–	2
नाइजर	1	2	3
फिलीस्तीन	–	1	1
पपुआ न्यू गिनी	–	1	1
फिलीपीन्स	2	2	4
रवान्डा	–	1	1
श्रीलंका	1	2	3
दक्षिण सूडान	–	1	1
सेनेगल	2	–	2
ताजिकिस्तान	1	–	1
तंजानिया	2	1	3
थाईलैण्ड	1	–	1
यूगांडा	2	2	4
उज़्बेकिस्तान	–	1	1
वियतनाम	2	–	2
जांबिया	1	3	4
;ksx	35	27	62

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

शैक्षिक योजना और प्रशासन में सुधार हेतु सांस्थानिक क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न वर्गों के शिक्षाकर्मियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकलाप के रूप में सतत जारी है। वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा के विभिन्न विकास क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और शिक्षा नीति योजना, प्रशासन के विविध पक्षों से जुड़े 40 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के विषय थे : स्कूलों की योजना और प्रबंधन, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन, माध्यमिक स्तर पर स्कूल प्रावधानों का आकलन, शैक्षिक वित्त की योजना और प्रबंधन, और स्कूल नेतृत्व आदि। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी थे जिला और राज्य स्तर के शिक्षाकर्मी, शिक्षा निदेशक और राज्य स्तर के अन्य अधिकारी, केंद्र, राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और अन्य प्राधिकारी, कालेज प्राचार्य और कालेजों तथा उच्च शिक्षा के वरिष्ठ प्रशासक, विश्वविद्यालय तथा समाजविज्ञान शोध संस्थानों के नवनियुक्त प्राध्यापक आदि। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गईं :

'kf{kd ;kstuk foHkkx

- शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीक के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 8–19 जुलाई, 2013 नई दिल्ली (22 प्रतिभागी)
- पूर्वोत्तर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की योजना पर मुख्य प्रशिक्षकों के लिये दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, 16–28 सितंबर, 2013 और 6–17 नवंबर, 2013, गुवाहाटी, असम (कुल 70 प्रतिभागी)
- शिक्षा में मात्रात्मक शोध विधि पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 16–27 दिसंबर, 2013 नई दिल्ली (43 प्रतिभागी)

'kSf{kd iz'kklu foHkkx

- बिहार के जि.शि.अ. और प्र.शि.अ. के लिये शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, 19–20 जून, 2013 (525 प्रतिभागी)
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 23–27 सितंबर, 2013 (29 प्रतिभागी)
- पूर्वोत्तर राज्यों के जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए शिक्षा व्यवस्था में अभिशासन संबंधी मुद्दे पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 7–11 अक्टूबर, 2013 (23 प्रतिभागी)
- शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य पर अभिविन्यास सहित कार्यशाला, 2–6 दिसंबर 2013 (11 प्रतिभागी)
- विश्वविद्यालयों और कालेजों में विविधता और समता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 2–6 दिसंबर, 2013 (26 प्रतिभागी)
- गुजरात के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का अध्ययन दौरा, 23–26 दिसंबर, 2013 (27 प्रतिभागी)
- शैक्षिक योजना और प्रशासन पर डीडीपीआई और बीईओ के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन, 7–8 जनवरी, 2014 (216 प्रतिभागी)
- राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों के लिये संगठनात्मक विकास पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 27–31 जनवरी, 2014 (33 प्रतिभागी)

'kSf{kd foÙk foHkkx

- विश्वविद्यालय के वित्त की योजना और प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23–27 सितंबर, 2013, जलगांव, महाराष्ट्र (24 प्रतिभागिता)
- उच्च शिक्षा की वित्त व्यवस्था की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 11–15 नवंबर, 2013 (12 प्रतिभागी)
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिये स्कूल व्यवस्था की योजना एवं प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, नेहू, शिलांग, मेघालय, 25–29 नवंबर, 2013, (29 प्रतिभागी)
- स्कूल वित्त व्यवस्था की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 9–13 दिसंबर 2013 (9 प्रतिभागी)

'kf{kd uhfr foHkkx

- शिक्षा में मात्रात्मक शोध विधि (विषयः शिक्षा में समता) पर अभिविन्यास कार्यक्रम 22 जुलाई – 2 अगस्त, 2013 (33 प्रतिभागी)
- समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 9–13 सितंबर, 2013 (26 प्रतिभागी)
- शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर अनिल बोर्डिया नीति संगोष्ठी, 16–17 सितंबर, 2013 (38 प्रतिभागी)
- पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय प्राधिकरण की भूमिका और कार्यकलापों पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 3–7 फरवरी, 2014, गुवाहाटी, असम (25 प्रतिभागी)

Ldy vkj vukipkfjd f'k{kk foHkkx

- स्कूल शिक्षा में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य स्तरीय सम्मेलन (नागालैंड) 13–14 मई, 2013, कोहिमा, नागालैंड (107 प्रतिभागी)
- स्कूल शिक्षा में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य स्तरीय सम्मेलन (गुजरात) 30–31 मई, 2013, आनंद, गुजरात (114 प्रतिभागी)
- शिक्षा का अधिकार पर दो अभिविन्यास कार्यक्रम, 22–26 जुलाई, 2013 और 5–8 अगस्त, 2013 (कुल 58 प्रतिभागी)
- उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के यौन अपराध को रोकने पर परामर्श बैठक, 27 अगस्त 2013 (35 प्रतिभागी)
- स्कूल शिक्षा में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य स्तरीय सम्मेलन (अरुणाचल प्रदेश), 18–19 सितंबर 2013, इटानगर
- स्कूल शिक्षा में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य स्तरीय सम्मेलन (त्रिपुरा), 15–16 नवंबर 2013, त्रिपुरा, (72 प्रतिभागी)
- स्कूल शिक्षा में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य स्तरीय सम्मेलन (सिक्किम) 19 दिसंबर 2013, गंगटोक, (26 प्रतिभागी)
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की स्कूल में भागीदारी में सुधार पर कार्यशाला, 27–31 जनवरी, 2014 (48 प्रतिभागी)
- लोकतंत्र और शिक्षा, विकासः समता, समावेशन और स्थायित्व पर अंतरराष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, 6–8 मार्च, 2014 (115 प्रतिभागी)

mPp ,o 0;kolkf;d f'k{kk foHkkx

- जम्मू और कश्मीर के कालेज प्राचार्यों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 23–27 जून, 2013, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
- विश्वविद्यालयों के बीच अध्यापन अधिगम पर विषय आधारित नेटवर्क पर कार्यशाला, 29–31 अगस्त, 2013, (24 प्रतिभागी)
- कालेज प्राचार्यों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 30 सितंबर – 5 अक्टूबर, 2013, (13 प्रतिभागी)
- भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली पर कार्यशाला, 28–30 अक्टूबर, 2013, (30 प्रतिभागी)
- उच्च शिक्षा में अध्यापन–अधिगम केंद्रों के रूप में अकादमिक स्टाफ कालेजों की परिकल्पना पर कार्यशाला, 26–29 नवंबर, 2013, (32 प्रतिभागी)
- स्वायत्त कालेजों में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य व्यवहार पर कार्यशाला, 9–13 दिसंबर, 2013 (37 प्रतिभागी)

'kf{kd ic/ku lpuk i.kkyh foHkkx

- एकीकृत डाइस पर कार्यशाला 29–30 जुलाई, 2013 (75 प्रतिभागी)
- 'एजुसेट के माध्यम से डाइस डाटा कैप्चर फार्मेट' पर 'अभिविन्यास कार्यक्रम (चुनिंदा राज्यों के लिए 13 सितंबर, 2013 (प्रतिभागी : स्टूडियो में 20 और देशभर में 10,000)
- माध्यमिक शिक्षा की योजना और अनुश्रवणों में संकेतकों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 16–20 सितंबर, 2013, (44 प्रतिभागी)
- 'एजुसेट के माध्यम से डाइस डाटा कैप्चर फार्मेट' पर 'अभिविन्यास कार्यक्रम (चुनिंदा राज्यों के लिए)
- शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की योजना एवं अनुश्रवण में संकेतकों को उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3–7 फरवरी, 2014 (45 प्रतिभागी)

'kf{kd if'k{k.k vkj {kerk fodkl foHkkx

- बेसिक शिक्षा अधिकारियों, डीआईओएस और बीईओ के लिये शैक्षिक योजना और प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23–24 अप्रैल, 2013, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (531 प्रतिभागी)
- भूटान के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिये शैक्षिक योजना और प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5 मई – 2 जून 2013, (24 प्रतिभागी)
- अल्पसंख्यक प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्षमता विकास पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 4–8 नवंबर, 2013, (28 प्रतिभागी)
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु अपेक्षित क्षमता विकास के लिए डायट की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों की पहचान पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 27–31 जनवरी, 2014, गुवाहाटी, असम (30 प्रतिभागी)
- जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत आश्रम स्कूलों के प्रमुखों के लिये क्षमता विकास पर दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुरोध कार्यक्रम) 27–31 जनवरी 2014, नासिक, महाराष्ट्र (30 प्रतिभागी)

- इंडोनेशिया के शिक्षा अधिकारियों का शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर अध्ययन दौरा, 13–27 नवंबर, 2013 (इंडोनेशिया के 11 प्रतिभागी)
- मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रबंधित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए सांस्थानिक योजना पर आठवां वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम, 9–20 दिसंबर, 2013 (53 प्रतिभागी)
- गुजरात के डायट की योजना और प्रबंधन शाखा के संकाय के क्षमता विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुरोध कार्यक्रम) 6–10 जनवरी, 2014 (200 प्रतिभागी)

jk"Vªh; fo|ky; urRo dsUnz

dsUnz esa 2013&14 ds nkSjku iwjh dh xbZ Lrjokj xfrfof/k;ka %

Lrj&1% ikB~;p;kZ vkSj lkexzh fodkl&

- एनसीटीएल, यू.के,, राष्ट्रीय संसाधन समूह और राज्य संसाधन समूह के साथ सात राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं (188 प्रतिभागी)

Lrj 2% {kerk fodkl

- चरण–1 के राज्यों के राज्य संसाधन समूहों की क्षमता विकास के लिये 13 कार्यशालाएं (588 प्रतिभागी)

- स्कूल प्रमुखों के क्षमता विकास के लिये दो पायलट कार्यक्रम– एक इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालय प्रमुखों के लिये (50 प्रतिभागी) और दूसरा दमन दीव, दादरा और नागर हवेली के माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों के साथ (41 प्रतिभागी)
- एनसीटीएल, यू.के. के सहयोग से राजस्थान और तमिलनाडु के माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों के लिये संकुल आधारित क्षमता विकास कार्यशालाएं (1400 प्रतिभागी)

Lrj 3 % uVod vkj lLFkk fodkl

- चरण I के राज्यों में 9 परामर्श कार्यशालाएँ (518 प्रतिभागी)
- राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या ढांचा और विद्यालय नेतृत्व विकास पर हस्तपुस्तिका के शुभारंभ के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ आयोजित राष्ट्रीय लोकापर्ण समारोह (250 प्रतिभागी)
- चरण–1 और चरण–2 के राज्यों के साथ राष्ट्रीय समीक्षा योजना कार्यशाला (88 प्रतिभागी)

केंद्र का विज़न विद्यालयों के लिए नेतृत्व की ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना है जो प्रभावकारी अभिशासन के द्वारा विद्यालयों को सतत रूप से अधिगम संगठनों के रूप में रूपांतरित करे और समता और समावेशन के साथ सृजनात्मक और उत्कृष्टता को बढ़ावा दे।

वर्ष 2013–14 के दौरान डिप्लोमा कार्यक्रमों के अलावा विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 93 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आदि आयोजित किए जिनमें कुल 6455 प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें 6342 प्रतिभागी (तालिका 2.4) भारतीय थे और शेष 116 प्रतिभागी अन्य दूसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के थे।

rkfydk 2-3% lHkh dk;Øeksa esa ns'kokj Hkkxhnkjh

Ø- l-	ns'k	Hkkxhnkjksa dh la[;k
1.	बांग्लादेश	3
2.	भूटान	30
3.	बोत्सवाना	1
4.	चिली	1
5.	कंबोडिया	2
6.	जीबोती	1
7.	इथियोपिया	2
8.	घाना	3
9.	गिनी	1
10.	इंडोनेशिया	11
11.	लाइबेरिया	1
12.	मेडागास्कर	2
13.	मलावी	2
14.	मलेशिया	1
15.	मालदीव	1
16.	नेपाल	1
17.	नाइजीरिया	2
18.	नाइजर	3
19.	फिलीस्तीन	1
20.	पपुआ न्यू गिनी	1
21.	फिलीपीन्स	4
22.	रवान्डा	1
23.	श्रीलंका	3
24.	दक्षिण अफ्रीका	4
25.	दक्षिण सूडान	1
26.	सेनेगल	2
27.	ताजिकिस्तान	1
28.	तंजानिया	3
29.	थाइलैंड	1
30.	यू एस ए	8
31	युनाइटेड किंगडम	7
32.	यूगांडा	4
33.	उजबेकिस्तान	1
34.	वियतनाम	2
35.	जांबिया	4
;ksx		116

rkfydk 2-4% 0;kolkf;d fodkl dk;Øek e
jkT;@l?k 'kkflr {k=kokj Hkkxhnkjh 2013&14

jkT;@l?kh; {k=	Hkkxhnkjh dh l[;k
आंध्र प्रदेश	121
अरुणाचल प्रदेश	94
असम	119
बिहार	555
छत्तीसगढ़	129
गोवा	12
गुजरात	459
हरियाणा	28
हिमाचल प्रदेश	85
जम्मू और कश्मीर	47
झारखण्ड	16
कर्नाटक	293
केरल	81
मध्य प्रदेश	32
महाराष्ट्र	111
मणिपुर	30
मेघालय	46
मिजोरम	130

jkT;@l?kh; {k=	Hkkxhnkjh dh l[;k
नागालैण्ड	124
ओडिशा	65
पंजाब	12
राजस्थान	1864
सिक्किम	16
तमिलनाडु	327
त्रिपुरा	79
उत्तराखंड	24
उत्तर प्रदेश	853
पश्चिम बंगाल	110
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
चंडीगढ़	15
दादरा और नगर हवेली	25
दमन और दीव	27
दिल्ली	404
लक्षद्वीप	0
पुडुचेरी	5
;kx	6342

LEVEL-WISE PARTICIPATION: 2013-14

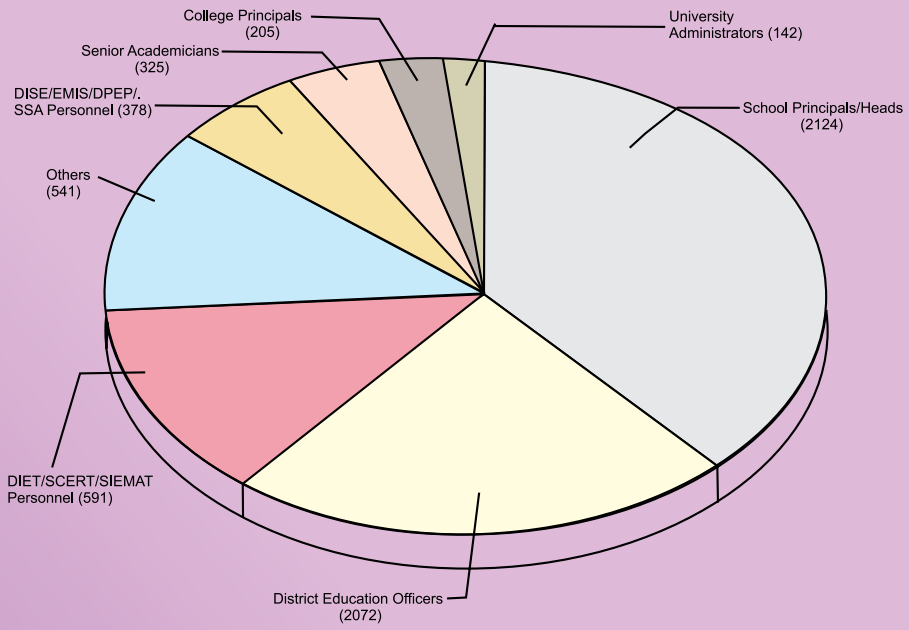

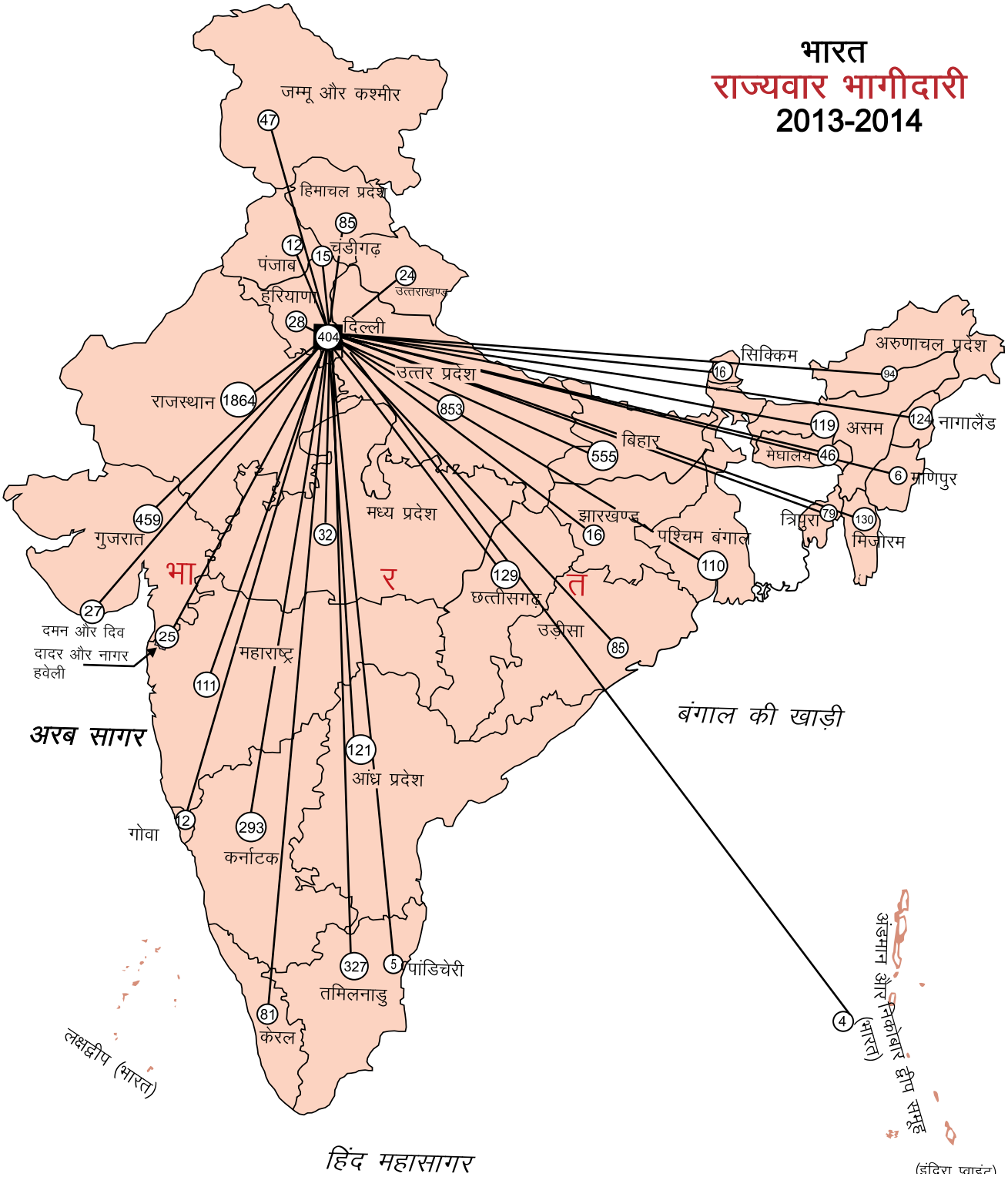

भारत

राज्यवार भागीदारी

2013-2014

3

अनुसंधान

एवं मूल्यांकन

अनुसंधान एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्र के विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु साक्ष्यों के आधार पर विकल्प और रणनीति तैयार करने के लिए नए ज्ञान सृजन करने के क्रम में शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ अंतर – अनुशासनात्मक अनुसंधान करता है और वित्तीय सहयोग देकर इसको बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में और अन्य देशों में मौजूदा नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों, शैक्षिक योजना तकनीकों में तुलनात्मक अध्ययन और प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रियाओं का मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, समीक्षा और मूल्यांकन करता है।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में और अन्य देशों में मौजूदा नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों, शैक्षिक योजना तकनीकों में तुलनात्मक अध्ययन और प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रियाओं का मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, समीक्षा और मूल्यांकन करता है।

शैक्षिक नीतियों, योजना और प्रबंधन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए ज्ञान का सृजन करने हेतु अनुदैर्ध्य अध्ययन सहित, कार्रवाई अनुसंधान पर बल दिया गया है। एम.फिल. और पी–एच.डी. अध्ययन के अलावा, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित अनुसंधान कार्यक्रमों में अन्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अध्ययन, कार्यक्रम मूल्यांकन अध्ययन और डेटा प्रबंधन अध्ययन, संकाय सदस्यों द्वारा शोध अध्ययन को शामिल किया गया। शोध अध्ययन शिक्षा प्रणाली में संभावित उभरने वाले प्राथमिकता के मुद्दों से निपटने हेतु या भारतीय शिक्षा प्रणाली में वास्तविक मुद्दों से संबंधित होते हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान 16 शोध अध्ययन पूर्ण किये गये, जबकि 29 अध्ययन जारी थे।

पूर्ण अनुसंधान अध्ययन

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

1- lehl vkdMk 2009&10 d vkèkkj ij f'k{kk d ikoèkku vkj Ldy dk;l fu"iknu ¼fcuk lgk;rk fufèk½

vUos"kd % Mk- ,u-d- ekgrh

fu"d"kk dk lkjk'k

शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने और उसमें सुधार लाने में शैक्षिक सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुतः भारत के शैक्षिक संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। कम और अपर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं संस्थानों की संपूर्ण कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत भारत में शैक्षिक सुविधाओं, जैसे–मूलभूत सुविधाओं, अध्यापक, शिक्षण–अधिगम सामग्री और भारत के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक सम्प्राप्ति के बीच परस्पर संबंधों का अन्वेषण करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में अधिगम पर भारी प्रभाव डालने वाली स्कूली सुविधाओं के विविध आयामों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के उद्देश्य थेः 1. माध्यमिक स्तर पर स्कूली सुविधाओं की स्थिति और विद्यार्थियों को कार्य निष्पादन का विश्लेषण करना 2. माध्यमिक स्तर पर स्कूली सुविधाओं और विद्यार्थी कार्य निष्पादन के बीच संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा और 3. माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु समुचित तरीके और माध्यमों के बारे में सुझाव देना।

यह अध्ययन माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (सेमीस) के अंतर्गत सभी 35 राज्यों/संघ क्षेत्रों के सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों/कालेजों से सभी घटकों (पहुंच, भागीदारी, प्रतिधारण और परिणाम) पर 2009–10 के लिए उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण पर अधारित है।

इस अध्ययन से पता चलता है कि माध्यमिक स्तर के स्कूलों में मूलभूत शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। विद्यालय भवन, चारदीवारी, खेल के मैदान, जेनसेट, इंटरनेट और कंप्यूटर, प्रयोगशाला, साफ–सफाई सुविधाएं विशेषकर लड़कों और लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचालय सुविधायें माध्यमिक स्तर के अधिकांश संस्थानों में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अतः सुधार कार्यक्रमों जैसे– आरएमएसए और अन्य दूसरे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में मौजूदा माध्यमिक स्कूलों/वर्गों में मूलभूत सुविधाओं और पर्याप्त स्टाफ की तैनाती पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है यह प्रयास निश्चित तौर पर माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने और उसे मजबूत बनाने में और साथ ही साथ भारत भर के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और संस्थानों के समग्र कार्य निष्पादन में दूरगामी प्रभाव डालेगा।

2- xtjkr e i[kM Lrj d i'kklu dk v/;;u % mHkjrh pqukfr;k vkj lèkkj dh vko';drk,

vUos"kd % ik- dekj lj'k vkj Mk- vkj-, l- R;kxh

fu"d"kk dk lkjk'k

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ब्लाक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना और

उन्हें दूर करने के लिये अपेक्षित कदमों का सुझाव देना था। इस अध्ययन में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि नीतिगत सुधार की चुनौतियों से निपटने और अपेक्षित दायित्वों की पूर्ति में प्रशासन का मौजूदा ढांचा कितना सक्षम और पर्याप्त है। यह भी पता लगाने की कोशिश की गयी कि शिक्षा अधिकार, स.शि.अ. और दोपहर का भोजन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे के प्रति ब्लाक स्तर का प्रशासनिक ढांचा कितना कारगर है।

गुजरात में ब्लाक स्तर के प्रशासनिक ढांचे, क्रियाकलापों और समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद और अन्य दूसरे राज्यों के अनुभवों को देखते हुए इस अध्ययन के मौजूदा ढांचे में सुधार की सिफारिश की गई। इस अध्ययन में नये ढांचे का प्रस्ताव किया गया है जिसमें ब्लाक स्तर के शैक्षिक प्रशासन में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार, स.शि.अ. और दोपहर का भोजन योजना के कार्यान्वयन और सामान्यतः शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों को सुगम बनाया गया। अन्य दूसरे राज्यों के अनुभवों के आधार पर और गुजरात की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए इस अध्ययन में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के लिये विस्तृत जॉब चार्ट बनाने की सिफारिश की गई है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समन्वयन और अभिमुख दायित्व तय किया जा सके। वस्तुतः ब्लाक स्तरीय प्रशासनिक ढांचे का अभिमुखीय और क्षमतापूर्ण सरोकार को नए ढांचे में केंद्रीय स्थान दिया गया है।

3- v#.kkpy izns'k d s 'kSf{kd iz'kklu esa iz[kkM Lrjh; lq/kkj

vUo"kd % Mk- vkj-, l- R;kxh vkSj Mk- eatw u:yk

fu"d"kZ dk lkjka'k

इस अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर ब्लाक और जिला स्तर के शैक्षिक प्रशासन का स्थितिजनक विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा ढांचा ब्लाक शिक्षा अधिकारी की ड्यूटी और कार्यकलापों तथा दायित्वों की समीक्षा करना था जो उच्च प्राथमिक स्तर के कनिष्ठ अध्यापकों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्यतः नियुक्त किये जाते हैं। इसकी समीक्षा के बाद राज्य में ब्लाक शिक्षा अधिकारी का एक समुचित संवर्ग बनाने का सुझाव दिया गया है।

इस अध्ययन में जिला और ब्लाक स्तर के ढांचे की समीक्षा की गई। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लाक शिक्षा अधिकारी को उनकी नियुक्ति, चयन, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रोन्नति और सेवा शर्तों के साथ–साथ उनकी ड्यूटी और दायित्वों की समीक्षा करने का प्रयास किया गया।

यह अध्ययन अरुणाचल प्रदेश में ब्लाक शिक्षा अधिकारी का समुचित संवर्ग बनाने की सिफारिश करती है जहां ब्लाक शिक्षा अधिकारी ब्लाक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य प्रभारी/प्रशासनिक मुखिया होगा। यह पुनः सिफारिश करता है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और साक्षरता एवं प्रारंभिक शिक्षा विकास के कार्यक्रमों जैसे– स.शि.अ., दोपहर का भोजन और साक्षर भारत जैसे कार्यक्रमों का मुख्य नियंत्रक और कार्यान्वयन अधिकारी होगा। ब्लाक शिक्षा अधिकारी संसाधनों के अभिसरण और अंतर विभागीय समन्वयन के प्रति जवाबदेह होगा।

4- fnYyh d s pfunk Ldwyk s e s 0;kolkf;d ekxZn'kZu vkSj dfj;j ifjiDork dk v/;;u

vUo"kd % Mk- fofurk fljksgh

fu"d"kZ dk lkjka'k

वस्तुतः भारत स्कूल स्तर पर समुचित मार्गदर्शन और परामर्श सेवा के विकास के मामलों में अन्य देशों से पीछे है। हमारे देश में विशेषतौर पर चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन और परामर्श का प्रणालीबद्ध कार्य नहीं किया जा रहा है। यद्यपि इस सेवा के लिये अनेक आयोगों और समितियों ने अपनी सिफारिश की थी फिर भी इसके स्कूलों में उपलब्ध नहीं कराया गया है। आज के शैक्षिक और व्यावसायिक चयन के बदलते स्वरूप के मद्देनजर मार्गदर्शन और परामर्श सेवा का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है।

माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्णय कार्य की दुनिया में किसी व्यक्ति के भावी निर्णय का मार्ग

प्रशस्त करते हैं। करियर विकास के विस्तार के अन्तर्गत करियर परिपक्वता का महत्वपूर्ण स्थान है और यह विविध जनांनकीय दबाव और बाजार से प्रभावित होता है। वर्षों से करियर परिपक्वता और इसके सहसंबंध पर किये गये शोध निष्कर्ष असंगत हैं और एक ही सुर अलापते हैं। करियर परिपक्वता के संबंध में और अधिक शोध करने की जरूरत है जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया है। प्रस्तुत अन्वेषण में माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक मार्गदर्शन के प्रावधानों का अध्ययन किया गया है और कक्षा, स्कूल के प्रकार, लिंग और व्यावसायिक मार्गदर्शन के प्रावधानों के मद्देनज़र विद्यार्थियों के करियर परिपक्वता के स्तर की समीक्षा की गई है।

अध्ययन हेतु स्तरवार प्रतिदर्श तकनीक के माध्यम से कक्षा, लिंग, स्कूल के प्रकार और व्यावसायिक मार्गदर्शन के प्रावधानों पर प्रतिदर्श का चुनाव किया गया। दिल्ली के चुनिंदा माध्यमिक स्कूलों के कक्षा 10 और 12वीं के 320 विद्यार्थियों के प्रतिदर्श एकत्र किये गये। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से यह पता चलता है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन वाले विद्यालय, लिंग और स्कूल के प्रकार की दृष्टि से कक्षा 10वीं और 12वीं की सक्षमता में कोई खास अंतर नहीं है। कक्षा 12वीं की सक्षमता परीक्षण में लड़कियों की योजना डोमेन में करियर परिपक्वता अधिक दिखाई पड़ती है जबकि सरकारी स्कूलों के लड़के समस्या समाधान में बेहतर पाए गए। यद्यपि सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं की लड़कियों ने लक्ष्य निर्धारण में उच्च परिपक्वता प्रदर्शित की। आंकड़ा के सम्पूर्ण विश्लेषण से पता चलता है कि माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवा के प्रभाव से करियर परिपक्वता में सुधार होता है। इस अध्ययन में साक्ष्य मिलता है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवा वाले विद्यालयों की अपेक्षा बिना व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवा वाले विद्यालयों की में पढ़ रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परिपक्वता मनोवृत्ति औसत से कम है। अतः जिन स्कूलों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवा के प्रावधान हैं, वहां के विद्यार्थियों में स्वजागरूकता, व्यावसायिक सूचना लक्ष्य निर्धारण की दृष्टि से करियर परिपक्वता अपेक्षाकृत व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवा से वंचित स्कूलों के विद्यार्थियों से अधिक है। निःसंदेह व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवा स्कूलों के लिये अनिवार्य है। स्कूल प्राचार्यों, पार्षदों ओर विद्यार्थियों ने भी इसकी आवश्यकता व्यक्त की है। अतः इसकी ओर नीति निर्माताओं का ध्यान आर्कषित किया जाता है कि इन सीमाओं का संस्थानीकरण किया जाए है और मौजूदा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया जाय ताकि संसूचित करियर चयन को प्रोत्साहित करने के लिये माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों में करियर परिपक्वता बढ़ाई जा सके

5- Hkkjr esa ikjfHkd f'k{kk dk foÙkiks"k.k% ikjfHkd f'k{kk esa fuf/k vkoaVu izfreku vkSj lalk/kuksa dk mi;ksx

vUos"k.k % Mk- xhrkjkuh

fu"d"kksZ dk lkjka'k

अध्ययन के उद्देश्य थे : वार्षिक कार्य योजना और बजट के रूप में पीएवी में स्वीकृत परिव्यय के बीच बढ़ते अंतराल के कारणों की खोज करना, 2. राज्यों तथा जिलों में स्वीकृत परिव्यय के प्रवाह की पहचान करना; 3. (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) राज्यों से जिला और उप जिला स्तरों पर निधि प्रवाह के प्रतिमान की प्रक्रिया और कालक्रम को समझना; 4. स्वीकृत संसाधनों की पूर्ण या उच्च उपयोगिता प्राप्त न करने के कारणों का पता लगाना।

इस अध्ययन के माध्यमिक और प्राथमिक आकड़ों के स्रोत हैं: भारत सरकार के अधिकारिक प्रकाशन जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, मा.स.वि.मं. के प्रकाशन जैसे –चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी, शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण और स.शि.अ. से संबंधित अन्य माध्यमिक सूचना।

इस अध्ययन से पता चलता है कि 2001–02 में शुभारंभ के समय के रु. 500 करोड़ के परिव्यय के बाद इसके परिव्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है फिर भी कार्यक्रम की आवश्यकता के मद्देनजर यह कम है। इसके साथ ही विभिन्न कारणों से उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी नहीं किया जा सका।

यहां चुनौती यह है कि राज्यों और जिलों को विभिन्न घटकों में समुचित व्यय करने की गति को कैसे बढ़ाया जाए। क्षमताओं के अलावा यह भी एक सच्चाई है कि राज्यों और जिलों को वित्तीय वर्ष के अंत में संसाधन प्राप्त है जिसे वह समयाभाव के कारण उपयोग करने

में असमर्थ होते हैं। इसके कारण निधि प्राप्त होने में देरी के चलते एक चक्र निर्मित हो जाता है– कम उपयोग– अव्ययित निधि– अगले वर्ष के लिए स्थानांतरण निधि–मौजूदा वर्ष के बजट में कटौती। निधि के उपयोग में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं:

- स.शि.अ. के अंतर्गत कार्यक्रम की रूपरेखा के कारण योजना और संसाधन वित्तपोषण के बीच असंगतता।
- विश्लेषण में एक विचलन सामने आया है जो योजना ओर कार्यान्वयन के बीच है। निधि प्रवाह की प्रक्रिया– समय और किश्तों की संख्या– केंद्र से राज्यों और राज्यों से कार्यान्वयन सोसायटी को धनराशि का स्थानांतरण।
- भारत सरकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपर्याप्त धनराशि का प्रवाह और इसी क्रम में राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृत परिव्यय के प्रवाह में अड़चने।
- वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में एकमुश्त धनराशि जारी करना जिसके कारण व्यय की गुणवत्ता के साथ समझौता।

jkT; Lrjh; fo'y"k.k % r|yukRed l|i{k.k

उत्तर प्रदेश ने एस पी डी के अनुसार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन 1980–81 में 2.21 प्रतिशत बढ़ाकर 2009–10 में 3.79 प्रतिशत कर दिया। इसके विपरित गुजरात में इसमें कटौती की गई जो 1980–81 के 2.21 प्रतिशत से घटकर 2009–10 में 1.5 प्रतिशत हो गया। कर्नाटक में 1980 के दशक के दौरान यह लगभग 4 प्रतिशत रहा और 1990 के दशक में घटाकर 3.5प्रतिशत कर दिया गया। इसमें आगे और कटौती की गई और नई सहस्त्राब्दी के प्रथम दशक में यह लगभग 3 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार तमिलनाडु में 1980 के दशक में 4 प्रतिशत था जो 1990 के दशक में घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया और मौजूदा दशक में यह 3 प्रतिशत से भी कम है। यह ह्रास सभी प्रतिदर्श राज्यों में देखने को मिला सिवाय उत्तर प्रदेश के ।

उत्तर प्रदेश ने अपने कुल बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित करता है। गुजरात 1980 के दशक में 20 प्रतिशत आवंटित किया जो नई सहस्त्राब्दी के प्रथम दशक में घटकर लगभग 15 प्रतिशत हो गया। कर्नाटक की भी कमोबेस यही स्थिति रही। 1980 के दशक में शिक्षा बजट लगभग 20 प्रतिशत था जो नई सहस्त्राब्दी के प्रथम दशक में घटकर लगभग 19 प्रतिशत रह गया। तमिलनाडु में 1980 के दशक में शिक्षा बजट लगभग 20 प्रतिशत था जो आगे घटाकर लगभग 19 प्रतिशत कर दिया गया और नई सहस्त्राब्दी के प्रथम दशक में यह घटकर 16 प्रतिशत ही रह गया।

उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर प्रति विद्यार्थी व्यय मात्र रु. 3140/–है जो अनेक राज्यों की तुलना में सबसे कम है। गुजराज में प्रति छात्र व्यय केवल रु. 3212 है और प्रतिदर्श राज्यों में सबसे कम है और उत्तर प्रदेश से थोड़ा ही अधिक है। 2009–10 में कर्नाटक में प्रति छात्र व्यय रु.3560/– था जो प्रतिदर्श राज्यों में दूसरे नंबर पर था जबकि 2009–10 में तमिलनाडु में प्रति विद्यार्थी व्यय रु. 3926/– था और प्रतिदर्श राज्यों में यह प्रथम स्थान पर था।

देश और उत्तर प्रदेश, दोनों में स.शि.अ. का व्यय 2001–02 के रु. 3583 लाख से बढ़कर 2009–10 में 335049 लाख हो गया। इस प्रकार इसमें 1999–2000 मूल्य पर वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिदर्श राज्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई। गुजरात में भी 1999–2000 के मूल्य आधार पर 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई। और यह 2001–02 के 1385 लाख रूपये से बढ़कर 2009–10 में 43196 लाख रूपये हो गया। कर्नाटक में यह 2001–02 के रु. 3854 लाख से 2009 –10 में बढ़कर 42029 लाख रूपये हो गया। इसमें 27.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पाई गई। तमिलनाडु में स.शि.अ. व्यय 2002–03 में रु.10183 लाख था जो जो 2009–10 में बढऋकर रु. 88565 लाख रूपये हो गया और 1999–2000 के मूल्य स्तर पर इसमें 26.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पाई गई।

इससे यह पता चलता है कि सभी प्रतिदर्श राज्यों में धनराशि आवंटन ओर उपलब्धता के साथ–साथ राज्यों की व्यय क्षमता में भी समय के साथ सुधार हुआ है फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर निधि प्रवाह के प्रतिमान, उसकी समयाविधि और विलंब की दृष्टि से स.शि.अ. की वित्तीय योजना और प्रबंधन के मार्गदर्शिका में निहित मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है। मा. सं.वि.म. (2004–2010) द्वारा निर्धारित कैलेंडर का पालन

किया जाता है और न ही वित्तीय प्रवाह के प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में वर्ष के अंतिम तिमाही में निधि प्रवाह 20 प्रतिशत से अधिक की थी। उदाहरणार्थ वर्ष 2003–04 में स.शि. अ. के आरंभिक चरण में भारत सरकार से अंतिम तिमाही में 38 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई। गुजरात में चार वर्षों के दौरान अंतिम तिमाही में 20 प्रतिशत से अधिक धन राशि प्राप्त हुई। इस कारण एस आई एस के समुचित कार्यान्वयन के लिए कोई समय ही नहीं मिला पाया।

उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है। राज्य सरकार एस आई एस को 14 किश्तों में धनराशि स्थानांतरिक कर रही है। एस आई एस को धन की स्वीकृति और प्राप्ति में 8 से 104 दिनों का समय लगता है। इसी तरह गुजरात का हाल भी बुरा है। राज्य सरकार एस आई एस के खाते में 16 किश्तों में धन राशि डालती है और उसकी स्वीकृति और प्राप्ति में 3 से 78 दिन का समय लगता है। कर्नाटक की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार 12 किश्तों में धनराशि प्रदान करती है और इसकी स्वीकृति और एस आई एस को स्थानांतरण करने में 6 से 183 दिन का समय लगता है। राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के स्थानांतरण और तिमाही में असमान वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अगर हम 2004–05 से 2009–10 के दौरान वित्तीय वर्ष में अर्थ शेष की स्थिति पर विचार करें तो गुजरात में उपयोगिता दर 61–83 प्रतिशत के बीच है। जबकि कर्नाटक में यह 61–85 प्रतिशत है। यह कहना न होगा कि इन दोनों राज्यों में उपलब्ध कुल निधि के अर्थ शेष में किसी मानदंड का पालन नहीं किया जाता है। उपयोगिता दर में सुधार के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें सुधार की संभावना देखी जा सकती है। मगर उपलब्ध धनराशि के अर्थशेष और अंतशेष दोनों में कमी उपयोगिता सुधार को प्रकट करती है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। यद्यपि चिंता का विषय यह है कि अर्थ शेष का प्रतिशत राज्य और केंद्र से प्राप्त आवंटनों को कम करता है। इसके विपरित तमिलनाडु में कुल उपलब्ध निधि में अर्थशेष या अंतशेष दोनों ही बिल्कुल कम हैं।

उत्तर प्रदेश में एक दशक तक स.शि.अ. के कार्यान्वयन के बाद 2009–10 में उच्च प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर 70.25 प्रतिशत था जबकि प्रारंभिक स्तर पर समुच्चयित विद्यालय त्याग दर 53 प्रतिशत थी। गुजरात में 2009–10 स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर 86.5 प्रतिशत थी और प्रारंभिक स्तर पर सम्मुचयित विद्यालय त्याग दर 30 प्रतिशत थी। कर्नाटक में यह 2009–10 पर क्रमशः 89.3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत थी जबकि तमिलनाडु में 2009–10 में यह दर क्रमशः 100 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थी।

घटकवार उपयोगिता दर और व्यय के संघटकों में अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक वेतन, अध्यापक अनुदान और सीविल कार्य के प्रति पूर्वग्रह अधिक है। व्यय का घटकवार व्यय सीविल कार्य, शिक्षामित्र के मानदेय, निःशुल्क पुस्तकें, स्कूल रखरखाव अनुदान, स्कूल अनुदान, इ जी एस/ए आई ई/टी एल ई/डी जी ओ और स्कूल स्तर पर अध्यापक अनुदान में डी पी ओ स्तर पर कुल व्यय का लगभग 96 प्रतिशत भाग लग जाता है। यही स्थिति गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई गई है जहां से सुनियोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा की अपेक्षा की जाती है।

6- fcd e mPp f'k{kk ¼LVu QkM fo'ofo|ky; d lg;kx l½

vUo"kd % ik- t- ch- th- fryd vkj ik- ekfVu dkuk;

fu"d"kk dk lkjk'k

दुनिया के अनेक देशों में उच्च शिक्षा की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। ब्राजील, भारत और चीन की विकासशील अर्थ व्यवस्था में तेजी से वृद्धि में यह विस्तार उल्लेखनीय है। दुनिया में उच्च शिक्षा के नामांकन में रूस सहित ब्रिक देशों का बहुत बड़ा हिस्सा है। चार देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों और विद्यार्थियों की भारी संख्या के प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर यह अध्ययन ब्रिक देशों में उच्च शिक्षा की वृद्धि और नीति में प्रमुख बदलावों का विश्लेषण करता है।

व्यक्तिगत उच्च आर्थिक भुगतान की क्षमता यानि दूसरे शब्दों में प्रतिलाभ की उच्च निजी दर उच्च शिक्षा की निजी मांग को न्यायसंगत मानती है। सरकारें भी सामान्य रूप से आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा के महत्व को मान्यता देती हैं और विशेष रूप से भौगोलीकरण के दौर

में इसे आवश्यक मानती हैं। मगर ब्रिक देशों की सरकारें उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग की पूर्ति के संबंध में अलग तरह से प्रतिक्रिया प्रकट करती हैः

सभी देशों के निधि प्रतिमान में भारी बदलाव किया गया है। भारी सार्वजनिक सब्सिडी से लागत–वसूली उपायों और शुल्क पर अधिक निर्भरता है। यह केवल भारत और ब्राजील के लिए ही सही नहीं है बल्कि यह रूस और चीन के लिए भी लागू होता है। भारत और ब्राजील उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर मुड़ रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में ब्राजील और रूस में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में भारी वृद्धि हुई है। चीन और रूस में भी निजी संस्थानों में वृद्धि शुरू हो गई है। मगर चीन और रूस में यह वृद्धि केंद्र सरकारों द्वारा बहुत अधिक नियमित है। ब्राजील और भारत में यह बिल्कुल ही अनियमित है।

इसके साथ ही सरकारें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को आवश्यक मानती हैं जबकि कई निजी संस्थानों और सार्वजनिक संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। अतः उन्होंने इसके लिए अलग तरीका अपनाया है– कुछ चुनिंदा संस्थानों जिन्हें अभिजात्य कहा जाता है, में गुणवत्ता शिक्षा पर फोकस किया जाता है और साथ ही अन्य संस्थानों में जन उच्च शिक्षा की सस्ती और कम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। यद्यपि अभिजात संस्थानों को पूरा लोक निधि का आवंटन किया जा रहा है जबकि जन शिक्षा संस्थान अनुदान के अभाव में शुल्क और उच्च राजस्व स्रोतों पर पूरी तरह निर्भर है। यह विज्ञान और अभियांत्रिकी की शिक्षा में विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। इन देशों में विश्व स्तरीय रैंक के उद्देश्य से विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की अभिलाषा की पूर्ति होती है। वास्तव में इसके साथ ही उच्च शिक्षा के स्तर पर पहुंच, गुणवत्ता और समता को पूरा करने की रणीनति की भी आवश्यकता है।

अध्ययन की रूपरेखाः अध्याय 1ः राज्य और उच्च शिक्षा में बदलाव अध्याय 2 : उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार अध्याय 3 : उच्च शिक्षा में निवेश पर आर्थिक लाभ और ब्रिक देशों पर उसका प्रभाव अध्याय : उच्च शिक्षा के लिए वित्तपोषण का बदलता स्वरूप, अध्याय 5 : बदलाव की प्रक्रिया में संस्थान के रूप में ब्रिक विश्वविद्यालय अध्याय 6 : विद्यार्थी कौन है और ब्रिक उच्च शिक्षा संस्थानों में वे क्या बन रहे हैं, अध्याय 7 : ब्रिक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, अध्याय 8 : ब्रिक उच्च शिक्षा और सामाजिक समता और अध्याय 9 : ब्रिक उच्च शिक्षा का भावी प्रभाव।

अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन दल का नेतृत्व स्टैन फोर्ड विश्वविद्यालय में मार्टिन कार्नाय ने किया और इसमें भारत, ब्राजील, रूस और चीन के शोधार्थी शामिल थे।

7- dsUnz izk;ksftr jk"Vªh; lk/ku lg izfrHkk Nk= o`fÙk ;kstuk dk ewY;kadu v/;;u

vUos"kd % Mk- oh-ds- djh ih-,l- jkts

fu"d"kkZ dk lkjka'k

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मई 2008 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 8वां स्तर के मेधावी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करना था ताकि विद्यालय त्याग पर रोक लगाई जा सके और उन्हें कथा बारहवीं तक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस योजना के तहत उन एक लाख मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव था जिनके माता–पिता की सभी स्रोतों से प्राप्त आय डेढ़ लाख रूपये से अधिक न हो। प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए निश्चित कोटा तय था जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था। इसका आधार राज्यों/संघ क्षेत्रों में कक्षा सातवीं और आठवीं के नामांकन (2/3 भारमान)और संबंधित आयुवर्ग में बच्चों की आबादी (1/3 भारमान) को माना गया था। इसी आधार पर प्रत्येक राज्य ने अपने जिला के लिए कोटा तय किया था। इस योजना के अंतर्गत चुने गए प्रत्येक विद्यार्थी को चार वर्ष के लिए रु. 6000 प्रति वर्ष और रु500/– प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति का भुगतान तिमाही किश्तों में विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

यद्यपि इय योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था। इस स्थिति में इस

योजना के मूल्यांकन किए बगैर और इसकी कमियों और प्रभावों को जाने बगैर 12वीं योजना में भी इसे जारी करना उचित नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए न्यूपा से अनुरोध किया था। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2008–2009 से 2011–2012 तक राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना राज्यों/संघक्षेत्रों द्वारा केंद्र प्रायोजित इस योजना के उपयोग के मापदंड की समीक्षा करना और उपलब्ध छात्रवृत्ति के उपयोग न होने के कारणों को पता लगाना।
- समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों जिनके मां–बाप की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय डेढ़ लाख रूपये से अधिक नहीं है, को प्राप्त वित्तीय सहायता के प्रभाव और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यालय त्याग कम करने में यह कितना सहायक है, का पता लगाना।
- राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा जिलों के लिए छात्रवृत्तियां तय करने के विभिन्न मानदंड का पता लगाना, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और बैंक द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- 12वीं योजना में इस छात्रवृत्ति योजना को लागू करने के लिए सुझाव देना और सुधार के लिए सिफारिशें करना।

इस अध्ययन के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए मा.सं.वि.मं. के परामर्श से 6 प्रतिदर्श राज्यों का चयन किया गया। ये राज्य थे– मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, झारखंड, आंध्र–प्रदेश और उत्तर–प्रदेश। ये सभी राज्य देश भर के सभी प्रभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं: उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वोत्तर।

i;e[k fu"d"k

छात्रवृत्ति योजना का प्रभाव–राष्ट्रीय साधन सह–प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक को शिक्षा स्तर पर बच्चों की स्कूल भेजने में गरीब अभिभावकों की काफी मदद मिली है। अभिभावक और अध्यापक भी योजना की प्रवेश परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की क्षमता और दक्षता को स्वीकार करते हैं।

इस योजना ने विद्यार्थियों को आगे की परीक्षा जारी रखने और अपने शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करने में एक प्रेरणादायी भूमिका निभायी है। प्रवेश परीक्षा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है और भावी जीवन में सीविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा बेहतर करियर बनाने में उत्प्रेरक के रूप में प्रोत्साहित करती है। छात्रवृत्ति धारक अपने छोटे–भाई बहनों पर प्रेरणादायी प्रभाव डालते हैं। इसका प्रभाव पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर भी पड़ता है। छात्रवृत्ति धारक अन्य बच्चों को छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी में मदद करते हैं। छात्रवृत्ति पाने के बाद विद्यार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है।

इस छात्रवृत्ति योजना से अभिभावकों को अपने बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग कराने और आवश्यक पुस्तकें तथा कापियां खरीदने में आर्थिक मदद मिलती है। कुछ बच्चे छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बचा लेते हैं।

स्कूल प्रबंध समिति, अध्यापक और विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अपने विद्यार्थियों पर गर्व महसूस करते हैं। जिले के स्कूलों के बीच अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने की दिशा में प्रतिस्पर्धा होती है। अध्यापक भी बच्चों को पढ़ाने और उचित मार्गदर्शन करने में गहरी रूचि लेते हैं और इसके लिए उन्हें अध्ययन सामग्री भी प्रदान करते हैं। विद्यार्थी भी अपने अध्ययन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बाद अपनी संप्राप्ति में निरंतर सुधार की कोशिश करते हैं। आगे चार वर्षों तक छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए वे विशेष प्रयास करते हैं और कक्षा नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में बेहतर कार्य निष्पादन करते हैं।

छात्रवृत्ति धारक सीधे बैंक से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में खुशी जाहिर करते हैं क्योंकि इसमें किसी और व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है।

सभी संस्था प्रमुखों ने जाहिर किया कि इस योजना से विद्यालय त्याग दर में कमी आई है। माध्यमिक और ब. माध्यमिक स्तर पर कक्षा आठवीं से कक्षा दसवीं में यह स्पष्ट देखा जा सकता है।

छात्रवृत्तिधारक विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलाता है। वे नियमित रूप से स्कूल आते और अभिभावकों तथा अन्य दूसरे से अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के बाद उनका अकादमिक कार्य निष्पादन बेहतर हुआ है।

;kstuk esa lq/kkj ds fy, lq>ko

राज्य का नोडल अधिकारी राज्य स्कूल शिक्षा निदेशालय का अधिकारी होना चाहिए जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस योजना को लागू करवा सके ताकि जिले के कोटे का पूरा उपयोग किया जा सके।

राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अंदर इस योजना के लिए एक अलग से एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से इस योजना के लिए कार्य करे। मा.सं.वि.मं. को इस योजना के प्रशासन के लिए अनुदान देना चाहिए।

मा.सं.वि.मं. और राज्यों को इस योजना के बारे में समाचारों, टी.वी, रेडियो कार्यक्रमों के साथ–साथ पोस्टरों पम्फलेटों, परिपत्रों के द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए और इसे लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा जिलेवार कोटा का उपयोग करने में रियायत की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जिलों में कोटे का उपयोग सुनिश्ति किया जा सके। अगर किसी –किसी जिलें में सभी कोटा उपयोग में लाया गया है तो उसे अन्य जिलों के बचे हुए कोटे का उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए गुजरात के एक ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने अपने सभी विद्यालय प्रमुखों को जिले के लिए आवंटित कोटे का उपयोग करने के लिए अभिप्रेरित किया। जो राज्य अपने रा.सा.प्र.छा. योजना के पूरे कोटे का उपयोग कर रहा है तो उसे और अधिक कोटा दिया जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग द्वारा राज्य और जिलों में छात्रवृत्ति की कुल संख्या के आवंटन के लिए एक मानदंड या सूत्र प्रतिपादित किया जाना चाहिए। मसलन, भारत के कुछ जिले बहुत अधिक पिछड़े हैं और उन्हें छात्रवृत्ति आवंटित करते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बेहतर राज्यों की अपेक्षा उन्हें अधिक कोटा दिया जाना चाहिए।

विद्यार्थियों को पोस्ट आफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में शून्य बचत पर बचत खाता खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यद्यपि विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और अन्य ने इस योजना का स्वागत किया है फिर भी समाज के अन्य लोगों की राय थी कि अभिभावक की आय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। अतः बिना शर्त आय सीमा रु. 2,50000 करने पर विचार किया जाना चाहिए।

यह सिफारिश की गई है कि छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता पहले की तरह सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक ही रखा जाना चाहिए। अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए।

रा.सा.प्र.छा. योजना का आवेदन पत्र शिक्षा, विभाग, मा. सं.वि.म. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। विद्यालय भी योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को इसका आवेदन पत्र प्रदान करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक राज्य इसकी निःशुल्क परीक्षा आयोजित करे।

रा.सा.प्र.छा. योजना की केवल एक परीक्षा होनी चाहिए और उसकी अवधि दो घंटे की होनी चाहिए क्योंकि कक्षा सातवीं और कक्षा आठवीं के बच्चे दो घंटे की परीक्षा के लिए अभ्यस्त होते हैं। इस परीक्षा में मानसिक क्षमता, शैक्षिक योग्यता और अंग्रेजी में भाषा क्षमता और विशेषकर पठन और लेखन की परीक्षा ली जानी चाहिए।

प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। (आवेदन पत्र के आकार, परीक्षा शुल्क और राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया) ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस योजना में सुधार के लिए मा.सं.वि.म. बैंक और राज्य नोडल कार्यालय, जिला कार्यालय, ब्लाक, स्कूल तथा छात्रों के बीच अच्छा समन्वयन होना चाहिए। मा.सं.वि. म. और राज्य नोडल कार्यालय के बीच सम्प्रेषण अच्छा होना चाहिए। मा.सं.वि.म. द्वारा योजना की निगरानी की जानी चाहिए। राज्य शिक्षा सचिव द्वारा कार्यान्वयन के दौरान राज्य का दौरा किया जाना चाहिए।

पिछले वर्षों में महंगाई के कारण संदर्भ पुस्तकों कापियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इस परिस्थिति में यह सिफारिश की जाती है कि छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिये रु. 500 से बढ़ाकर रु. 1000 कर

दी जाए। और कक्षा 11 और 12 के लिये 1500/– कर दी जाए।

कुछ छात्रवृत्ति धारक विद्यार्थी कक्षा 10 के बाद आगे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। वे पालिटेकनीक, डिप्लोमा आदि करना चाहते हैं ताकि रोजगार मिल सके और वे अपने परिवार की मदद कर सकें। अतः सिफारिश की जाती है कि इस छात्रवृत्ति योजना का व्यावसायिक/पालिटेकनीक, डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि और आगे उच्च शिक्षा तक विस्तार किया जाना चाहिए।

परीक्षा का परिणाम समाचार पत्रों और वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। मा.सं.वि.मं. द्वारा रा.सा.प्र.छा. योजना की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए ताकि वे उच्च अध्ययन या नौकरी के अवसर पर इसे प्रस्तुत करके लाभ उठा सकें। मा.सं.वि.मं. को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति योजना से सबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिये नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए और केन्द्र तथा राज्य के बीच प्रभावकारी सम्प्रेषण का विकास करना चाहिए।

8- f'k{kk _.k ij dsanzh; C;kt lfClMh ;kstuk dk ewY;kadu

vUos"kd % Mk- ih- xhrk jkuh vkSj Mk- oSVdjh ih-,l- jktw

fu"d"kksZ dk lkjka'k

भारत सरकार के 2009–10 के बजट में भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी और व्यावसायिक शाखा में स्वीकृत पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारतीय बैंक परिसंघ के शैक्षिक तथा योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंकों से मोरेटोरियम बैंक ऋण की अवधि के दौरान ब्याज पर सब्सिडी देने की एक अनुपूरक योजना लागू की गई थी।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की मदद करना हैं। इस योजना का पूरक उद्देश्य समता, सार्वजनिक दायित्व और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह योजना उन विद्यालयों के लिये है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और उनके अभिभावक की आय रु. 4.5 लाख प्रति वर्ष है। उन्हें उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिये यह योजना लागू की जा रही है।

प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन 12वीं योजना में भी ब्याज सब्सिडी योजना लागू कराने के लिये एक समीक्षा अध्ययन है। इसका मूल उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस योजना (जो आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपये से कम है, को लाभ हो रहा है।

अतः यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि ज.जा./अ.ज.जा., विकलांग विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक लड़के/लड़कियों में से कितने विद्यार्थियों को इस योजना के तहत शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिल रही है जो सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं। अतः इस वर्ग के विद्यार्थियों को देशभर में स्वीकृत शैक्षिक ऋण और उस पर वास्तविक व्याज सब्सिडी से यह पता चलेगा कि इस योजना का लाभ कौन उठा रहा है।

iqeq[k fu"d"k

यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में 12वीं योजना को शैक्षिक ऋण व्याज सब्सिडी जारी रखने के लिये सब्सिडी ब्याज केंद्रीय सेक्टर योजना के कामकाज की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान योजना के लिये आवंटित धनराशि का उपयोग और लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। न्यूपा की बैठकों द्वारा उपलबध कराए गए आंकड़ों और अक्टूबर 2012 में केनरा बैंक बैंगलोर में आयोजित बैठक में प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सुझाव दिया गया है कि इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाए। इस योजना के मौजूदा मापदंड या शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के विषय में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

ब्याज सब्सिडी से संबंधित मुख्य बात विद्यार्थियों को ऋण प्रतिपूर्ति को तीव्र करने संबंधी मुद्दे हैं। वंचित वर्ग के लिये शैक्षिक ऋण की मंजूरी के बीच के समय का अंतराल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा विभिन्न बैंकों द्वारा प्रक्रिया में लिया जा रहा समय है। विद्यार्थियों से ब्याज सब्सिडी दावा प्राप्त करने और केनरा बैंक को मंजूरी के लिये भेजने और इसकी मंजूरी के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करने में लगने वाला समय भी एक विचारणीय मुद्दा है।

;kstuk esa lq/kkj dk lq>ko

संचार माध्यमों के द्वारा विद्यार्थियों के बीच इस योजना के बारे में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिये कैंप लगाकर विद्यार्थियों को योजना के बारे में बताया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को देखते हुए आय सीमा में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इसे 6 लाख रुपये या इससे अधिक किया जाना चाहिए। इसमें समय–समय पर संशोधन किया जाना चाहिए।

आय प्रमाण के जरिये अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों की पहचान के समस्याओं के मद्देनजर यह सुझाव दिया जाता है कि संगठित क्षेत्रों में कार्यरत वेतनभोगी अभिभावकों के लिए उनके संगठन द्वारा जारी फार्म–16 ही आय का सबसे पक्का और वैकल्पिक प्रमाण पत्र हो सकता है। इस संदर्भ में आय प्रमाण पत्र के लिये एक या दो विकल्प बनाने की आवश्यकता है। फार्म 16 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये और अन्य दूसरे के लिये राज्य द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रयोग में लाए जा सकते हैं।

एक दूसरी समस्या शिक्षा पूरी करने क बाद बच्चों की शिनाख्त करने की है। इस संबंध में सुझाव दिया गया है कि विद्यार्थियों को सीधे ऋण देने के बजाए संस्थान को ई–हस्तांतरण द्वारा ऋण राशि का भुगतान किया जाए। विद्यार्थियों से संपर्क बनाए रखने के लिये ऋण लेने वाले विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जाए और इस सूचना को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए।

9- Hkkjr dh jk"Vªh; fefyVªh Ldwyksa vkSj pfunk lSfud Ldwyksa dk ewY;kadu v/;;u

vUos"kd % izks- izfeyk esuu

fu"d"kksa dk lkjka'k

यह अध्ययन सैनिक स्कूल योजना की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर किया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के कामकाज संबंधी अध्ययन का प्रस्ताव केंद्रीय शासी परिषद की 24 अगस्त 2011 की बैठक में सुझाया गया था। यह माना गया कि मौजूदा स्कूलों के कार्यकलापों का किसी बाह्य एजेंसी से मूल्यांकन करवाया जाए और उसकी सिफारिशों के आधार पर इन स्कूलों को और अधिक मज़बूत और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए।

यह प्रस्तुत अध्ययन की पृष्ठभूमि है। इस अध्ययन का व्यापक केंद्र बिन्दु राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों और सैनिक स्कूलों के कामकाज से समझना है और काडर की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में उनकी भूमिकाओं का विश्लेषण करना है। काडर की रक्षा सेवा में जाने योगय बनाने में इन स्कूलों की भूमिकाएं कितनी कारगर हैं, इसकी समीक्षा करना भी एक उद्देश्य था। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- विद्यालयों को सुलभ आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
- प्रवेश नीति व कैडेट चयन की प्रक्रिया और उनके समग्र विकास संबंधी कार्यकलापों का विश्लेषण करना।
- इन स्कूलों द्वारा चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण और अध्यापकों के आकलन के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने हेतु किये जा रहे प्रयासों का आकलन करना।
- कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव देना।
- इन स्कूलों के समग्र कामकाज में सुधार लाने की दृष्टि से मूल्यांकन के आधार पर बदलाव लाने की सिफारिश करना।

इस अध्ययन में सभी पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों और 10 सैनिक स्कूलों को लिया गया था। इसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। स्कूल प्राचार्यों तथा अध्यापकों को प्रश्नावली भेजी गई थीं। कैडेट के कुछ अभिभावकों के साथ चर्चा की गई थी। स्कूल के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिये स्कूल प्रमुखों का सीधे साक्षात्कार लिया गया था। कक्षा प्रक्रियाओं का प्रेक्षण भी किया गया था। स्कूलों के स्थानीय निकायों से भी संपर्क किया गया। अप्रैल 2013 में यह अध्ययन पूरा हुआ।

i|e[k fu"d"k

यह पाया गया कि सैनिक स्कूल व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। उन्हें उन्नत बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रमुख बदलावों से निपटने में असमर्थ हैं। प्रशिक्षण और कार्यव्यवहार की मौजूदा विधि काफी पुरानी हैं। इसमें शायद ही कोई नवाचार किया जा रहा है। यद्यपि कुछ स्कूल प्रमुखों ने इसे आरंभ किया है। सैनिक स्कूल के लड़कों द्वारा दशकों पहले अर्जित मेरिट आर्मी स्कूलों और रक्षा प्रतिष्ठानों में स्थापित केंद्रीय विद्यालयों के सामने फीके पड़ गए हैं। अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों को देखते हुए अभिभावक दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने लगे हैं। अतः सैनिक स्कूलों के कुछ सरोकारों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के कामकाज में सुधार लाने के लिये इस अध्ययन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- स्कूल प्रशासन द्वारा विशिष्ट कौशलों और अनुभवों के आधार पर प्राचार्यों का चयन किया जाना चाहिए। यद्यपि सेवाकाल का मौजूदा मापदंड अपर्याप्त है भले ही इसका अपना महत्व है।
- प्रत्येक तीन वर्षों में प्रधानाचार्यों को बदलने की मौजूदा नीति का सांस्थानिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके भुक्तभोगी स्टाफ भी होते हैं क्योंकि उन्हें अलग–अलग प्रधानाचार्यों के नजरिए के अनुसार बदलना पड़ता है।
- इस प्रकार प्रधानाध्यापक का कार्यकाल चार से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाना चाहिए। इससे शैक्षिक कार्य निष्पादन के साथ–साथ जवाबदेही, प्रबंधन और अंतरवैयक्तिक संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। प्रधानाध्यापक के पद के लिए शिक्षा अधिकारियों की कमी या अनुपलब्धता की स्थिति में विभिन्न स्कूलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रोन्नति कर दिया जाए।
- स्वतंत्र व्यावसायिक परामर्शदाताओं की पहचान की जाए और प्रत्येक सैनिक स्कूल में आवश्यकतानुसार उन्हें तैनात किया जाए। यद्यपि दूरदराज के सैनिक स्कूलों में स्थाई परामर्शदाता की तैनाती की जा सकती है।
- एक पूर्णकालिक सैनिक स्कूल कक्ष की स्थापना आवश्यक है जिसमें एक पूर्णकालिक मानद सचिव और अवरसचिव हो। एक अकादमिक समिति का गठन किया जाए जो अकादमिक मुद्दों को संबोधित करे और सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी, डीआईपीआर आदि से संपर्क बना सके ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर परिणाम सुनिश्चित किया जा सके। यह समिति पुनर्निवेशन विधि के द्वारा सभी स्कूलों में अध्यापकों की क्षमता और अनुशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता पर आवधिक रूप से निगरानी करे। यह समिति स्कूलों और अध्यापकों के लाभ के मद्देनजर अंतर–स्कूल स्थानांतरण की समीक्षा करे और उसे लागू करे।
- इन स्कूलों का तकनीकी मूल्यांकन अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक संस्थानों और विषय विशेषज्ञों को आवधिक मूल्यांकन में शामिल किया जाए और सुधार हेतु उनके सुझाव प्राप्त किए जाएं।
- शैक्षिक स्कूलों के कार्यकलापों में बदलाव के लिये इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए।
- सभी सैनिक स्कूलों में राज्य अनुसमर्थन एक समान किया जाना चाहिए।

10- i|tkc e| ikfjokfjd vf/kxe vkj Ld|y Hkkxhnkjh d| chp l|c/kk| dh [kk|t ij vu|Hko tU; v/;;u

vUo"kd % ik- jf'e nhoku

fu"d"kk| dk lkjka'k

यह अध्ययन पूर्णतः जमीनी स्तर के अनुभवों पर आधारित है। इसमें पंजाब के लुधियाना के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र शामिल हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य लुधियाना के ग्रामीण एवं नगरीय, दोनों क्षेत्रों के सभी प्रकार के स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी की समीक्षा करना है। लुधियाना के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों से 6 स्कूलों का चयन किया गया। ये स्कूल सरकारी, निजी मान्यता प्राप्त और निजी गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी के थे। प्रत्येक श्रेणी के दो स्कूल–ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से एक–एक स्कूल चुने गये थे। इन स्कूलों के 360 विद्यार्थी प्रतिदर्श थे (प्रत्येक स्कूल से 60 विद्यार्थी) इन्हें प्रश्नावली दी गई। 144 परिवारों (प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों के 24 परिवारों

से) को लिया गया और उन्हें साक्षात्कार सूची दी गई। प्रत्येक स्कूल से कक्षा 5, 6, 7 और 8 के 60 विद्यार्थी चुने गये। (प्रत्येक कक्षा से 15 विद्यार्थी)। इन 15 विद्यार्थियों में प्रतिभाशाली, औसत और औसत से कम, तीनों स्तर के विद्यार्थी थे। इसमें संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवार थे। सरकारी और निजी स्कूलों और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के परिवारों से प्राथमिक आंकड़ा एकत्र किया गया। लुधियाना के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 72 परिवारों से आंकड़ा एकत्र किया गया। इस अध्ययन की लक्षित आबादी कक्ष 5–8 के प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थी थे जो वर्तमान में सरकारी और निजी स्कलों में पढ़ रहे थे। इसके साथ ही इस आबादी में स्कूल प्राचार्य, अभिभावक और बच्चे भी थे।

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष हैं: (1) राज्य के सभी प्रकार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की मांग है। अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वार्तालाप को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह अभिभावकों के लिये एक प्रतिष्ठा की बात है और इसके सहारे वह दूसरों पर रोब जमाते हैं। इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है और रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं। वे यह मानते हैं कि इससे लड़कियों को स्वागतकर्मी और लड़कों को सेल्समैन की नौकरी मिलती है। 41 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिये अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु भागीदारी में मदद करते हैं। जबकि 33 प्रतिशत अभिभावक किताबों, विश्वकोशों, समाचारपत्रों और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाकर उनकी मदद करते हैं। लड़के–लड़कियों के बीच अकादमिक संसाधनों के प्रावधानों में कोई खास भेद नहीं पाया गया। यद्यपि 79 प्रतिशत लड़कियों के पास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पाई गई हैं। जबकि अधिक लड़कों के पास लड़कियों की तुलना में सीडी और डीवीडी पाए गए। अभिभावकों का दावा है कि समाज में अंग्रेजी वार्तालाप और अच्छी शिक्षा की जरूरत है। (2) जो अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं वे उनकी पढ़ाई–लिखाई में अधिकतम दो घंटे दे पाते हैं। इस दृष्टि से संयुक्त परिवार और एकल परिवार में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई जाती है। 72 प्रतिशत संयुक्त परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिये समय निकाल पाते हैं जबकि 60 प्रतिशत एकल परिवार ऐसा कर पाते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य स्कूल बैठकों में संयुक्त परिवारों से दादा–दादी की भागीदारी है। दादा–दादी बच्चों की पढ़ाई में कुछ मदद नहीं कर सकते जबकि उनमें से कुछ माता–पिता के काम पर जाने के कारण अपने बच्चों के अध्यापकों से बातचीत करने स्कूल जाते हैं। (3) लुधियाना के ग्रामीण और नगरीय स्कूलों में पुस्तकों के मामले में समान स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में कंप्यूटर अधिक हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास आई.टी. संसाधनों की अपेक्षा पुस्तकें अधिक थीं। केवल 12 प्रतिशत के पास इंटरनेट हैं। अधिकांश बच्चे गेम खेलने में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। संगीत सुनते हैं। केवल एक चौथाई ही स्कूल के काम में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और अपना सामान्य ज्ञान सुधारते हैं। (4) पारिवारिक बौद्धिक प्रेरक माहौल के संबंध में निजी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच भारी अंतर है। निजी और गैर–मान्यता स्कूलों के 56 प्रतिशत बच्चे यह मानते हैं कि उनके घर का माहौल बौद्धिक रूप से प्रेरक है। यह स्थिति निजी मान्यता प्राप्त 23 प्रतिशत विद्यार्थियों में पाई गई। अ.जा. और अन्य जातियों में बौद्धिक अभिप्रेरणा न्यूनतम हैं (5) घरों में अकादमिक चर्चाएं नहीं होती हैं। केवल बड़े भाई–बहन अपने छोटे भाई–बहनों को होमवर्क करने में मदद करते हैं। इसका मुख्य कारण अभिभावकों के पास समय का अभाव और आर्थिक तंगहाली है। जिसके कारण उनकी इच्छाएं दरकिनार हो जाती है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अकादमिक माहौल मिलता है वे समृद्ध व्यापारी घराने के हैं। (6) एक सकारात्मक और खास बात यह है कि निजी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के 95 प्रतिशत अभिभावक सरकारी स्कूलों के अभिभावकों की तुलना में बच्चों के अध्यापकों से अधिक मिलते–जुलते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। इससे चर्चा के विषय से संबंधित मुद्दे, बच्चों के प्रति संबंधी सूचनाएं, स्कूल अनुशासन अध्यापक, यातायात के साधनों की व्यवस्था, अकादमिक संसाधनों की पहुँच होते हैं और वे स्कूल और अध्यापक के निवास पर उनसे मिलने जाते हैं। अन्य स्कूलों की तुलना में इन स्कूलों में घर–स्कूल की साझेदारी बेहतर पाई गई। इनमें विद्यार्थियों के शिक्षा परिणाम अच्छे पाए गए और अभिभावक भी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया से संतुष्ट नज़र आए। इसी प्रकार द्वितीय पीढ़ी के अभिभावक प्रथम पीढ़ी के अभिभावकों की तुलना में अधिक बार स्कूल के अध्यापकों से मिलने गए। ग्रामीण ओर नगरीय, दोनों क्षेत्रों क अभिभावकों ने स्कूल वातावरण को संतोषजनक बताया। (7) अभिभावकों का शिक्षा स्तर विद्यार्थी की

शैक्षिक उपलब्धि के मामले में प्रभावकारी होती है। जिनके माता–पिता स्नातक हैं उनके अंकों का औसत निरक्षर माता–पिता के बच्चे से अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों का औसत नगरीय स्कूलों से कम था। वहीं ग्रामीण लुधियाना के सरकारी स्कूलों की स्थिति उनके पड़ोसी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों और नगरीय सरकारी स्कूलों से बिल्कुल उत्तर थी। मगर ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों के निजी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता पाप्त स्कूलों के मध्यमान अंकों में खास अंतर नहीं पाया गया।

11- fo|ky; x|.koÙkk dk iujh{k.k

vUos"kd % Mk- e/kqferk c|kik/;k;

fu"d"kkZ dk lkjka'k

यह अध्ययन मुख्य परियोजना क्रिएट का भाग हे। अध्ययनपूर्ण हो चुका है तथा रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। अध्ययन दर्शाता है कि कई केंद्रीय परियोजनाओं के हस्तक्षेपों के बावजूद राज्य के कई क्षेत्र शैक्षिक रूप से अविकसित हैं और इसका बच्चों की भागीदारी और पहुँच पर गंभीरता से प्रभाव पड़ रहा है। कई बच्चों को अभी भी स्कूल की पहुंच प्राप्त नहीं हो पा रही है और अध्ययन दर्शाता है कि कक्षा 4 तथा 5 के बहुत से बच्चों को हिंदी और गणित में बहुत कठिनाई आ रही है, यहाँ तक कि विकसित क्षेत्रों में भी यही पाया गया है। हालांकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रदर्शन न्यूपा के परीक्षण में बेहतर पाया गया हैं। रिग्रेशन विश्लेषण बच्चों की पहुँच और विभिन्न परिवारों और विद्यालय संबंधी कारकों के बीच महत्वपूर्ण संबंध दर्शाता हे।

12- nl yk[k ls vf/kd vkcknh ds eyhe cfLr;ksa esa fo|ky; f'k{kk esa igqp] Hkkxhnkjh vkSj vf/kxe Lrj% gSnjkckn vkSj yqf/k;kuk dk dsl v/;;u

vUos"kd % Mk- lquhrk pqx

fu"d"kkZ dk lkjka'k

यह अध्ययन दो शहरी क्षेत्रों की मलीन में (हैदराबाद तथा लुधियाना) पहुंच, भागीदारी और स्कूल के प्रत्येक स्तर पर बच्चों की अधिगम क्षमता पर किया गया। यह 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बचचों की शिक्षा की थिति को दर्शाता है। यह इन प्रश्नों का उत्तर देता है कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति तथा अप्रवास से जुड़ी हुई है। अध्ययन में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुये। अध्ययन में लुधियाना तथा हैदराबाद में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। लुधियाना में स्लम में बुनियादी स्कूली सुविधाओं की कमी थी जबकि हैदराबाद में एक किलोमीटर के दायरे के भीतर बच्चों को स्कूली सुविधाएं प्राप्त थीं इसके अतिरिक्त हैदराबाद के स्लम में बच्चों की भागीदारी लुधियाना के बच्चों की भागीदारी से ज्यादा थी। हालांकि, स्लम क्षेत्रों में बच्चों को अधिगम स्तर दोनों शहरों में बहुत कम था।

13- fof'k"V vf/kxe foDykax cPpksa ds lesdu gsrq uhfr rFkk 0;ogkj v/;;u ¼U;wik QM ds fcuk vuqla/kku½

vUos"kd % Mk- ohjk xqIrk

fu"d"kkZ dk lkjka'k

इस अध्ययन का उद्देश्य स्कूली बच्चों के स्तर में सुधार गुणवत्तायुक्त शिक्षा द्वारा प्राप्त करना है। स्कूली छात्रों को आने वाली कठिनाइयों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 2012 के बिल के द्वारा 'डायसलेक्सिया' विशिष्ट अधिगम विकलांगता एस.एल डी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अध्ययन में बिल की समीक्षा के माध्यम से, एस.एल.डी की स्थिति, परिभाषा, कारण तथा सुधारों का विश्लेषण किया गया है। इसमें एस.एल.डी से प्राप्त ज्ञान तथा नीतियों के निर्माण के बीच व्याप्त अंतर को दर्शाया गया है।

अध्ययन में जिला सूचना प्रणाली और सरकारी नीतियों के घटकों का विश्लेषण किया गया है तथा एस.एल.डी उपलब्ध आंकड़ा, पहचान तथा स्कूल में उसके मूल्यांकन का अध्ययन किया गया है। यह बताता है कि भारत में एस.एल डी छात्रों के लिए नीतियां अप्रमाणित रूप से विकसित हैं। परिणामस्वरूप, केवल 0.1 प्रतिशत एस.एल. डी छात्रों की पहचान की गई है जबकि इनकी सख्या 20 प्रतिशत से भी अधिक है। अधिगम स्तर को बढ़ाने हेतु, यह आवश्यक है कि स्कूल जाने वाले इस बढ़े वर्ग को ध्यानपूर्वक संबोधित किया जाए। इन्हें केवल समझादार व्यक्तियों और गैर–सरकारी संगठनों पर न छोड़ा जाये। सरकार के साथ साझेदारी आवश्यक है। सरकार को शिक्षा कोड तथा शिक्षकों के प्रदर्शन मूल्यांकन, डायरी

तथा अध्ययन योजना के साथ नीति दस्तावेजों को परिभाषित करना होगा। पहचान, मूल्यांकन तथा एस.एल.डी. को प्रदान हस्तक्षेपों के संदर्भ में नियम तथा प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए। वृहद तथा सतत् मूल्यांकन संहिताएँ एस.एल.डी. के स्पष्ट प्रावधानों के लिये की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह भी पाया गया कि एस.एल.डी. प्राप्त आंकड़ा अर्पाप्त है। इस बात की आवश्यकता है कि गुणवत्तायुक्त अनुसंधानों के संचालन, उपलब्ध डाटा के विश्लेषण तथा और अधिक आंकड़ा के सृजन हेतु और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का एकीकरण अध्यापकों, परामर्शदाताओं तथा नीति–निर्माताओं के लिये उपलब्ध कराया जाये। सरकार को इस क्षेत्र में सघन अनुसंधानों के लिये प्रयास तथा प्रोत्साहन देना चाहिए। इन अध्ययन निष्कर्षों से भारत में एस.एल.डी. पर वृहद नीति के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे कम अधिगम स्तर की बिखरी हुई श्रृंखला को श्रृंखलाबद्ध करने में मदद मिलेगी। अध्ययन संस्तुति करता है कि अन्य विकसित देशों की तरह भारत में भी मानक प्रपत्र में नीति तथा प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जिससे कि भारत में 40 मिलियन एस.एल.डी. बचों को अन्य जनसंख्या की तरह लाभ मिल सके।

14- lo Z f'k{kk vfHk;ku esa eY;kdu rFkk leh{kk esa ySfxd rFkk lerk eqíks dk fdl izdkj lEcksf/kr fd;k x;k g\

vUos"kd % Mk- foeyk jkepUnu

fu"d"kksZ dk lkjka'k

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य लैंगिक तथा सामाजिक अंतर को दूर करना है। हालांकि यह अभियान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषित है, तीन बाह्य विकास पद्धति भी सर्वशिक्षा अभियान को वित्त पोषित करते हैं। मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय विश्वबैंक संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए युनाईटेड किंगडम विभाग तथा यूरोपीय संघ एक भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार तथा डी.पी. के साथ छह महीने का संयुक्त समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह डेस्क समीक्षा इस उद्देश्य से की गई कि दानकर्त्ता अभिकरण तथा सरकार द्वारा लैंगिक तथा समता लक्ष्यों पर किस प्रकार अनुश्रवण और संबोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट रूप से यह अध्ययन यह भी बताता है कि एस.एस.ए. फ्रेमवर्क के अंतर्गत समता तथा लैंगिक को किस प्रकार समझा जा रहा है। क्या एस.एस.ए., जे.आर.एम. तंत्र का केन्द्र बिन्दु आगत संकेतकों, प्रक्रिया संकेतकों तथा निर्गत संकेतकों पर है ओर एस.एस.ए., जे.आर.एम. में कौन से लैंगिक संबंधित मुद्दे हैं जिन्हें प्रमुख रूप से दर्शाया गया है तथा पिछले कुछ वर्षों में क्या संस्तुतियां की गई हैं?

- पहुंच पर जे.आर.एम. रिपोर्ट, चर्चा अधिकांश रूप से नामांकन, ड्राप–आउट दर, विद्यालय धारण, उपस्थिति, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्रमण तथा विद्यालय संरचना पर आधारित है। इसके अंदर, सूचना अधिकांश रूप से राज्य, जिला और राष्ट्रीय आंकड़ा तक सीमित है। केवल कुछ भाग में आंकड़ा लैंगिक, सामाजिक समूह (अधिकांश अ.जा./अ.ज.जा., मुस्लिम) तथा स्थान (ग्रामीण और शहर) पर उपलब्ध हैं।
- जे.आर.एम. रिपोर्ट समता के महत्वपूर्ण निर्धारकों पर चुप है क्योंकि यह बच्चों को उपलब्ध गुणवत्ता शिक्षा को निर्धारित करती है। त्याग दर की चर्चा तो की जाती है परन्तु इसके कारणों पर न तो चर्चा की जाती है न इनका विश्लेषण होता है।
- समता मुद्दों के लिये अधिगम परिणाम तथा गुणवत्ता मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता जबकि गुणवत्ता इसके केंद्र में है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अधिगम उपलब्धि स्तर को सुधारने और हस्तक्षेपों एवं विभिन्न कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग के लिये जे.आर.एम. तंत्र बहुत मजबूत है, परन्तु हमें यह नहीं पता कि हस्तक्षेपों के लिये किन बच्चों को लक्षित किया जा रहा है। इनसे कितने बच्चों को लाभ मिला है और अधिगम स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार, सभी राज्यों को लैंगिक तथा समता मुद्दों को विद्यालय पाठ्यचर्या तथा पुस्तकों में संयोजित करना है। परंतु, जे.आर.एम. रिपोर्ट लैंगिक और समता मुद्दे इस बात को बताने में अपूर्ण हैं कि किस प्रकार लैंगिक और समता मुद्दे आपस में जुड़े हैं।

- छात्रों के प्रति व्यवहार तथा अध्यापकों के दृष्टिकोण के प्रति जानकारी उपलबध नहीं है। अगर हम जे.आर.एम. रिपोर्ट को देखें तो हमें यह नहीं पता चलता कि कक्षा के अंदर क्या हो रहा है तथा कक्षा में अध्यापकों के क्या पूर्वाग्रह हैं। हालांकि कई अध्ययनों में इन पूर्वाग्रहों का उल्लेख आया है विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. बच्चों के प्रति। हम यह जानते है कि कितने अध्यापकों का नियुक्त किया जा रहा है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है परन्तु हम यह नहीं जानते कि समेकित कक्षा में सृजन हेतु अध्यापक क्या भूमिका अदा कर रहा है।
- आमतौर पर जे.आर.एम. लैंगिक तथा समता मुद्दों का अलग से देखता है। यह सर्व शिक्षा अभियान में समता के प्रति कम समझ के कारण हे। समता को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समान अवसरों के रूप में देखा जाता है। (मा.सं.वि.मं., 2010) यह परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि 'समान अवसर' क्या हैं? क्या इसका अर्थ है कि सभी बच्चों को स्कूल की सुविधा, संसाधन तथा बुनियादी सुविधायें प्राप्त होगी तथा कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा तथा सभी बच्चों को अधिगम की समान सुविधा उपलब्ध होगी? यह अस्पष्ट है।
- अधिकांश जे.आर.एम. रिपोर्ट में सी.डब्ल्यू.सी.एन., अप्रवासी बच्चों और शहरी गरीबों पर चर्चा अस्पष्ट है। हम इन समूहों के बारे में बहुत कम जानते हैं और यह कैसे गठित हुए। सी.डब्ल्यू.सी.एन. को सम्मान देते हुए, जे.आर.एम. रिपोर्ट चिन्हित तथा नामांकिंत बच्चों तथा इन्हें दिये जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों तक सीमित है। जे.आर.एम. रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि बच्चों की पहचान तथा विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि, हम सी.डब्ल्यू.सी.एन. के लैंगिक और सामाजिक समूह संगठन को नहीं जानते हैं। हम यह नहीं जानते कि सी.डब्ल्यू.सी.एन. के किस समूह के स्कूल की अधिक पहुंच है, तथा सी.डब्ल्यू.सी.एन. के लिए कौन से समेकित व्यवहार उपलब्ध हैं तथा सी.डब्ल्यू.सी.एन. के प्रति अध्यापकों और बच्चों का क्या दृष्टिकोण है?

अंत में, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के प्रति जे.आर.एम. का पूर्वाग्रह हैं। भारत सरकार डाइस आंकड़ा के प्रयोग में सुविधाजनक है। तथा एन.एस.एस.ओ. के आंकड़ा का भी प्रयोग करती है। परन्तु सामाजिक आर्थिक संकेतकों तथा बच्चों के शैक्षिक भागीदारी पर सूचना का एकीकरण अभी भी चुनौतीपूर्ण कार्य है।

15- Hkkjr esa futh fo'ofo|ky;ksa dk v/;;u

vUos"kd % Mk lxhrk vxke

fu"d"kZ dk lkjka'k

2002 में एक्ट द्वारा निजी विश्वविद्यालय की संकल्पना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हुई। यह विश्वविद्यालय स्वःवित्तपोषित हैं और पंजीकृत प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा संचालित है।। तथा स्थापना के लिये विधायी स्वीकृति और यू.जी.सी. से अनुमोदित हैं। इनमें से कई विश्वविद्यालय बहु–आयामी पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।

वर्तमान में, 150 निजी विश्वविद्यालय भारत में कार्यरत हैं तथा पिछले 2/3 वर्ष में निजी विश्वविद्यालयों का उद्भव चिंता का विषय है। निजी राज्य विश्वविद्यालय एक्ट अकादमिक कार्यो में पूर्ण स्वायतत्ता तथा वित्तीय स्वायतत्ता की स्वतंत्रता देता है। हालांकि, निजी विश्वविद्यालयों का अभिशासन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तरह ही है परन्तु इनके गठन, प्राधिकरण के आकार तथा नियुक्ति के स्वरूप और अधिकारियों के कार्य के संदर्भ में व्यापक अंतर है। विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए पाठ्यक्रम बाजार–मांग और रोजगार पर उपलब्ध हैं अधिकांश निजी विश्वविद्यालय सीमित स्टाफ रखते हैं। तथा इन विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टाफ की गुणवत्ता भी कम होती है। अध्ययन के अंतर्गत आने वाले अधिकांश निजी विश्वविद्यालयों में नीति–संगठन, वेतन–ढांचा तथा स्टाफ–विकास योजना के लिए कोई निर्धारित नीति नहीं है। छात्रों का प्रोफाईल दर्शाता है कि अधिकांश छात्र सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके परंतु उनके पास निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के हेतु फीस देने के लिये धन था। प्रतिदर्श विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया तथा अधिकांश नामांकन स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में हुआ।

इन विश्वविद्यालयों के आय का मुख्य श्रोत ट्यूशन फीस था और बहुत कम विश्वविद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतर्गत आने वाले निजी विश्वविद्यालय आंतरिक मूल्यांकन के साथ सत्रीय व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।। त्याग दर बहुत कम है तथा प्रतिदर्श विश्वविद्यालयों में स्नातक दर बहुत अधिक है। अनुसंधान का स्तर कम है तथा प्रशिक्षण और नौकरी दिलवाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इनके सामने मुख्य चुनौतियां गुणवत्तायुक्त छात्र, नाकांकन में वृद्धि, अनुभवजन्य संकाय तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिये निधि हेतु अभिकरणों को प्राप्त करना है। भारत में निजी विश्वविद्यालयों के बीच बहुत विविधता हैं और उनमें से अधिकांश अव्यवस्थित और असंयोजित हैं।

16- jktLFkku rFkk gfj;k.kk e iol&ikFkfed f'k{kk dh ekx dk lekfJtd vk;ke

vUos"kd % Mk- e/kferk c|kik/;k;

fu"d"kk dk lkjk'k

यह अनुसंधान पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्य सरलीकरण हेतु आपूर्ति प्रयास एवं मांग के अनुरूप इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के लिये किया गया। इसमें समीपवर्ती क्षेत्रों में पूर्व–स्कूल केंद्र की उपलब्धता, स्कूलों की कार्य प्रणाली, पूर्व स्कूलों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण, पूर्व–स्कूल से प्राथमिक स्कूल में बच्चों का संक्रमण, पूर्व–स्कूल शिक्षा में बच्चों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, विभिन्न प्रबंधनों द्वारा भौतिक तथा अकादमिक सुविधाएं सम्मिलित हैं। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा पर आधारित हैं। 3280 पूर्व–स्कूल छात्रों के साथ प्राथमिक आंकड़ा 84 स्कूलों और 72 आंगनवाड़ी से एकत्र किये गये। आंकड़ा 84 स्कूल प्रमुखों, 67 पूर्व–प्राथमिक शिक्षकों, 72 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं तथा सहायिकाओं, 1132 प्रतिदर्श अभिभावकों के साक्षात्कार माध्यम से भी एकत्र किया गया। पूर्व स्कूल से प्राथमिक स्कूल में संक्रमण के मूल्यांकन हेतु, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में नामांकित लगभग 3500 (अनुमानित) बच्चों के लिये स्कूल रोस्टर आंकड़ा का संग्रह किया गया।

स्कूलों तथा आंगनवाड़ी सर्वेक्षण से यह पता चला कि पूर्व–स्कूल की पहुंच में हरियाणा की स्थिति राजस्थान से बेहतर है। हरियाणा में नर्सरी ग्रेड सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध था जबकि राजस्थान में निजी स्कूलों के अलावा आंगनवाड़ी पूर्व–स्कूल की सुविधा प्रदान कर रहे थे। यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों की तुलना में दोनों राज्यों में निजी स्कूल पूर्व–स्कूल की सुविधाएं प्रदान करने में आगे थे। सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी में सेवाओं की गुणवत्ता असंतोषजनक थी, हालांकि अलग–अलग ब्लॉक में विविधता भी व्याप्त थी।

जारी अनुसंधान अध्ययन

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

1- rfeyukM rFkk mMhlk e ftyk ek/;fed f'k{kk ;kstuk fodkl ij dk;Z&vuql/kku ifj;kstuk

vUos"kd % ik- , l-,e-vkb-,- tSnh] ik- d- fcLoky rFkk Mk- ,u-d- ekgrh

यह प्रयास कार्य अनुसंधान के माध्यम से आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना की तैयारी में राज्यों द्वारा अनुसरित योजना प्रक्रिया, विधि तथा तकनीकों का समीक्षात्मक विश्लेषण हेतु है। इसका बुनियादी उद्देश्य व्याप्त दशाओं तथा नीति निर्माण के लिये तकनीकी, सांस्थानिक तथा अन्य बाधाओं को समझना तथा जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की योजना तथा प्रबंधन के अनुप्रयोग तथा आर.एम.एस.ए. के कार्यान्वयन की सीमाओं को समझना है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया और डी.एस.ई.पी. के निर्माण में व्यावसायिक बाधाएं तथा तकनीक और सांस्थानीकरण को समझने में शायद ही कोई अध्ययन किया गया हो। अध्ययन शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण गतिविधियों की आपूर्ति तथा प्रभावी रूपरेखा हेतु प्रशिक्षक के रूप में न्यूपा संकाय की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने हेतु कार्य–अनुसंधान के माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान के सृजन

हेतु लक्षित हैं। इस संदर्भ में, कार्य–अनुसंधान तमिलनाडु तथा उड़ीसा में क्रियान्वित किया गया। तमिलनाडू के चार जिलों (सेलम, थेनी, कुड्डालोट तथा मदुराई) और उड़ीसा से दो जिले (कोयनझार तथा गंजम) अनुसंधान के क्रियान्वयन के लिये चुने गये।

अभी तक, संबंधित साहित्य की समीक्षा की जा चुकी है। अनुसंधानदल ने राज्य तथा जिला योजना दल के साथ बैठकों के कई दौर किए है। आर.एम.एस.ए. में योजना पर बल देते हुए और सामान्य रूप से विद्यालयी शिक्षा में जिला योजना के विभिन्न पहलुओं पर चार परामर्शकारी बैठक और दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। संगठित आंकड़ा प्रपत्र संग्रह तैयार किया गया और प्रासंगिक आंकड़ा प्राप्त करने से पहले परीक्षण किया गया अन्य विधियां जैसे सामूहिक कार्य, सामूहिक चर्चा, जिला तथा उपजिला प्रशासनिक स्तर एककों, स्कूलों में क्षेत्र भ्रमण किया जा चुका हे। कोडिंग, फीडिंग तथा आंकड़ा संशोधन किया जा चुका है। टी.एस.जी., आर. एम.एस.ए. भारत की जनगणना, एन.एस.एस.ओ. तथा यू.डी.आई.एस.ई. से प्राप्त आंकड़ों का संशलेषण किया जा रहा है। प्रतिदर्श राज्यों का आर.एम.एस.ए. योजना दस्तावेज़ की समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में प्रथम चरण की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

2- Hkkjr esa rqyukRed f'k{kk dh LFkkfud xfr'khyrk

vUo"kd % ik- ekuk [kjs

प्रस्तावित अध्ययन निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर खोजता है:

- क्या देश में अग्रणी या पिछड़े क्षेत्र हैं?
- क्या आर्थिक रूप से अग्रणी तथा पिछड़े क्षेत्र हैं? जो शैक्षिक रूप से अग्रणी तथा पिछड़े हैं?
- क्या कुछ पिछड़े शैक्षिक क्षेत्र हैं और तुलनात्मक रूप से नुकसान में हैं?
- भारत में शैक्षिक और आर्थिक विकास का क्षेत्रीय पैटर्न क्या है?
- क्या अंतर–क्षेत्रीय आर्थिक विकास की विषमाताएं उच्च स्तरीय शिक्षा पर अधिक है?
- भारत में तुलनात्मक शिक्षा के कारण क्या हैं? और किस हद तक आर्थिक विषमताओं को वर्णित किया जा सकता है?
- भारत में शिक्षा के संदर्भ में, एक क्षेत्र का आर्थिक ढांचा किस प्रकार शैक्षिक विकास को प्रभावित करता है?
- शिक्षा में स्थानीय योजना किस प्रकार समतावादी स्थानीय विकास को प्रभावित करती है?

अब तक, साहित्यिक समीक्षा पूर्ण हो चुकी हैं विद्यालय शिक्षा विकास सूचकांक के लिये अंतर–राज्यीय सारणीकरण तथा आंकड़ा–विश्लेषण जारी है। उच्च शिक्षा विकास के संकेतकों की पहचान की जा चुकी है और द्वितीय स्रोतों से आंकड़ा संकलन का कार्य जारी है।

3- Hkkjr esa fo|ky; ekufp=.k ¼fcuk fuf/k vuqlaFkku d½

vUo"kd % ik- d- fcLoky

हाल ही के वर्षों, में विद्यालय मानचित्रण, एक स्थानीय स्तर की योजना तकनीक प्रत्येक विकासशील देश में विद्यालयी प्रावधान के विस्तार और संगठनीकरण हेतु रणनीतिक निर्णयों के लिये महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। निर्णय समर्थन उपकरण के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के वितरण में विधायी प्रावधानों से उत्पन्न हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में विद्यालयी मानचित्रण सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिये– अनिवार्य शिक्षा एक्ट, आई.टी. अनुप्रयोग के साथ, स्कूल मैपिंग विभिन्न मानदंडों और मानकों में निजी निवेश के अनुकरण हेतु एक शक्तिशाली उपकरण है। इस संदर्भ में अनुसंधान अध्ययन भारत में आजकल प्रयोगरत विद्यालय मानचित्रण तकनीक की समालोचना नीति तथा कार्यक्रम योजना के लिये करता है। विशिष्ट रूप से आलेख योजना उपकरण के लिये स्कूल मैपिंग के उद्भव, संकल्पना की व्याख्या, विधि तथा योजना नीति तथा संसाधनों के आवंटन की लघु चर्चा के लिये करता है।

यह आलेख जी.आई.एस. आधारित प्रारंभिक स्तर पर राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित विद्यालय मानचित्रण का परीक्षण करता है। यह तमिलनाडु के जिले में विद्यालय मानचित्रण पर डिस्टेन्स मैट्रिक्स तथा

सर्व शिक्षा अभियान एवं आर.एम.एस. के अंतर्गत एक केस अध्ययन को भी सम्मिलित करता है वर्तमान में आलेख का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

4- 'kSf{kd :i ls fiNMs ftyksa esa oSdfYid mikxe vuqla/kku ekuksxzkQ

vUos"kd % iks- ekuk [kjs

यह मोनोग्राफ शैक्षिक विकास/पिछड़ापन के विभिन्न बहुश्रेणी विविध मार्गदर्शिका के लिये गाईड है। हालांकि, यह तकनीक स्वरूप में सांख्यिकी और गणितकीय हैं, मोनोग्राफ गैर–गणितकीय और गैर–सांख्यिकीय प्राथमिक रूप से प्रस्तुत करेगा। इसका बुनियादी उद्देश्य पाठकों को निम्नांकित प्रदान करने में होगाः

- शैक्षिक विकास के बहुसंख्यक संकेतकों की पहचान तथा समझ
- बहुसंख्यक संकेतकों के संदर्भ से जुड़ी समस्याओं को समझना तथा इस्तेमाल करना।
- बहुश्रेणी अधिगम विकास वैकल्पिक तकनीक शैक्षिक विकास के बहुश्रेणी इंडैक्स के गठन हेतु विभिन्न विधि का इस्तेमाल
- शैक्षिक विकास बहुआयामी अनुक्रमणिका को विकसित करने हेतु विभिन्न विधियों का उपयोग
- एस.पी.एस.एस. जैसे साफ्टवेयरों का प्रयोग अनुक्रमणिका को विकसित करने हेतु वास्तविक आंकड़ा।

इस समय, मोनोग्राफ का पहला ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें सिद्धांत वर्णित हैं। इससे वास्तविक जीवन आंकड़ा सेट द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।

5- mPp f'k{kk ls ckgj çoklu ds dkj.kksa vkSj ifj.kkeksa ij ,d LFkkfud ifjç{;% fgekpy çns'k dk ,d dsl v/;;u

vUos"kd % Mk- lqeu uxh

संबंधित साहित्य और आंकड़ा संग्रह की समीक्षा का कार्य प्रगति पर हैं। माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक और शिक्षा प्रोफाइल, पर दो अध्यायों का ड्राफ्ट रूपरेखा तैयार किया गया। प्रवास से संबंधित डाटा (2011 की जनगणना तालिका डी2 और डी3) पूरा हो चुका है। डी4 प्रवास तालिका छंटनी प्रक्रिया के तहत है। सभी राज्यों के लिए अंतिम तालिकाएं तैयार हैं। प्रश्नावली विकसित की गई और कुल्लू जिले के दो गांवों में संचालित की जा रही हैं।

6- uks jkT;ksa esa vkfnoklh cgqy {ks=ksa esa çkFkfed vkSj mPp çkFkfed f'k{kk ds fy, miyC/k lqfo/kkvksa dk vkdyu

vUos"kd % çks- ds- lqtkrk vkSj Mk- oh- lqpfjrk

आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन पर एक अध्ययन नौ राज्यों के 25 विशेष फोकस जिलों जनजातीय क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैंः (क) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा और मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच करना (ख) मौजूदा शैक्षिक सुविधाओं लैंगिक, आदिवासी बच्चों की भाषाई और सामाजिक–सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जांच और (ग) उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं और उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में माता–पिता के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए आदिवासी बच्चों के संदर्भ में अध्यापक परिप्रेक्ष्य। अब तक, प्राथमिक आंकड़ा नौ राज्यों के 25 जिलों से आए 750 नमूना गांवों से एकत्र किया गया है। आंकड़ा विश्लेषण और राज्य रिपोर्ट की तैयारी प्रगति पर है।

7- rhljk vf[ky Hkkjrh; 'kSf{kd iz'kklu losZ{k.k

leUo;d % Mk- vkj-,l- R;kxh

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने हेतु (1973 में पहली बार, और 1990 में दूसरी बार) दो शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण किये गये। सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य प्रणाली की बदलती मांगों के अनुरूप शैक्षिक प्रशासन की स्थिति और इसकी जवाबदेही की

जांच करना, पिछले दो दशकों के दौरान, राज्य, क्षेत्र, जिला, उप–जिला और संस्थागत स्तर पर सुधारों और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कई नीतिगत पहल और शैक्षिक कार्यक्रमों को विभिन्न स्तरों पर शुरू किये गये। इन प्रयासों और उपायों ने शैक्षिक प्रशासन में नया आयाम जोड़ दिया है। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की स्थिति की जांच करने हेतु और शैक्षिक प्रशासन में परिवर्तन के लिए, न्यूपा ने शैक्षिक प्रशासन और शासन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए कई विषयगत अध्ययनों के साथ 2013 में प्रारंभ किया। अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान स्थिति की जांच करना
- शैक्षिक प्रशासन में अधिक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए प्रमुख मुद्दों और हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करना
- राष्ट्रीय, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रशासन में सुधार के लिए उपाय सुझाना

सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित अध्ययन और गतिविधियाँ की गईं

- डा. आरएस त्यागी द्वारा केरल में शैक्षिक प्रशासन पर पायलट अध्ययन;
- डा. मंजू नरूला द्वारा बिहार में शैक्षिक प्रशासन पर पायलट अध्ययन; अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- इन पायलट अध्ययन के आधार पर, तीसरे सर्वेक्षण के लिए उपकरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है; और
- प्रो. सुरेश कुमार द्वारा मध्य प्रदेश और बिहार में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की क्षमता और साझा जिम्मेदारियों पर अध्ययन।

अब तक राज्यों के साथ संस्थागत व्यवस्था सर्वेक्षण के संचालन के लिए बनाई गई है। आंकड़ा संग्रह के लिए उपकरण विकसित किया गया है। केरल और बिहार में प्रारंभिक पढ़ाई की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

8- djy esa 'kSf{kd ç'kklu ij ik;yV vè;;u

vUos"kd % Mk- vkj-,l- R;kxh

केरल में पिछले दो दशकों के दौरान शैक्षिक प्रशासन और उभरते आयामों में परिवर्तन का इस अध्ययन में मानचित्रण करना है। सूचना और आंकड़ा संग्रह पूरा हो गया है। आंकड़ा जिला और ब्लॉक स्तर से और समर्थन संस्थाओं, सचिवालय, निदेशालय और एससीईआरटी, सीमेट और परीक्षा बोर्ड से एकत्र किया गया है। शिक्षा नीति की पहल, प्रशासनिक संरचना, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यों की इस अध्ययन के तहत जांच की गई है। डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर है।

9- fcgkj esa 'kSf{kd ç'kklu ij ik;yV vè;;u

vUos"kd % Mk- eatw u:yk

बिहार में पिछले दो दशकों के दौरान शैक्षिक प्रशासन और उभरते आयामों में परिवर्तन का इस अध्ययन में मानचित्रण करना है। सूचना और आंकड़ा संग्रह पूरा हो गया है। आंकड़ा जिला और ब्लॉक स्तर से और समर्थन संस्थाओं, सचिवालय, निदेशालय और एससीईआरटी, सीमेट और परीक्षा बोर्ड से एकत्र किया गया है। शिक्षा नीति की पहल, प्रशासनिक संरचना, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यों की इस अध्ययन के तहत जांच की गई है। डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर है।

10- e/; izns'k vkSj fcgkj esa çkFkfed f'k{kk ds çcèku esa lk>k ftEesnkfj;ksa ij vè;;u vkSj LFkkuh; fudk;ksa dh {kerk

vUos"kd % çks- dqekj lqjs'k

अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में राज्य और स्थानीय निकायों के बीच संबंधों की प्रकृति को दर्शाने का प्रयास करता है। मानचित्रण के दो स्तर

हैं। पहले स्तर पर, राज्य अधिनियमों, सरकार के आदेश और परिपत्रों के माध्यम से उन्हें प्रदान की गई शक्ति और जिम्मेदारियों के आधार पर स्थानीय निकायों की क्षमता की जांच करना है। परीक्षा के दूसरे स्तर पर जमीनी स्थिति पर राज्यों, स्थानीय निकायों के शक्तियों और जिम्मेदारियों की जांच करना है।

प्रासंगिक अधिनियम, परिपत्र, सरकार के आदेश अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं, अधिकांश प्रासंगिक दस्तावेज बिहार से एकत्र किये गये हैं। प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और स्थानीय निकायों के बीच रिश्ते से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए राज्यों के नमूने लिए जा रहे हैं।

11- ikFkfed Lrj ij vkèk çn'k vkj mÙkj çn'k e efLye cPpk d xj&ukekdu vkj R;kx nj d dkj.k% ,d rqyukRed vè;;u

vUo"kd % Mk- oV dj ih-,l- jkt

अध्ययन मुख्य रूप से भारत के दो राज्यों में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों की ड्रॉप आउट और गैर–नामांकन के कारणों की पहचान करता है। तदनुसार, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा गैर नामांकन और ड्रॉप आउट के प्रारंभिक स्तर पर, पूरा हो गया है। साहित्य समीक्षा दर्शाती है कि कोई भी पर्याप्त अनुसंधान और अकादमिक साहित्य प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के अनामांकन तथा त्याग दर को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा, प्रासंगिक माध्यमिक आंकड़ा भी एनएसएसओ, डीआईएसई और जनगणना रिपोर्ट से एकत्र किया गया है।

12- ekè;fed f'k{kk d fy, yMfd;k dk çkRlkgu jk"Vh; ;ktuk dh dUæ çk;kftr ;ktuk dk eY;kdu vè;;u ¼,u,lvkbZ,lb½

vUo"kd % Mk- oV dj ih-,l- jkt

आठ नमूना राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी से संपर्क किया गया है और क्षेत्र का दौरा स्कूलों से जानकारी को अंतिम रूप देने के लिये किया गया। अध्ययन का दो जिलों के 20 स्कूलों और प्रत्येक राज्य से 200 छात्रों का है। छात्रों, संस्थानों और शिक्षा अधिकारियों के प्रमुखों से डेटा संग्रह के लिए उपकरण, विकसित किया गया। तीन राज्यों में दौरा किया गया – पुडुचेरी, पंजाब और मध्य प्रदेश के नमूना स्कूलों से डाटा एकत्र करने हेतु। अब तक प्रतिदर्श पांच जिलों, 50 स्कूलों और 500 से अधिक छात्रों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में, कोडिंग और डेटा की फीडिंग का कार्य प्रगति पर हैं।

13- Hkkjr e bthfu;fjx f'k{kk dk fodkl

vUo"kd % çk- tk/;kyk chth fryd

ब्रिक देशों में उच्च शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन के एक भाग के रूप में, 2009–10 में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के करीब 40 इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों पर आंकड़ा एकत्र किया गया। सर्वेक्षण में इन संस्थानों के 7000 छात्रों को कवर किया। उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, शिक्षा पर उनके व्यय, और इंजीनियरिंग शिक्षा और इसी तरह के पहलुओं की गुणवत्ता पर उनके विचार – छात्र सर्वेक्षण डेटा, छात्रों की विशेषताओं के संदर्भ में प्रदान करता है.

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया। भारत में बहुत कम अध्ययन इस दिशा में हुए हैं। इस संदर्भ में 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय पर वी.के.आर.वी. राव का अध्ययन शामिल हैं; और दूसरा 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के विकास सान्याल का आई.आई.ई.पी. अध्ययन।

वित्त पोषण, फीस, ऋण और अन्य पहलुओं से संबंधित नीति बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण विस्तृत विश्लेषण हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन किया गया और पूरा अंतिम परिणाम एक पुस्तक के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास पर अध्ययन हेतु विशाल आंकड़ा का उपयोग किया जा रहा है:

- सार्वजनिक और निजी इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए विकास
- कौन से छात्र इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए जा रहे हैं?

- इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए मांग के निर्धारकों की जांच
- निजी शिक्षा के विकास की व्याख्या करने वाले कारक
- इंजीनियरिंग शिक्षा की लागत (घरेलू और सार्वजनिक)

अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। कुछ अध्यायों का ड्राफ्ट पूरा हो चुका है और बाकी कार्य प्रगति पर है।

14- Ldwy vuqnku ds mi;ksx ij vè;;u vkSj loZ f'k{kk vfHk;ku ds rgr mudk mi;ksx iSVuZ½ e?kky; dk dsl LVMh ¼U;wik ls fcuk /ku ds leFkZu ds lkFk½

vUos"kd % çks ; tkyh tkWlfQu

सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्त पोषण स्थायी होना चाहिए। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी पर एक लंबी अवधि के नजरिए की आवश्यकता के तहत सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिये भारत मे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90:10 तथा अन्य क्षेत्रों के लिये 65:35 होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल अनुदान सहित मेघालय और इसके जिलों के लिए केंद्र से धन के उपयोग का विश्लेषण, राज्यों से डाईस/यू–डाईस और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों और माध्यमिक और प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर मुख्य रूप से किया गया था।

आंकड़ा और संबंधित जानकारी के प्रारंभिक विश्लेषण बताते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बजट प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों में निर्दिष्ट सभी उपायों को समाहित करते हुए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी. तथा बी) के रूप में तैयार किया जाता है। एक वर्ष के लिए मदनुसार बजट की मांग ए.डब्ल्यू. पी. तथा बी में शामिल किए गए। ए.डब्ल्यू.पी. तथा बी. प्रस्तावों की दो भागों में परिकल्पना की गई है, चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित और पिछले वर्ष की गतिविधियों का सिंहावलोकन किया गया है।

वित्त आयोग भी राज्य सरकार के माध्यम से समाज को कुल बजट परिव्यय से सहयता अनुदान प्रदान करता है 12वें वित्त आयोग, ने यह सिफारिश की कि उत्तर पूर्वी राज्य के अलावा दूसरे राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के अनुदान 15% दिया जाये। उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में 12वें वित्त आयोग ने संस्तुति की कि 2007–08 तथा 2008–09 मे प्रत्येक राज्य द्वारा अंशदान की गई राशि के अंतर को 10% अंशदान के साथ दी जाए। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 90:10 के अंशदान पद्धति को वित्त आयोग द्वारा दिए गए सहायता अनुदान को घटाकर दिया जाए। पी.ए.बी. की तिथियों पर निर्भर करते हुए, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान समिति को पहली सूची जारी की और आगे की किश्त भी तभी जारी की गई जब राज्य सरकार समाज को बराबर का अनुदान प्रदान करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त 50% निधि का व्यय करेगी।

चालू वर्ष की अनुमोदित बजट परिव्यय के आधार पर, राज्य परियोजना कार्यालय को योजना के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान किया। राज्य परियोजना कार्यालय जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार से इसी तरह की प्रक्रिया से धन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जिलों को अपनी धनराशि प्रदान करता है। जिला परियोजना कार्यालय कार्यान्वयन के लिए उप–जिला कार्यालय और ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र को निधि जारी करता है। प्रत्येक जिला कार्यालय को चालू वर्ष का बजट प्रदान किया जाता है जिसे तदनुसार खर्च किया जाता है। समाज में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को अपनाते हुए, विद्यालय प्रबंधन समिति को सिविल कार्य, अध्यापन–अधिगम उपकरण, विद्यालय अनुदान तथा वार्षिक अनुदान के लिए निधि दी जाती है।

15- f'k{kk _.k ij C;kt lfClMh dh dsUæh; {ks= dh ;kstuk dk eWY;kadu% ykHkkfFk;ksa dh lkekftd&vkfFkZd fLFkfr dk ,d fo'ys"k.k

vUos"kd % Mk- xhrk jkuh

भारत सरकार, यूनियन बजट 2009–10, ने भारतीय बैंक एसोसिएशन के अंर्तगत शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋण को कवर करने के लिए स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक पूरक योजना की शुरुआत की।

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के मुख्य उद्देश्य के साथ इस ब्याज सब्सिडी योजना को शुरू किया है। योजना के उद्देश्य इक्विटी, सार्वजनिक जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। योजना (प्रति वर्ष कम से कम 4.5 लाख की पैतृक आय के साथ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं और उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है.

इस मूल्यांकन का प्रयोजन यह जानने के लिये है कि केन्द्रीय क्षेत्र की इस शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना से लाभ किसको है। तदनुसार, इस मूल्यांकन से अनुसंधान के निम्नांकित प्रश्न उठते हैं:

- क्या सामाजिक समूहों में ब्याज सब्सिडी के लाभ में कोई असमानता है?
- क्या आर्थिक समूहों में ब्याज सब्सिडी के लाभ में कोई असमानता है?
- क्या राज्यों में ब्याज सब्सिडी के लाभ में कोई असमानता है?
- क्या बैंकों में ब्याज सब्सिडी के लाभ में कोई असमानता है?

निम्नानुसार इस मूल्यांकन के उद्देश्य हैं:

- सामाजिक समूहों ब्याज सब्सिडी में उठाया गया लाभ असमानता का पता लगाने के लिए
- आर्थिक समूहों द्वारा ब्याज सब्सिडी के लाभ के वितरण की जांच करना
- राज्यों द्वारा ब्याज सब्सिडी के लाभ की असमानता का अनुमान लगाने के लिए
- बैंकों द्वारा उठाया गया ब्याज सब्सिडी में अंतर का विश्लेषण करने के लिए

बैंकों से प्राप्त आंकड़ों को यहां प्रस्तावित अनुसंधान सवालों और उद्देश्यों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

16- p;fur jkT;ksa esa vkjVhbZ ds rgr futh LdwYkksa esa ofpr lewgksa vkSj detkj oxZ ds cPpksa ds fy, 25 çfr'kr lhVksa ds laoS/kkfud çkoèkku dk vè;;u% uhfr vkSj vkpj.k

vUos"kd % çks vfouk'k dqekj flag

निजी गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) का अधिकार अधिनियम, अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत राज्यों (ईडब्ल्यूएस) के कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। अधिनियम का कार्यान्वयन अपने चौथे वर्ष में है, प्रावधानीकरण से संबंधित नियमों और विनियमों, को कार्यान्वित किया जा रहा है, इस संबंध में कार्यकर्ताओं के बीच बहुत स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के लिए, बच्चों के चयन और पहचान के लिए पात्रता मानदंड क्या है? कैसे विभिन्न राज्यों में निजी स्कूलों की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं और प्रावधानों को पूरा करने में नियमों और विनियमों का पालन हो रहा है? इन अधिकारों को हासिल करने में माता–पिता और बच्चों द्व ारा किन समस्याओं और बाधाओं का सामना कर रहे हैं? आरटीई के अंतर राज्य विविधता प्रावधान के कार्यान्वयन में इसकी सूचना दी गई है। यह खोजपूर्ण अध्ययन देश के पांच अलग–अलग क्षेत्रों में फैले चयनित 10 राज्यों में शिक्षा अधिनियम–2009 के तहत नीति और वंचित बच्चों की शिक्षा के तरीकों की समझ को विकसित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हैं: (क) नीति और प्रथाओं के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षण प्रावधान के कार्यान्वयन की प्रकृति और सीमा का आकलन करना; (ख) वंचित श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों और माता पिता के बीच आरक्षण प्रावधानों पर जागरूकता के स्तर का पता लगाना; (ग) स्कूल और कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चों के समायोजन से संबंधित मुद्दों की जांच करना; (घ) नए तरीकों की पहचान करने के लिए विभिन्न राज्यों में स्कूलों में आरक्षण प्रावधानों के कार्यान्वयन समस्याएं और विभिन्न हितधारकों, माता–पिता, बच्चों, शिक्षकों

और शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा आरटीई के प्रावधानों के कार्यान्वयन में पेश आ रही बाधाओं की पहचान करना; और (च) निजी स्कूलों में आरक्षण के आरटीई के प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अधिक प्रभावी योजना के लिये उपयुक्त उपाय सुझाना.

उपरोक्त अनुसंधान परियोजना संग्रह और अनुसंधान उपकरण विषय और विकास से संबंधित साहित्य की समीक्षा कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है. साहित्य की समीक्षा के तहत चयनित राज्यों और माध्यमिक सरकारी आंकड़ों के आधार पर राज्यों में आरटीई के मानदंडों के अनुपालन में प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है. अध्ययन के तहत तैयार मापदंड पर चयनित 10 राज्य केरल, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय शामिल हैं. इसके अलावा, डेटा संग्रह के उपकरणों के प्रारूपों को तैयार किया जा रहा हैं। निम्नलिखित उपकरण तैयार किये जा रहे हैं:

- घरेलू सूचना अनुसूचियां
- स्कूल सूचना अनुसूची
- हेड टीचर और अन्य शिक्षकों के लिए अनुसूची
- वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अनुसूची
- उन बच्चों के माता–पिता और अन्य समुदाय के सदस्यों के लिए कार्यक्रम
- स्कूल शासी समितियों के सदस्यों के लिए कार्यक्रम
- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए जाँच सूची (क्लस्टर, ब्लॉक, जिला राज्य)

17- ,d gtkj fo|ky;ksa vuqlaèkku ifj;kstuk% vPNs Ldwyksa dh [kkst

vUos"kd% Mk- ujs'k dqekj

एक औपचारिक संगठन और जहां सबसे अच्छी संभव शिक्षा छात्रों को प्रदान होगी, ऐसी जगह के रूप में स्कूलों का अध्ययन – भारत में एक अच्छे शोध का क्षेत्र नहीं है। मुद्दों, चुनौतियों और विविध गुणवत्ता जैसे कुछ महत्वपूर्ण संकेतक पर एक खंडित तरीके से अध्ययन किया गया है। स्कूली शिक्षा में, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। विविध हितधारकों के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है, फिर भी, स्कूलों में लागू सभी चुनौतियों पर यह एक संवाद करने में विफल रहा है, कि क्या बच्चों के लिए अच्छी तरह से स्कूल काम कर रहा है इस दृष्टिकोण के निहितार्थ दूरगामी हो गए हैं। अक्सर, नीति निर्माता, शोधकर्ता, जन और अभिभावक हैं प्रदर्शन, संस्कृति में मतभेद और समान छात्र जनसंख्या और शिक्षक प्रावधानीकरण के साथ एक ही स्कूल में बच्चों की शिक्षा संदर्भ एक पहेली है।

पिछले दो दशकों से, विद्यालय चयन एवं परिवर्तनकारी उम्मीदें, निजी स्कूलों की ओर पर्याप्त बदलाव ला रही है। निजी स्कूल 20 प्रतिशत हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की आबादी का 80 प्रतिशत से अधिक है इन्हें कम गुणवत्तायुक्त के रूप में चिह्नित किया गया है। जनता के विश्वास और माता पिता का विकल्प बनाने के लिए सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता पीछे है।

14,12,178 प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक स्तर के 128,370 स्कूलों में कई परिदृश्य और स्कूलों की गुणवत्ता की व्याख्याओं और सुविधाओं में विविधता है। स्कूल प्रभावशीलता पर एक साहित्य ने स्कूलों की शैक्षणिक उपलब्धि पर मतभेद पर कोई खास असर नहीं है कि इस धारणा को चुनौती दी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्कूल संकेतकों और छात्र परिणामों का आधार सफल और उच्च प्रदर्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न हितधारकों द्वारा भारत में सरकारी स्कूल अच्छे स्कूल के रूप में पहचाने जाते हैं जो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसलिए, एकाधिक दृष्टिकोण से विविध प्रसंग में स्थित अच्छे स्कूलों के वर्णन विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए इस रूप में परियोजना राज्य भर में विभिन्न स्कूलों के कामकाज को समझने और शिक्षा के क्षेत्र में कर्मियों के साथ इसे साझा करने के क्रम में हितधारकों के माध्यम से सरकार के पक्ष में स्कूल शिक्षा को कामयाब करने में अग्रसर है इससे अच्छा स्कूल बनाने की समझ विकसित होगी?

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- एक अच्छा स्कूल विविध दृष्टिकोण के संदर्भ में

- संदर्भ विशिष्टता के साथ सभी स्कूलों को जोड़ने का दस्तावेज़
- जनता की धारणा को बदलने के लिए विभिन्न हितधारकों और सार्वजनिक मीडिया के साथ अच्छे स्कूलों के विवरण को साझा करना
- 'अच्छा स्कूल कैसे बनता है' प्रमुख विशेषता और समझ प्राप्त करने के लिए

अब तक, अच्छे स्कूलों की एक व्यापक सूची विभिन्न स्रोतों द्वारा (माता–पिता, शिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों, आदि) द्वारा तैयार की गई है।

18- uhfr ifjçs{; vkSj lkekftd èkkj.kk,% vkjVhbZ dh rgr lehk{kk bfDoVh

vUosf"kd % Mk- ujs'k dqekj

यह अध्ययन क्षेत्र से सामाजिक धारणाओं को लेते हुये इक्विटी के विचार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि जोड़ने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए शिक्षा (आरटीई) के अधिकार के तहत दिए गए समता प्रावधानों पर फोकस किया जायेगा। समता लाभ की 'सामाजिक धारणा' का महत्व अस्पष्ट है। इस तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6–14 साल की उम्र के बीच के सभी बच्चों के लिए, विभिन्न प्रावधानों के साथ, समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही समग्र ढांचा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विभिन्न समावेशी प्रावधानों के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में इक्विटी हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुणात्मक प्रस्थान की पहल दर्शाता है। आजादी के बाद भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से पहले कोई नीति/कार्यक्रम, इक्विटी पर मौलिक विचार/दृष्टिकोण नहीं रखता है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में इक्विटी के बारे में संबंधित सामाजिक धारणाओं का शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर एक व्यापक रूपरेखा तैयार करना है। तथा आर.टी.ई. के तहत विभिन्न हितधारकों की अवधारणा को समझना है। ऐसा करके, यह शोध उन धारणाओं के लिए आधार बनेगा।

सामान्य रूप में, अनुसंधान के मुख्य विचार आरटीई के तहत इक्विटी प्रावधानों पर सामाजिक धारणाओं को समझने के लिए, विशिष्ट मामले में, नीति दृष्टिकोण और सामाजिक धारणाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में इक्विटी का एक तुलनात्मक समझ विकसित करता है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य, इसलिए, निम्नलिखित हैं:

- सामाजिक धारणाओं के संदर्भ में विचारों को समझना।
- आरटीई के प्रावधानों के बीच संबंध समझने के लिए (कम्पोजिट कक्षा, पड़ोस स्कूली शिक्षा) शिक्षा के क्षेत्र में इक्विटी.
- प्रदत्त आरटीई एक्ट द्वारा इक्विटी के अर्थ के अंतर को समझना।
- समान शिक्षा नीति से लोगों को बड़ी उम्मीदों की पहचान करना

अब तक संबंधित साहित्य की समीक्षा की गई है। परियोजना विषय से संबंधित एक पृष्ठभूमि आलेख प्रगति पर है. पायलट अध्ययन के लिए प्रश्नावली प्रगति पर भी है।

19- bVju'kuy ckMZ lsa lc) Ldwyksa dk ,d vè;;u

vUosf"kd % çks ç.kfr ikMk

भूमंडलीकरण और शिक्षा पर नव उदारवादी नीति के आगमन के साथ, स्कूल शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण में पिछले एक दशक के दौरान तेजी आई है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण महानगरीय पूंजी और भविष्य के लिए प्रासंगिक क्षमताओं के साथ प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में दुनिया भर में स्थानीय स्कूलों में एक अधिक सामान्य घटना बन गई है। जड़ विचार के रूप में दुनिया की नागरिकता, स्कूल शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मूल अवधारणा है। भारत में स्कूली शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक ऐसी ही घटना को देखा गया है। भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्कूल, ग्लोबल स्कूल, का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है .. वर्तमान में, भारत में क्रमशः आईबी और सीआईई द्वारा अधिकृत 106 और 320 स्कूल हैं. अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की विषम प्रकृति प्रवासी शिक्षकों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के साथ ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्कूल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कई अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के बगैर स्थापित छोटे स्कूलों की है।

देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इंटरनेशनल स्कूल का प्रमुख हिस्सा है। यह स्कूल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबद्ध दो विदेशी बोर्डों, जिनेवा में आरंभ हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर (आईबी), और माध्यमिक शिक्षा की ब्रिटेन स्थित इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट (आई.जी.सी.एस.ई.), से संबद्ध हैं। ये स्कूल भारत के महानगरों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों के अन्य शहरों में स्थापित हैं।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कमीशन इस अध्ययन, में देश में स्कूली शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की घटना की रूपरेखा करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- विदेशी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के नामकरण और प्रोफाईल का औचित्य;
- प्रवेश नीति, ऐसे स्कूलों में प्रवेश और शुल्क संरचना के लिए मांग की जांच करना;
- भारतीय स्कूलों की संबद्धता देने के लिए विदेशी बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रथाओं का पता लगाना;
- ऐसे स्कूलों को मान्यता देने के लिए राज्यों द्वारा विनियामक ढांचा, यदि कोई हो, तो उसकी जांच करना;
- विकासशील देशों में विदेशी बोर्डों के साथ संबद्धता की नीतियों और प्रथाओं की पहचान करना;

विदेशी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए और देश में विदेशी बोर्ड के संचालन के लिए एक नियामक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता और आवश्यकता को चित्रित करना;

- वर्तमान में, अध्ययन रिपोर्ट अंतिम संपादन चरण में है. प्रारंभिक निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:
- भारत में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के प्राधिकरण के मौजूदा दो अलग तरीके हैं– पहले से ही राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की तरह भारतीय बोर्ड से संबद्ध विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। और हाल ही में स्थापित स्कूलों ने अंतरराष्ट्रीय संबद्धता की मांग की है और राज्यों से भूमि अनुमोदन प्राप्त किया है।
- विकसित देशों के बीच अमरीका में आईबी (1528) और सीआईई (120) की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में विकासशील देशों के बीच आईबी और सीआईई के स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है।

भारत में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भारत से बाहर उच्च शिक्षा में आसान उपयोग और संक्रमण प्रदान विचारों के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष आगे बताते हैं कि:

- अतिशयोक्ति सुविधाओं के साथ एक कीमत पर भी बेहतर शैक्षिक मानकों हेतु इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों के शामिल होने के लिए उच्च और मध्यम वर्ग के माता–पिता के बीच भारी आकांक्षा है।
- ऐसे स्कूलों को व्यापार और लाभ के लिए एक विकास क्षेत्र के रूप में कॉर्पोरेट व्यावसायिक घरानों से लेकर स्कूल फ्रेंचाइजी के स्थानीय स्तर पर काम कर रहे उद्योगपति माना जाता है।

20- dkSu Ldwy tkrk g\ vuqHkotU; lk{; dk ,d fo'ys"k.k

vUos"kd % Mk- eekferk c/kikè;k;

यह अध्ययन क्रिएट के तहत सृजित मुख्य परियोजना का परिणाम है। अध्ययन, 31 मई, 2012 को अनुमोदित किया गया। परियोजना के कर्मचारियों को सितम्बर 2012 से (आंशिक रूप से) नियुक्त किया गया। माध्यमिक डेटा का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं:

- भारत में साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा : उभरते हुए मुद्दे और नीति मानदंड
- गुणवत्ता विद्यालय के माध्यम से बहिष्करण पर काबू पाना
- कमजोर वर्गों के बच्चों की भागीदारी:
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर विशेष फोकस
- लिंग और स्कूल भागीदारी

- अनुपस्थिति और बच्चों की पुनरावृत्ति
- शिक्षकों और शिक्षण के बारे में मुद्दे एवं सीखने की प्रक्रिया
- स्कूल प्रबंधन और भागीदारीः मुख्याध्यापक पहल और विचार
- बच्चों के प्रदर्शन और सीखने की उपलब्धि : संकट में बच्चों पर बल

21- Hkkjr esa 'kgjh efyu cfLr;ksa esa f'k{kk ds {ks= esa cPpksa dh Hkkxhnkjh dk egRoiw.kZ ewY;kadu

vUos"kd % M, lquhrk pqx

भारत में शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा में बच्चों की भागीदारी का एक समालोचित आकलन भारत के 10 चुनिंदा शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करता है। अध्ययन, विशेष रूप से, शिक्षा का अधिकार 2009 के कानून के संदर्भ में, चयनित स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रावधानों की जांच करने का प्रयास करता है। अध्ययन, आरटीई 2009 के कानून के जनादेश को पूरा करने में बाधाओं की पहचान करने का प्रयास करता है।

- पहुंच और गुणवत्ता प्रावधान पर ध्यान देते हुए, स्लम क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने का प्रयास;
- चुनिंदा स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पड़ोस में स्कूली शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता की हद की जांच करना;
- स्कूली शिक्षा में बच्चों की भागीदारी और प्रावधान में विविधीकरण का पता लगाना;
- विविध प्रावधान में बच्चों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना;
- शिक्षा के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की ओर माता–पिता के रवैये की जांच करना;
- बाहर के स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रावधान की जांच करना;
- नामांकन, अवधारण और प्रारंभिक शिक्षा चक्र के पूरा होने को सुनिश्चित करने में एसएमसी की भूमिका की जांच करना;

अध्ययन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, माध्यमिक स्रोतों जैसे एनएसएसओ से जनगणना डाटा एकत्र किया गया है और माध्यमिक स्रोतों पर आधारित चुनिंदा शहरों का संक्षिप्त वर्णन, तैयार किया गया है। प्रासंगिक अध्ययन की समीक्षा की जा रही है और काफी संख्या में समीक्षा की गई है। शहरी स्तर पर कुछ नोडल संस्थाओं और प्रमुख व्यक्तियों, से डेटा संग्रह में मदद ली गई है। डेटा संग्रह के लिए उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। शहर के सभी समन्वयकों के साथ एक सलाहकार रूपरेखा और डेटा संग्रह के लिए उपकरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

22- Ldwy çeq[kksa dh Hkwfedk vkSj ftEesnkfj;ka% jk"Vªh; ifjçs{;

tkapdrkZ% çks jf'e nhoku vkSj Mk- d';i h voLFkh

हर बच्चे को अधिगम सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रमुख की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हुये और हर स्कूल उत्कृष्ट हो वर्तमान अनुसंधान के लिए प्रेरित कारक है। भर्ती, प्रेरणा और स्कूल प्रमुखों के सतत व्यावसायिक विकास से संबंधित एक सूचित समझ के अभाव में, भूमिका और जिम्मेदारियों की एक वैज्ञानिक जांच निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रगति पर है:

- राज्य दस्तावेजों में व्यक्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों की निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अध्ययन करने के लिए अन्वेषण तथा अध्ययन।
- अलग राज्य दस्तावेजों और परिपत्रों के बीच, स्पष्टता, व्यापकता, विशिष्टता, अंतर–राज्य विविधताओं, विसंगति, के संदर्भ में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों की निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विश्लेषण करना।
- विभिन्न प्रबंधनों के तहत ग्रामीण / शहरी छोटे / बड़े, माध्यमिक / प्राथमिक स्कूलों की तरह अलग–अलग स्कूल संदर्भों में स्कूल प्रमुखों की भूमिका पर एक समझ विकसित करना।

पूर्व और बाद की आरटीई अवधि के संबंध में स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं की जांच करने के संदर्भ में संबंधित साहित्य, की समीक्षा का कार्य प्रगति पर है. साथ ही, भूमिकाओं और स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारियों से संबंधित दस्तावेज मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और बिहार से प्राप्त कर राज्य वेबसाइटों में सरकारी दस्तावेज को डाउनलोड किया गया है। शेष तीन राज्यों से राज्य दस्तावेजों और उपलब्ध डेटा के संग्रह का विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

23- mPp f'k{kk esa foÙk ik"k.k vkSj lkeF;Z ¼;wthlh foÙk ikf"kr½

vUos"kd% çks- lq/kka'kq Hkw"k.k

विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर जब उच्च शिक्षा में सामर्थ्य के मुद्दे की बात आती है तब नीति–निर्माण बहुत कठिन हो जाता है। एक हाथ पर, सार्वजनिक खर्च महत्वपूर्ण है और संसाधन जुटाने के तरीके और गरीबों को सब्सिडी लक्षित करने के लिए प्रयास जरूरी हैं। वहीं उच्च शिक्षा की निजी (घरेलू) वित्तपोषण का सवाल भी महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के घरेलू वित्त पोषण के निजीकरण की ओर रुझान बढ़ने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के निजीकरण ने फीस की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया और उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए घरों का बोझ बढ़ गया। यह सामर्थ्य के मुद्दे को उठाती है। सामर्थ्य का विषयों की पहुँच और चुनाव पर प्रभाव डालती है। सामर्थ्य के कारण विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों में अलग–अलग रुझान दिखाई दे सकते हैं। यह ग्रामीण और शहरी संदर्भों के बीच और विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों में अलग–अलग हो सकता है। उपरोक्त के प्रकाश में, अनुसंधान परियोजना का केंद्रीय उद्देश्य निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में सामर्थ्य की क्षमता का अध्ययन करना है।

24- Hkkjrh; mPp f'k{kk lLFkkuksa esa Lok;Ùkrk

vUos"kd% Mk- uhyw Lugh

उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता का मुद्दा भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। स्वायत्तता इंगित करता है कि यह समस्याओं के लिए एक रामबाण है। परियोजना का उद्देश्य किस हद तक स्वायत्तता सामान्य रूप में, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में और स्नातक कॉलेजों में विशेष रूप से: कितनी स्वायत्तताय कॉलेजों के लिए होनी चाहिए और किस वर्ग को स्वायत्तता देनी चहिए– प्रबंधन, शिक्षक, छात्र और स्वायत्तता, राज्य, विश्वविद्यालय यूजीसी–सेंटर किससे प्राप्त हो?

मन में इन लक्ष्यों के साथ, अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज में स्वायत्तता की भूमिका को समझना है, और विशेष रूप से, स्नातक संस्थानों; स्नातक संस्थानों को स्वायत्तता देने में हितधारकों की भूमिका की जांच करना है; स्वायत्त संबद्ध कॉलेजों की तुलना संबद्ध कॉलेजों के कामकाज की तुलना के संबंध में विश्लेषण; और स्वायत्त और गैर स्वायत्त संबद्ध कॉलेजों के कामकाज में अनुभवों का दस्तावेज़ीकरण करना है।

परियोजना इस उद्देश्य पर आधारित है: उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न संस्थाओं के कामकाज, स्वायत्तता की अवधारणा को समझने के लिए मौजूदा स्वायत्तता का प्रभाव स्वायत्तता देने में हितधारकों की भूमिका, सामग्री विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन का एक मिश्रित बैग तैयार किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालयों के लिए विधियों, अध्यादेश और राज्यों की विधियों के साथ विश्वविद्यालयों के कालेजों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्रणाली में स्वायत्तता की अवधारणा के विकास का विश्लेषण किया जा रहा है। माध्यमिक डेटा की समीक्षा इन संबंध में चल रही है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं से विभिन्न पुस्तकों और शोध लेख की सामग्री का विश्लेषण भी शामिल है। इसके अलावा, प्रश्नावली का पहला सेट तैयार है और अनुसंधान उपकरण संचालित होने की प्रक्रिया में है। क्षेत्र कार्य चल रहा है, जो परियोजना की एक जरूरत है।

25- MhvkbZ,lbZ vkadMk+sa dk ç;ksx djrs gq, çkjfEHkd f'k{kk lacèkh vuqlèkku dk;ZØe

vuqlèkku leUo;d% çks- v:.k lh- egrk

ईएमआईएस विभाग ने 'डीआईएसई आंकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक शिक्षा संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम' प्रारम्भ किया है। यह अनुसंधान कार्यक्रम विशेष रूप से डीआईएसई आंकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक शिक्षा

संबंधी छोटे अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों, आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों, इत्यादि में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करवाने का अवसर उपलब्ध करवाता है। लगभग 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक आंतरिक समिति ने इन प्रस्तावों की समीक्षा की है और 10 प्रस्तावों को चुना है। न्यूपा ने एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और सुझावों के आधार पर सभी अनुसंधानकर्ताओं ने अपने–अपने प्रसतावों को संशोधित किया। इस अनुसंधान कार्यक्रम का वित्त पोषण न्यूपा द्वारा किया गया है। पहली किस्त जारी की जा रही है।

26- Ldy f'k{kk lcèkh Hk&LFkkfud lpuk ç.kkyh fodflr dju lcèkh ç;kfxd ifj;ktuk

vUos"kd % Jh ,xyk ,u- jìh

स्कूल शिक्षा संबंधी भू–स्थानिक सूचना प्रणाली विकसित करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य स्कूलों के भू–स्थानिक आंकड़ों को एकत्र करने और उन्हें शैक्षिक आयोजना और मानीटरिंग में उपयोग में लाने के लिए स्कूल शिक्षा संबंधी भू–स्थानिक सूचना प्रणालियों को विकसित करने में विभिन्न राज्य सरकारों के अनुभवों की समीक्षा करना है। दूसरा उद्देश्य किसी ब्लाक में स्कूल शिक्षा के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणाली का माडल विकसित करना और स्थानीय स्तर पर शैक्षिक आयोजना में भू–स्थानिक आंकड़ों संबंधी पद्धति और अनुप्रयोग का प्रदर्शन करना है। राज्य के अनुभवों की समीक्षा जीआईएस वेबसाइटों पर जाकर और वेबसाइटों की विषय–वस्तु तथा वेबसाइट पर ऐसे विभिन्न साधनों की उपलब्धता की जांच करके की जा रही है जिन्हें कि स्कूल अवस्थिति और मानीटरिंग के आयोजन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात स्कूल शिक्षा के लिए विकसित जीआईएस और उन्हें आयोजन और निगरानी में प्रयोग करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धतियों पर गहन विचार–विमर्श के लिए राज्यों के दौरे किए जाएंगे। एक आदर्श भू–स्थानिक सूचना प्रणाली विकसित किए जाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में एकत्र किए गए स्कूलों के भू–स्थानिक आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं। इन आंकड़ों की सहायता से आदर्श जीआईएस विकसित किए जाने और इसे प्रायोगिक तौर पर कार्यान्वित किए जाने की योजना है।

27- vu lfpr tutkfr d cPpk d chp f'k{kk% jktLFkku d nk xkok dk l?ku vè;;u

vUos"kd % çk- ch-d- ikMk

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संवैधानिक लोकतंत्र की संरचना ने अवसरों का सृजन किया है जिससे कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ऊपर उठाया जा सके क्योंकि स्वतंत्र भारत में अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को विकास की आयोजना का मार्गदर्शी सिद्धांत माना गया। संवैधानिक सुरक्षा और बेहतर शैक्षिक और आर्थिक सुविधाओं के साथ यह आशा की जाती है कि यह सामाजिक सक्रियता के उन्नयन में यह एक प्रेरणात्मक कारक बनेगा जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य गैर–अनुसूचित जनसंख्या के समान स्तर पर आ सकेंगे। अतः प्रश्न उठता है कि स्कूलों में इन समुदायों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में किस सीमा तक सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, यदि स्कूल इन समुदायों के बच्चों को आकर्षित करने की स्थिति में नहीं है तो समुदाय के बच्चों की राह में बाधक बनने वाले कारकों को गहन रूप से समझने की आवश्यकता है। ऐसे अनुमानों के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों को अध्ययन किए जाने के लिए अभिज्ञात किया गया हैः

- राजस्थाान राज्यों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के बीच शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों को समझना;
- शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जाति के परिवारों और समुदायों तथा उनकी प्राथमिकता महत्वांकांक्षा को विस्तृत रूप से समझना;
- अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक बाधाओं की पहचान करना; और
- राज्य की नीतियों में किए गए ऐसे प्रावधानों को समझना जोकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं।

अभी तक, साधनों की समीक्षा और विकास संबंधी मूल कार्य किया गया है और साधनों के परीक्षण और मूल आंकड़ों के एकत्र का कार्य बहुत शीघ्र प्रारंभ किया जाना है।

28- fnYyh esa çh&Ldwy f'k{kk miyCèk djokus okyh futh Ýpkbft;ksa dk vè;;u

vUos"kd % Mk- lfork dkS'ky

इस अध्ययन का उद्देश्य चुनिंदा निजी प्री–स्कूल फ्रैंचाइजियों की शैक्षिक और प्रशासनिक संरचना तथा अभिशासन का विश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त चुनिंदा निजी प्री–स्कूल फ्रैंचाइजियों में प्रवेश प्रक्रिया और उपलब्ध करवाई जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं की भी जांच की जाएगी। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पृष्ठनभूमि का अध्ययन किया जाएगा। इसमें सैंपल स्कूलों में अध्यापकों द्वारा अपनाई गई पाठ्यक्रम कार्यान्वयन तकनीकों का भी अन्वेषण किया जाएगा और निजी प्री–स्कूल फ्रैंचाइजी की कार्यप्रणाली के संबंध में उपलब्धियों अथवा कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाया जाएगा। संबंधित साहित्य की समीक्षा के आधार पर आंकड़े एकत्र करने संबंधी साधन तैयार किए गए हैं। विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच की गई है। इन साधनों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया गया है और अंतिम रूप दिया गया है। प्री–स्कूलों से आंकड़े एकत्र करने कार्य चल रहा है।

29- çkjfHkd vkSj ekè;fed Ldwy f'k{kdksa dh dk;Z fLFkfr;ksa ij jk"Vªh; vè;;u

vUos"kd% Mk- foeyk jkepUnu

10 जनवरी, 2014 को क्षमता व आवश्यकता आकलन बैठक सहित नौ राज्यों का एक अध्ययन प्रारंभ किया गया जिसमें कि संभावित भागीदारों को यह प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया था कि वे यह अध्ययन कैसे करेंगे। इस बैठक में पीएसी सदस्यों तथा परियोजना की कोर टीम ने भाग लिया। परियोजना के भागीदारों का चयन करने के पश्चात न्यूपा में 17–18 फरवरी, 2014 को सभी अनुसंधान भागीदारों के लिए एक अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अध्ययन के लिए झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों का चयन किया गया।

31 मार्च, 2014 तक परियोजना के अधिकांश भागीदारों को निधि जारी कर दी गईं। इसके पश्चात परियोजना टीम ने अनुसंधान डिजाइन पर काम किया और एक परियोजना कोर टीम (परियोजना से संबंधित शैक्षिक और प्रबंधकीय दोनों ही मुद्दों पर मार्गदर्शन और सहायता के लिए) तथा एक परियोजना अनुमोदन समिति (बजट, अनुसंधान सहभागियों और प्रशासनिक तौर तरीकों को अनुमोदित करने के लिए) का भी गठन किया। ये दोनों ही समितियां सक्रिय हैं और इन्होंने यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि प्रस्तावित अनुसंधान अध्ययन सर्वोच्च शैक्षिक मानकों का पालन करता है। आठ राज्यों में भागीदारों की पहचान कर ली गई है और न्यूपा ने एक राज्य अर्थात पंजाब में सीधे तौर पर अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

अधिकांश राज्यों में आंकड़ा एकत्रण (अध्यापक प्रबंधन, मुख्य सूचक साक्षात्कारों और संकेंद्रित सामूहिक चर्चाओं से संबंधित सरकारी आदेशों/अधिसूचनाओं का एकत्रण और अवलोकन) का कार्य पूरा हो चूका है। न्यूपा की अनुसंधान टीम ने आंकड़ा एकत्रण की मानीटरिंग करने और अध्ययन के लिए विकसित किए गए प्रारूपों में आंकड़ा प्रविष्टि के संबंध में राज्य अनुसंधान टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिकांश राज्यों का दौरा किया।

4

सहचर्या
और सहभागिता

सहचर्या और सहभागिता

सहभागिता प्रणाली

dsanz vkSj jkT; ljdkjksa dks 0;kolkf;d@rduhdh vuqleFkZu vkSj ijke'kZdkjh lsok,a

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013–14 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की सरकारों को तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों/शिक्षा विभागों और केंद्र तथा राज्य स्तर के संस्थानों को व्यावसायिक/तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया ताकि वे अपने विशिष्ट क्षमता विकास की जरूरतों को पूरा कर सकें और शैक्षिक नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण में सुधार हेतु उन्हें मदद मिल सके। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में व्यावसायिक/तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग की अनेक समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किए। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में प्रगति आकलन हेतु राज्य/संघीय सरकारों को व्यावसायिक

सहयोग प्रदान किए गए। राज्यों/संघीय सरकारों तथा केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियों/संस्थानों को तकनीकी/व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान करने के साथ–साथ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे– यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों को भी परामर्शकारी और व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान किया।

vrjk"Vh; fudk;k d lkFk lnL;rk vkj le>kr

- न्यूपा हिरोशिमा शैक्षिक विकास नेटवर्क के लिये अफ्रीका एशिया विश्वविद्यालय वार्ता का एक संस्थापनक सदस्य है और जुलाई 2013 में नेटवर्क की अनुसंधान बैठक में हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान द्वारा आयोजित दूसरी महासभा में भाग लिया।
- न्यूपा ने अनुसंधान, शिक्षण और विनिमय के क्षेत्रों में शैक्षिक सहयोग के लिए शिक्षा में अंतराष्ट्रीय सहयोग के लिए केन्द्र, हिरोशिमा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- न्यूपा यूनेस्को, बैंकाक की शिक्षा अनुसंधान पहल नेटवर्क (इरी–नेट) का सदस्य है। प्रो. जे.बी.जी. तिलक, को नेटवर्क का संचालन समूह के लिये चुना गया। न्यूपा ने अक्टूबर में नेटवर्क द्वारा आयोजित विशेषज्ञ बैठकों और अनुसंधान सेमिनार में भाग लिया, बैंकाक 2013

ई.एम.आई.एस. विभाग के संकाय सदस्यों द्वारा जुलाई, 2013 में आयोजित कार्यशाला में एकीकृत डीआईएसई के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान किया गया।

6 और 13 सितम्बर पर एडुसैट के माध्यम से यूडीआईएसई डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर अभिविन्यास कार्यक्रम के अलावा विश्वविद्यालय ने सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की संयुक्त समीक्षा मिशन के समकक्ष, वर्ष के दौरान दो बार यू.डी.ओई.एस.ई. आंकड़ा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया और एक बार सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त समीक्षा मिशन के समकक्ष डाईस आंकड़ा विश्लेषण प्रस्तुत किया।

5

न्यूपा में नई पहल

KINLEY

न्यूपा में नई पहल

अध्यापक विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु पीठ

अध्यापक विकास और प्रबंधन पर राजीव गांधी फाउण्डेशन जून 2013 से प्रारम्भ किया गया। यह न्यूपा के अध्यापक विकास और प्रबंधन पर अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त भारत में अध्यापक विकास और प्रबंधन की प्रभाविकता में सुधार हेतु नीतियों और व्यवहार संबंधित मुद्दों पर भी यह फाउण्डेशन बल देता है।

विद्यालय की क्षमता बढ़ाने/संस्थागत नेतृत्व एवं व्यावसायीकरण हेतु; प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अध्यापकों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिये तथा शिक्षा की मांग को पूरा करने हेतु अध्यापकों का प्रावधान, आवंटन और उपयोग परस्पर रूप से संबंधित हैं। हालांकि ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक विकास तथा प्रबन्धन के विविध पक्षों को संबोधन करने हेतु एक सुसंगत नीति और कार्यक्रम संबंधी ढांचे की कमी है। प्रो. विमला रामचन्द्रन राजीव गांधी फाउण्डेशन पीठ की प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

ihB dh fo'k"k xfrfof/k;k e lfEefyr g%

- विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शिक्षकों तथा संबंधित शैक्षिक प्रबंधन के मुद्दों पर स्वतंत्र और सहयोगात्मक अनुसंधान। यह आशा की जाती है कि इससे नीतियों की एक की एक सुसंगत रूपरेखा तैयार करने हेतु और सूचित निर्णय प्रक्रिया के लिये आवश्यक ज्ञान के आधार को समृद्धि प्राप्त होगी।
- अध्यापक विकास और प्रबन्धन व्यवहार में सुधार हेतु राज्य मंत्रियों तथा अन्य राज्यों / संघ क्षेत्र स्तर संस्थानों को तकनीकी समर्थन।
- अनुमोदित कार्यक्रम संबंधी उपायों में हितधारक तथा राज्य स्तरीय शैक्षिक प्राधिकरण को सम्मिलित करते

हुये अध्यापक विकास तथा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत चर्चा को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना।

- अनुसंधान निष्कर्षों समेत, ज्ञान और सूचना का प्रसार तथा दस्तावेजीकरण, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचित निर्णय प्रक्रिया की सुविधा हेतु हितधारकों के बीच सर्वोत्तम व्यवहार तथा नवाचार।
- प्रभावी शिक्षक विकास और प्रबंधन के तरीकों को अपनाने पर बल देना।

nks ifj;kstuk,¡ py jgh gSA

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों की सभी श्रेणियों की भर्ती और तैनाती की नीतियों और व्यवहार, वेतन और काम की परिस्थितियां (स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पेशेवर विकास और विकास) (नियमित और संविदा शिक्षकों) का विश्लेषण और दस्तावेजीकरण हेतु 9 राज्यों में अनुसंधान अध्ययन जारी हैः यह शिक्षक प्रबंधन में शामिल मुख्य प्रशासकों के साथ सरकारी सूचनाएँ, आदेश और साक्षात्कार के अवलोकन से जुड़े राज्य स्तर के क्षेत्र आधारित अध्ययन के माध्यम से किया जा रहा है

अनुसंधान समर्थन – पी.एम.यू. के माध्यम से

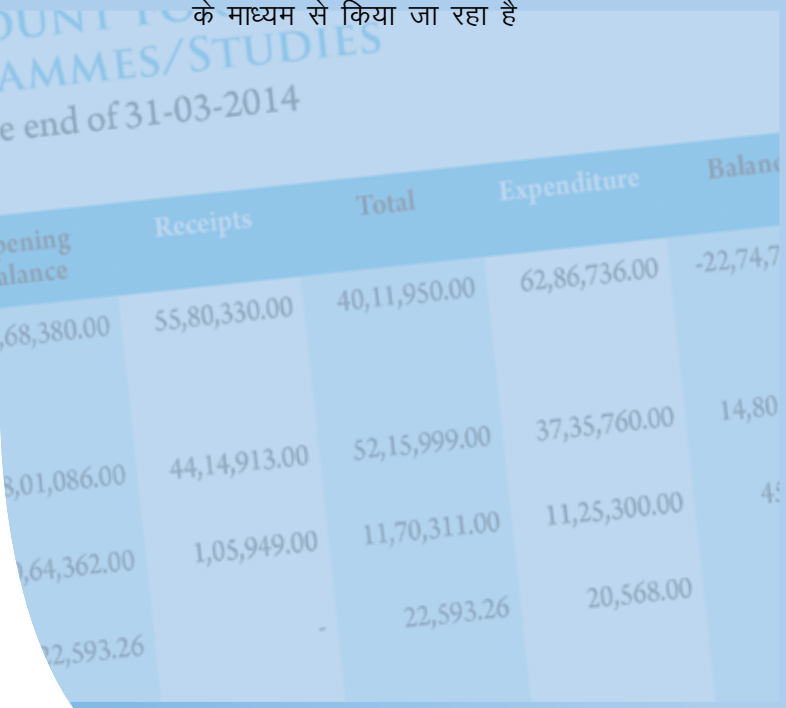

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) समर्थन और प्रायोजित अनुसंधान के प्रबंधन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

यह एकक शिक्षा नीति और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (व्यक्ति शोध) के क्षेत्र में अध्ययन के लिए न्यूपा सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत अध्ययन सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिये अनुदान सहायता योजना, विभाग के सभी बाह्य वित्त–पोषित और आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं के उचित समन्वय के लिये प्रशासन की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

यूनिट सामान्य रूप से, परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और संबंधित समर्थन सेवाएँ प्रदान करने सहित न्यूपा में किए गए विभिन्न परियोजनाओं के प्रबंधन के लिये प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, यह सभी मामलों में धन और घरेलू व्यय के लेखा सहित न्यूपा – परियोजना भर्ती और नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

पीएमयू विभिन्न परियोजनाओं के लेखांकन, परियोजना स्टाफ की भर्ती, बजट के अलावा विश्वविद्यालय में चल रहे पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्यों का देखभाल करता है।

पीएमयू एकक में अध्यक्ष, कुलपति द्वारा चयनित किया जाता है। इसके अलावा पांच अन्य अकादमिक तथा समर्थन स्टाफ भी चयनित किये जाते हैं। समर्थन स्टाफ में परियोजना परामर्शदाता, परियोजना प्रबंधक तथा कनिष्ठ परामर्शदाता सम्मिलित है। एकक के अध्यक्ष प्रो. के. बिस्वाल हैं।

स्कूल मानक तथा मूल्यांकन एककक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) में स्कूल मानक और मूल्यांकन पर एक इकाई का गठन किया है, स्कूल में सुधार को स्वीकारते हुए स्कूल के मानकों और मूल्यांकन बनाने के लिये प्रमुख उद्देश्य स्थापित करने और मानकों और प्रक्रियाओं का एक सहमत ढांचा सभी स्कूलों को प्राप्त करने के लिये प्रयास करना चाहिए। यह जवाबदेही के साथ स्कूल में सुधार की दिशा में आत्म और बाह्य मूल्यांकन के लिये प्रत्येक स्कूल के लिये स्पष्ट रास्ते प्रदान करेगा। स्कूल मानकों और मूल्यांकन के आधार पर स्कूल सुधार के लिये तथ्य आधारित प्रणाली, प्रयास के एक नए क्षेत्र के रूप में, एक प्रगतिशील रास्ते पर स्कूल के विकास के लिये होगी।

राज्यों और विशेषज्ञ के साथ आपसी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इकाई द्वारा निम्नांकित कार्य को संबोधित किया जाएगाः

- विविधता और बदलते संदर्भों और स्थितियों के संदर्भ में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिये स्कूल के मानकों के सहमत ढांचे पर स्कूल मानक और मूल्यांकन (NFSSE) पर राष्ट्रीय ढांचे का विकास;
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन के लिये पुस्तिका का विकास;
- एक आपसी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से राज्य विशेष स्कूल मानकों और मूल्यांकन को संस्थागत करना;
- नियमित रूप से और स्वतंत्र स्कूल मूल्यांकन और स्कूल सुधार के लिए प्रतिक्रिया के लिए प्रत्येक राज्य में संस्थागत तंत्र की रूपरेखा;
- मूल्यांकनकर्त्ताओं का प्रोफाइल बनाना और राज्य स्तर पर क्षमता विकास के लिये अवसर प्रदान करना;
- आवधिक समीक्षा करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच बनाने और सभी संबंधित पक्षों के बीच अनुभवों को साझा करना।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में, एक राष्ट्रीय तकनीकी समूह गठित किया गया है और स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की विकास हेतु प्रक्रिया की पहल की जा रही है।

6

पुस्तकालय

और प्रलेखन सेवाएं

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

ज्ञान और सूचना की साझेदारी

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षिक नीतियों, योजना और प्रबंधन से संबंधित मौजूदा और नवीनतम ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्य आरंभ किए हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान और सूचना प्रलेखन और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र द्वारा वर्ष 2013–14 में की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

विश्वविद्यालय का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र विश्वविद्यालय के संकाय और स्टाफ सदस्यों, देश–विदेश के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालय के एम.फिल. तथा पी.एच.डी. के विद्यार्थियों, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अतिथि संकाय सदस्यों तथा पाठकों की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता रहा है। पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अधिगम और शोध में सहयोग के लिए आधुनिक अध्यापन– अधिगम सामग्री, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रानिक सुविधाएं जैसे– वाई–फाई से सुसज्जित है। समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत पुस्तकालय ने अपनी संग्रह नीति में व्यापक परिवर्तन किया है। पुस्तकालय लगभग 80 प्रतिशत जर्नल मुद्रित और ऑनलाईन स्वरूप में मंगाता है। हालांकि, पुस्तकों को मुद्रित रूप में ही प्राथमिकता दी जाती है।

समीक्षित काल में पुस्तकालय में 882 नए पुस्तकों/दस्तावेजों का संग्रह किया गया। वर्तमान वर्ष में पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास संयुक्त राष्ट्र, युनेस्को, ओ.ई.सी.डी, आई.एल.ओ., यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों इत्यादि के अलावा 57,210 पुस्तकों और दस्तावेजों का संग्रह है। समीक्षाधीन वर्ष में पुस्तकालय ने शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंधन तथा इससे संबंधित विषयों पर 250 राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय जर्नल एवम् पत्रिकाएं मंगाईं। इन पत्र–पत्रिकाओं से 1061 प्रमुख आलेखों का सूचीकरण किया गया। पाठकों की सुविधा हेतु संग्रह को चार खण्डों में विभाजित किया गया है–सामान्य, संदर्भ, श्रृंखला और क्षेत्र अध्ययन संग्रह।

हर पखवाड़े में आने वाली शैक्षिक पत्रिकाओं के लेखों के बारे में पाठकों को जानकारी देते रहने के लिये पुस्तकालय ने अपना पाक्षिक अनुलेखित प्रकाशन – पीरियाडिकल्स आन एजुकेशन : टाइटिल्स रिसीव्ड एंड दियर कंटेंट का प्रकाशन जारी रखा। पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में आनेवाले प्रकाशनों की कंप्यूटर से मासिक सूचियां भी तैयार की जाती हैं ताकि इससे पाठकों को उनकी रुचि के दस्तावेजों, लेखों और नई सामग्रियों की जानकारी मिलती रहे। समीक्षाधीन वर्ष में पुस्तकालय ने 6,991 जर्नलों को उपयोगकर्त्ताओं को सूचना प्रदान करने के लिए जिल्द में तैयार किए। न्यूपा ने चार आनलाईन डाटाबेस एलसेवियर सेज, एमेराल्ड, डाटाबेस तथा जे. स्टोर खरीदे। न्यूपा पुस्तकालय पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। पुस्तकालय के पास 523 ई–बुक का संग्रह है।

न्यूपा पुस्तकालय ने वर्ष 2013–14 के दौरान नई आनलाईन सूचना सेवाएँ जैसे कि– ''न्यूज फ्लैश'', 'न्यूपा इन द प्रेस', एस.डी.आई. (न्यूपा संकाय के अकादमिक कार्य का प्रसार) तथा 'न्यू अराईवल'

प्रारम्भ किया है। पुस्तकालय विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की ग्रन्थ सूची तैयार की है। उपभोक्ताओं को संदर्भ सामग्री, आलेखों, रिपोर्टों इत्यादि के लिये फोटोग्राफी सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

न्यूपा पुस्तकालय में सभी गतिविधियाँ, जैसे कि सूची बनाना, प्राप्तियाँ, प्रसार तथा श्रेणी नियंत्रण पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत है। इसके लिये लिबसिस 7 साफ्टवेयर पैकेज का नवीनतम वर्ज़न का प्रयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु न्यूपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र डेलनेट का सदस्य हैं इससे न्यूपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र में उपलब्ध शैक्षिक योजना और प्रशासन पर वृहद रूप से उपलब्ध अमूल्य अधिकारिक दस्तावेज़ों के पहचान की सुविधा उपलब्ध हुई है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुये सभी दस्तावेज़ों तथा रिकार्ड का डिजीटलीकरण हेतु परियोजना चलाई जा रही है। यह अपेक्षा की जा रही है कि इससे देश में शिक्षा पर वृहद ऑनलाईन अभिलेखीय सूचना उपलब्ध हो पायेगी।

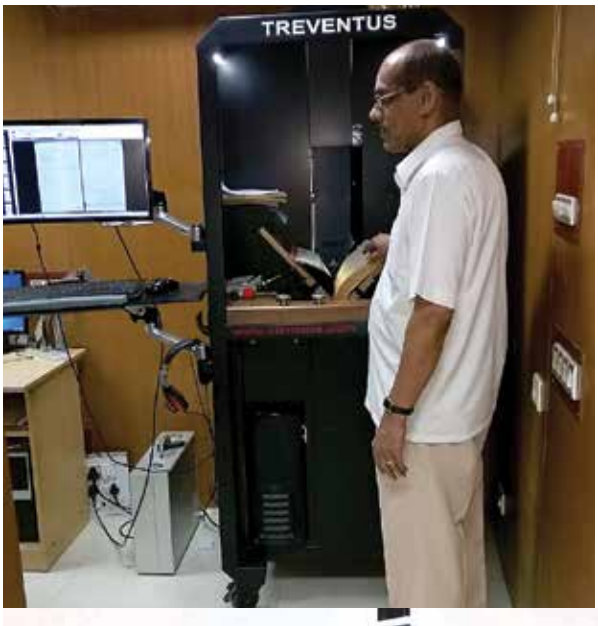

प्रलेखन केंद्र

न्यूपा पुस्तकालय में शैक्षिक योजना और प्रबंधन प्रशासन पर 19,000 से अधिक का वृहद और महत्वपूर्ण संग्रह है। पुस्तकालय में विदेशी और भारतीय सहित 250 मुद्रित जर्नलों के साथ सेज़ शिक्षा संग्रह एलसेवियर तथा जे.स्टोर ऑनलाईन डाटाबेस उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रकाशनों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन भी सम्मिलित हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रकाशनों में राज्य तथा जिला जनगणना रिपोर्ट, राज्य तथा जिला गज़ट, केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम तथा विधान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान, राज्यों के लिये सांख्यिकी पुस्तिकाऐं, अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण आयोग तथा समिति की रिपोर्ट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य शैक्षिक योजनाएं, राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्टें, तथा पंचवर्षीय योजनाएं सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य अध्ययन जैसे अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्टें (1962–2013), प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्टें, विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्टें, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस की रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। प्रलेखन केन्द्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पर शोध अध्ययनों का एक समृद्ध संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय

शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, पेरिस के प्रकाशनों का संग्रह–केन्द्र है। इसके पास अ–पुस्तक पाठ्य सामग्री जैसे इंडैक्सिंग डाटाबेस, भारत की जनगणना, राज्य मानव संसाधन विकास केन्द्र और शिक्षा तथा इसे जुड़े संबंधित क्षेत्रों पर अन्य प्रकाशनों पर संग्रह है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रलेखन केन्द्र ने अपने उपलब्ध दस्तावेज़ों में 283 दस्तावेज़ों का संग्रह किया।

प्रलेखन केन्द्र लिबसेस सॉफ्टवेयर 7.0 (आर.ई.एल. 1.0) के प्रयोग द्वारा पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग और इलैक्ट्रानिक डाटाबेस की पहुंच, विभिन्न सूचना संसाधनों तथा सेवाओं के साथ, उपयोगकर्त्ता को उसके डेस्कटॉप तक पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त, इसका समृद्ध संग्रह, विस्तृत सरणी और विविध सेवाएं तथा सुविधाएं देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से भी उपयोगकर्ताओं को इसके संसाधन और सेवाओं का प्रयोग करने के लिये आकर्षित करता है। प्रलेखन केन्द्र में अध्ययन के लिये आरामदायक, शांतियुक्त तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण है और यह सुसज्जित प्रकाश, वातानुकूलन और जनरेटर बैक–अप सुविधायुक्त है। प्रलेखन केन्द्र की पठन सुविधाओं का प्रयोग संकाय, विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं, डेपा एवं आईडेपा के भागीदार तथा आगन्तुक संकाय द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। प्रलेखन केन्द्र पूरे वर्ष सोमवार से शनिवार तक खुला रहता है।

डिज़ीटल संसाधनों की पहुंच

इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय संकाय तथा अनुसंधानविद्ों के बीच विभिन्न प्रकार की सूचना की साझेदारी, संपर्कता, सहभाजन के लिए इंटरनेट गतिविधियों को सुदृढ़ तथा विकसित किया गया है। यह सूचना तथा ज्ञान का संग्रह, सृजन, हस्तांतरण तथा एकीकरण करता है। इसके डिज़ीटल संसाधन जैसे पुस्तकें, आलेख, अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, सम्मेलन संगोष्ठी के कार्यकलाप, विख्यात शिक्षाविद् व्याख्यान श्रृंखला, दृश्य–श्रव्य व्याख्यान, समिति तथा समिति रिपोर्टें, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यह सभी संसाधन पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र के वेब पृष्ठ [http://www.nuepa.org/libdoc/index.html, पर भी उपलब्ध हैं। प्रलेखन केन्द्र शिक्षा तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के 5,000 दस्तावेज़ों के डिजीटल अभिलेख उपलब्ध कराता है। यह दस्तावेज़ इंटरनेट या इंटरानेट के माध्यम से [http://www.nuepa.org.archives/index.html, पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त नई प्राप्तियों की सूची, नए जर्नलों तथा बंद किऐ जाने वाले जर्नलों की सूची, पाक्षिकों के वर्तमान घटक; जे. स्टोर तथा ऑनलाईन जर्नल डाटाबेस का सम्पूर्ण टेक्स्ट एक्सेस; संदर्भ ग्रंथ सूची – मांग पर प्रेस कतरनें, साहित्य की खोज तथा इलैक्ट्रानिक दस्तावेज़ वितरण प्रणाली (ई.डी.डी.एस.) के लिये इंटरनेट के माध्यम से चौबीस घंटे की पहुंच पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र को विस्तारित की गई हैं। इससे अंतः पुस्तकालय ऋण तथा डेलनेट के माध्यम से पुस्तकों, दस्तावेज़ों, आलेखों, इत्यादि के लिये प्रयोगकर्त्ता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सुदृढ़ीकरण हुआ है।

7

कंप्यूटर

और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर केंद्र विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैम्पस नेटवर्क आधार तथा इसके सक्रिय संघटकों को कंप्यूटर केंद्र द्वारा संचालित, रखरखाव तथा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर केंद्र एन.एम. ई.आई.सी.टी परियोजना के अंतर्गत एन.आई.सी/एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की गई 1 जी.बी.पी.एस ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट संपर्कतता से सुसज्जित है। कंप्यूटर केंद्र सभी स्टाफ सदस्यों, प्रशिक्षुओं, परियोजना स्टाफ, कार्यक्रम भागीदारों, अनुसंधानविदों को कंप्यूटर सुविधा तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेटवर्क संसाधानों का प्रयोग करने हेतु सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय सदास्यों को उच्च गति वाली इंटरनेट संपर्कतता तथा नेटवर्क प्वाइंट प्रदान किये गये हैं। न्यूपा डोमेन पर सभी स्टाफ तथा संकाय सदस्यों को व्यक्तिगत ई–मेल खाता की सुविधा दी गई है। कुलपति तथा अन्य सभी संकाय सदस्यों के निवास पर ब्राड–बैन्ड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय को डैस्कटाप कंप्यूटर सुविधा दी गई है। कंप्यूटर केंद्र की सुविधाएं बिना किसी व्यावधान के लगातार 12 घंटे उपलब्ध रहती हैं। कंप्यूटर केन्द्र पर विश्वविद्यालय के अपने कंप्यूटरों तथा संबंधित उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी है जिसे वारंटी या वार्षिक रखरखाव संविदा के तहत किया जाता है।

कंप्यूटर केन्द्र विश्वविद्यालय की दैनिक अकादमिक तथा गैर अकादमिक गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रकार के नवीनतम कंप्यूटर और प्रिंटरों तथा मल्टी–फंक्शन डिवाईज़ेज से सुसज्जित

है। विश्वविद्यालय के सभी तलों पर सभी कमरे लोकल एरिया नेटवर्क (विंडोज़ 2008 आपरेटिंग सिस्टम सहित) से जुड़े हुए हैं।

न्यूपा भवन से न्यूपा हास्टल को उच्च गति इंटरनेट संपर्कतता उपलब्ध कराई गई है। न्यूपा छात्रावास के सभी तलों पर अतिथियों के लिये प्रमाणित तथा सुरक्षित वाई–फाई संपकर्तता उपलब्ध–कराई गई है।

यह केंद्र अकादमिक एककों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण और प्रणाली स्तर के प्रबंधन संबंधी मुद्दे तथा दूसरे कार्यकलापों में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गैर–अकादमिक एककों जैसे – पुस्तकालय, प्रशासन तथा वित्त विभागों को भी सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान की डाटा प्रोसेसिंग तथा वर्ड प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों/ कार्यक्रमों के लिए अन्य विशिष्ट कंप्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करता है।

लेखा अनुभाग को भी कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए समर्थन दिया जाता है। इसमें शामिल है, वेतन पर्ची, आयकर गणना, पेंशन, भविष्य निधि गणना आदि। इसके लिए एस पी एस एस सांख्यिकी पैकेज नेटवर्क वर्जन सर्वर के साथ स्थापित किया गया है ताकि प्रयोगकर्त्ता नेटवर्क पर गणना कर सकें। कंप्यूटर केंद्र दैनिक गतिविधियों के लिये ओपन स्रोत साफ्टवेयरों को प्रोत्साहन देता है।

विश्वविद्यालय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधुनिक डाटा केन्द्र स्थापित किया गया है। डाटा केन्द्र उच्च गुणवत्तायुक्त डाटा सर्वर तथा वेब सर्वर से जुड़ा है जोकि चौबीसों घंटे उपभोक्ताओं के लिये ऑन–लाईन उपलब्ध है। डाटा सेंटर समर्पित समानांतर यू.पी.एस. सिस्टम से समर्थ है जो सर्वर को पावर बैक–अप प्रदान करता हैं। घरेलू डाटा सेंटर को सुदृढ़ बनाने हेतु एस.ए. एन. स्टोरेज़ के साथ ब्लेड सर्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इंटरनेट संलग्नता में वृद्धि तथा समर्थतता हेतु एवं डाटा केन्द्र का इंटरनेट लिंक हेतु बैक–अप कनेक्टिविटी के लिये 10 एम.बी.पी.एस. रेडियो फ्रीक्वेन्सी लिंग (आर.एफ. लिंक) का भी प्रस्ताव है और इसके स्थापना तथा चलाने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।

भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जाने–माने कार्यक्रम डाईस के लिये सर्वर की प्राप्ति हेतु संगणक केन्द्र ने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

कंप्यूटर केन्द्र ने वेब आधारित साफ्टवेयर 'ऑनलाईन रिक्यूरमेन्ट सिस्टम' की रूपरेखा तैयार कर विकसित की और उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया है, कि इसे भविष्य में सभी नियुक्तियों के लिये प्रयोग किया जायेगा।

कंप्यूटर केन्द्र सक्रिय रूप से एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन में संल्पित हैं। डाईस तथा सेमिस के शिक्षा के लिये एकल एकीकृत सूचना प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु कंप्यूटर केन्द्र के सहयोग से कार्य किए जा रहे है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बोर्ड कक्ष में टेलीकान्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना से उपभोक्ताओं को (ऑडियो के माध्यम से) किसी भी समय चार उपभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिलेगीं

महत्वपूर्ण रूप से शैक्षिक योजनाकारों के लिये न्यूपा वेब पोर्टल की संकल्पना की प्रगति एन.आई.सी. द्वारा शैक्षिक योजनाकारों के लिये विकसित वेबपोर्टल के साथ की जा रही है।

8

प्रकाशन

कार्यक्रम

JOURNAL OF EDUCATIONAL
PLANNING AND ADMINISTRATION
(Subscriptions details available)

प्रकाशन कार्यक्रम

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रकाशन एकक विश्वविद्यालय द्वारा की गई शोध और विकास गतिविधियों के निष्कर्षों के प्रकाशन और प्रसारण द्वारा ज्ञान की साझेदारी संबंधी कार्यकलापों का अनुसमर्थन व्यापक स्तर पर करता रहा। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के अनुक्रम में प्रकाशन एकक समसामयिक आलेख/जर्नल/पाक्षिक न्यूजलेटर, पुस्तकें, एम.फिल. और पी–एच.डी. की विवरणिका और प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेण्डर प्रकाशित करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षणों की रिपोर्टों की श्रृंखला भी प्रकाशित करता है। प्रकाशन एकक कंप्यूटरों तथा प्रिंटरों से सुसज्जित है और विश्वविद्यालय के डीटीपी कार्य भी करता है।

वर्ष 2013–14 के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले – जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (अंग्रेजी), *परिप्रेक्ष्य (हिंदी) शिक्षा का सामाजिक–आर्थिक संदर्भ* पर जर्नल और एंट्रीप न्यूज लेटर, एम.फिल तथा पी–एच.डी. कार्यक्रमों की विवरणिका तथा पाठ्यचर्या गाईड। विश्वविद्यालय ने अनेक शोध और संगोष्ठियों/सम्मेलनों की रिपोर्टें पुस्तक और मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने निम्नांकित प्रमुख प्रकाशन निकाले :

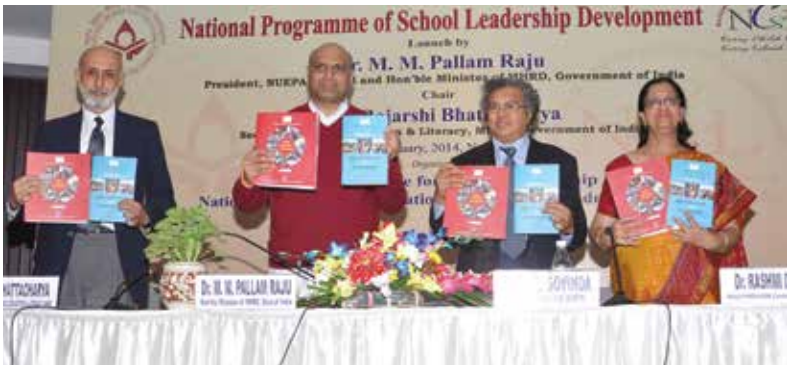

t u'y

- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVII अंक 1, जनवरी 2013
- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVII अंक 2, अप्रैल 2013
- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVII अंक 3, जुलाई 2013
- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVII अंक 4, अक्तूबर 2013
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XXVII अंक 3, दिसंबर, 2011
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XXVII अंक 1, अप्रैल, 2012
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XXVII अंक 2, अगस्त, 2012
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XXVII अंक 3, दिसम्बर, 2012

leY; idk'ku% वर्ष 2013–14 के दौरान समूल्य प्रकाशनों की सूची निम्नांकित है:

- लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशनः स्लेक्ट रीडिंग्स, ए. मैथ्यू तथा जांध्याला बी.जी. तिलक; आई.एस. बी.एन. 978–81–7541–706–9, पृष्ठ I-X 428, दिल्ली न्यूपा, शिप्रा प्रकाशन

fu%'kYd idk'ku% समीक्षाधीन वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित निःशुल्क प्रकाशन निकाले गये :

- एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया : व्हेयर डू वी स्टेंड? डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स 2010–11 (जिल्द I तथा II)
- डाईस एनालिटिकल रिपोर्ट 2009–10 तथा एनालिटिकल टेबल्स 2009–10
- फ्लैश स्टैस्टिक्स 2010–11
- रिपोर्ट ऑफ द स्टैन्डिग कमेटी ऑन नेशनल माइनरटी एजुकेशन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर प्रकाशित)
- न्यूपा कैलेंडर आफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 2013–14 (अंग्रेजी)
- न्यूपा प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013–14 (हिंदी)
- स्टैटेस्टिक्स ऑन सेकेण्डरी एजुकेशन इन इंडिया 2009–10 (ई.एम.आई.एस.)
- वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 (अंग्रेजी)
- वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 (हिंदी)
- रिपोर्ट आफ नेशनल टास्क फोर्स आन जियो–स्पैशियल एजुकेशन (मा.सं.वि. मंत्रालय की ओर से प्रकाशित)
- प्रास्पेक्ट्स (एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रम) 2014–15
- स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट : करीकुलम फ्रेमवर्क
- रिपोर्ट आफ नेशनल टास्क फोर्स आन जियो–स्पैशियल एजुकेशन (मा.सं.वि. मंत्रालय की ओर से पुनः मुद्रित)

,uVhi U;wt yVj% समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनट्रीप (एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन एजुकेशनल प्लानिंग) न्यूजलेटर के – जिल्द XXVII, अंक 1, जुलाई–दिसम्बर, 2012 तथा जिल्द XXVII, अंक–1, जनवरी–जून, 2013 प्रकाषित किए गए।

lelkef;d vkys[k% वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित समसामयिक आलेख प्रकाशित किए गएः

- न्यूपा समसामयिक आलेख सं. 43: एक्सेस टू सेकेण्डरी एजुकेशन इन नार्थ इस्टर्न स्टेट्स, व्हाट सेमिस डाटा रिविल? एस.एम.आई.ए. जैदी, नई दिल्ली, न्यूपा, पृष्ठ 54
- न्यूपा समसामयिक आलेख सं. 44 : स्टूडेंट मोबिलिटी एट टीचर लेवल इन इंडिया : स्टेट्स, प्रास्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, नीरू स्नेही, न्यूपा, नई दिल्ली, पृष्ठ 49

vU;

- ईयर प्लानर ए–4 बुकलेट 2014
- सिंगल शीट प्लानर
- डेस्क कैलेण्डर 2014
- ग्रीटिंग कार्ड
- राईटिंग पैड
- डॉकेट फोल्डर
- डेपा, आईडेपा तथा अन्य विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए घोषणा पत्रा
- न्यूपा फोल्डर
- 1000 स्कूल परियोजना/नवाचार के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार, स्थापना दिवस, मौलाना आजाद शिक्षा दिवस तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये पोस्टर
- लोकतंत्र, शिक्षा तथा विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु फोल्डर (6–8 मार्च, 2014)
- डी.ई.ओ./बी.ई.ओ. के लिये शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु फोल्डर (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
- डिजीटल आर्काईव के लिये विवरणिका

fefe;kxkQ idk'ku% समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों, समसामयिक आलेखों, न्यूपा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों की रिपोर्ट/प्रशिक्षण सामग्री/मिमियोग्राफ प्रकाशित किए।

U;wik oSclkbV dk ;xnku% न्यूपा ने ज्ञान और सूचना के वृहद प्रचार–प्रसार के लिए वेबसाइट का निर्माण किया है। प्रकाशन विभाग ने अपने प्रकाशनों से संबंधित निम्नांकित सूचनाएं अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराई है : न्यूपा के समूल्य तथा निःशुल्क प्रकाशनों की वृहद सूची तथा न्यूपा के लिए निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची; जेपा के वर्तमान तथा भविष्य के अंकों के बारे में सूचना; न्यूपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर; न्यूपा एट ए ग्लान्स, प्रेस विज्ञापन तथा एम.फिल और पी–एच.डी. प्रोग्राम; न्यूपा में दिए गए महत्वपूर्ण संभाषण एवं व्याख्यान; निगम ज्ञापन और नियम (न्यूपा); हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य; न्यूपा समसामयिक आलेख को अपलोड करना; एंट्रीप न्यूजलेटर को अपलोड करना; न्यूपा वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण) 2012–13।

9 न्यूपा में सहायता अनुदान योजना

न्यूपा में सहायता अनुदान योजना

कार्य योजना के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही योजना में उसकी पुनः व्याख्या के विभिन्न मानकों के क्रियान्वयन हेतु उद्देश्यों का वृहद प्रचार आवश्यक है तथा शिक्षा के क्षेत्र मे कार्यरत गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ निकटतम सहयोग आवश्यक है। नीति के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वयन हेतु, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर समर्थन व्यवस्था समेत अंतःशास्त्रीय उपागम का विकास आवश्यक है।

इस संदर्भ में ये आवश्यक हैं: (अ) देश में शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति वृहद जागरूकता पैदा करना, (ब) नीति उन्मुख अध्ययनों तथा संगोष्ठियों को आरंभ करना ताकि मध्य–पाठ्यक्रम सुधार, संशोधन तथा नीति हस्तक्षेपों के साथ समायोजन किया जा सके (स) अध्यापकों, छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं और संचार माध्यमों को प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके साझा मंच प्रदान करना। (द) शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी तथा अच्छे व्यवहार एवं सफल प्रयोग को बढ़ावा देना (य) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना की समीक्षा को सुविधाजनक बनाना।

उपरोक्त प्रयोजन के लिये, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार ने सहायता अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत योग्य संस्थानों तथा संगठनों को वित्तीय सहायता शिक्षा नीति के प्रबंधन तथा क्रियान्वयन पक्ष पर सीधे प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के आधार पर प्रदान की जायेगी। इसके अंतर्गत सम्मेलनों का आयोजन, प्रभावी तथा मूल्यांकन अध्ययन, सर्वोत्तम विकल्पों पर परामर्शकारी अध्ययन, भारत सरकार को सलाह देने हेतु तथा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मॉडल, विडियो फिल्म इत्यादि का निर्माण सम्मिलित हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय के माध्यम से यह योजना संचालित की है जो सहायता अनुदान समिति के द्वारा इसे संचालित करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार इस समिति के निम्नांकित सदस्य हैं:

1. प्रोफेसर नीलम सूद – अध्यक्ष
2. प्रोफेसर ए. के. शर्मा – सदस्य
3. प्रोफेसर कुमार सुरेश – सदस्य
4. प्रोफेसर वाई. जोसेफिन – सदस्य
5. प्रोफेसर प्रमिला मेनन – सदस्य
6. श्री बसवराज स्वामी – सदस्य सचिव

सहायता अनुदान समिति ने इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए जनवरी 2014 में आयोजित समिति की बैठक में मौजूदा प्रपत्रों की समस्याओं पर चर्चा की गयी और उन्हें दूर किया गया। आवेदन प्रक्रिया को सरल और बोधगम्य बनाने के लिए सामान्य अनुदेश बनाये गए और वेबसाईट पर उसे उपलोड किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत समिति ने निम्नांकित सहायता अनुदान की संस्तुति प्रदान की। जिसका विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है :

vçy 2013 l ekpl 2014 d nkjku lLrr çLrkok dh lph

Ø- l-	lxBu dk uke	ifj;ktuk dk 'kh"kd	LohÑr lgk;rk vunku jkf'k
1.	एस एंड टी शिक्षा मंच, नई दिल्ली	भारत में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में वैज्ञानिक चेतना के विकास हेतु विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग में समस्याएँ तथा सम्भावनाएँ हरियाणा के पलवल जिले का अध्ययन	रु. 5,00,000/–
2.	अल्पसंख्यक शिक्षा समिति, महाराष्ट्र	अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा की महत्ता पर दो दिवसीय संगोष्ठी	रु. 1,50,000/–
3.	समाजिक अनुसंधान तथा विकास संस्थान, मणिपुर	मणिपुर में आदिवासी समुदाय के बीच शिक्षा की समस्याओं के प्रति – उपागम	रु. 2,50,000/–
4.	ग्राम स्वराज कुमारप्पा संस्थान, जयपुर, (जयपुर)	अप्रवासी बच्चों के लिये शिक्षा – ईंट भट्ठा मज़दूरों पर अध्ययन, जयपुर जिले का चाकसू ब्लॉक	रु. 4,88,400/–
5.	अभ्युदय संस्थान (उत्तर प्रदेश)	आर.टी.ई. एक्ट 2009 के विशेष संदर्भ में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन हेतु समुदाय भागीदारी (विद्यालय प्रबंधन समिति) की भूमिका पर कार्यशाला	रु. 3,00,000/–
6.	भारत के मुस्लिमों की शिक्षा और संस्कृति विकास केन्द्र, अलीगढ़	परंपरागत बनाम आधुनिक शिक्षा : मुस्लिम संस्थानों का दृष्टिकोण तथा योजना पर संगोष्ठी	रु. 3,00,000/–

Ø- l-	lxBu dk uke	ifj;kstuk dk 'kh"kZd	LohÑr lgk;rk vuqnku jkf'k
7.	विकलांगता तथा पुनर्वास अध्ययन हेतु समिति, नई दिल्ली	भारत में राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी पर राष्ट्रीय चर्चा	रु. 3,00,000 / –
8.	अर्थशास्त्र विभाग, कोलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकत्ता	'शिक्षा, विविधता तथा जनतंत्र' पर भारतीय तुलनात्मक शिक्षा समिति का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कोलकत्ता	रु. 5,00,000 / –
9.	भारतीय इतिहास कांग्रेस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	भारतीय इतिहास कांग्रेस का वार्षिक सत्र, 74वां सम्मेलन, कटक। ओडिशा, दिसंबर 28–30, 2013	रु. 3,00,000 / –
10.	अलीगढ़ इतिहास समिति, अलीगढ़	इतिहास में 'व्यापारियों एवं सौदागरों' पर संगोष्ठी	रु. 3,00,000 / –
11.	भारतीय महिला अध्ययन संघ, नई दिल्ली	महिला अध्ययन : विषय–वस्तु : समानता; बहुलवाद तथा राज्यः महिला आन्दोलन से संप्रेक्ष्य	रु. 3,00,000 / –
12.	सेंट अलयूसिस कालेज (स्वायत्त) मंगलौर	उच्च शिक्षा के बदलते प्रतिमान : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रयास पर संगोष्ठी	रु. 3,00,000 / –

10

प्रशासन

एवं वित्त

प्रशासन एवं वित्त

प्रशासन

विश्वविद्यालय के पास हाउसकीपींग तथा सुरक्षा सेवाओं के लिये बाह्य सेवा–स्रोतों के अतिरिक्त निम्नांकित स्वीकृत पद हैं।

प्रशासन तथा अकादमिक एवं तकनीकी समर्थन सेवाएं प्रशासन के कार्य के अनुसार स्थापित अनुभागों द्वारा नियंत्रित तथा समन्वित की जाती हैं।

इसके अनुभाग कार्यकलापों के अनुसार स्थापित किये गए हैं जिन्हें संगठनात्मक आरेख में प्रदर्शित किया गया है। विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के अलावा विभिन्न अकादमिक और अनुसचिवीय पदों पर 70 परियोजना कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं।

ckg; loxl in	l[;k
कुलपति	01
कुलसचिव	01
संवर्ग पद	
संकाय (कुलपति, प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर)	42
अकादमिक समर्थन स्टाफ़	15
प्रशासन, वित्त, सचिवीय तथा अन्य तकनीकी स्टाफ	66
सहायक स्टाफ (एम.टी.एस.)	37
	162

समीक्षाधीन वर्ष 2013–14 के अंतर्गत, निम्नांकित नियुक्तियां/सेवानिवृत्तियां की गईं।

fu;qfDr;k

leg ^,*

Ø-l-	uke	in	fu;qfDr dh frfFk
1.	श्री बसवराज स्वामी	कुलसचिव	05.11.2013
2.	श्री जी. वीराबाहू	प्रशासनिक अधिकारी	20.03.2014

leg ^ch*

Ø-l-	uke	in	bLrhQk dh frfFk
1.	डा. बिनोद कुमार सिंह	कुलसचिव	04.07.2013

lsokfuofÙk;k

leg ^,*

Ø-l-	uke	in	lsokfuofÙk dh frfFk
1.	प्रो. प्रमिला मेनन	प्रोफेसर	30.04.2013

leg ^ch*

Ø-l-	uke	in	fu;qfDr dh frfFk
1.	सुश्री उज्ज्वल भट्टाचार्य	अनुभाग अधिकारी	31.10.2013
2.	श्री एच.के. बत्रा	सहायक	30.11.2013

leg ^lh*

Ø-l-	uke	in	frfFk
1.	श्री एच. इमैनुअल	पुस्तकालय अटैन्डेंट	31.10.2013
2.	श्री सुलतान सिंह रावत	एम.टी.एस.	31.08.2013

foÙk rFkk y[kk foHkkx

न्यूपा में वित्त तथा लेखा सेवाएं लेखा अनुभाग द्वारा संचालित की जाती हैं जिसका अध्यक्ष वित्त अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखाकार और कार्यालय के आठ सदस्य तथा अनुसचीवीय स्टाफ होता है। यह अनुभाग बजट की तैयारी, मासिक वेतन तथा पेंशन बिल, अन्य व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति जैसे चिकित्सा, एल.टी.सी. बिल, अग्रिम इत्यादि, वस्तुओं की खरीद के लिये बिल भुगतान प्रक्रिया, कार्य, संविदा इत्यादि, पूर्व लेखा परीक्षा, बाह्य परीक्षा के साथ समन्वयन तथा वित्त तथा लेखा से जुड़े अन्य मसलों के लिये उत्तरदायी होता है। यह सभी वित्तीय मसलों पर समयबद्ध परामर्श देता है तथा वित्तीय भागीदारी, लेखा बयान, उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि हेतु सभी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु प्रभावी सहायता प्रदान करता है। वित्त अधिकारी वित्त समिति का सदस्य सचिव होता है जो विश्वविद्यालय के वित्त, निर्देशन तथा विभिन्न श्रेणियों के लिये व्यय की सीमा तय करता है। पिछले पांच वर्षों में मंत्राालय से प्राप्त अनुदान निम्नांकित है :

प्राप्त अनुदान का व्यौरा (2009–2014) (रु. लाख में)

Ø- l-	'kh"k	2009&10	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14
1.	सहायता अनुदान (योजना)	1,000.00	1,013.59	1,197.60	1,129.80	1,185.00
	सहायता अनुदान (योजनेतर)	1,050.00	1,092.00	1,033.55	1,070.44	1,415.00
	आंतरिक प्राप्तियां	126.97	117.13	110.11	101.87	28.98
	योग	2,176.97	2,222.72	2,341.26	2,302.11	2,628.98
2.	व्यय (योजना)	851.60	980.33	1,106.38	1,325.69	1,272.97
	व्यय (योजनेतर)	1,137.74	1,123.05	1,059.36	1,307.54	1,441.86
	योग	1,989.34	2,103.38	2,165.74	2,633.23	2,714.83
3.	आंतरिक प्राप्तियां व्यय के प्रतिशत के रूप में	1%	1%	1%	1%	1%
4.	सहायता अनुदान व्यय का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान सहायता अनुदान में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है और इसी अनुपात में इसका व्यय भी बढ़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यूपा अपनी मुख्य गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दे रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन / हिंदी कक्ष

fgnh d{k

हिंदी कक्ष अनुवाद की सुविधा के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रशासन में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकाशनों के हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के साथ–साथ राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के हिंदी कक्ष द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान रोजमर्रा के कार्यों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए :

- हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।
- हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य के चार अंक प्रकाशित किए गये।
- एन.सी.एस.एल. की पाठ्यचर्या का हिंदी अनुवाद और संपादन
- हिंदी में निम्नलिखित सामग्री का अनुवाद करके उन्हें प्रकाशन के लिए तैयार किया गया :
  - वार्षिक रिपोर्ट : 2012–13
  - प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2013–14
- हिंदी दिवस के उपलक्ष में 13–27 सितम्बर 2013 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किया गए :
  - एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
  - हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नमंच और विश्वविद्यालय के वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के लिये हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गयी और कुल 36 पुरस्कार दिए गए ।

fo'k"k miyfC/k & jkt Hkk"kk 'khYM

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्वविद्यालय को राजभाषा शील्ड प्रदान किया ।

अनुलग्नक

संकाय का
अकादमिक योगदान

अनुलग्नक

संकाय का अकादमिक योगदान

शैक्षिक योजना विभाग

ik- , l-, e-vkb-,- tnh ¼foHkkxk/;{k½

idk'ku

''स्टैटिसटिक्स ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन इंडिया'' (प्रो. के. बिस्वाल और डा. एन.के. मोहन्ती के साथ) न्यूपा, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, अप्रैल, 2013

एक्सैस टू सेकेण्डरी एजूकेशन इन नार्थ–इस्टर्न स्टेट्स व्हॉट सेमिस डाटा रिवील, न्यूपा, ओकेज़नल पेपर नं. 43, 2013

lEeyu@lxk"Bh@dk;'kkykvk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;

''एजुकेशनल प्लानिंग ऐट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया'' विषय पर उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय डी.ई.ओ., बी.ई.ओ. के सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण दिया, लखनऊ, अप्रैल 23–24, 2013।

''एजुकेशनल प्लानिंग ऐट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया'' विषय पर गुजरात के राज्य स्तरीय डी.ई.ओ., बी.ई.ओ. के सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण दिया, आनंद, मई 30–31, 2013

''एजुकेशनल प्लानिंग ऐट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया'' विषय पर बिहार के राज्यस्तरीय डी.ई.ओ., बी.ई.ओ. के सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण दिया, पटना, जून 19–20, 2013

vrjk"Vh;

'डेमोक्रेसी, एजुकेशन और डवलपमेंट : इसूज रिलेटिंग टू इंक्लूजन एक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी', विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, न्यूपा द्वारा आयोजित, क्लेरियन कलेक्शन, कुतुब होटल, नई दिल्ली, मार्च 6–8, 2014

'एजूकेशन ऐस ए राईट एक्रॉस द लेवल्स : चैलेंजेस, ऑपर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज,' विषय पर भाग लिया, शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और यूनेस्को (नई दिल्ली) द्वारा, जामिया नगर, नई दिल्ली में आयोजित, मार्च 10–11, 2014 'एनहैंसिंग रेलीवेंस ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन : एक्सप्लोरिंग ऑपर्चुनीटिज एंड स्ट्रेटज़ीज़' सत्र की अध्यक्षता भी की, मार्च 11, 2014

0;k[;ku

संसाधन व्यक्ति के रूप में, क्षमता निर्माण कार्यक्रम में व्याख्यान एजूकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर सीनियर एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफ मध्य प्रदेश, विषय पर दिया। नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च (एनआईएआर) द्वारा आयोजित, एलबीएसएनएए, इंदिरा भवन, मंसूरी, अगस्त 26–27, 2013

संसाधन व्यक्ति के रूप में, बिहार सरकार के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रम में क्षमता निर्माण विषय पर व्याख्यान दिया। नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च (एनआईएआर) द्वारा आयोजित, एलबीएसएनएए, इंदिरा भवन, मंसूरी, अगस्त 26–27, 2013

संसाधन व्यक्ति के रूप में, ''रोल ऑफ एसएमसीडी अंडर आरटीई एक्ट'' विषय पर व्याख्यान दिया, सीआरसी संयोजकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में, डाईट द्वारा आयोजित, मोतीबाग, फरवरी 4, 2014

एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, ''स्कूल डवलपमेंट प्लान'' एमसीडी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया, डाईट द्वारा आयोजित, पूर्वी दिल्ली जिला, डाईट, कड़कड़डूमा, फरवरी 7, 2014

एक संसाधन व्यक्ति के रूप में एक पैनल परिचर्चा में 'रमसा इनिशिएटिव टूवार्ड्स क्वालिटी स्कूल एजूकेशन,' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया, एससीईआरटी द्वारा आयोजित, दिल्ली, फरवरी 11, 2014

lkoZtfud fudk;ksa dks lg;ksx vkSj ijke'kZu

रमसा तकनीकी सहयोग निधि (टीसीएफ) की पहली संचालन समिति कार्यक्रम, मनाव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, सितंबर 30, 2013

एक सदस्य के रूप में प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की मध्यावधि समीक्षा बैठक, डाईट, दरियागंज, एससीईआरटी, नई दिल्ली, दिसंबर 16, 2013, को भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की मध्यावधि समीक्षा बैठक, डाईट, कड़कड़डूमा, एससीईआरटी, नई दिल्ली, दिसंबर 16, 2013, को भाग लिया।

एक नामित सदस्य के नाते रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिऑर्गेनाजेशन ऑफ सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम की बैठक, योजना को पुनर्गठित करने हेतु चर्चा में एससीईआरटी, नई दिल्ली, में भाग लिया, एससीईआरटी, दिसंबर 19, 2013,

एक सदस्य के रूप में प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की मध्यावधि समीक्षा बैठक, डाईट, मोतीबाग, एससीईआरटी, नई दिल्ली, दिसंबर 20, 2013

एक सदस्य के रूप में वार्षिक कार्यक्रम सलाह समिति (पीसी) की डाईट, एससीईआरटी, नई दिल्ली, में मार्च 13, 2014, को भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में वार्षिक कार्यक्रम सलाह समिति (पीसी) की डाईट, एससीईआरटी, दरियागंज, नई दिल्ली, में मार्च 14, 2014, को भाग लिया।

टेक्निकल को–ऑपरेशन फंड के स्टिपरिंग कमिटी की दूसरी बैठक (टीसीएफ) माध्यमिक शिक्षा हेतु (रमसा), की बैठक, मा.सं.वि.मं, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, मार्च 31, 2014 को भाग लिया।

ekuk [kjs

idk'ku

''एम्प्लॉयमेंट एम्प्लायेबिलिटी एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया– द मीसिंग लिंक्स'', हायर एजुकेशन फार द फ्यूचर (1) 39–62, 2014 द केरल स्टेट हायर एजुकेशन, सेज पब्लिकेशन।

''एजुकेशन डवलपमेंट एंड को–आपॅरेशन इन द एशिया–पेसिफिक शिफ्टिंग डायनॉमिक्स, इन्क्रीजिंग कोलोबरेशन'' (कंट्री रिपोर्ट इंडिया) वेब पब्लिशड् अपलेबल ऐट http//www.unescobkk.org/educaion/epr/eprpartnerships/unesco_kedia/2013/day/

एजुकेशन ऐड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इंडिया: शिफ्टिंग डायनॉमिक्स, इन्क्रीजिंग कोलोबरेशन'', इन हुसांग एंड–जु–चान (सं) इंटरनेशनल एजुकेशनल एड इन डवलपिंग एशिया–पैसिफिक एंड प्रेक्टिसेज (इन प्रिंट)

lEesyu@laxks"Bh@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;

क्वालिटल एश्योरेंस एंड अक्रेडिटेशन पर कार्यशाला,

एमएचआरडी द्वारा आयोजित, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन एंड वीआइसीआईईआरआइ द्वारा आयोजित, मई 12—13, 2013

'ओपन डेटा डवलपमेंट एंड ट्रांसपरेंसी इनिशिएटिव्स' के प्रशिक्षण कार्यशाला में सहयोग, वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित, नई दिल्ली, जुलाई 19, 2013

एआइएमएएस का 40वां प्रबंधन सम्मेलन 'करेल इन अनसर्टेंट, होटल ले मेरिडियन, नई दिल्ली, सितंबर 26—27, 2013

संसाधन व्यक्ति, दो दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी डीईओ और बीईओ, न्यूपा द्वारा आयोजित, सिक्किम, दिसंबर 9—10, 2013

vrjk"Vh;

यूनेस्को—केडी के क्षेत्रीय नीति संगोष्ठी में वक्ता 'एजुकेशन डवलपमेंट एंड कोआपरेशन इन दी एशिया पैसिफिक : शिफ्टिंग डाइनामिक्स, इंक्रीजिंग कोलाबोरेशन', विषय पर, बैंकाक, थाइलेंड, अगस्त 5—7, 2013

ब्रिटिश काउंसिल के एशिया डॉयलॉग सीरीज पर वक्ता, ''दी क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस : द स्किल्स रिवोल्यूशन इन दी यू.के. एंड साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस, लंदन, सितंबर 23—24, 2013

यू.के. हायर एजुकेशन काउंसिल राउण्ड टेबल में व्याख्याता 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन टीचिंग—लर्निंग' विषय पर लंदन, सितंबर 25, 2013।

lEeyu@lxk"Bh@dk;'kkyk dk vk;ktu

'क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन' विषय पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। 43 सहभागियों के साथ जो 13 राज्यों के 23 निश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि थे, न्यूपा, नई दिल्ली, दिसंबर 16—27, 2013।

ykd fudk;k e 'kf{kd lg;kx vkj ijke'ku

सदस्य, शिक्षा में सेवा उत्पाद के सूची को उप—समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय, सीएसओ।

65वें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संसाधन व्यक्ति, यूजीसी—अकेडमिक स्टॉक कॉलेज द्वारा आयोजित, बीएचयू के कॉलेज एवं वि.वि अध्यापकों हेतु, अक्टूबर—नवंबर, 2013

एनआईओएस के रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल के स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में विशेषज्ञ सदस्य, जनवरी 17, 2014।

जयपुर विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा प्रोग्राम में सेल्फ—लर्निंग मैटेरियल का मूल्यांकन, जयपुर, यूजीसी — दूरस्थ शिक्षण ब्यूरो में विशेषज्ञ के रूप में।

इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च (आइसीएसएसआर) के शिक्षा विषयक शोध पुस्तकों का मूल्यांकन, नई दिल्ली।

ब्रिटिश काउंसिल एकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का अध्ययन 'उच्च शिक्षा में महिला नेता' विषय पर साक्षात्कार।

पीपुल्स इन एजुकेशन की चौथी रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम के सदस्य, एमएचआरडी।

एसोसिएट एडीटर, इंडियन एकानॉमिक जर्नल, ऑल इंडिया एकोनॉमिक जर्नल।

2013 के रीजनल पॉलिसी सेमिनार में रिपोर्ट तैयार करने में योगदान, ''एजुकेशन डवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन दी एशिया पेसिफिक'', यूनेस्को—केडी।

समीक्षक, हिमगिरि एजुकेशन रिब्यू, आइएसएसएन 2321—6336, हिमगिरि जी यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड

U;ik d ckgj ie[k ldk;k dh lnL;rk

सदस्य, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा उत्पाद सूची की उप—समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय, भारत सरकार।

सदस्य, स्टेंडिंग कमिटी ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटि ऑफ नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा।

सदस्य, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज इन एकोनॉमिक्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट।

वाइस प्रेसीडेंट, एम.पी. एकानॉमिक एसोसिएशन इंटरनेशनल एडवाइजर, जर्नल ऑन बिजनेस एंड टेक्नॉलॉजी (इन्वाइटेट)

आजीवन सदस्य, इंडियन एकोनॉमिक असोसिएशन।

फेलो मेंबर, जर्नल ऑफ एनवाइरनमेंटल रिसर्च एंड डवलपमेंट।

आजीवन सदस्य, मध्य प्रदेश एकोनॉमिक असोसिएशन।

आजीवन सदस्य, मध्य प्रदेश रीजनल साइंस असोसिएशन।

बाह् सदस्य, अकेडमिक काउंसिल, एसएनजीजीपीजी कॉलेज (ऑटोनॉमस), भोपाल।

समीक्षक, बिजनेस पर्सपेक्टिव, बीमटेक, नोएडा।

d- fcLoky

çdk'ku

'kks/k i=@ys[k@fVIi.kh

आलेख– स्टैटिस्टिक्स आन एजुकेशन (प्रो. जे.बी.जी. तिलक और प्रो. पी.आर. पंचमुखी) के साथ एमओएसपीएल, भारत सरकार, नई दिल्ली, मार्च 2011 http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Them_Paper_Education.pdf. पर उपलब्ध

(प्रो जे.वी.जी. तिलक और एन.के. मोहती के साथ) फायनेंसिंग आफ सेकेंडरी एजूकेशन इन एशिया–पैसिफिक रीजन, एजुकेशन पालिसी रिसर्च सीरीज डिस्कसन डाक्यूमेंट्स नं. 4 वार्षिक बैठक के लिए तैयार ''भारत में उच्च शिक्षा के लिए संक्रमण'' शिक्षा, यूनेस्को, बैंकाक, 17 19 अक्टूबर 2013 के लिए ब्यूरो यह यूनेस्को, बैंकाक से प्रकाशित किया जा रहा है।

(प्रो जे.बी.जी. तिलक और डा. एन.के. मोहंती के साथ) ''एशिया प्रशांत क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा का वित्त पोषण'' शिक्षा नीति अनुसंधान सीरीज चर्चा दस्तावेज नं. 4, शिक्षा नीति और सुधार यूनिट, यूनेस्को 2013: // unesdoc-unesco-org/images/0022/002255/225507 पर पीडीएफ उपलब्ध

vuqla/kku v/;;u

तमिलनाडु और ओडिशा में रा.मा.शि.अ. के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना शुरू की। जैदी, एस.एम.आई.ए. और ड. एन.के. मोहंती (परियोजना टीम), के साथ इन दोनों राज्यों के सहयोग से अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित।

laxksf"B;k@lEesyuk@dk;Z'kkykvksa esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;

रा.मा.शि.अ., असम, गुवाहाटी, द्वारा 'स्कूल सुधार योजना के लिए मैनुअल का विकास' पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य, 13–15 फरवरी, 2014

varjjk"Vªh;

न्यूपा द्वारा 'समावेशन, समता और स्थिरता संबंधित मुद्दों लोकतंत्र, शिक्षा और विकास' पर आयोजित, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

çf'k{k.k lkexh vkSj ikB~;Øe dk fodkl vkSj f'k{k.k

न्यूपा, मई 2013 तक आयोजित भूटान के जि.शि.अ. के प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना मॉड्यूल (प्रो. एस.एम. आई.ए. जैदी और डॉ एनके मोहंती के साथ)।

'शैक्षिक योजना में तकनीक', पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (डॉ एनके मोहंती के साथ) का आयोजन किया, न्यूपा, नई दिल्ली, 8–9 जुलाई, 2013

पूर्वोत्तर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की योजना पर मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजाइन और संपादन, गुवाहाटी, असम, 16–28 सितंबर, 2013 (डा. एन.के. मोहंती के साथ)

डिजाइन और पूर्वोत्तर राज्यों, गुवाहाटी, असम, 06–17 नवम्बर, 2014 में माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण (डॉ एनके मोहंती के साथ) का आयोजन

vU; 'kSf{kd xfrfof/k;ka

एम.फिल. लघु शोध प्रबंध का निर्देशन और मूल्यांकन– भारत में शैक्षिक योजना में आईसीटी की भूमिका (सुश्री निधि रावत) 2013.

पी–एच.डी. शोध प्रबंध निर्देशन– भारत में प्रारंभिक शिक्षा का जीआईएस आधारित स्कूल मैपिंग (सुश्री निधि रावत)

डेपा लघु शोध प्रबंध निर्देशन– जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सरकारी मिडिल स्कूलों के एसएमसी की भूमिका और कार्यकलाप का अध्ययन श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

आईडेपा लघु शोध प्रबंध शीर्षक– 'अदीस अबाबा, इथियोपिया के द्वितीय चक्र प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के सशक्तिकरण का एक अध्ययन' श्री के. डरबिव, अप्रैल 2013

पाठ्यक्रम समन्वयक और संचालक– डेपा पाठ्यक्रम सं. 108; भारत में शैक्षिक योजना, नवंबर 2013

आईडेपा पाठ्यक्रम सं. 205 : 'परियोजना नियोजन और भारत में व्यष्टि स्तरीय योजना का समन्वयन और संचालन, मार्च 2014

lkoZtfud fudk;ksa dks ijke'kZdkjh lsok,a vkSj vdknfed vuqlEFkZu

सदस्य, स.शि.अ. संयुक्त समीक्षा समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 17–24 जून, 2013

आरएमएसए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दस्तावेज–निगरानी परिणाम फ्रेमवर्क के विकास में ड. एन.के. मोहंती के साथ योगदान दिया और आरएफडी में मात्रात्मक संकेतकों में से प्रत्येक के लिए लक्ष्य प्रदान किया।

सदस्य, प्रो जे.बी.जी. तिलक, न्यूपा की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित स्कूल शिक्षा पर वित्तीय डेटा पर विशेषज्ञ समूह,.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएमएसए के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य और जिला माध्यमिक शिक्षा योजना (परिप्रेक्ष्य और एडब्ल्यूपी और बी) में आरएमएसए के तहत की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की।

vU; 'kSf{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

प्रमुख, परियोजना प्रबंधन इकाई, न्यूपा, फरवरी 2014 में अनुसंधान की निगरानी के लिए दस्तावेज (1 एवं 2) तैयार किया।

संयोजक, न्यूपा अनुसंधान समूह की समीक्षा करने और न्यूपा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

सदस्य, डेपा कार्यक्रम, न्यूपा, नई दिल्ली के पुनर्गठन के लिए समिति

सदस्य, कार्य समीक्षा और सलाहकार समिति, न्यूपा

सदस्य, न्यूपा का प्रकाशन सलाहकार समिति

सदस्य, न्यूपा नीति संक्षिप्त श्रृंखला के लिए संपादकीय समिति

सदस्य, समिति एम.फिल./पी–एच.डी में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के डिजाइन के लिए समिति, न्यूपा

सदस्य, एम.फिल./पी–एच.डी. की लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सदस्य, समिति

भारत में माध्यमिक शिक्षा में विकेन्द्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देने के लिए आरएमएसए–टीसीए और न्यूपा सहयोगी कार्यक्रम में भाग लिया।

एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए कोर पाठ्यक्रम सं सीसी–3 (शिक्षा नीति एवं योजना) (ड. एन.के. मोहंती और प्रो. सुधांशु भूषण के साथ) का विकास और शिक्षण 2013–14

एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए विकसित और वैकल्पिक पाठ्यक्रम सं. ओ.सी–1 (शिक्षा में उन्नत योजना तकनीक) (ड. एन.के. मोहंती के साथ) का विकास और शिक्षण 2013–14

,u-ds- eksgarh

çdk'ku

'kks/k i=@ys[k@fVIi.kh

स्टैटिस्टिक्स आन सेकेण्डरी एजुकेशन इन इंडिया (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी अैर डा. के बिस्वाल के साथ), न्यूपा, अप्रैल 2013

vuqla/kku vè;;u

विद्यालय प्रावधान और माध्यमिक स्तर पर स्कूल प्रदर्शन पर अध्ययन पूरा. (न्यूपा में एक सामयिक आलेख के

रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत) यह आलेख उपलब्ध माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त करने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (सेमीस), 2009–10 से एकत्र आंकड़ों और जानकारी के विश्लेषण पर आधारित था.

तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर, क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना शुरू की और प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी अैर डा. के बिस्वाल, (परियोजना टीम), के साथ इन दो राज्यों के सहयोग से अनुसंधान परियोजना के सहयोग से कार्यान्वित .

lxkf"B;k@lEesyuk@dk;'kkykvk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

'स्कूल सुधार योजना पर मैनुअल का विकास और अंतिम रूप देना पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।

आरएमएसए, गुवाहाटी, असम, में फरवरी 13–15, 2014 तक आयोजित की।

vrjk"Vh;%

'लोकतंत्र, शिक्षा और विकास' समावेशन, समता और स्थिरता से संबंधित मुद्दों' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और रिपोर्टर का काम किया, न्यूपा, नई दिल्ली, मार्च 6–8, 2014.

çf'k{k.k lkexh vkj ikBîØe dk fodkl vkj f'k{kk

न्यूपा, नई दिल्ली, 'शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास और आयोजन 8–19 जुलाई, 2013.

आरएमएसए पर केंद्रित माध्यमिक शिक्षा में जिला योजना पर विमर्श और कार्याभ्यास (डा. के बिस्वाल के साथ) का संशोधन, अगस्त, 2013

यूपीई के लिए एक योजना के परिप्रेक्ष्य विकास पर विमर्श अभ्यास (डां के. बिस्वाल के साथ) का संशोधन, सितंबर 2013.

गुवाहाटी, असम, में पूर्वोत्तर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना में मास्टर ट्रेनर्स के कार्यक्रम की डिजाइन और आयोजन (डा. के. बिस्वाल के साथ) 16–28 सितम्बर, 2013

पूर्वोत्तर राज्यों के लिये गुवाहाटी, असम, में माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण (डा. के. बिस्वाल के साथ) का आयोजन 06–17 नवम्बर, 2013

न्यूपा में शैक्षिक योजना पर कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का शिक्षण।

vU; 'k{kf.kd xfrfofèk;k

एम.फिल. / पी–एच.डी. कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम सं ओसी–1 (शिक्षा में उन्नत योजना तकनीक) (डॉ के. बिस्वाल के साथ). 2013–14.

लघु शोध प्रबंध निर्देशनः अपव्यय को रोकने के लिये फेल न करने की नीति के निहितार्थ और विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर का उन्नयनः अंशुल सलूजा, शोध छात्रा, न्यूपा।

श्री टी. जमीर, उप परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, नागालैंड के 'सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा के तहत रिसोर्स शिक्षक और स्वयंसेवकों का एक अध्ययन' डेपा शोध प्रबंध 2013 का मूल्यांकन किया।

निर्देशन और मूल्यांकन, आईडेपा लघु शोध प्रबंधः मेडागास्कर के अलमांगा में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय त्याग के कारण– आईडेपा 2013, सुश्री आर.एम. प्रिस्का

निर्देशन और मूल्यांकन, आईडेपा लघु शोध प्रबंध– हट्टन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में विद्यालय स्तरीय परीक्षा और विद्यालय स्तरीय मूल्यांकन के प्रभाव का अध्ययन श्री जान निकोलस, श्रीलंका, 2013

एम.फिल. / पी–एच.डी. कार्यक्रम 2013–14 में प्रवेश के आवेदन पत्र की छंटाई और अन्य संबंधित गतिविधियों में सहायता।

एम.फिल. / पी–एच.डी. 2013–14 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन में सहायता।

lkoltfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

रमसा का परिणाम ढांचा और अनुश्रवण का विकास और अंतिम रूप देना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (डा. के. बिस्वाल के साथ) सेमीस 2009–10 और 2012–13 के आकड़ा आधार पर आरएफडी मे सभी मात्रात्मक संकेतकों के लिये बेसलाइन 2009–10 और 2012–13 के आधार पर प्रत्येक मात्रात्मक संकेतक के लिये लक्ष्य तय किया जो पूर्व और भावी रूझानों पर आधारित था। इससे माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दाताओं से समझने में मदद मिलेगी ओर यह आरएमएसए के अनुश्रवण के लिये आरएफडी को अंतिम रूप देने में सहायक होगा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएमएसए के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य और जिला माध्यमिक शिक्षा योजना (परिप्रेक्ष्य और एडब्ल्यूपी और बी) आरएमएसए तहत तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की।

आरएमएसए विभिन्न परियोजना मंजूरी के लिए आयोजित बोर्ड बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, में भागीदारी, मई 2013 से फरवरी 2014

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

आईडेपा पाठ्यक्रम सं. 207 जनशक्ति नियोजन, का संयोजक, अप्रैल 2013

शैक्षिक योजनाः अवधारणा, प्रकार और दृष्टिकोण, पर डेपा पाठ्यक्रम–106 का संयोजन और संचालन, नवंबर 2013

आईडेपा पाठ्यक्रम सं. 204: शैक्षिक योजना का समन्वयक और संचालक, फरवरी 2014

l|eu uxh

lxk"Bh@lEeyu@dk;l'kkyk e Hkkxhnkjh

'सार्वजनिक निजी शिक्षा में भागीदारी', पर जेएनयू, नई दिल्ली, में 24 फरवरी, 2014 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत और सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोग' शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत किया।

'पूर्वोत्तर भारत में अल्पसंख्यकों के समावेश और विकास की प्रक्रिया' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'पूर्वोत्तर में अल्पसंख्यक शिक्षा की स्थिति' शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत किया। सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक, 22–23 मार्च, 2014.

dk;'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øek dk vk;ktu

शिक्षा में मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन

çf'k{k.k lkexh vkj ikBîØe dk fodkl vkj f'k{k.k

संसाधन व्यक्ति, कोहिमा, नगालैंड में जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन

नगालैंड में स्कूल शिक्षा में प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार की

संसाधन व्यक्ति, पूर्वोत्तर राज्यों के लिये गुवाहाटी में माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण दल के सदस्य

lkoltfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

गुजरात, मिजोरम और दादरा और नगर हवेली के लिए आरएमएसए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का मूल्यांकन.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को शिक्षा पर जन रिपोर्ट के अध्याय में साक्षरताः शैक्षिक विकास और व्यावसायिक शिक्षा की बुनियादी नींव 'विस्तार की आवश्यकता' में योगदान

शैक्षिक प्रशासन विभाग

d- l tkrk ¼foHkkxkè;{k½

çdk'ku

''गुरुकुलम एट रेजीडेंसियल स्कूल्सः इक्विटी एंड एक्सलेंस इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया'' इन जे.एम.बीच, एम. यंगर, (एडीटर) अ कॉमन वेल्थ आफ लर्निंगः मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स रिविजिटेड, रूटलेज़, अबींगडन, 2013

''इंडियन एंड इंटिग्रेसन अंडर राइट टू एजुकेशन – अ केस स्टडी आफ दिल्ली पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली'' (मिमियो) डा. वी. सुचरिता के साथ

vuqlèkku vè;;u

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन संयुक्त रूप से डा. वी. सुचरिता के साथ – राष्ट्रीय संश्लेषण की रिपोर्ट के साथ राज्य रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

dk;'kkyk@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;kstu

बिहार में जि.शि.अ. और प्र.शि.अ. के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, 19–20 जून, 2013.

कर्नाटक में जि.शि.अ. और प्र.शि.अ. के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य स्तर के सम्मेलन 7–8 जनवरी, 2014.

vU; 'k{kf.kd xfrfofèk;k

,efQy-@ih&,p-Mh- e f'k{k.k

शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन (अन्य के साथ)

दो पी–एच.डी. छात्रों और एक एमफिल. छात्र का निर्देशन

vkbMik e f'k{k.k

शैक्षिक प्रशासन (अन्य के साथ)

विभाग में आयोजित सभी कार्यक्रमों में व्याख्यान/सत्र

U;ik d ckgj çf;kr fudk;k dh lnL;rk

सदस्य, आदिम जाति कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान, आन्ध्र प्रदेश के शासी बोर्ड

सदस्य, एनसीईआरटी, नई दिल्ली के शिक्षा विशेष समूह के विभाग की कार्यक्रम सलाहकार समिति.

सदस्य, एनआईओएस, नोएडा अनुसंधान सलाहकार समिति.

सदस्य, सिमेट केरल की कार्यकारी समिति.

सदस्य, 'अनुसूचित जनजाति और अनुसूचितों जातियों के शैक्षिक स्थिति' प्राप्ति और चुनौतियांश विषय पर अनुसंधान परियोजना के लिए आईसीएसएसआर सलाहकार समिति.

सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, ने–फायर

सदस्य, इंडियन जर्नल आफ वोकेशनल स्टडी के संपादकीय मंडल पीएसएससीआईवीई

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी (सीईएसआई).

dekj lj'k

'kk/k v/;;u

प्राथमिक शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के अनुरोध पर गुजरात में ब्लॉक स्तर के शैक्षिक प्रशासनः ''उभरती चुनौतियों और सुधार की आवश्यकता'' पर (संयुक्त रूप से डा. आर.एस. त्यागी) के साथ एक अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है.

tkjh v/;;u

शैक्षिक प्रशासन विभाग द्वारा किए गए शैक्षिक प्रशासन का तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में ''साझा जिम्मेदारियों और मध्य प्रदेश और बिहार में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की क्षमता'' पर एक अध्ययन।

l xk"Bh@lEeyu@dk;l'kkyk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

शिक्षा और सामाजिक अधिकारिता सिद्धांत, नीतियां और प्रचलन पर अनिल बोर्डिया मेमोरियल संगोष्ठी में उच्च शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई और भागीदारी की समानताः ''नीति के परिप्रेक्ष्य और संस्थागत उत्तरदायित्व'' पर एक आलेख प्रस्तुत किया, न्यूपा, नई दिल्ली, 16–17 दिसंबर, 2013

vrjk"Vh;%

लोकनीति और अभिशासन केंद्र, रामजस कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संयुकत रूप से 'संघीय प्रणाली में राजनीति, नीति और अभिशासन पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा में नीतिगत सुधार का समिश्रण और भारत तथा अमरीका में संघ–राज्य संबंधों का पुनः संयोजन पर आलेख प्रस्तुत किया, 14–16 नवंबर, 2013

dk;l'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;kstu

''विश्वविद्यालयों और कालेजों में विविधता और समता का प्रबंधन'' पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 2–6 दिसंबर, 2013

vU; 'kf{kd xfrfofèk;k

,e-fQy-@ih&,p-Mh- e f'k{k.k%

शिक्षा नीति पर पाठ्यक्रम (अन्य के साथ)

शिक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकार (अन्य के साथ)

शैक्षिक प्रबंधन (अन्य के साथ)

दो पी–एच.डी. शोधार्थियों का निर्देशन

Mik e f'k{k.k

डेपा कार्यक्रम का कोर्स 102ः शैक्षिक प्रशासन के लिए सह–संकाय.

lkoZtfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

विभिन्न समितियों में यूजीसी नामिनी

U;ik d ckgj ç[;kr fudk;k dh lnL;rk

सदस्य, भारतीय गांधी अध्ययन सोसायटी के द्विवार्षिक जर्नल आफ गांधीयन स्टडीज का संपादन मंडल

सदस्य, अकादमिक स्टाफ कॉलेज के शैक्षणिक सलाहकार निकाय, श्री रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सदस्य, शासी निकाय, सेंट जेवियर्स शिक्षा कॉलेज, पलायमकोटि, तमिलनाडु

सदस्य, शोध अध्ययन बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग, इग्नू, नई दिल्ली

fouhrk fljksgh

çdk'ku

'kksèk i=@yš[k@fVIi.kh

वोकेशनल गाइडेंस एंड कैरियर मैच्युरिटी अमंग सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेंट्सः एन इंडियन एक्सपीरिएंस, यूरोपियन साइंटिफिक जर्नल, जून 2013/विशेषांक/संस्करण–2

vuqlèkku vè;;u

''दिल्ली के चयनित स्कूलों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परिपक्वता'' पर अध्ययन, जुलाई 2013

dk;l'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;kstu

''योजना और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंधन'', उन्मुखीकरण कार्यक्रम, 23–27 सितम्बर, 2013

vU; 'kf{kd xfrfofèk;k

f'k{k.k xfrfofèk;k

मणिपाल सिटी गाइड द्वारा आयोजित आईएलओ अध्ययन पर आलेख की समीक्षा.

पीएसएससीआईवीई द्वारा प्रकाशित जर्नल आफ वोकेशनल स्टडीज, के लिए आलेख की समीक्षा

एक पीएचडी शोधार्थी का निर्देशन

lkoltfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

शिक्षा क्षेत्र, में सेक्टर कौशल परिषद की स्थापना पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए अकादमिक सहायता, 21 मई 2013

सदस्य, कार्यकारी समिति, एससीईआरटी, न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता, दिल्ली

आजीवन सदस्य, नैदानिक मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन

आजीवन सदस्य, एप्लाइड मनोविज्ञान इंडियन एसोसिएशन

सदस्य, संपादकीय टीम, इंडियन जर्नल आफ वोकेशनल एजुकेशन पीएसएससीआईवीई

vkj-,l- R;kxh

'kk/k v/;;u

i.k%

प्राथमिक शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के अनुरोध पर 'गुजरात में ब्लॉक स्तर के शैक्षिक प्रशासनः उभरती चुनौतियों और सुधार की आवश्यकता'' पर एक अध्ययन (संयुक्त रूप से प्रो सुरेश कुमार के साथ आयोजित), अध्ययन पर रिपोर्ट,

स्कूल शिक्षा विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर (संयुक्त रूप से डॉ मंजू नरूला के साथ आयोजित) 'अरुणाचल प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन में ब्लॉक स्तर सुधारों' पर एक अध्ययन

tkjh

केरल में शैक्षिक प्रशासन का प्रारंभिक सर्वेक्षण

lxk"Bh@lEeyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

vrjk"Vh;%

'शिक्षा, विविधता और लोकतंत्र' पर आयोजित सीईएसआई के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''विकेन्द्रीकृत प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन और गुजरात और मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका'', पर एक आलेख प्रस्तुत अर्थशास्त्र विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय 28–30 दिसंबर, 2013.

''लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः समावेशन, समता और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और समावेशन, समानता और लोकतंत्र'', के लिए सत्र की रिपोर्ट तैयार की, 6–8 मार्च, 2014, न्यूपा, नई दिल्ली,

dk;'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;ktu

न्यूपा, नई दिल्ली में, अक्टूबर 7–11, 2013 को पूर्वोत्तर के राज्यों के जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए 'शिक्षा प्रणाली में शासन के मुद्दे' पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम (23 प्रतिभागियों ने भाग)

गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की अध्ययन यात्रा, न्यूपा, नई दिल्ली, 23–26 दिसम्बर, 2013 (27 प्रतिभागियों ने भाग)

vU; 'kf{kd xfrfofèk;k

विकास प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन पर डेपा के संख्या 105 पाठ्यक्रम संयोजक

एमफिल और पी–एच.डी. के लिए शैक्षिक प्रबंधन पर पाठ्यक्रम का संयोजक (2013)

सदस्य सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित आदर्श शिक्षा संहिता की तैयारी पर समिति.

एक एम.फिल. छात्र को शोध निर्देशन

U;ik d ckgj ç[;kr fudk;k dh lnL;rk

सदस्य, स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी, हरियाणा बोर्ड में नियमन और तुल्यता पर समिति

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी, शिक्षा समितियों के विश्व कांग्रेस से संबद्ध।

e!t! u:yk

çdk'ku

'kkèk i=@y![k@fVIi.kh

''हिस्टोरीकल डवलपमेंट आफ ऐलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया, फ्राम कंपनी रूल टू 1947'' जयंत मेटे एंड अजीत मंडल (सं.) राइट टू एजुकेशन : पालिसी, पर्सपेक्टिव एंड डवलपमेंट, एपीएच पब्लिशर्स, नई दिल्ली 2014 पृ. 106–116

''सेकेण्डरी एजुकेशनः इश्यू रिलेटेड टू एक्सेस एंड क्वालिटी'', प्रतिमान, आईएएसई, भोपाल, मध्य प्रदेश (2013)

''एजुकेशनल डवलपमेंट आफ मुस्लिम माइनरिटी : विद स्पेशल रिफरेंस टू मुस्लिम कांस्टेरेशन इन इंडिया'', जर्नल आफ एजुकेशन एंड रिसर्च, वाल्यूम 4, नं.–1, पृ. 93–108, मार्च 2014,

vu|lèkku vè;;u

i!.k! v/;;u

स्कूल शिक्षा विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर (संयुक्त रूप से आरएस त्यागी के साथ आयोजित) 'अरुणाचल प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन में ब्लॉक स्तरीय सुधारों' पर अध्ययन।

tkjh

बिहार में शैक्षिक प्रशासन का प्रारंभिक सर्वेक्षण।

l!xk"Bh@lEe!yu@dk;!'kkyk e! Hkkxhnkjh

v!rjk"Vh;%

कोयम्बटूर में, '21वीं सदी के लिए जि.शि.अ. की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में' आरटीई के संदर्भ में बदलते परिप्रेक्ष्य बिहार में जिला स्तरीय प्रशासन विषय पर एक आलेख प्रस्तुत, 2–3 अगस्त, 2013

dk;!'kkyk,!@lEe!yu@çf'k{k.k dk;!Øe dk vk;k!tu

राज्य और जिला स्तर के प्रशासकों, के लिए शैक्षिक प्रशासन पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम, न्यूपा, 27–31 जनवरी, 2014

vU; 'k!{kf.kd xfrfofèk;k!

एक एम.फिल. शोधार्थी का निर्देशन

शैक्षिक प्रबंधन और संगठनात्मक विकास पर डेपा पाठ्यक्रम सं. 104 का संयोजक

U;!ik d! ckgj ç[;!kr fudk;k! dh lnL;rk

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी

सदस्य, शिक्षा और आर्थिक विकास सोसायटी

oh- l!pfjrk

çdk'ku

'kkèk i=@y![k@fVIi.kh

''निगोसिशएटिंग विटवीन फेमिली, पीयर्स एंड स्कूल : अंडरस्टैंडिंग दि वर्ल्ड आफ गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स'', जेसीआईई, 44, इश्यू 3, 379–393

''इन्क्लूजन एंड इंटिग्रेशन अंडर राइट टू एजुकेशन– ए केस स्टडी आफ दिल्ली पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली (मिमियाग्राफ) प्रो. के. सुजाता के साथ

vu|lèkku vè;;u

राष्ट्रीय संश्लेषण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि प्राथमिक और (संयुक्त रूप से प्रो के. सुजाता के साथ) जनजातीय क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन पूरा हो चुका है.

l!feukj@lEe!yu@dk;!'kkyk e! Hkkxhnkjh

'शिक्षा में नवाचार' पर एक कार्यशाला में ''स्कूल के बाहर शिक्षाः बंगलौर, कर्नाटक में शिक्षा नवाचार मामले का अध्ययन'' शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़, जुलाई 22–24, 2013.

हैदराबाद, विश्वविद्यालय हैदराबाद में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आलोक

में गुणवत्ता तलाश' शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुद्दे और कार्यान्वयन में चिंताएं', 25–26 फरवरी, 2014

vU; 'k{kf.kd xfrfofèk;k¡

,e-fQy- dk;Øe esa f'k{k.k%

अनुसंधान क्रियाविधि पर पाठ्यक्रम, सीसी–2 (दूसरों के साथ)

Mikse esa dk;Øe esa f'k{k.k%

शैक्षिक प्रशासन पर पाठ्यक्रम सं 101 का संयोजक (अन्य के साथ)

U;iik d s ckgj ç[;kr fudk;k s dh lnL;rk

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक एजुकेशन सोसायटी (सेजी)

शैक्षिक वित्त विभाग

tk/;kyk ch th frykd ¼foHkkxkè;{k½

çdk'ku

iqLrd@vè;k;%

लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशनः स्लैक्ट रीडिंग्स, नई दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन्स/न्यूपा, 2014 (ए. मैथ्यू के साथ)

यूनीवर्सिटी एक्सपेंशन इन चेंजिंग ग्लोबल इकॉनॉमीः ट्रिम्प आफ द ब्रिक्स? (मार्टिन कॉर्नाय, प्रशांत लॉयल्का, मारिया डोब्रीकोवा, रफिक दोसानी, इश्क फ्रामिन, कैथेरिन कूहन्स एंड रांग वांग), स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, जुलाई 2013

हायर एजूकेशन इन इंडियाः इन सर्च आफ इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी। रीडिंग ऑन द इकानॉमिक एंड पॉलीटिकल एंड सोसायटी (इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली), हैदराबादः ओरियन्ट ब्लैक स्वान, 2013 (संपादन)

iqLrdkdkj eksukxzkQ

फाइनेंसिंग आफ सेकण्डरी एजूकेशन इन एशिया–पैसिफिक बैंकाकः यूनेस्को बैंकाक एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ब्यूरो आफ एजूकेशन, एजुकेशनल पालिसी एंड रिसर्च सीरीजः डिस्कशन डाक्यूमेंट नं. 4, (2013)

iqLrd@yis[k leh{kk%

विश्वविद्यालय रैंकिंग (जे.सी. शिन एट अल), जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 27 (2) (अप्रैल 2013)– 221–24

हायर एजुकेशन इन ग्लोबल सोसायटी (सं. डीबी जॉनस्टोन एट अल.), जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 27 (3) (जुलाई, 2013)ः 347–48

पीपीपी पाराडोक्स (पी गोपालन), जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 27 (4) (अक्टूबर 2013)ः 427–28

स्टूडेंट फाइनेंसिंग आफ हायर एजुकेशनः एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य (सं. डी.ई. हेलर और सी. कैलेंडर), जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 28 (1) (जनवरी 2014)ः 107–09

'kksèk i=@yis[k@fVIi.kh

ब्रिक देशों में उच्च शिक्षाः तुलनात्मक पैटर्न और नीतियां, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 48 (14) (6 अप्रैल, 2013)ः 41–47, http://www.epw.in/system/files/pdf/2013_48/14/ Higher_Education_in_the_BRIC_Member Countries.pdf; and http://www.wcces.com/CESI%202013%20 Presidential%20Address-pdf पर उपलब्ध

द कन्सैप्ट आफ पब्लिक गुड्स, द स्टेट एंड हायर एजुकेशन फाइनेंसः ए व्यू फ्राम ब्रिक्स, हायर एजुकेशन (प्रेस में 2014) (एम. कॉरनॉय, आई. फ्रॉमिन एंड पी. लॉयल्का के साथ) इसके अलावा एसएसआरएन आलेख सिरीज पर भी उपलब्ध (जून 2013) http://papers-ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2289126

द क्वालिटी आफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द ब्रिक कन्ट्री (पी. लॉयल्का, एम. कॉरनॉय, आई. फ्रॉमिन, रफिक दोसानी एंड पोयांग के साथ) (जुलाई 2013)

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2293331, उच्च शिक्षा (आगामी)

एजुकेशन इन द बजट (2013–14), इनफोकस (अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बंगलौर) 2013 (द बुलेटिन आफ द सेंटर फार पॉलिसी स्टडी 17(6) (अगस्त 2013): 17–19.

इंडिया रिफ्रामिंग एजुकेशन इन द नेओ–लिबरल ईरा, इन एजुकेशन पॉलिसी री–फार्म ट्रेंड इन जी20 मेंबर (एड. यान वांग)., स्प्रिंगर 2013, पृ. 33–53

साउथ–साउथ कोपरेशनः इंडिया प्रोग्राम आफ डवलपमेंट असिस्टेंट – प्रकृति, आकार और कामकाज, एशियाई शिक्षा और विकास अध्ययन, 2014,3 (1): 58–75

प्रौढ़ शिक्षाः इंडियन परसैप्शन इन इवाल्यूशनरी पर्सपैक्टिव, इन लिट्रेशी एंड एडल्ट एजुकेशनः स्लैक्ट रीडिंग (संपादन ए. मैथ्यू और जध्याला बी.जी. तिलक.) नई दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन/न्यूपा, 2014 पृ.सं. 1–18 (संयुक्त रूप से एक मैथ्यू के साथ)

ग्रोथ एंड रीजनल इनइक्वालिटी इन लिटरेसी इन इंडिया, इन लिट्रेसी एंड एडल्ट एजुकेशनः स्लैक्ट रीडिंग्स (सं. ए. मैथ्यू और जध्याला बी.जी. तिलक) नई दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन/न्यूपा, 2014 पृ.सं. 113–25

lxks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;

डीडीजीटडी वैष्णव कॉलेज, चेन्नई, में अप्रैल 12–13, 2013 को 'उच्च शिक्षा और आर्थिक विकास की गुणवत्ता' पर राष्ट्रीय सम्मेलन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित), में प्रमुख वक्ता

अगली पीढ़ी के विश्वविद्यालय, 'भारत में उच्च शिक्षा के लिए रोडमैप, गुजरात और निरमा युनिवर्सिटी, नॉलेज कंसोर्टियम पर अहमदाबाद, में 17 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्ण वक्ता

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मुंबई, में सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर एक गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख वक्ता, 20 अप्रैल, 2013

शिक्षा विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, में 6–7 जून, 2013 को 'पूर्वोत्तर भारत में विकास' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, में विशेष व्याख्यान,

'भारत के लिए शैक्षिक दृष्टिः रणनीति और कार्य पर विचार' पर संगोष्ठी में परिचर्चाकार, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली, 15–16 जुलाई, 2013

भवन्स कॉलेज, मुंबई, में 11–12 सितंबर, 2013 को 'उच्च शिक्षाः दिशात्मक प्रोत्साहन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्ण वक्ता

आईजीआईडीआर, मुंबई के रजत जयंती समारोह संगोष्ठी में मानव विकास सम्मेलन में एक आलेख प्रस्तुत किया, 26–28 सितम्बर, 2013

आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद, में 6 दिसंबर, 2013 को आयोजित 'बचपन गरीबी', गोलमेज के एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली, दिसंबर 17–18, 2013 को चौथा आईजीसी आईएसआई भारत विकास नीति सम्मेलन, एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की

भारतीय आर्थिक संघ, मीनाक्षी विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, की 96 वीं वार्षिक सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र में परिचर्चाकार 27–29 दिसंबर, 2013

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता, में दिसंबर 28–30, 2013 को भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन में एक पूर्ण और तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की और समापन भाषण दिया।

यूएसआईपी–सीआरडीडीपी वार्षिक सम्मेलन, नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014 को समावेशी उच्च शिक्षा की रूपरेखा पर व्याख्यान

इंदिरा गांधी महिला कॉलेज, कटक, में 30 जनवरी, 2014 को बारहवीं योजना में उच्च शिक्षाः समस्याएं और संभावनाएं पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण

फरवरी 21–22, 2014 को श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान प्रशांति निलयम में 'भारतीय अर्थव्यवस्था' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेष व्याख्यान

vrjk"Vªh;

'तुलनात्मक शिक्षा' पर 15वें विश्व कांग्रेस में एक आलेख प्रस्तुत किया और दो तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता की, ब्यूनस विश्वविद्यालय आयर्स, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, 24–28 जून, 2013

शैक्षिक विकास नेटवर्क, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, हिरोशिमा, जापान, में जुलाई 22–24, 2013 को अफ्रीका एशिया विश्वविद्यालय वार्ता की दूसरा महासभा और रिसर्च बैठक

विश्व कांग्रेस में एक पूर्ण चर्चा संबोधन और परिचर्चाकार माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा की पहुंचः शिक्षा से बंचितों को शिक्षा की सुलभता एक्सेस नेटवर्क, लंदन, मांट्रियल (कनाडा), शिक्षा के वित्तपोषण पर एक समानांतर सत्र में एक प्रस्तुति दी, 07–10 अक्तूबर, 2013

शिक्षा अनुसंधान पहल (इरी नेट), यूनेस्को, बैंकाक, अक्टूबर 17–19, 2013 को 'उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा से संक्रमण' पर 2013 की वार्षिक बैठक में आलेख प्रस्तुत

'शिक्षा नीति और शोध' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान संस्थान, बीजिंग, चीन, में 29 अक्टूबर 2013 को आलेख प्रस्तुत

चीन अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा सम्मेलन में मुख्य भाषण, चीन उच्च शिक्षा, निन्गवो, चीन, नवम्बर 1–3, 2013

उच्च शिक्षा नीति कार्यशाला, विश्वविद्यालय सैन्स मलेशिया और आईपीपीटीएन, कुआलालंपुर, 14 नवंबर, 2013

'सार्वजनिक नीति और प्रशासन' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड, केरल, में फरवरी 12–14, 2014 को मुख्य व्याख्यान

तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, टोरंटो, कनाडा, के 58 वें वार्षिक सम्मेलन में 10–14 मार्च 2014 को विश्वविद्यालय परिचर्चाकार

0;k[;ku fn;k

''भारतीय उच्च शिक्षा में संकटः संस्थाएं, नीतियां और नया ज्ञान' पर विशेष व्याख्यान, राष्ट्रीय उन्नत अध्यापन संस्थान, बंगलौर, अप्रैल 4–5, 2013

शिक्षांश ए.एन. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना, में 7 सितंबर, 2013 को 'शिक्षा का अधिकार' पर डॉ मदन मोहन झा स्मारक व्याख्यान

'भारत में निजी उच्च शिक्षा', 14 सितंबर 2013, को डा रामनाथम स्मारक व्याख्यान, पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स, नई दिल्ली

अजीम प्रेमजी स्कूल शिक्षा/टाटा समाज विज्ञान संस्थान, हैदराबाद में भारत में उच्च शिक्षा, पर सार्वजनिक व्याख्यान, 19 दिसंबर, 2013

lkoltfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा में वित्तीय सांख्यिकी पर समिति, नई दिल्लीरू मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य, कार्य समूह, 71वां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नई दिल्लीः राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, भारत सरकार

अध्यक्ष, शिक्षा अनुसंधान समिति, सामाजिक भारतीय विज्ञान अकादमी

सदस्य, शैक्षणिक परिषद, बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय गया

सदस्य, गीतम विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यक्रम समीक्षा समिति, (भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की भारतीय परिषद)

सदस्य, शैक्षणिक समिति, शैक्षिक अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, पुणे

सदस्य, शैक्षणिक समिति, मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य, संचालन समूह, शिक्षा अनुसंधान पहल, बैंकॉकः एशिया एवं प्रशांत यूनेस्को (2013 अक्टूबर)

U;kik d ckgj ç[;kr fudk;k dh lnL;rk

सदस्य, कार्यकारी समिति, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी

बोर्ड के सदस्य, एशिया तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी

सदस्य, विश्व शिक्षा फोरम (शिकागो, संयुक्त राज्य अमरीका)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, कंपेयर ए जर्नल आफ कम्परेटिव एजुकेशन (इंग्लैंड)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, हायर एजुकेशन पालिसी

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, पीबॉडी जर्नल आफ एजुकेशन (बंडरबिल्ट युनिवर्सिटी, अमरीका)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, एशियन अफ्रीकन जर्नल आफ इकानमिक्स एंड इकोनेमेट्रिकस (पांडिचेरी)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, कांटेमपोरेरी एजुकेशन डायलाग (बैंगलोर)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, सोशल चेंज (नई दिल्ली)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, ग्रासरूट्स गवनेंस जर्नल (तिरुपति)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, इंडियन जर्नल आफ ह्यूमन डवलपमेंट, नई दिल्लीः मानव विकास संस्थान

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, आईएएसएसआई क्वार्टलीः कांट्रब्यूशंस टू इंडियन सोशल साइंसेज (नई दिल्ली)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, जर्नल आफ सोशल एण्ड डवलपमेंट (नई दिल्ली)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, जर्नल आफ सोशल इकानमिक डवलपमेंट. बैंगलोरः सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, राजगिरी जर्नल आफ सोशल चेंज (केरल)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, एशियन पैसिफिक जर्नल आफ एजुकेटर्स एंड एजुकेशन यूनिवर्सिटी सैन मलेशिया

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, एशियन एजुकेशन एंड डवलपमेंट स्टडीज़ (इमेराल्ड पब/हांगकांग विश्वविद्यालय)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, एशियन पैसिफिक जर्नल आफ सिंगापुर (सिंगापुर)

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, स्प्रिंगर पुस्तक श्रृंखला, 'एशिया में उच्च शिक्षाः गुणवत्ता, उत्कृष्टता और अभिशासन'

; tkyh tklfQu

çdk'ku

i|Lrd@vè;k;%

''चेंजिंग फेस आफ ह्यूमन रिर्सोस डवलपमेंट'' इन द एडीटेड बुक एजूकेशन एंड ससटेनेबल डवलपमेंट, शिप्रा पब्लिकेशंस

''21वीं सदी स्कूल्स' एक्प्लोरिंग इफिकेसी आप पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स इन इंडिया'' इन एडीटेड बुक एजुकेशनल लीडरशिप एंड लीडरशिप एजुकेशन इन एशिया, युनिवर्सिटी आफ फिलीपीन्स प्रैस

'kks/k i=@vkys[k@fVIi.kh

''फीमेल फोटिसाइड इन कन्टम्पोरेरी इंडिया–इंक्रीजिंग जेंडर इनइक्वालिटी'' (फ्रेंन्च) रियूनियनः एल'हारमेतन (ब्यूरो ट्रान्सवर्सल डेस कोलाक्स, डे ला रीसर्च एट डेस पब्लिकेशन्स)

vuqla/kku v/;;u

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत विद्यालय अनुदान के उपयोग पर अध्ययन

dk;Z'kkyk,@lEesyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;kstu

dk;Øe leUo;d d : i e%

उच्च शिक्षा के वित्त और योजना का प्रबंधन, न्यूपा, 11–15 नवंबर, 2013 में प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेटुकुरी पी. एस. राजू के साथ)

स्कूल वित्त का प्रबंधन और योजना, न्यूपा, 09–13 दिसम्बर, 2013, उन्मुखीकरण कार्यक्रम

lalk/ku 0;fä d : i e dk;Øe%

अभिविन्यास योजना में कार्यक्रम और उत्तर पूर्वी राज्यों, नेहू, शिलांग, के लिए स्कूल वित्त का प्रबंधन (वेटुकुरी पी.एस. राजू के साथ) मेघालय, 25–29 नवम्बर, 2013

çf'k{k.k lkexh vkj ikBîØe dk fodkl vkj f'k{k.k

12वीं योजना और (संयुक्त रूप से (वेटुकुरी पी.एस. राजू के साथ) उच्च शिक्षा वित्त का प्रबंधन, न्यूपा, नवंबर 11–15, 2013 में प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा के लिये, एक चर्चा पत्र

जेंडर बजटिंग का महत्व

पूर्वोत्तर राज्यों, नेहू, शिलांग, मेघालय, के लिए स्कूल वित्त के प्रबंधन और योजना में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए (वेटुकुरी पी.एस. राजू के साथ) ''आरटीई–का

प्रयोग संकेतकों के तहत स्कूल विकास योजना'' 25–29 नवम्बर, 2013

स्कूल शिक्षा में वित्तीय सुधार

स्कूल वित्त की योजना प्रबंधन, में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए 'शिक्षा में जेंडर बजटिंग' न्यूपा, 09–13 दिसम्बर, 2013

vU; 'kS{kf.kd xfrfof/k;k

शिक्षा पाठ्यक्रम में वित्तीय योजना और प्रबंधन (कोर्स 109) 34वें आयोजन में संयोजक शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (डेपा) में डिप्लोमा कार्यक्रम 2013–14

एम.फिल. / पी–एच.डी. के लिए 'वैश्वीकरण और शिक्षा' पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के संयोजक. (पाठ्यक्रम प्रभारी के रूप में)

lkoZtfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

सुश्री भावना अरोड़ा, पीएच.डी., सलाहकार, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (सीआईई), दिल्ली विश्वविद्यालय

सुश्री पूजा सिंह, पीएच.डी., आरजीएनएफ–एसआरएफ के रूपांतरण के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ के रूप में, दिल्ली विश्वविद्यालय (सीआईई)

इग्नू में एम.ए. शिक्षा के लिए परीक्षक

पी–एच.डी., सलाहकार समिति, सदस्य शिक्षा शोध विषय पर शिक्षा विभाग, दिल्ली केन्द्रीय संस्थान, 'सर्व शिक्षा अभियान और नागालैंड में उत्पादीकरण कार्यक्रम पर इसका प्रभाव'

पी–एच.डी., सलाहकार समिति, सदस्य शिक्षा शोध विषय, शिक्षा, दिल्ली केन्द्रीय संस्थान विभाग, 'उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा विकासः नीतियां, मुद्दे और चुनौतियां'

U;kl ds ckgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

महिला विश्व कांग्रेस

fofHkUu ç'kklfud vkSj 'kS{kf.kd lfefr;ksa dh lnL;

सदस्य, एम.फिल. / पी–एच.डी. की संचालन समिति. कार्यक्रम (2006 के पश्चात)

सदस्य, शैक्षणिक परिषद (2006 के बाद)

सदस्य, प्रबंधन बोर्ड (2011 के बाद)

सदस्य, अनुदान सहायता समिति, न्यूपा

ih- xhrk jkuh

çdk'ku

'kks/k i=@ys[k@fVIi.kh

''चेंजिंग लीडरशिप आफ हायर एजुकेशन इन तमिलनाडु'', इन वी.के. नटराज एंड ए. वैद्यनाथन (सं.) डवललपमेंट नैरेटिव्सः द पालीटिकल इकॉनमी आफ तमिलनाडु, 2014

''इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन आफ इंडिया गर्वनमेंट सब्सिडीज आन एजुकेशन,'' इंटरनेशनल जर्नल आफ एजुकेशन एंड इकानमिक डवलपमेंट, 2014, वाल्यूम 5, पीपी 1–39

''ए रिव्यू आफ फंडिंग एंड प्रोग्रेस आफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद सर्व शिक्षा अभियान इन कर्नाटक'', इंडिया मैन एंड डवलपमेंट, 2013, वाल्यूम 35(2), पीपी. 99–120

''फंड फ्लो पैटर्न एंड फाइनैंशियल ऐफिशियन्सी आफ रिसोर्स युटिलाइजेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान इन गुजरात'', अर्थशास्त्रः इंडियन जर्नल आफ इकॉनमिक एंड रिसर्च, 2013, वाल्यूम 2, पीपी 12–23

vuqla/kku v/;;u

12वीं योजना अवधि के लिए 11वीं योजना से जारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन करने हेतु।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत संसाधन के फंड प्रवाह पैटर्न और उपयोगः भारत में फाइनेंसिंग प्राथमिक शिक्षा पर अध्ययन की रिसर्च रिपोर्ट पूर्ण

l xk"Bh@lEeyu@dk;l'kkyk e Hkkxhnkjh

आलेख प्रस्तुत 'भारत में शिक्षा ऋण और वित्तपोषण उच्च शिक्षाः 33वां स्कॉच फाउंडेशन, नई दिल्ली, पीएचडी हाउस, नई दिल्ली, 3–04 सितम्बर को आयोजित शिखर सम्मेलन और 17 विचारकों और लेखकों का फोरम, 2013.

श्रम अर्थशास्त्र का भारतीय समाज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली, दिसंबर 16–18, 2013 के 55 वें वार्षिक सम्मेलन, 'भारत में आय और शिक्षा में असमानताएं' शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत किया।

अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, जनवरी 6–7, 2014 तक आयोजित 'विकास अर्थशास्त्र में समकालीन मुद्दों' पर 23वां वार्षिक सम्मेलन, 'भारत में आय और शिक्षा में असमानताएं' शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत किया.

dk;l'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;ktu

उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव, सितंबर 2013 प्रशिक्षण की योजना, कार्यक्रम और सहयोग में विश्वविद्यालय वित्त का प्रबंधन, समन्वित।

vU; 'k{kf.kd xfrfofèk;k

,e-fQy-@ih&,p-Mh- e f'k{k.k%

पीएच.डी. के लिए अनुसंधान मार्गदर्शन भारत में विदेशी शिक्षा प्रदाता के सहयोगी तंत्र

Mik dk;Øe e f'k{k.k%

शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन (दस सत्र के साथ क्रेडिट कोर्स) पर कोर्स के लिए संयुक्त संयोजक के रूप में, शिक्षा क्षेत्र में वित्त पोषण और वित्तीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर सत्र।

vkbMik dk;Øe e f'k{k.k%

शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन (बीस सत्र के साथ दो क्रेडिट कोर्स) पर कोर्स के लिए संयोजक के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण और वित्तीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर सत्र और प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम काम का मूल्यांकन किया.

oVdjh ih-,l- jktu

çdk'ku

iLrd@vè;k;%

चैप्टर आन ''कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन एंड एजुकेशन फार आलः ए केस स्टडी आफ आसाम'' 'नई सहस्राब्दी के लिए शिक्षा' पुस्तक में (संपादन मीनाक्षी सिंह और आलोक गार्डिया) वाराणसीः नूतन प्रकाशन नवंबर 2013, पीपी. 336–348.

चैप्टर आन ''एजुकेशन फार ऑल इन द नार्थ ईस्टर्न स्टेट आफ इंडियाः चैलेजेज फार द अफैक्टिव इंप्लीमेंटेशन आफ आरटीई एक्ट, 2009'' पुस्तक राइट टू एजुकेशनः 'द वे फॉरवर्ड' (संपादन जयंत मेटे और अजीत मंडल)ः दिल्लीः एपीएच पब्लिशिंग कोरपोरेशन, फरवरी 2014.

'kkèk i=@y[k@fVIi.kh

मध्याह्न भोजन योजना, (ग्राम गुंटूर और महबूबनगर, आंध्र प्रदेश के जिलों में स्कूलों का अध्ययन) को लागू करने में स्कूल प्रबंधन समितियां और महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जर्नल आफ प्रोफेशनल स्टडीज़, पीपी 3 (1) (जून 2013) 148–154

माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षणः एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, जर्नल आफ नॉलेज 1 (2) (2013 दिसंबर)ः पृ. सं. 113–119.

सिक्किम में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक प्रबंधन इंटरनेशनल जर्नल ज्ञान भव, शिक्षक शिक्षा जर्नल, 1 (1) (2014 फरवरी)ः पृ. सं. 27–35

vulèkku vè;;u

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन हेतु केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय योजना का मूल्यांकन

गैर नामांकन एवं आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चरण में मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउटः एक तुलनात्मक अध्ययन

lxk"Bh@lEeyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

न्यूपा, नई दिल्ली, 27 अगस्त 2013 'उच्च शिक्षा में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध से निपटने' पर परामर्श में भाग लिया।

शिक्षा नीति विभाग, न्यूपा, नई दिल्ली, दिसंबर 16–17, 2013 के दौरान आयोजितः 'नीतियां और आचरण शैक्षणिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण' पर अनिल बोर्डिया मेमोरियल नीति संगोष्ठी में भाग लिया.

vUrjk"Vh;%

अर्थशास्त्र विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिसंबर 28–30, 2013 के दौरान विभाग द्वारा आयोजित 'शिक्षा, विविधता और लोकतंत्र', पर सीईएसई वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2013 में: 'गरीब छात्र और छात्रवृत्ति भारत में माध्यमिक शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई' पर एक आलेख प्रस्तुत किया.

'लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः समावेशन, इक्विटी और स्थिरता से संबंधित मुद्दों' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, न्यूपा द्वारा आयोजित, बिगुल संग्रह, नई दिल्ली, 6–8 मार्च, 2014.

dk;'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;kstu

उच्च शिक्षा वित्त का प्रबंधन और योजना समन्वयन, न्यूपा, नवंबर 11–15, 2013

पूर्वोत्तर राज्यों के लिये, नेहू, शिलांग, मेघालय, 25–29 नवम्बर, 2013 में अभिविन्यास योजना कार्यक्रम और स्कूल वित्त प्रबंधन के लिए समन्वयक

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर डी.डी.पी.आई. और बी.ई.ओ.एस. के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन, (शैक्षिक प्रशासन विभाग के सहयोग से) बंगलौर, कर्नाटक, 7–8 जनवरी, 2014

çf'k{k.k lkexh vkj ikBîØe fodfl r vkj fu"ikfnr

डेपा अनुसंधान पर आधारित रिसर्च 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक विकास पर शोध अध्ययन'

डेपा अनुसंधान पर आधारित रिसर्च सार 'भारत में शैक्षिक वित्त पर शोध अध्ययन'

भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों (सांख्यिकीय जानकारी) में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति.

vU; 'k{kf.kd xfrfofèk;k

श्री दीपेंद्र कुमार पाठक, एम.फिल. को मार्गदर्शन, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का अध्ययन प्राथमिक स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य'

डा. अनिल कुशवाहा, जिला देवास, मध्य प्रदेश के स्कूलों के श्रेष्ठ निष्पादन के साथ टीचर क्षमता और शिक्षक व्यवहार पर मार्गदर्शन दिया

बैकालियू विश्वविद्यालय में गैर अंग्रेजी शिक्षण प्रेरणा और दृष्टिकोण प्रभावित करने वाले कारक पर श्री क्वान बुई मानहा, वियतनाम, आईडेपा प्रतिभागी को दिया मार्गदर्शन

lkoZtfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

राष्ट्रीय सह योग्यता साधन छात्रवृत्ति योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना (एनएमएमएसएस) के मूल्यांकन अध्ययन. रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(डॉ गीता रानी के साथ) शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन.स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

डेस्क मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में पीएबी बैठकरू राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एकीकृत वार्षिक कार्य योजना बजट 2014–15 (आंध्र प्रदेश)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में डेस्क मूल्यांकन और पीएबी बैठकः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एकीकृत वार्षिक कार्य योजना बजट 2014–15 (छत्तीसगढ़)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (एनआईओएस) और टीएसजी (आरएमएसए) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली की परियोजना मंजूरी बोर्ड में भाग लिया।

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

सदस्य, एम.फिल. की समिति

सदस्य आयोजन पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा

समन्वयक, पाठयक्रम 213: शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में संगणक अनुप्रयोग (आईडेपा कार्यक्रम–2013)

पाठ्यक्रम के लिए टीम के सदस्य, 107: शैक्षिक योजना में कंप्यूटर के उपयोग के मात्रात्मक पहलु (डेपा कार्यक्रम–2013)

U;ik d ckgj ç[;kr fudk;k dh lnL;rk

सदस्य, भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी

सदस्य, शैक्षिक योजना के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (IIEP यूनेस्को), पेरिस, पूर्व छात्र

fofHkUu ç'kklfud vkj 'k{kf.kd lfefr;k dh lnL;rk

न्यूपा की सभी खरीद के लिए निविदा खोलने वाली समिति के सदस्य

न्यूपा की परियोजना पदों के लिये स्क्रीनिंग समिति के सदस्य

शैक्षिक नीति विभाग

vfouk'k dekj flg ¼foHkkxk/;{k½

çdk'ku

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh

डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेंशन एंड एजुकेशनः प्रास्पेक्ट्स एंड जर्नल आफ सोशल साइन्स एंड इकॉनामिक स्टड़ीज, वॉल्यूम (22), नं.–2, जुलाई से दिसंबर, 2012, पृ.सं. .66–77 आईएसबीएनः 0377–0508

'स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता पर कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में (शैक्षिक विचार की प्रासंगिकता) स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह (एसवीएचएस), नई दिल्ली, नवंबर 2013 द्वारा प्रकाशित पृ.सं. 100–04

द क्राइज़ेज आफ सोशल साइंस एजुकेशन इन इंडियाः इशूज़ एंड पर्सपेक्टिव 'विषय पर शोध पत्रश शिक्षा, विविधता और लोकतंत्र पर सीईएसआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता, दिसंबर 28–30, 2013

lxk"Bh@lEesyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स (एम.एड.), शिक्षा विभाग, बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, 4 मई, 2013 को पाठ्यक्रम रूपरेखा कार्यशाला

'सामाजिक विज्ञान का अध्यापन' पर राष्ट्रीय कार्यशाला, सामाजिक विज्ञान शिक्षा, विभाग एनसीईआरटी, नई दिल्ली, मई 7–8, 2013

कोहिमा, नगालैंड, में डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. के क्षमता निर्माण पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, 13–14 मई, 2013

राष्ट्रीय कार्यशाला जम्मू एवं कश्मीर में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन और योजना पर, श्रीनगर, 24–28 जून, 2013

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विभाग में 'बाहर के स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग', एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2013 को कार्यशाला

शिक्षा में गुणात्मक अनुसंधान के तरीके, न्यूपा, नई दिल्ली, 22 जुलाई–2 अगस्त 2013 को ओरिएंटेशन कार्यशाला

दो दिवसीय शिक्षा में मुद्दे और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा मिलो, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पत्रकारिता और संचार, भोपाल, अक्टूबर 5–6, 2013

अनिल बोर्डिया 'शिक्षा और सामाजिक अधिकारिताः नीति सुधार और आचरण' पर राष्ट्रीय नीति संगोष्ठी, न्यूपा, नई दिल्ली, दिसंबर 16–17, 2013

गुवाहाटी (असम), फरवरी 3–7, 2014 'पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी पर उन्मुखीकरण कार्यशाला.

शिक्षा में इक्विटी और समावेशन पर यूजीसी राष्ट्रीय संगोष्ठी, पटना महिला कॉलेज, पटना, 6–7 मार्च, 2014.

vrjk"Vªh;%

शिक्षा, विविधता और लोकतंत्र पर सीईएसआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षा का संकटः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य विषय पर पेपर प्रस्तुत किया, भारतीय सांखयिकी संस्थान, कोलकाता, दिसंबर 28–30, 2013

उच्च शिक्षा में पहुंच और इक्विटी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सामाजिक विज्ञान, मुंबई, मार्च 3–4, 2014, टाटा इंस्टीट्यूट.

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 'लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः इक्विटी, समावेशन और स्थिरता', न्यूपा, कुतुब होटल, नई दिल्ली, मार्च 6–8, 2014 तक आयोजित

lkoZtfud fudk;¨a d¨ ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

अर्थशास्त्र, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम विभाग

सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, जेएनयू, नई दिल्ली केंद्र

जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, जेएनयू, नई दिल्ली

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, स्कूल आफ एजुकेशन

इग्नू, नई दिल्ली, स्कूल आफ एजुकेशन

हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्कूल आफ एजुकेशन

U;wik d¨ ckgj ç[;kr fudk;¨a dh lnL;rk

सदस्य, वोल्फसन कॉलेज सोसायटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

सदस्य, रिसर्च छात्रों की सोसायटी, शिक्षा लंदन संस्थान विश्वविद्यालय

सदस्य, अध्ययन बोर्ड, शिक्षा स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

सदस्य, भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी

सदस्य, भारतीय सामाजिक सोसायटी

ohjk xqIrk

çdk'ku

iqLrd@v/;k;%

वोकेशनल आफ एजुकेशन ग्लोबल पब्लिशर्स, मार्च 2014, आईएसबीएनः 978–93–80570–49–5

'k¨/k i=@ys[k@fVIi.kh

पॉलिसी इंटेन्टस एंड पालिसी इन्स्ट्रूमेंट : ए केस स्टडी आफ सीबीएसई इंटरनेशनल जर्नल आफ ह्यूमनिटीज एंड एप्लाइड साइंसेज (आईजेएचएएस). वॉल्यूम. 2, नं. 5, 2013 आईएसएसएन 2277–4386

एक राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार, यूरोपीय साइन्टेफिक जर्नल, जून 2013 आईएसएसएन 1857–7881 (प्रिंट). ई आईएसएसएन 1857–7431 (संस्करण 2)

lfeukj@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;%

इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लि. द्वारा आयोजित ई–इंडिया 2013

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भारत सरकार और. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर द्वारा आयोजित 23–24 जुलाई, 2013

उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न, न्यूपा, 27 अगस्त, 2013

कार्यशाला, एससीईआरटी, गुड़गांव, जनवरी 20–21, 2014, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए संकेतक डिजाइन

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देने हेतु हैंडबुक की तैयारी के लिए राष्ट्रीय परामर्श, एनसीईआरटी, 22–23 जनवरी, 2014

भविष्य की नीतियां पर इकॉनमिक टाइम्स द्वारा नेशनल कांफ्रेंस, 26–27 फरवरी, 2014

एसोचैम, 4 मार्च, 2014 तक आयोजित विकास के लिए आईसीटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन

संभावनाएँ और चुनौतियांः हर्षित अधिगम, महाराजा सूरजमल इंस्टिट्यूट, दिल्ली, राष्ट्रीय संगोष्ठी 29 मार्च, 2014

vrjk"Vh;%

अंतर्राष्ट्रीय अंतर अनुशासनात्मक सम्मेलन, एएचसी अज़ोरेस, पुर्तगाल, 24–26 अप्रैल, 2013

दक्षिण एशियाई पर संगोष्ठी जेंडर आईसीटी, और शिक्षा, यूनेस्को और इंटेल, दिल्ली, 24–26 सितम्बर, 2013

मानवता, भूगोल और अर्थशास्त्र (आईसीएचजीई 2013), दुबई में 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (यूएई), अक्टूबर 6–7, 2013

इक्विटी, समावेशन और स्थिरताः लोकतंत्र, शिक्षा और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, न्यूपा, मार्च 6–8, 2014

çf'k{k.k lkexh vkj ikB;Øe fodflr vkj fu"ikfnr

विशेष बच्चों के विशेष प्रशिक्षण के प्रबंधन पर आरटीई कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण सामग्री, न्यूपा, 09–13 सितम्बर, 2013

एनसीईआरटी के लिए आरटीई हैंडबुक

हरियाणा सरकार के लिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए सीसीई मैनुअल

vU; 'k{kf.kd xfrfof/k;k

विश्व बैंक संस्थान, शिक्षक नीति के आयाम विषय पर एक ई–पाठ्यक्रम पूर्ण 11 नवंबर से 20 दिसंबर 2013,

lkotfud fudk;¨ d¨ ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

जामिया मिलिया इस्लामिया, को आयोजित शिक्षा में पुनश्चर्या के लिए संसाधन व्यक्ति, 10 अप्रैल – 2 मई, 2013

सदस्य, समीक्षा समिति, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 16 अप्रैल, 2013 आंध्र प्रदेश एसईटी एजेंसी का आकलन

सदस्य, आयुक्त एवं स्कूल शिक्षा और पूर्व–पदेन परियोजना निदेशक आरएमएसए के निदेशक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश मई 7–11, 2013 के दौरान आंध्र प्रदेश, द्वारा आरएमएसए तहत के स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए समिति साक्षात्कार

सदस्य, शैक्षणिक परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), 24 मई 2013

सलाहकार टीएसजी आरएमएसए, के पद के लिए साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञ. सीआईएल, 24 मई 2013

सर्व शिक्षा अभियान, एडसिल के लिए सलाहकार के चयन के लिए विषय विशेषज्ञ. सीआईएल, 24–25 जुलाई, 2013

एडसिल के लिए सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान के पद के लिए साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञ. सीआईएल, 1 अक्टूबर 2013

वायुसेना मुख्यालय, दिल्ली, नवंबर 28,2013 द्वारा आयोजित शिक्षा संगोष्ठी के लिए संसाधन व्यक्ति,

स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण पर पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन एनसीईआरटी, भोपाल, जनवरी 7–10, 2014 तक आयोजित राज्यों से, आरटीई के तहत उपयुक्त उम्र में कक्षाओं में भर्ती

डिजाइनिंग संकेतकों और डीएनएस शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना, के प्रभाव मूल्यांकन के लिए डेटा स्रोत के लिए विशेषज्ञ एससीईआरटी, हरियाणा, जनवरी 20–21, 2014

सदस्य, एनसीईआरटी, जनवरी 21–23 2014 तक आयोजित विशेष आवश्यकताओं के साथ बच्चों पर ध्यान देने के साथ आरटीई हैंडबुक की तैयारी के लिए राष्ट्रीय परामर्श बैठक

प्रबंधन बोर्ड (यूजीसी द्वारा गठित), सदस्य, के.जे. सोमैया कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय, 31 जनवरी 2014

तकनीकी शिक्षा के लिए भारतीय समाज द्वारा आयोजित 'प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण शिक्षाशास्त्र' पर राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति, फरवरी 19–21, 2014

प्रांतीय शिक्षा निदेशकों और अफगानिस्तान से शिक्षा प्रबंधकों, के एक समूह के लिए पर्यावरण शिक्षा के लिए संसाधन व्यक्ति, अहमदाबाद, केंद्र द्वारा आयोजित शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में परिणाम आधारित प्रबंधन श्पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10 मार्च, 2014

U;ik d ckgj ç[;kr fudk;¨ dh lnL;rk

सदस्य, प्रबंधन बोर्ड, के.जे. सोमैया कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय

सदस्य, शैक्षणिक परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)

सदस्य, पीजी कॉलेज शासी निकाय, तमिलनाडु

,l-d- efyd

lfeukj@lEeyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

vrjk"Vh;

इक्विटी और स्थिरता समावेश से संबंधित लोकतंत्र, शिक्षा और विकास के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दूत के रूप में काम किया और न्यूपा, मार्च 6–8, 2014 तक आयोजित अन्य शैक्षणिक गतिविधियो में भाग लिया।

अकादमिक स्टाफ कॉलेज (एएससी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, मार्च तक आयोजित सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान क्रियाविधि पर रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया 31 मार्च–19 अप्रैल 2013

प्रभारी डेपा और आईडेपा के लिए विषयगत संगोष्ठी का कोर्स

डेपा और आईडेपा के लिए परियोजना का काम की देखरेख

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;¨xnku

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन (न्यूपा पत्रिका) के लिए संपादकीय सहायता

uj'k dekj

lxk"Bh@lEeyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;

शिक्षा नीति विभाग, न्यूपा, नई दिल्ली, दिसंबर 16–17, 2013 के दौरान आयोजित अनिल बोर्डिया राष्ट्रीय नीति संगोष्ठी में भाग लिया

vrjk"Vh;

न्यूपा, नई दिल्ली, मार्च 6–8, 2014 के दौरान आयोजित समावेशन, इक्विटी और स्थिरता से संबंधित मुद्दे लोकतंत्र, शिक्षा और विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

dk;'kkyk@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;¨tu

शिक्षा नीति विभाग, न्यूपा, द्वारा आयोजित शिक्षा में गुणात्मक अनुसंधान के तरीके पर कार्यशाला 22 जुलाई–2 अगस्त, 2013

vU; 'kf{kd xfrfof/k;¨

66वें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम में भाग लिया अकादमिक स्टाफ कॉलेज, बीएचयू, वाराणसी, 3–30 जनवरी, 2014

34वें डेपा शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण, न्यूपा नई दिल्ली

f'k{k.k dk;Z

शिक्षा और विकासः एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (कोर्स नं 202) – 30वां आईडेपा

प्रतिभागी संगोष्ठी (कोर्स नं 212) – 34वां डेपा

lko tfud fudk;¨ d¨ ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

बाहरी मूल्यांकनकर्ता और एम.फिल. के लिए आयोजित सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर निबंध, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र

बिहार, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यों के लिए आरएमएसए एकीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की समीक्षा की

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;¨xnku

संयोजक, डेपा पाठ्यक्रम में संशोधन और पुनर्गठन के लिए समिति के तहत सामाजिक संदर्भ और भागीदार संगोष्ठी (कोर्स नं 101 और 112) पर उप समिति

संयोजक – न्यूपा संवर्धन

सदस्य, 2014 न्यूपा के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए संकाय विकास पर उप समूह और अनुसंधान समिति

सदस्य, प्रवेश समिति और छात्र कल्याण समिति, न्यूपा.

स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा विभाग

ufyuh tujktk ¼foHkkxk/;{k½

çdk'ku

'kks/k i=@ys[k@fVIi.kh

आरटीई और शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे: जर्नल आफ नेशनल ह्यूमन राईट कमीशन वॉल्यूम. 12 पृ. 201–224

jk"Vªh;

14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा में क्या संस्थापक 0–6 आयु समूह को शामिल करने का इरादा रखते हैं? शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत भारत के लिए शैक्षिक दृष्टि: रणनीति और कार्य पर विचार संगोष्ठी में, सामाजिक विकास, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 16 जून, 2013 के लिए परिषद द्वारा आयोजित

ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल, 27 जून, 2013 को आयोजित लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत बनाने में लॉ स्कूल की भूमिका पर एक सम्मेलन में आलेख प्रस्तुत

दिल्ली न्यायिक अकादमी, जनवरी की एक बैठक में भाग लिया, 2014

प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में बाल अधिकार संरक्षण, नई दिल्ली, 14–15 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया,

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देते हुए आरटीई हैंडबुक की तैयारी के लिए राष्ट्रीय परामर्श में भाग लिया, 21–23 जनवरी 2014 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

डीएचजेएस और डीजे (मिश्रित समूह), 1 फरवरी 2014 को अधिकारियों के लिए सामाजिक संदर्भ अधिनिर्णय पर न्यायिक संगोष्ठी में, रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया,

सामाजिक समानता और समावेशन (सीएसईआई), वायएमसीए सभागार, केंद्र द्वारा आयोजित खंड 12(1)सी की शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैपिंग के कार्यान्वयन, पर राष्ट्रीय परामर्श में, रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।

जोश, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 27 मार्च, 2014 को आयोजित दिल्ली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट के विमोचन में भाग लिया

ऑक्सफेम और आरटीई फोरम, भारत पर्यावास केन्द्र, 28 मार्च, 2014 तक आयोजित आरटीई के संदर्भ में शिकायत निवारण विषय पर परामर्श में भाग लिया

vrjk"Vªh;

शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान, 11 अक्तूबर, 2013 अध्ययन के लिए केंद्र द्वारा आयोजित 165वें सीआईसीई ओपन सेमिनार में भारत में शिक्षा के अधिकार का संस्थानीकरण शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत

शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान, अक्टूबर 23, 2013 अध्ययन के लिए केंद्र द्वारा आयोजित 165वें सीआईसीई ओपन सेमिनार में 'भारत में शिक्षा के अधिकार के इतिहास का शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत

शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान, 12 नवंबर, 2013 अध्ययन के लिए केंद्र द्वारा आयोजित 166वे सीआईसीई ओपन संगोष्ठी में

मुद्दे: कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियं और आरटीई 2009 शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत

शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान, दिसंबर में अध्ययन के लिए केंद्र द्वारा आयोजित, हिरोशिमा विश्वविद्यालय सेन्स युनिवर्सिटी मलेशिया छात्र फोरम में भाग लिया। 2–6 दिसंबर, 2013

शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान, 12 दिसंबर, 2013 को अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित 167वें सीआईसीई ओपन संगोष्ठी में स्कूलों में आर्थिक रंगभेद के खिलाफ भारत के नए जनादेश आलेख प्रस्तुत

क्यूशू विश्वविद्यालय, शिक्षा संकाय, 15 दिसंबर, 2013 में क्यूशू शाखा द्वारा आयोजित जापान के दक्षिण एशियाई समाज विषय पर एक संगोष्ठी, पर एक आलेख प्रस्तुत किया.

lkoZtfud fudk;¨a d¨ ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

31 दिसंबर 2013 को, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान, द्वारा 1 सितम्बर से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अध्ययन के लिए केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य

अतिथि संपादक, शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जर्नल (आईएसएसएन 1344–2996 वॉल्यूम 16, नंबर 1, स्पेशल इशू आनद राईट टू एजुकेशन (मार्च 2014)

U;kik dk ckgj ç[;kr fudk;¨a dh lnL;rk

सदस्य, विभाग सलाहकार बोर्ड (डीएबी), सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग (एनसीईआरटी) न्यूपा,

uhye lwn

çdk'ku

iqLrd@v/;k;

मीनिंगफुल एक्सेज़ एंड क्वालिटी आफ प्री–स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, जर्मनी: लैपलैम्बर्ड 2014, पृ. सं. 125, आईएसबीएन 978–3–8473 4013–3

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh

एनहान्सिंग क्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन विद स्टुडेंट डाइवरसिटी : एक्सपिरियंसेज़ फ्राम इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन की कार्यवाही, कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2013 में ऑनलाइन प्रकाशित http://www.cluteinstitute.com/ कार्यवाही/2013 आलेख/लेख: 20152 पीडीएफ

lfeukj@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

30 जून, 2013 सेन्टम लर्निंग, लखनऊ, द्वारा आयोजित स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए एक कार्यशाला में समावेशी शिक्षा पर स्कूल प्रशासकों के लिए संभावनाएँ और चुनौतियां

स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ राज्य परामर्श में भाग लिया और प्रारंभिक संबोधन रायपुर, 12 सितम्बर 2013

dk;Z'kkyk,@lEesyu@çf'k{k.k dk;ZØe dk vk;¨tu

मुख्य व्यक्ति के रूप में नागालैंड के शैक्षिक प्रशासकों के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में शिक्षा की पहुंच, भागीदारी और गुणवत्ता पर बात की कोहिमा, 13–14 मई, 2013

सलवान पब्लिक ट्रस्ट, 20 मई, 2013 शिक्षकों के लिए चुनौतियां स्कूलों में सोच और समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने पर एक दिवसीय परामर्श, न्यूपा, 27 अगस्त, 2013 के आदेश पर, संगठित।

उद्घाटन भाषण तथा अरुणाचल प्रदेश के जिला और ब्लॉक स्तर के शैक्षिक प्रशासकों के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन, 18 सितंबर 2013।

त्रिपुरा के जिला और ब्लॉक स्तर के शैक्षिक प्रशासकों के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन किया और 15 नवम्बर 2013 को स्कूल शिक्षा में शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका पर व्याख्यान।

सिक्किम के शैक्षिक प्रशासकों के राज्य सम्मेलन के आयोजन के लिए नेतृत्व और सिक्किम, गंगटोक, 9 दिसंबर, 2013 में शैक्षिक प्रशासकों द्वारा मौजूदा चुनौतियों पर प्रशासकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया।

कार्यशाला आयोजित समावेशी शिक्षा के प्रतिः क्लासरूम में चुनौतियों के समाधान, सलवान पब्लिक ट्रस्ट, फ़रवरी 17, 2014

vU; 'kS{kf.kd xfrfof/k;k

एम.फिल. / पी–एच.डी. में अनुसंधान क्रियाविधि (सीसी–2) पर कोर पाठ्यक्रम का भाग अध्यापन कार्यक्रम और डेपा

lkoZtfud fudk;¨a d¨ ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

एम.एस.सी. के प्रश्न पत्र की मॉडरेशन परीक्षा

पाठ्यक्रम परामर्श और परिवार थेरेपीः बुनियादी अवधारणाओं और सैद्धांतिक दृष्टिकोण; अनुसंधान के तरीके और सांख्यिकी, इग्नू, 29 अप्रैल 2013

24 जून, 26 सितंबर और 11 नवंबर 2013 को बाल विकास, इग्नू में डॉक्टरेट अनुसंधान परियोजना के समर्थित समीक्षा

महिलाओं के लिए अविनाशी विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, 9 जुलाई 2013 को मूल्यांकन, पी–एच.डी. शोध और वायवा–वोस आयोजित

दमन और दीव, 14 अक्टूबर, 2013 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सोसाइटी के कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया

संयुक्त परीक्षक, पत्र संख्या 1334, विकलांग विकास भाग द्वितीय, एमएससी (सेम. तृतीय), लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, 12 नवम्बर 2013

टीम सदस्य, 19–23 नवम्बर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का द्वितीय राष्ट्रीय मूल्यांकन, 2013

फुलब्राइट विशेषज्ञ (यूनिसेफ), 9 जनवरी, 2014 के लिए समीक्षा प्रक्रिया में योगदान

एमिटीः पैनल की ओर बढ़ते कदम महिला सशक्तीकरण की दिशा में लैंगिक संवेदीकरण पर सदस्य युनिवर्सिटी, नोएडा, 10 मार्च 2014

U;kl d¢ ckgj çk[;kr fudk;¨a dh lnL;rk

सदस्य, डॉक्टोरल रिसर्च समिति, बाल विकास, इग्नू

सदस्य, शैक्षिक जर्नल एवं मनोवैज्ञानिक शोध के लिए संपादकीय बोर्ड

सदस्य, भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद की कार्यकारी समिति

iz.kfr ikMk

çdk'ku

iqLrd@v/;k;%

चैप्टर आन अन्डरस्टेंडिंग द एजुकेशनल चेंज प्रोसेस एंड टीचर्स' वर्क'' इन 'ट्रांसफॉरमिंग टीचर्स वर्क ग्लोबलीः इन सर्च आफ बैटर वे फार स्कूल्स एंड देअर कम्यूनिटीज़ (सं. ऐजा किमोनेन एंड रैमो नवलैनेन) द नीदरलैंडः सेंज पब्लिशर्स, 2013 आईएसबीएनः 978–94–6209–468–0 (पेपरबैक). आईएसबीएन 978–94–6209–469–7. (हार्डबैक), पीपी 339–345.

''ट्रान्सफारमेटिव रोल आफ एजुकेशन फार पीस फार प्रीपेयरिंग टीचर्स'' इन इंडियाः क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन पालिसी एंड प्रैक्टिसेज' (लीड पेपर, 261–271). गांधी विद्या मंदिर और आईएएसई (डी) विश्वविद्यालय, सरदारशहर (राजस्थान), 2013

''स्कूल परफारमेंस मैनेजमेंट इन इंडिया'' इन एजुकेशन फार द न्यू मिलेनियम', बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आईएसबीएनः 978–81–927002–1–2, 2013, पृष्ठ 171–184

lfeukj@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;%

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, 10–14 जून, 2013 'शिक्षकों के लिए स्कूल सुरक्षा' पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में, पूर्ण स्कूल अवधारणा (आरटीई, सर्व शिक्षा

अभियान और यूएनसीआरसी लिंकेज) के साथ स्कूल सुरक्षा जोड़ने पर एक आलेख प्रस्तुत।

स्कूल मानक और मूल्यांकन के लिए आधारभूत अध्ययन, 14–15 नवंबर, 2013 को कार्यशाला में स्कूल मानक और मूल्यांकन पर एक आलेख प्रस्तुत किया।

भुवनेश्वर, ओडिशा, 16–17 दिसंबर, 2013 (अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान पर यूरोपीय संघ परियोजना के भाग के रूप में) 'बच्चों को बचाओ', राष्ट्रीय प्रसार संगोष्ठी में स्कूल प्रदर्शन मानकों और मूल्यांकन पर एक आलेख प्रस्तुत

अध्यापक–शिक्षणः पाठ्यक्रम परिवर्तनश पर राज्य संगोष्ठी, तमिलनाडु सरकार, 22–23 दिसम्बर, 2013, पाठ्यक्रम प्रबंधन और अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन (2014), आलेख प्रस्तुत

अध्यापक शिक्षा, कोलकाता, 30 दिसंबर, 2013 अधिगम पर संयुक्त समीक्षा मिशन के सीखने के बंटवारे पर प्रसार संगोष्ठी में एक आलेख प्रस्तुत

अध्यापक शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर एक आलेख प्रस्तुत कियाः ओडिशा के राज्य के लिए संभावनाएं तलाश, ओडिशा में शिक्षा, यूनिसेफ और सरकार का दृष्टिकोण ओडिशा, मार्च 6–7, 2014

vrjk"Vh;%

ट्रांसफार्मिंग स्कूल गुणवत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कनेक्शन, (अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान पर यूरोपीय संघ परियोजना के हिस्से के रूप में) तुलना और संभावनाएं भारत में शिक्षक प्रदर्शन मानकों पर एक आलेख प्रस्तुत नई दिल्ली, अप्रैल 12–14, 2013

'दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए स्कूल में सुरक्षा पर एक कार्य योजना विकसित करने के लिए स्कूलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की एकता पर रिसोर्स पर्सन के रूप में एक आलेख, प्रस्तुत किया, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, नई दिल्ली, 6 फ़रवरी, 2014

स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण प्रणाली, 17–21 फ़रवरी, 2014 को ब्रिटेन के लिए कक्षा अध्ययन यात्रा पर स्कूल मानक और भारत में मूल्यांकन पर एक प्रस्तुति पेश की

if'k{k.k lkexh vkj ikB;Øe fodflr ,o fu"ikfnr

स्कूल विकास और अभिशासन (2014)

जवाबदेही (2014).

lkoltfud fudk;ka dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

अध्यापक शिक्षा पर संयुक्त समीक्षा मिशन के लिए दल के नेता के रूप में (ओडिशा) विभिन्न शिक्षक शिक्षा संस्थानों का दौरा, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशों के साथ राज्य रिपोर्ट (10–16 मार्च, 2013) तैयार की। इसके बाद ओडिशा राज्य द्वारा जे. आर.एम. प्रयास प्रस्तुत किये। (Teindia-nic-in).

भारत सरकार, आर.एम.एस.ए. संयुक्त समीक्षा मिशन दल के मनोनीत सदस्य के रूप में, 13–27 जनवरी, 2014 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्य का दौरा किया और जेआरएम टीम के भाग के रूप में राज्य की रिपोर्ट और राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की।

तुलनात्मक शिक्षा, यूनेस्को की त्रैमासिक समीक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समीक्षक के रूप में।

स्कूल प्रदर्शन प्रबंधन पर शोध अध्ययन पर आरएमएसए–टीसीए के साथ सहयोग किया और उपकरणों और अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के विकास में भागीदारी

भारत में स्कूलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण अभ्यास पर यूनिसेफ और सीड परियोजना के लिए शैक्षिक समर्थन दिया।

टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए नेशनल स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) (एनडीएमए), भारत सरकार के लिए शैक्षिक समर्थन दिया.

तीन पी–एच.डी., उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा, डॉ बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और जेएनयू, नई दिल्ली के शोध का मूल्यांकन और शिक्षा में दो शोध अध्ययन के लिए परीक्षक के रूप में कार्य किया।

न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य सचिव, अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड केडी जर्नल एजुकेशनल पॉलिसी

सदस्य, सर्व शिक्षा अभियान में नवाचार के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर परियोजना (यूरोपीय संघ परियोजना वित्त पोषित).

सदस्य, शिक्षक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड (टीईएबी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी).

सदस्य, विभागीय सलाहकार बोर्ड, मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्थान.

सदस्य, अनुसंधान समिति, स्ट्राइड, इग्नू.

सदस्य, संस्थागत सलाहकार बोर्ड, शिक्षा, एनसीईआरटी क्षेत्रीय संस्थान.

सदस्य, केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति, नई दिल्ली

रश्मि दीवान

प्रकाशन

पुस्तक/अध्याय

'प्रैक्टिकल टिप्स फार टीचिंग मल्टी–ग्रेड क्लासेस' (विशेष बुकलेट सं.–4) इन इम्ब्रेसिंग डाइवरसिटी: टूलकिट फार क्रिऐटिव इन्क्लूसिव, लर्निंग–फ्रेंडली इनवायरनमेंट्स सीरिज, बैंकाक: यूनेस्को, 2013 पीपी 57.

''अटलांटिक एजुकेशन: कनसैप्ट एंड इवाल्युशन'' (सैल्फ इन्स्ट्रक्शनल मॉड्यूल फार द पीजीडीईएमए प्रोग्राम), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (एमईएस–048), दिसंबर 2013 पीपी 52..

चैप्टर टाइटल ''एडल्ट लिट्रेसी, एजुकेशन एंड लाईफ लॉंग लर्निंग: टूवार्ड्स ससटेन्ड डवलपमेंट आफ आल'' इन एजुकेशन एज ए राइट अक्रॉस द लेवल्स: चैलेंजेस, अर्पच्युनिटी एंड स्ट्रेटेटीज' विभा बुक्स, 2014. पीपी 218–231.

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला में भागीदारी

राष्ट्रीय

''वयस्क साक्षरता, शिक्षा और सभी के निरंतर विकास की दिशा में आजीवन अधिगम'', अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन (2014 आईईसी), जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, मार्च 10–11, 2014.

अंतर्राष्ट्रीय

'भारत में स्कूल नेतृत्व: सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए प्रस्ताव' एक आलेख प्रस्तुत, गोलमेज सम्मेलन, टीचिंग और नेतृत्व का नेशनल कॉलेज (एनसीटीएल), नॉटिंघम, 28–29 नवम्बर, 2013

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित तथा निष्पादित

स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूल नेतृत्व को समझना।

स्कूल विकास योजना की तैयारी के माध्यम से मार्गदर्शन: स्कूल प्रमुखों के लिए एक पुस्तिका (संयुक्त रूप से डा. बी.के. पांडा के साथ).

मॉड्यूल लघु अग्रणी मल्टी ग्रेड स्कूल प्रधान शिक्षकों के लिए एक व्यावहारिक गाइड विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए विशेष फोकस के साथ (संयुक्त रूप से डॉ मोना सेदवाल के साथ) स्कूल नेतृत्व विकास के भाग के रूप में इस्तेमाल किया।

न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

स्कूल नेतृत्व, नॉटिंघम, ब्रिटेन नेशनल कॉलेज के सहयोग से भारत में स्कूलों के नेतृत्व क्षमता के विकास पर परियोजना समन्वयक.

सदस्य, नेतृत्व कार्यक्रम पर सलाहकार समिति और स्कूल प्रबंधन, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली

आजीवन सदस्य, शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक, नई दिल्ली इंडियन एसोसिएशन.

आजीवन सदस्य, शैक्षणिक प्रशासक, न्यू इंग्लैंड विश्वविद्यालय, आर्मीडेल्स राष्ट्रमंडल परिषद

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी (सीईएसआइ), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सदस्य, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली, राज्य परिषद द्वारा गठित, अनुसंधान सहायता समूह

सस्थापक सदस्य, डा एस राधाकृष्णन मॉडल स्कूल की स्थापना के लिए स्कूल शिक्षा, हरियाणा बोर्ड द्वारा गठित डा एस राधाकृष्णन शिक्षा समिति, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव रणनीतियों और तरीकों के परीक्षण के लिए एक लैब स्कूल के रूप में कार्य

e/kferk c|kik/;k;

çdk'ku

iLrdk@v/;k;%

एंड आफ डिकेट नोट ऑन ''यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन (ईएफए गोल 2)'' इन एशिया पैसिफिक रीज़न ईएफए इवाल्यूशन डाक्यूमेंट', बैंकाकः यूनेस्को बैंकाक, यूनिसेफ ईएपीआरओ और यूनिसेफ आरओएसए आईएसबीएनः 978–92–9223433–1 (प्रिंट संस्करण) (डा. बिस्वाल के साथ सह लेखक,)

चैप्टर आन ''एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन आफ चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल्स इन कान्टेस्ट आफ आरटीई एक्ट, 2009'' इन बुक आन 'एजुकेशन फार ऑल' (सं. जे. मेटे और ए मंडल). नई दिल्लीः एपीएच पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, आईएसबीएनः 978.93=313.2283.8, जनवरी 2014, पृ. सं. 57–71

'kks/k i=@y[k@fVIi.kh

नागरिक समाज संगठन और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधानरू अनुभवजन्य अध्ययन से अनुभव, मध्य प्रदेश में सामाजिक विज्ञान की समीक्षा, वॉल्यूम. 17 नंबर 1, आईएसएसएनः 07–855X, (2013), पृ.सं. 40–58 (सह लेखक मायत्री डे के साथ)

'भारत में शिक्षा और विकासरू प्राथमिक स्तर पर स्कूल भागीदारी पर बल और बच्चों के अधिगम परिणाम' (ऑनलाइन प्रकाशन) उपलब्ध http://www.ukfiet.org/cop/wp-content/uploads/2013/11/Bandyopadhyay_Education-and- Development-in-india.pdf

''एक्सेस एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडियाः चैलेंजेज फार ए पोस्ट–2015 एजुकेशन एजेंडा'' इन कम्पेयर फोरम, 2014 बीएआईसीई, यूके http://baice.ac.uk/2014/access-and-quality-in-elementary-education-vy-india-challenges-for-a-post-2015-education-agenda/#comments

lxkf"B;k@lEesyuk@dk;l'kkykvk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित, भारत में लोक सेवा वितरण प्रणाली को बदलने हेतु लोकतांत्रिक शासन' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आकलनः शिक्षा अधिनियम, 2009 के अधिकार के कार्यान्वयन पर एक आलेख प्रस्तुत, नवंबर 5–6, 2013.

शिक्षा विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज द्वारा आयोजित भारतीय शिक्षा मुद्दों और चुनौतियों के बदलते स्वरूप, पर शैक्षिक संगोष्ठी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकारः हमारी स्थिति पर आलेख प्रस्तुत (दिल्ली विश्वविद्यालय), फरवरी 12–13, 2014

vrjk"Vh;

भारत में शिक्षा और विकासः स्कूल की भागीदारी पर फोकस और बच्चों के अधिगम परिणाम प्राथमिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय यूकेएफईटी सम्मेलन में शिक्षा और विकास समीक्षा, सीएफबीटी तथा बीएआई द्वारा आयोजित, सीएफबीटीआईसीई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, सितंबर 10–12, 2013 एक आलेख प्रस्तुत

dk;l'kkyk,@lEesyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;ktu

समावेशन, इक्विटी और स्थिरता के लिए संबंधित मुद्दे लोकतंत्र, शिक्षा और विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी समन्वित, न्यूपा, मार्च 6–8, 2014

çf'k{k.k lkexh vkj ikBîØe fodflr vkj fu"ifknr

कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार, 27–31 जनवरी, 2014

lkoltfud fudk;ks dks ijke'kZ vkj vdknfed lgk;rk

भारत बाह्य रिपोर्ट के विकास में, न्यूपा से एक सदस्य के रूप में भाग लिया

इक्विटी स्टडीज केंद्र, नई दिल्ली और परियोजना के लिए शिक्षा, गरीबी और बहिष्करण पर एक आलेख प्रस्तुत।

सुश्री दीपा इदनानी, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग के नेतृत्व में एक अनुसंधान दल में नेतृत्व के रूप में: दिल्ली में एमसीडी स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों का एक तुलनात्मक अध्ययनः प्राथमिक विद्यालयों में अनुपस्थिति पर एक अनुसंधान के संचालन में 'मेंटर' के रूप में शैक्षिक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिनव परियोजना की योजना के अंतर्गत

माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विस्तार के लिए परामर्श, समन्वित और संबंधित पृष्ठभूमि नोट के साथ रिपोर्ट तैयार

U;ik dks ckgj ç[;kr fudk;ks dh lnL;rk

सदस्य, भारत तुलनात्मक शैक्षिक समिति (सीईएसआई)

तुलनात्मक सदस्य, अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक समिति (सीआईईएस)

सदस्य, आकांक्षा, दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन

d';ih voLFkh

çdk'ku

iqLrdksa@v/;k;%

'डब्ल्यू.टी.ओ., गैट्स एंड हायर एजुकेशन इन इंडियाः ए स्वाट अनालिसिस' पुस्तक 'हायर एजुकेशन इन इंडिया' (सं. राजीव कुमार और नरेंद्र कुमार) नई दिल्ली, अटलांटिक पब्लिशर्स

lxks"Bh;ksa@lEesyuksa@dk;Z'kkykvksa esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;%

शिक्षा विभाग (केस), शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक संकाय, एम.एस., बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा, गुजरात, 28 फरवरी–1 मार्च 2014 में 'अध्यापक समताः मानचित्रण और प्रबंधन' पर राष्ट्रीय सेमिनार में 'कोचिंग एंड मानीटरिंगः एन इफेक्टिव मीन्स फार रिड्यूसिंग गैप्स इन टीचर कम्पेटेन्सी' पर आलेख प्रस्तुत किया।

varjk"Vªh;%

सर्व शिक्षा अभियान में उत्कृष्ट कार्य व्यवहार संबंधी नवाचार परियोजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये विद्यालय रूपांतरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, 12–14 अप्रैल, 2013

लोकतंत्र शिक्षा और समावेशन, समता और स्थायित्व से जुड़े विकास के मुद्दे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी, न्यूपा, 6–8 मार्च, 2014

dk;Z'kkyk,@ lEesyu@izf'k{k.k dk;ZØe dk vk;kstu

गुजरात में राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिये दो दिवसीय कार्यशाला का सह संयोजक। 'शैक्षिक नेतृत्व और बदलाव विषय पर एक व्याख्यान दिया। इसके अलावा प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकताएँ और चुनौतियां पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की। (30–31 मार्च, 2013)

त्रिपुरा में राज्य स्तरीय प्रशासकों के लिये दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन और विद्यालयों में सुधारः 'शैक्षणिक नेतृत्व की भूमिका' पर एक व्याख्यान दिया। इसके अलावा त्रिपुरा में प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकताएँ और चुनौतियां पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की। (15–16 नवंबर, 2013)

U;ik dks ckgj iæq[k fudk;ks dh lnL;rk

सदस्य, डाक्टोरल शोध समिति, बाल विकास, इग्नो

सदस्य, जर्नल, संपादक मंडल, रिसेंट एजुकेशनल एंड साइक्लोजीकल रिसर्च

सदस्य, कार्यकारी समिति, भारतीय स्कूल शिक्षा परिषद।

उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

l ?kk'k Hk"k.k ¼foHkkx/;{k½

ikdk'ku

iLrd@v/;k;

चैप्टर आन ''ह्यूमन डवलपमेंट'' इन 'दिल्ली ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट' (प्रेपेयर्ड बाइ द इंस्टीट्यूट आफॅ ह्यूमन डवलपमेंट फार द गवर्नमेंट आफ एनसीटी आफ दिल्ली), 2013

'kk/k vkyi[k@fVIi.kh

लिगल हार्डल इन द इन्ट्री आफ फारैन यूनिवर्सिटीज (ओपीनियन पीस), इंडियन एक्प्रेस, अक्टूबर 1, 2013

'अनइम्प्लायेबल ग्रेजुएट इन इंडिया' (पब्लिशड् इन नॉन–रेफर्ड जर्नल), सी.एम. कॉलेज, दरभंगा, 2013

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान – इम्प्लायमेंटेशन चैंलेज', कॉलेज पोस्ट, जनवरी–मार्च, 2014

iLrd@vkyi[k leh{kk

रिव्यू आफ पवन अग्रवाल (सं.) बुक 'ए हॉफ–सेंचुरी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशनः एस्से बाइ फिलिप जी. अल्टबाख, नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन इंडिया 2012. 628 पेज इन कन्टम्पोरेरी एजूकेशन डायलॉग, 11, 1(2014): 115–135

lxkf"B;k lEeyuk@dk;'kkykvk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;

'उच्च शिक्षा और रोजगारपरकताः विश्वविद्यालय में स्नातकों की तैयारी, गुवाहाटी कालेज, 16 जून, 2013

आलेख– 'केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर समान विधेयकः उच्च नियामक प्रावधान' की प्रस्तुति, सीएसजीएस, दिल्ली, 1 सितंबर 2013

पांडिचेरी विश्वविद्यालय में मानव संसाधन के विकास में विश्वविद्यालय और कालेजों की भूमिकाः पाठ्यचर्या के बाहर पर आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यशाला में 'उदार शिक्षा : विद्यार्थियों के मस्तिष्क का सम्पोषण' पर आलेख प्रस्तुति

पटना में आयोजित सातवां बिहार शैक्षिक सम्मेलन में 'नीति निर्माण में राजस्व की स्वायत्तता' पर आलेख प्रस्तुति, 22–23 अक्टूबर, 2013

छाया गाँव कालेज, छायागांव, असम में आयोजित 60वां असम कॉलेज परिसंघ सम्मेलन में 'भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा पर मुख्य आलेख की प्रस्तुति, 23–26 अक्टूबर, 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में अनिल बोर्डिया स्मारक राष्ट्रीय नीति संगोष्ठी में उच्च शिक्षा की नीतियां, पर आलेख प्रस्तुत किया, 16–17 दिसंबर 2013

वि. अ. आ., अकादमिक स्टाफ कालेज, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में 12वीं योजना के शैक्षणिक सुधार की कार्यसूची के विश्लेषणात्मक मुद्दे पर आलेख प्रस्तुती, 27 जनवरी, 2014

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानः विज्ञान और मानविकी शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में संबर्धन के लिये मूलभूत बदलाव पर राष्ट्रीय सम्मेलन में 'आर.यू.एस.ए. की प्रमुख चुनौतियां' पर आलेख प्रस्तुति, 28 फरवरी, 2014

vrjk"Vh;

टीकापुर मल्टीपल कालेज, नेपाल में आयोजित एक संगोष्ठी में जिज्ञासा संस्कृति पर आलेख प्रस्तुति, 21–22 सितंबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः बहिष्करण, समता और स्थायित्व से संबंधित मुद्दे में उच्च शिक्षा में समता और वहनीयता पर आलेख प्रस्तुति (6–8 मार्च, 2014)

0;k[;ku

संबलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम में भा.सा.वि.शो.प. में शोध के विचार विषय पर व्याख्यान, 17 मई, 2013

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में शोध प्रविधि पाठ्यक्रम में 'शोध की रूप रेखा' पर व्याख्यान, 10 सितंबर, 2013

केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, में शोध प्रविधि पाठ्यक्रम में शोध की रूपरेखा पर व्याख्यान 15–16 नवंबर, 2013

सेंट अन्न शिक्षा कालेज (स्वायत्त), में मंगलौर में 'गुण ावत्ता विमर्श और अध्यापकों की चुप्पी पर मदर जासेफीन स्मारक व्याख्यान, 8 फरवरी, 2014

ykd fudk;k dk i jke'kdkjh vkj 'k{kf.kd vu|l/kku

सदस्य, समीक्षा समिति, वि.अ.आ., आय के स्रोत और वि. अ.आ. तथा विश्वविद्यालयों को सुझाव

सदस्य, शैक्षणिक परिषद, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश

आमंत्रिती सदस्य,कार्यबल, अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. से गुणवत्तापूर्ण संकाय का विकास और प्रोन्नति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संयोजक, उपसमूह, अध्यापक और अध्यापन पर राष्ट्रीय आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य, विशेषज्ञ समिति, एक से अधिक डिग्री पाठ्यक्रम करने हेतु दिशा–निर्देश का विकास, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सदस्य, टीकापुर मल्टीपल परिसर, कैलई नेपाल के लिये गुणवत्ता आश्वासन पर समीक्षा दल (9–13 जून, 2013 के दौरे के दौरान)

vU; 'k{kf.kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

भा.स.वि. शोध परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाज विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन पुरस्कार से सम्मानित।

vkjrh JhokLro

i dk'ku

'kk/k vky[k@vky[k@fVIif.k;k

हायर एजूकेशन रिविजिटिंग द रूरल, युनिवर्सिटी न्यूज क्लोजिंग द स्किल गैप इन इंडिया, ग्लोबल डायजेस्ट

टीचिंग लर्निंग सैन्टर इन हायर एजूकेशन, कॉलेज पोस्ट

यूनिट्स ऑन 'स्कूल डवलपमेंट प्लान', इग्नो

यूनिट्स ऑन 'असपैक्ट ऑफ स्कूल डवलपमेंट प्लान', इग्नो

lxkf"B;k@lEeyuk@dk;'kkykvk e Hkkxhnkjh

श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के कालेज प्राचार्यों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रतिभागिता और योगदान, 24–28 जून, 2013

विश्वविद्यालयों के बीच विषय आधारित अध्यापन अधिगम नेटवर्क की स्थापना पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 19–23 अगस्त, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रतिभागिता और योगदान, 30 सितंबर – 5 अक्तूबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में 'भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली पर आयोजित कार्यशाला में भागीदारी, 28–30 अक्टूबर, 2013

0;k[;ku

विश्व शिक्षा समिति– रोजगार के लिये कौशल, अप्रैल 2013

असम विश्वविद्यालय में शोध प्रविधि सत्र, अप्रैल 2013

शिक्षा का अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त जनशक्ति शोध संस्थान, नई दिल्ली, मई 2013

लिंग और विकास, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, मई 2013

परीक्षणः मुख्य बिंदुओं का विकास, दे.अ. विश्वविद्यालय, इंदौर, अगस्त 2013

प्राचार्यों के लिये प्रभावकारी प्रबंधन, दिल्ली सरकार, दिल्ली, सितंबर 2013

हिंदुत्व की समझ, दि लाइस फ्रेंक्सडि, दिल्ली, नवंबर, 2013

अध्यापक गुणवत्ता, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, दिसंबर 2013

उच्च शिक्षा के आयाम, नेशनल कालेज, लखनऊ, दिसंबर 2013

सर्वेक्षण की विधि, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, जनवरी 2014

शान्ति और शिक्षा पर शोध, बी.एच.यू. वाराणसी, जनवरी 2014

शिक्षा, नीतियाँ और कार्यक्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, जनवरी 2014

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, फरवरी 2014

उच्च शिक्षा की समझ, एन.जी.ओ. फार काज, जयपुर, मार्च 2014

एफ.वाई.यू.पी.: लाभ या हानि, एन.जी.ओ.–सन, नई दिल्ली, मार्च 2014

dk;'kkykvk@lEeyuk@if'k{k.k dk;Øek dk vk;ktu

उच्च शिक्षा में अध्यापन–अधिगम केंद्र पर कार्यशाला का संयोजन 26–29 नवंबर 2013

vU; vdknfed xfrfof/k;k

आईआईईपी/यूनेस्को पाठ्यक्रम– 'उच्च शिक्षा के अनुश्रवण में संकेतकों के उपयोग' में भागीदारी, आईआईईपी, पेरिस, 22 अप्रैल – 21 जून 2013

एम.फिल. छात्रा सुश्री अपराजिता गणतायत और पी–एच.डी. छात्रा सुश्री अमुनीता मिश्रा के शोध का निर्देशन।

ykd fudk;k dk ijke'kdkjh vkj 'kk{kf.kd vu|leFkku

भा.स.वि.शे.प. में शोध परियोजना का मूल्यांकन इग्नो परीक्षाओं में परीक्षक

ज.ने.वि. में एम.फिल. शोध प्रबंधन का परीक्षक

ज.ने.वि. में पी–एच.डी. शोध प्रबंध का परीक्षक

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पी–एच.डी. का शोध प्रबंध का परीक्षक

vU; 'kk{kf.kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा समिति, न्यूपा

एम.फिल./पी–एच.डी. स्क्रीनिंग समिति, न्यूपा

एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा मूल्यांकन समिति, न्यूपा

विद्यार्थी अनुसमर्थन समिति, न्यूपा

शोध प्रविधि पर डेपा पाठ्यक्रम संशोधन

U;ik l ckgj ie[k fudk;k dh lnL;rk

आजीवन सदस्य, प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली (1999)

आजीवन सदस्य, भारतीय ज्ञानपीठ परिवार, नई दिल्ली (1999)

आजीवन सदस्य, आई एस एल ई (1998)

आजीवन सदस्य, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (1998)

आजीवन सदस्य, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड (2003)

आजीवन सदस्य, थियोसोफिकल सोसायटी, वाराणसी (2004)

आजीवन सदस्य, सी ई एस आई, नई दिल्ली (2010)

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शैक्षिक शोध संघ

uh : Lugh

idk’ku

iLrd@v/;k;

चैप्टर आन ''कॉलेज आटोनामीः एन इंडियन एक्सपीरियन्स'', इन बुक 'एजूकेशन एज ए राइट अक्रास द लेवल्स', इंटरनेशनल एजूकेशन कान्फ्रेंस (2014), विभा बुक्स, 2014

’kk/k vkys[k@vkys[k@fVIif.k;k

''स्टूडेंट मोबिलिटी एट टरटैरी लेवल आफ एजूकेशन इन इंडिया–स्टेट्स, पर्सपैक्ट एंड चैंलेजेज'', न्यूपा ओकेजनल पेपर, 2013

सस्टेनिंग साइटिफिक रिसर्च एट 'टरटैरी लेवल – ए चैलेंज, युनिवर्सिटी न्यूज, जून 2013

साईंस एजूकेशन एट टरटैरी लेवल– रिविजिटिंग साईंस पॉलिसीज, युनिवर्सिटी न्यूज (स्पेशल इश्यू आन हायर एजूकेशन पॉलिसी), फरवरी 17–21, 2014

''कॉलेज आटोनामीः एन इंडियन एक्सपीरियन्स'', इन बुक 'एजूकेशन एज ए राइट अक्रास द लेवल्स', इंटरनेशनल एजूकेशन कान्फ्रेंस (2014), विभा बुक्स, 2014।

lxkf"B;k@lEeyuk@dk;l’kkykvk e Hkkxhnkjh

jk"Vh;

नई दिल्ली में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्कूल सुधार योजना' पर आलेख प्रस्तुति, मई 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा शोध अध्ययन केन्द्र द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत शोध' पर आयोजित परामर्श बैठक में भागीदारी, सितंबर 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रतिभागिता और योगदान, 30 सितंबर – 5 अक्टूबर 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली पर आयोजित कार्यशाला प्रतिभागिता और योगदान, 28–30 अक्टूबर, 2013

नई दिल्ली के फिक्की फेडरेशन हाउस में भारतीय उच्च शिक्षा रूपांतरण के लिये नेटवर्क का विकासः मूल्यों के शिक्षण हेतु सक्षमता पर आयोजित फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में 'उच्च शिक्षा में विषयवार नेटवर्क, पर आलेख की प्रस्तुति, 13–14 नवंबर 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा में अध्यापन–अधिगम केन्द्र पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 25–29 नवंबर, 2013

सीईएसआई, कोलकाता में 'भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के अध्यापक' पर आलेख प्रस्तुति, 28–30 दिसंबर, 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और एक सत्र की अध्यक्षता, 27–31 जनवरी, 2014

श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा की बदलती रूपरेखा पर आयोजित शैक्षिक परिसंवाद में प्रतिभागिता और एक सत्र की अध्यक्षता, 12–13 फरवरी, 2014।

न्यूपा, नई दिल्ली में राज्य उच्च शिक्षा परिषद पर आयोजित परामर्श बैठक में प्रतिभागिता और आर.यू.एस.ए. और राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की भूमिका पर आयोजित सत्र की रिपोर्ट तैयार की। 25–26 मार्च, 2014।

vrjk"Vh;

एचईआईआरए – सीएससीएस और फोर्ड फउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षा पर आयोजित दक्षिण एशिया सम्मेलन में प्रतिभागिता, 5–7 अगस्त, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः समेकन, समता और स्थायित्व संबंधी मुद्दे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभागिता और सत्र–शिक्षा और विकास की रिपोर्ट तैयार की, 6–8 मार्च, 2014

जमिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में 'कालेज की स्वायत्तताः भारतीय अनुभव' पर आलेख प्रस्तुति, 10—11 मार्च, 2014।

dk;Z'kkyk,¡@lEesyu@ifj'k{k.k dk;ZØe

अकादमिक स्टाफ कालेज, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम का संयोजन, 24—28 जून, 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में 'विषय आधारित नेटवर्क' पर राष्ट्रीय कार्यशाला का संयोजन, 29—31 अगस्त, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के कालेज प्राचार्यों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम का समन्वयन, 30 दिसंबर – 5 अक्टूबर, 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में 'स्वायत्त कालेज' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का समन्वयन, 9—13 दिसंबर 2013

vU; vdknfed xfrfof/k;k¡

आईआईईपी/यूनेस्को द्वारा आयोजित दूरवर्ती पाठ्यक्रम 'उच्च शिक्षा के अनुश्रवण में संकेतकों के उपयोग' में प्रतिभागिता, पेरिस, 22 अप्रैल – 21 जून 2013।

ykd fudk;ksa dks ijke'kZ@dk;Z lewg vkSj 'kS{kf.kd vuqlaèkku

'शिक्षा – 2012—13 पर जन रिपोर्ट' की तैयारी में योगदान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

dkS'kj fotkjr

laxks"Bh;ka@lEesyuksa@dk;Z'kkykvksa esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;

न्यूपा, नई दिल्ली में 'विश्वविद्यालयों के बीच अध्यापन—अधिगम पर विषय आधारित नेटवर्क की स्थापना' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 19—23 अगस्त, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध से मुक्ति पर आयोजित परामर्श बैठक में सहभागिता, 27 अगस्त, 2013

आईआईसी, नई दिल्ली में 'विभाजन के बाद के संस्मरण' पर आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभागिता, 12 सितंबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र द्वारा 'उच्च शिक्षा में नीतिगत अनुसंधान' पर आयोजित परामर्श बैठक में प्रतिभागिता, सितंबर 2013।

न्यूपा, नई दिल्ली में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 28—30 अक्टूबर, 2013

सीडब्ल्यूडीएस द्वारा आईआईसी, नई दिल्ली में 'श्रम, संस्कृति और राजनीति : कामकाजी महिलाओं का इतिहास और अनुभव' पर आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभागिता, 7 नवंबर, 2013

नई दिल्ली में 'भारतीय उच्च शिक्षा के रूपांतरण के लिये नेटवर्क का विकास' पर आयोजित आईसीसीआई उच्च शिक्षा समिति —2013 में प्रतिभागिता, 13—14 नवंबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा के शिक्षण अधिगम केन्द्र' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 25—29 नवंबर, 2013

नई दिल्ली में रेक्टर, इम्पीरियल कालेज, लंदन के साथ 'नवाचार' और विचारों से मूल्यों का सृजन' पर आयोजित विशेष सत्र की प्रतिभागिता, 9 जनवरी, 2014

vUrjk"Vªh;

न्यूपा, नई दिल्ली में लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः समेकन, समता और स्थायित्व' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागिता, 6—8 मार्च, 2014

dk;Z'kkykvksa@lEesyuksa@ifj'k{k.k dk;ZØeksa dk vk;kstu

अकादमिक स्टाफ कालेज, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम का संयोजन, 24—28 जून, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम का समायोजन, 30 सितंबर – 5 अक्टूबर, 2013

vU; 'kS{kf.kd xfrfof/k;k

आईआईईपी/यूनेस्को द्वारा आयोजित दूरवर्ती पाठ्यक्रम 'उच्च शिक्षा के अनुश्रवण में संकेतकों के उपयोग' में प्रतिभागिता, पेरिस, 22 अप्रैल – 21 जून 2013।

अकादमिक स्टाफ कालेज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में 'मीडिया अध्ययन और शासन' पर आयोजित द्वितीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रतिभागिता 14 जनवरी – 3 फरवरी, 2014।

U;ik ls ckgj dh izeq[k fudk;ksa dh lnL;rk

सदस्य, पहचान, मेवात, हरियाणा में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा हेतु कार्यरत एनजीओ

lxhrk vxzke

izdk'ku

'kks/k vkys[k@vkys[k@fVIif.k;k

फाइनेंसिंग आफ प्राइवेट युनिवर्सिटीज इन इंडिया, प्रोसीडिंग आफ नार्थ ईस्ट इंडिया एजूकेशन सोसायटी कान्फ्रेंस, नेहू, शिलांग, नवम्बर 2013

अकादमिक क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजूकेशनः रेलिवैंस एंड इफैक्टिवनैश इन इंडिया, प्रोसीडिंग आफ इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस, मुंबई यूनिवर्सिटी, जनवरी 2014,

ग्रोथ आफ हायर एजूकेशन इन मणिपुरः स्टेटस एंड पॉलिसी पर्सपैक्टिव, जर्नल आन हायर एजूकेशन फार द फ्यूचर, वाल्यूम 1, इश्यू 1, जनवरी 2014, सेज़ पब्लिकेशन

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडियाः स्टेटस एंड पालिसी पर्सपैक्टिव, यूनिवर्सिटी न्यूज; स्पेसल इश्यू, फरवरी 2014

laxksf"B;k@lEesyuk@dk;Z'kkykvksa esa Hkkxhnkjh

jk"Vªh;

महाराजा बुद्धचंद्र कालेज, इम्फाल, मणिपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में संसाधन व्यक्ति के रूप में भागीदारी और 'भारत में उच्च शिक्षा के स्वरूप का विकास और मणिपुर में इसकी तैयारी' पर आलेख प्रस्तुत किया 19–20 अप्रैल, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में 'विश्वविद्यालयों के बीच अध्यापन–अधिगम विषय पर आधारित नेटवर्क की स्थापना' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 19–23 अगस्त, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध से मुक्ति पर आयोजित परामर्श बैठक में सहभागिता, 27 अगस्त, 2013

अकादमिक स्टाफ कालेज, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम का संयोजन, 24–28 जून, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के कालेज प्राचार्यों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम का समायोजन, 30 सितंबर – 5 अक्टूबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में 'भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली' पर आयोजित कार्यशाला में 'भारतीय विश्वविद्यालयों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणालीः तुलनात्मक समझ' विषय पर आलेख प्रस्तुति, 28–30 अक्टूबर, 2013

सेंट एल्वायसस कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 'अध्यापन में नवाचार प्रयोग पर आलेख प्रस्तुति, नवंबर 2013

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर अरूणाचल प्रदेश, में आयोजित पूर्वोत्तर वार्षिक सम्मेलन में 'विश्वविद्यालयों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणालीः पूर्वोत्तर भारत में इसके प्रयोग की तुलनात्मक समझ' पर आलेख प्रस्तुति, 6–7 नवंबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में अध्यापन अधिगम केन्द्र पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता और योगदान, 25–29 नवंबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में स्वायत्त कालेज पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभागिता, 9–13 दिसंबर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में राज्य उच्च शिक्षा परिषद पर आयोजित परामर्श बैठक में प्रतिभागिता और रिपोर्ट लेखन, 25–26 मार्च, 2014

vrjk"Vh;

कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता में आयोजित सीईएसई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'भारतीय निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की विशेषताएँ : दो निजी विश्वविद्यालयों का अध्ययन' विषय पर आलेख प्रस्तुति, 28–30 दिसंबर, 2013

मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई में आयोजित अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'उच्च शिक्षा में शैक्षणिक क्रेडिट प्रणाली : भारत में उसकी प्रासंगिकता और प्रभाव' पर आलेख प्रस्तुति, 8–10 जनवरी, 2014

कुतुब होटल, नई दिल्ली में 'लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः समेकन, समता और स्थायित्व संबंधी मुद्दे' न्यूपा द्वारा आयोजित अतंर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागिता और सत्र–अध्यापन एवं अधिगम का रिपोर्ट लेखन, 6–8 मार्च, 2014।

dk;Z'kkykvk@lEesyuk@if'k{k.k dk;Øek dk vk;ktu

न्यूपा, नई दिल्ली में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली पर आयोजित' राष्ट्रीय कार्यशाला का संयोजन, 28–30 अक्टूबर, 2013

vU; vdknfed xfrfof/k;k

आईआईईपी/यूनेस्को द्वारा आयोजित दूरवर्ती पाठ्यक्रम 'उच्च शिक्षा के अनुश्रवण में संकेतकों के उपयोग' में प्रतिभागिता, पेरिस, 22 अप्रैल – 21 जून 2013

ykd fudk;k dk ijke'kdkjh lok,¡ vkj 'k{kf.kd vuqlaeFku

'शिक्षा – 2012–13 पर जन रिपोर्ट' की तैयारी में योगदान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

U;ik d ckgj ie[k fudk;k dh lnL;rk

सदस्य, पूर्वोत्तर भारत शिक्षा सोसायटी

सदस्य, कार्यकारी समिति, पूर्वोत्तर भारत शिक्षा सोसायटी, शिलांग

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग ने कार्यक्रमों के आयोजन, प्रकाशन और अपने वेबसाइट के रखरखाव तथा अद्यतन संबंधी कार्यों में संलग्न रहा जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है।

idk'ku

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः प्रोग्रेस टूवार्ड्स यूईईः डाईस फ्लैश स्टेटिटिक्स

एलिमेंट्री एजूकेशन इन रूरल इंडियाः अनालिटिकल टेबल्स (वेब–इनेब्ल्ड)

एलिमेंट्री एजूकेशन इन अर्बन इंडियाः अनालिटिकल टेबल्स (वेब–इनेब्ल्ड)

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः व्हैअर डू वी स्टैण्ड? डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स, वाल्यूम I

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः व्हैअर डू वी स्टैण्ड? डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स, वाल्यूम II

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः व्हैअर डू वी स्टैण्ड? स्टेट रिपोर्ट कार्ड्स, (वेब–इनेब्ल्ड)

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः व्हैअर डू वी स्टैण्ड? प्रोग्रेस टूवार्ड्स यूईईः अनालिटिकल टेबल्स, (वेब–इनेब्ल्ड)

u, ifCyd'ku ¼;&Mkbl1½ 2012&13½

सेकण्डरी एजूकेशन इन इंडियाः प्रोग्रेस टूवार्ड्स यूईईः डाईस फ्लैश स्टेटिटिक्स (वेब–इनेब्ल्ड)

सेकण्डरी एजूकेशन इन इंडियाः व्हैअर डू वी स्टैण्ड? डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स, (वेब–इनेब्ल्ड)

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः थिमेटिक मैप्स बेस्ड आन डाइस डाटा (वेब–इनेब्ल्ड)

एलिमेंट्री एजूकेशन इन इंडियाः अ ग्रैफिक प्रजेंटेशन (वेब–इनेब्ल्ड)

सेकण्डरी एजूकेशन इन इंडियाः अ ग्रैफिक प्रजेंटेशन (वेब–इनेब्ल्ड)

dk;'kkykvk@lEeyuk@if'k{k.k dk;Øek dk vk;ktu

एकीकृत डाइस पर कार्यशाला, 22–23 जुलाई 2013

एजुसेट के द्वारा यू–डाइस आंकड़ा संकलन प्रपत्र पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 6 सितंबर 2013।

एजुसेट के द्वारा यू–डाइस आंकड़ा संकलन प्रपत्र पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 13 सितंबर 2013

माध्यमिक शिक्षा की योजना और अनुश्रवण में संकेतकों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23–27 सितंबर 2013।

शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की योजना और अनुश्रवण में संकेतकों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3–7 फरवरी, 2014

vU; 'k{kf.kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

viu ekStnk oclkbV dk v|ru@j[kj[kko

www.dise.in

www.schoolreportcards.in

www.semisonline.net

डाइस आंकड़ा पर आधारित प्रकाशनों के अलावा वर्ष 2012–13 से संबंधित स्कूल विशेष आंकड़ा भी उपर्युक्त वेबसाइटों पर डाला गया।

v#.k lh egrk ¼foHkkxk/;{k½

lxkf"B;k@lEeyuk@dk;'kkykvk e Hkkxhnkjh

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों के सम्मेलन में प्रतिभागिता और ‘उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति’ पर आलेख प्रस्तुति, 2 अप्रैल 2013।

गुवाहाटी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित आंकड़ा संकलन प्रपत्र पर ईएमआईएस समन्वयकों की राष्ट्रीय कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रतिभागिता, 8 अगस्त, 2013

रायपुर, छत्तीसगढ़ के एम.आई.एस. अधिकारियों के लिये डाइस पर आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रतिभागिता, 9 अगस्त, 2013

सीमेट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एम.आई.एस. समन्वयकों के लिये यूडाइस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रतिभागिता, 21–23 सितंबर, 2013

गुणवत्ता शिक्षा पर सीआईआई प्रायोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और डाईस, बंगलौर, 28 सितंबर, 2013 को एक प्रस्तुति पेश की

सर्व शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, 27 अक्टूबर, 2013 तक आयोजित यूडाईस पर कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया

पूर्वी क्षेत्र के लिए यूडाईस पर कार्यशाला प्रायोजित मा.सं.वि.मं. में संसाधन व्यक्ति, भुवनेश्वर, 14 नवंबर, 2013 के रूप में भाग लिया

हरियाणा की एमआईएस अधिकारियों के लिए यूडाईस पर कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, चंडीगढ़, 26–27 नवंबर, 2013

बिहार के अधिकारियों के लिए यूडाईस पर कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया पटना, 29–30 नवम्बर 2013

0;k[;ku fn;k

ईएमआईएस पर एक कोर्स का आयोजन किया और न्यूपा में, भूटान के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सत्रों में व्याख्यान दिया 5 मई– 2 जून 2013

इवोल्विंग ईएमआईएस इन इंडिया, मई 6, 2013

भूटान में ईएमआईएस की समीक्षा और सुधार, के लिए सुझाव, मई 7, 2013

डाईस, समूह कार्य 13–14 मई, 2013

न्यूपा में घाना, के शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष ईएमआईएस और डाईस पर प्रस्तुतीकरण किया, अगस्त 21–22, 2013

माध्यमिक शिक्षा की योजना में संकेतक का उपयोग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सत्र में व्याख्यान, न्यूपा, सितंबर 16–20, 2013

2012–13 यूडाईस, पर प्रस्तुति 16 सितंबर, 2013

जनसंख्या और जनसांख्यिकीय अनुमान, 17 सितंबर, 2013

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की आंतरिक क्षमता के संकेतक, 18 सितंबर 2013

यूडाईस पर समूह कार्य, सितंबर 19, 2013

यूडाईस पर समूह कार्य, सितंबर 20, 2013

डेपा, न्यूपा, शैक्षिक योजना की मात्रात्मक पहलुओं के एक पाठ्यक्रम के निम्नलिखित सत्रों में व्याख्यान, अक्टूबर 28–30, 2013

डाईस के विकास पर प्रस्तुति

जनसंख्या के अनुमान पर प्रस्तुति, अक्टूबर 29, 2013

नामांकन अनुमान पर प्रस्तुति, 30 अक्टूबर 2013

पूर्वोत्तर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन अनुमान और ईएमआईएस पर व्याख्यान 06–17 नवम्बर, 2013

न्यूपा, नई दिल्ली में इंडोनेशिया के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष डाईस पर प्रस्तुति, 18 नवंबर, 2013

न्यूपा में अनुसंधान प्रणाली, के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनसांख्यिकीय अनुमान पर एक व्याख्यान प्रस्तुति, 16–27 दिसम्बर, 2013

न्यूपा में गुजरात के डाईट की योजना प्रबंधन के संकाय के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में यूडाईस का परिचय और डेटा विश्लेषण पर व्याख्यान, जनवरी 6–10, 2014

न्यूपा में प्रारंभिक शिक्षा की योजना के लिए संकेतक के प्रयोग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नलिखित सत्रों में व्याख्यान 3–7 फरवरी, 2014

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और मुद्दे एवं आरटीई पर प्रस्तुति, फरवरी 3, 2014

यूडाईस का परिचय, फरवरी 4, 2014

शैक्षिक विकास के संकेतकः पहुंच और भागीदारी, फरवरी 4, 2014

जनसंख्या और नामांकन अनुमान, फरवरी 6, 2014

डाईस डाटा पर समूह कार्य, फरवरी 7, 2014

आईडेपा में निम्नलिखित व्याख्यान दिया

जनसांख्यिकीय अनुमान, फरवरी 28, 2014

ईएमआईएस भाग–1 का परिचय, फरवरी 3, 2014

ईएमआईएस भाग–2 का परिचय, फरवरी 5, 2014

कम्प्यूटरीकृत ईएमआईएस का विकास, फरवरी 10–11, 2014

शैक्षिक प्रशासन विभाग, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा (वडोदरा) में 14 मार्च, 2013 को अफगानिस्तान के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईएमआईएस और डाईस पर विभिन्न सत्रों का आयोजन

संयुक्त समीक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान एवं आरएमएसए), नई दिल्ली में निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण

आरएमएसए के द्वितीय संयुक्त समीक्षा मिशन के दौरान यूडाईस पर प्रस्तुतीकरण, जुलाई 30, 2013

आरएमएसए के तृतीय संयुक्त समीक्षा मिशन के पहले यूडाईस पर प्रस्तुति, 13 जनवरी, 2014

सर्व शिक्षा अभियान, के 19 वें संयुक्त समीक्षा मिशन के समक्ष डाईस पर प्रस्तुति, जनवरी 13, 2014

lko|tfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed vu|leFku

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर में संशोधक के रूप में आमंत्रित, 29–31 मार्च, 2013

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

विभागीय सलाहकार समिति, न्यूपा, 13 मार्च, 2014 को एक बैठक बुलाई।

,-,u- j|ìh

çdk'ku

“रीजनल डिस्पार्टीज़ इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल डवलपमेंट इन अनडिवाईडेड आन्ध्र प्रदेश, इंडिया (दूसरों के साथ) वर्किंग पेपर नं. 47, आईसीआरआईएसएटी रिसर्च प्रोग्रामः बाजार, संस्थान और नीतियां

vu|l/kku v/;;u

डाईस डेटा के उपयोग से प्राथमिक शिक्षा पर समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम (प्रो. ए.सी. मेहता के साथ)

स्कूल शिक्षा के लिए भू स्थानिक सूचना प्रणाली विकसित करने के लिये पायलट परियोजना का संयोजन

l|xk"Bh@lEe|yu@dk;|'kkyk e| Hkkxhnkjh

यूनिसेफ, और रोसा द्वारा काठमांडू (नेपाल), में स्कूल के बाहर के बच्चों पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भागीदारी और एक सत्र की अध्यक्षता, 14–16 मई, 2013

चंडीगढ़ में यू–डाईस पर आयोजित 13वीं राष्ट्रीय कार्यशाला में भागीदारी 30–31 मई, 203

भारत में शहरीकरणः बहुशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर आयोजित आईजीआईडीआर सिल्वर जुबिली सम्मेलन में आलेख प्रस्तुत

dk;|'kkyk,|@lEe|yu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;ktu

माध्यमिक शिक्षा योजना और निगरानी में संकेतकों का उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, 16–20 सितम्बर, 2013

आरटीई के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की योजना निगरानी में संकेतकों के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन टीम के सदस्य, फरवरी 03–07, 2014

vU; 'kS{kf.kd xfrfof/k;k

,e-fQy-@ih&,p-Mh- e| v/;kiu- dk;Øe%

एम.फिल. / पी–एच.डी. के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का अध्यापन शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (ओसी–5)

Mik dk;Øe e| f'k{k.k%

संयोजक, पाठ्यक्रम 107ः डेपा के भाग के रूप में शैक्षिक योजना की मात्रात्मक और शैक्षिक योजना में कम्प्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल

vkbMik dk;Øe e| f'k{k.k%

संयोजक, पाठ्यक्रम 206ः आईडेपा के भाग के रूप में शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग

आईडेपा भागीदार के शोध प्रबंध कार्य का निर्देशन और मूल्यांकन

lko|tfud fudk;k dk ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

सर्व शिक्षा अभियान–III, विश्व बैंक तैयारी मिशन के लिए यू–डाईस पर एक प्रस्तुति, जून 2013

सर्व शिक्षा अभियान और आरएसएसए, जेआरएम के लिए यू–डाईस पर एक प्रस्तुति, जून 2013

अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग, के समक्ष मुस्लिम बच्चों की स्कूल शिक्षा की स्थिति पर एक प्रस्तुति पेश की 1 अक्टूबर, 2013

आरएमएसए टीसीए से संबंधित कई बैठकों में भाग लिया

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति की स्थायी समिति की कई बैठकों में भाग लिया

2013 में उच्च और तकनीकी शिक्षा में अल्पसंख्यकों के संबंध में डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रारूप विकसित करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित समिति का सदस्य

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;kxnku

मेटा डेटा और डेटा मानक के कई बैठकों में भाग लिया

भूटान के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) पर पाठ्यक्रम का शिक्षण

शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण विभाग

utek v[rj ¼foHkkxk/;{k½

çdk'ku

एक्सेस टू हायर एजुकेशन अमंग मार्जलेनाईस्ड ग्रुप इन इंडिया : आब्जेक्टिव एंड प्रामिसिंग एवन्यू (सह लेखक) डावरसाईट–कैनेडियन ('क्यूबेक और भारत में इक्विटी पुनर्विचारः समावेशी सोसायटी की ओर' पर अंक), वॉल्यूम–10.1, स्प्रिंग 2013, पृ.सं. 91–95,

चैलेन्जस् आफ टीचर मेंनेजमेंट इन द डवलपिंग वर्ल्ड–क्वालिटी डवलपमेंट ट्रेजेक्टरी (सह लेखक), जामिया जर्नल आफ एजुकेशन, वॉल्यूम. 1, नंबर 1, 2014.

बैलेन्सिंग डाइवरसिटी एंड कॉमन सोशलाईजेशन : कम्पेरिंग एजुकेशन डिबेट्स इन इंडिया क्यूबेक 'क्यूबेक और भारत में इक्विटी पर पुनर्विचार अंक में, (सह लेखक) कैनेडियन विविधता (कैनेडियन स्टडीज एसोसिएशन का द्विभाषी प्रकाशन), वॉल्यूम. 10: 1 स्प्रिंग 2013 पृ.सं. 70–75

lfeukj@lEeyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक सत्र की अध्यक्षता की

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, मार्च 5–6, 2014 तक आयोजित

dk;'kkyk,@lEeyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;¨tu

उत्तर प्रदेश के 600 डी.आई.ओ.एस., बी.एस.ए. तथा बी.ई.ओ. ने भाग लिया। 23–24 अप्रैल, 2013 तक भाग लिया शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन।

अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों, के प्रमुखों के लिए पांचवां वार्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम, 04–08 नवम्बर, 2013।

अल्पसंख्यक प्रबंधित माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों के लिए संस्था निर्माण में वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम, 08–20 नवम्बर, 2013

06–10 जनवरी, 2014, जिला शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण, गुजरात की योजना और प्रबंधन शाखा के संकाय के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, न्यूपा

जनवरी 23–25, 2014 में – आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमताओं के निर्माण के क्रम में डाइट संकाय के प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान पर पूर्वोत्तर प्रशिक्षण कार्यशाला, असम (पूर्वोत्तर राज्य)

ओडिशा और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे आश्रम स्कूलों के स्कूल प्रमुखों के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने में सहायता प्रदान की.

'स्तर के पार एक अधिकार के रूप में शिक्षा : चुनौतियां, अवसर और रणनीति' पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित जामिया मिलिया इस्लामिया, समिति, शिक्षा और यूनेस्को के दिल्ली कार्यालय के संकाय के एक सदस्य के रूप में 10 मार्च और 11 मार्च, 2014 को सत्र की अध्यक्षता।

çf'k{k.k lkexh vkj ikB;Øe fodfl r vkj fu"ikfnr

प्रशिक्षण डिजाइन, मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रबंधित स्कूलों के प्रमुखों के लिए संस्था निर्माण पर सामग्री

प्रशिक्षण डिजाइन और सामग्री, अल्पसंख्यक प्रबंधित डिग्री कॉलेजों के लिए शैक्षिक प्रशासन कार्यक्रम के लिए विकसित

स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए साझा अनुभव उपकरण

उच्च शिक्षण संस्थान के संस्थागत प्रमुखों के लिए साझा–अनुभव प्रपत्र।

स्कूलों के जिला निरीक्षक के लिए प्रशिक्षण की जरूरत मूल्यांकन के लिए उपकरण (हिन्दी में)

vU; 'k{kf.kd xfrfof/k;k

Mik@vkbMik fuc/k ekxn'ku%

सुश्री नफीस फातिमा द्वारा ''श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में संघर्ष क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा'' पर निर्देशित डेपा। शोध प्रबंध (डेपा–XXXIV)

शोध प्रबंध निर्देशित ''मुद्दे और मुख्य धारा में चुनौतियों का एक अध्ययन – रोहतक के शहरी वंचित बच्चे'' (डेपा–XXXIII)

मार्गदर्शन सुश्री खुयेन दिन नगोक बिच को (वियतनाम) ''प्रायोगिक स्कूल वी.एन.ई.एस, में आईसीटी (आईडेपा–XXIX) का अनुप्रयोग

एम.फिल./पीएच.डी. अनुसंधान मार्गदर्शनः

पी–एच.डी. ''अनुशासन के उपायों और माध्यमिक स्कूलों के प्रबंधन का एक अध्ययनः इलाहाबाद के एक मामले'' पर सुश्री नम्रता को मार्गदर्शन (अब प्रस्तुत)

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;¨xnku

fMIy¨ek dk;Øe@dk;Øe fun'kd d : i e vk;¨ftr%

29वें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (आईडेपा), 30 अप्रैल, 2013 को तीन महीने के कार्यक्रम के समापन में भागीदारी

34वें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमा कार्यक्रम (डेपा), सितम्बर–नवम्बर, 2013

33वां आरडी शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमा कार्यक्रम (डेपा) 20–24 मई, 2013

dk;Øe fun'kd d : i e vk;¨ftr vrjk"Vh; vuj¨/k dk;Øe%

भूटान, 5 मई, जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम–2 जून, 2013

शैक्षिक योजना और प्रबंधन, 13–29 नवम्बर, 2013 में इंडोनेशिया के शिक्षा अधिकारियों की अध्ययन यात्रा

lkoltfud fudk;¨ d¨ ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित सदस्य, आदर्श शिक्षा संहिता की तैयारी पर समिति के रूप में, भारत सरकार की समिति की एक बैठक में भाग लिया, 30 अप्रैल, 2013.

सदस्य, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा अनुसंधान सलाहकार समिति, की बैठक में भाग लिया, 14 मई 2013

प्रधानाध्यापकों पर संघ लोक सेवा आयोग की विशेषज्ञ चयन समिति की बैठक में भाग लिया, 16–21 सितंबर 2013।

सदस्य के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया, संकाय की शिक्षा समिति की बैठक में भाग लिया, 23 सितंबर 2013

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, की बैठक में भाग लिया, 28 सितंबर 2013,

संसाधन व्यक्ति के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), की बैठक में भाग लिया, 3 अक्टूबर 2013

सदस्य, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के स्कूल की शिक्षक समिति की बैठक में भाग लिया, 30 अक्टूबर 2013

सदस्य, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शैक्षणिक सलाहकार समिति, की 40वीं बैठक में भाग लिया, 18 नवंबर, 2013.

डीईजीएसएन, एनआईई कैम्पस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, की विभागीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लिया, 11 दिसंबर 2013

यूजीसी की विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, पांच विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गठित 11 नवंबर 2013 और 27 जनवरी 2014 को क्रमशः पहली और दूसरी बैठक में भाग लिया।

संसाधन व्यक्ति के रूप में, 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूलों के साथ अधिकांश प्रयोगशालाओं को जोड़ने – सबसे ग्रांड एलायंस' पर बुद्धिशीलता बैठक

में भाग लिया, प्रौद्योगिकी भवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014 का विभाग

पीजी शैक्षिक कार्यक्रम 2013–15 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए पोस्ट–ग्रेजुएट इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत पुरस्कार के चयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में समिति की बैठक में भाग लिया, 4–6 फरवरी, 2014

विशेषज्ञ के रूप में, एन.सी.आर.एम.पी. क्षमता निर्माण अध्ययन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, (एनआईडीएम), नई दिल्ली, के तहत मान्यता और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर कार्यशाला में भाग लिया, 5 फरवरी, 2014

'हुनर से रोजगार तक' पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, भारत इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली, में भाग लिया, 26 फ़रवरी, 2014

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, में आयोजित उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, पर एक सत्र की अध्यक्षता की 5–6, मार्च 2014

एडसिल द्वारा आयोजित मुस्लिम पूर्व प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन नामक परियोजना के लिए विशेषज्ञ बैठक में भाग लिया। सर्व शिक्षा अभियान, के लिए सीआईएल टीएसजी समूह, 14 मार्च, 2014

यूजीसी ऑब्जर्वर, जे.एन.यू. चयन समिति की बैठक, 21 मार्च, 2014

रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कार्यकारी परिषद में राज्यपाल के नामिती के रूप में,, परिषद, की विशेष बैठक में भाग लिया, 26 मार्च 2014

U;ik dk ckgj ç[;kr fudk;¨ dh lnL;rk

यूजीसी की सलाहकार समिति में यूजीसी पद के नामिती – अकादमिक स्टाफ कॉलेज, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (सीजी)

यूजीसी अकादमिक स्टाफ कॉलेज की सलाहकार समिति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में यूजीसी पद के नामिती

यू.जी.सी. अध्यक्ष डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए गायत्री विद्या परिषद कॉलेज की स्वायत्त स्थिति का विस्तार करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, एमवीपी कैम्पस/कालोनी, विशाखापत्तनम

यूजीसी के अध्यक्ष (केरल) एमईएस मनपॉड कॉलेज, मलप्पुरम के स्वायत्त स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित

यूजीसी ऑब्जर्वर के रूप में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) के तहत व्याख्याता से प्रोफेसर के लिए चयन प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु जेएनयू चयन समिति की बैठक में भाग लिया, 21 मार्च, 2014

सदस्य, कई स्कूलों की प्रबंधन समिति पर डीपीएस सोसायटी

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कार्यकारी परिषद में राज्यपाल के नामिती

सदस्य, डीईजीएसएन की विभागीय सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर, एनसीईआरटी

बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, यूजीसी नामिती, जेएसएस लॉ कॉलेज (मैसूर विश्वविद्यालय)

भारती विद्यापीठ, डीम्ड विश्वविद्यालय, पुणे की अनुश्रवण और योजना बोर्ड पर यूजीसी नामिती

कार्यकारी परिषद में आंगतु नामिती, जामिया मिलिया इस्लामिया

सदस्य, शासी निकाय, वायु सेना, केन्द्रीय विद्यालय

सदस्य, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति, एनसीईआरटी,

सदस्य, कोबसे की कार्यकारी समिति

मानद सदस्य, अल्पसंख्यक बालिका शिक्षा के मुद्दों का समर्थन करने के लिए विशेष जनादेश के साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएमईआइ)

शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति पर आगन्तु नामिती

सदस्य, यूजीसी विशेषज्ञ समिति महाराजा कॉलेज, विजयनगरम (आंध्र विश्वविद्यालय) की स्वायत्त स्थिति

के विस्तार के लिए प्रदर्शन और शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु

सदस्य, इंदौर विश्वविद्यालय, इंदौर के अकादमिक स्टाफ कॉलेज की सलाहकार समिति

सदस्य, अध्ययन बोर्ड, सी.जी.एस. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली.

सदस्य, जाईट के लिए केवीएस सलाहकार समिति

सदस्य, एप्लाइड मैनपावर रिसर्च संस्थान की जनशक्ति जर्नल का संपादकीय बोर्ड

ch-d- ikMk

çdk'ku

iLrd@v/;k;%

स्टडी आफ पार्टिसीपेशन अमंग शेड्यूल कास्ट गर्ल्स इन स्कूल्स, एलएपी लैम्बर्ट शैक्षणिक प्रकाशन, जर्मनी, आईएसबीएन नंबर 978–3–659–8484–4398–7, 2012, पृ. 106.

एक्सेज एंड पार्टिसिपेशन आफ ट्राइब्स चिल्ड्रन इन स्कूल इन इंडिया, एलएपी लैम्बर्ट शैक्षणिक प्रकाशन, जर्मनी, आईएसबीएन नंबर 978–3–659–25274–7, 2012, पृ. 102.

मध्य प्रदेश और कर्नाटक का एक तुलनात्मक अध्ययन – प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रबंधन, एलएपी लैम्बर्ट शैक्षणिक प्रकाशन, जर्मनी, 25372–7 2013 आईएसबीएन नंबर 978–3–659, पृ. सं. 82..

शहरी गरीबों की शिक्षा: दिल्ली के स्लम निवासियों का एक अध्ययन, एलएपी लैम्बर्ट शैक्षणिक प्रकाशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आईएसबीएन नंबर 978–3–659–45366–3, 2013, पृ. सं. 95.

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh %

एक्सेज टू हायर एजूकेशन अमंग मार्जेनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया : आब्जेक्टिब्स एंड प्रमिसिंग एवेन्यू (सह–लेखक) इन डाइवर्सेटीज़–कैनेडियन 'क्यूबेक और भारत में इक्विटी पुनर्विचारः समावेशी सोसायटी की ओर' पर अंक, वॉल्यूम. 10.1, स्प्रिंग 2013, पृ.सं. 91–95

''विकासशील देशों में टीचर प्रबंधन की चुनौतियां – गुणवत्ता के विकास प्रक्षेपवक'' जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, खंड द्वारा शुरू की एक पत्रिका में (सह लेखक). नंबर 1, 2014., जिल्द–1

''आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया का संपादनः विकास के लिए कुंजी के रूप में मातृ भाषा'' (आदिवासी भाषा और संस्कृति), पर विशेषांक वॉल्यूम. 52, नंबर 1 और 2 जून और दिसंबर 2012, (आईएसबीएन सं 2277–7245) पृ सं. 1–9.

''अनुसूचित जनजातियों की सेवा–आश्रम स्कूलों का सशक्तीकरण – एक आत्मनिरीक्षण,'' सामाजिक गजट, वॉल्यूम. 12, नंबर 3, 2013, पृ.सं. 25–38.

lkotfud fudk;¨ d¨ ijke'k vkj vdknfed lgk;rk

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर में एनसीईआरटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य

आईआईएफटी, नई दिल्ली में तकनीकी संस्थानों के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया.

lfork d©'ky

çdk'ku

iLrd@v/;k;%

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, 2014ः 'एजुकेशन एज़ ए राईट अक्रॉस द लेवल्सः चैलेन्जेस, अर्पच्यूनिटीज़ एंड स्ट्रेटीज़ पुस्तक में 'एजुकेशन आफ मार्जेनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स ओपन स्कूलिंग' पर अध्याय, वीवा ग्रुप प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 652–666

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh

अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया पर लेख प्राथमिक शिक्षक, जुलाई से अक्टूबर 2013

प्रोलिफिरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्सः एक विश्लेषण. इंटरनेशनल जर्नल, ज्ञान भव, शिक्षक शिक्षा, पर जर्नल

वॉल्यूम. 2, नंबर 1, 2013 फरवरी, आईएसएसएन नं. 23198419

(मुस्लिम समुदाय के विशेष संदर्भ में) सीमांत सामाजिक समूह की शैक्षिक स्थिति. सामाजिक विज्ञान का प्राणगनया जर्नल , अंक संख्या 4, खंड 1 सितंबर 2013, आईएसबीएन नंबर 2229–4864

किताब में अनुच्छेद ''विद्यालय नेतृत्व को एक अवधारणा के तौर पर समझना प्रारंभिक पाठन लेखन के लिये बेहतर विद्यालय नेतृत्व एक रूप–रेखा'', दिल्ली

jk"Vªh;

'वायु सेना के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का शैक्षिक सम्मेलन', एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2013 को 'स्कूल के नेतृत्व और संगठनात्मक विकास' विषय पर व्याख्यान दिया।

वायु सेना स्कूल, एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली, 28 नवंबर, 2013 को वायु सेना के कार्यकारी निदेशक और हेड मिस्ट्रेज़ को 'प्रारंभिक वर्षों में मल्टी स्किल डेवलपमेंट पर सोच' विषय पर, रिसोर्स पर्सन के रूप में, व्याख्यान दिया

'2014 अगले अच्छे कदम के लिए खेल का प्रयोग' विकास और शांति के लिये खेल, दिल्ली, 10–14 फ़रवरी, 2014 को आयोजित सम्मेलन में भाग। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

vUrjjk"Vªh;

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली के सहयोग से जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित 'चुनौतियों, अवसरों के स्तर के पार एक अधिकार के रूप में शिक्षा पर 2014 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में ''ओपन स्कूलिंग के माध्यम से सीमांत सामाजिक समूहों की शिक्षा के लिए रणनीति'' पर आलेख प्रस्तुत 10–11 मार्च, 2014, यूनेस्को

dk;Z'kkyk,a@lEesyu@çf'k{k.k dk;ZØe dk vk;¨tu

जिला शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण गुजरात, योजना और प्रबंधन शाखा संकाय के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वित, 6–10 जनवरी, 2014, न्यूपा

vU; 'kS{kf.kd xfrfof/k;k

मीडिया स्टडीज और प्रशासन में 2 रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित, 14 जनवरी से 3 फ़रवरी 2014

lkoZtfud fudk;¨a d¨ ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

पी–एच.डी. के मूल्यांकन के लिए परीक्षक – एक केस स्टडी कैदी छात्रों को सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के संबंध में अनाथालयों की पारिस्थितिकी विषय पर शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में सुश्री असफ़िया दानिशयार की थीसिस

सदस्य, शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पाठ्यक्रम संशोधन समिति के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, दिल्ली, 14 जून और 24 जून 2013, समिति की बैठकों में भाग लिया।

सदस्य, मुक्त विद्यालय के माध्यम से पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास की समिति, एनआईओएस, 13 और 20 जुलाई 2013 को समिति की बैठक में भाग लिया, पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए एक अध्याय का योगदान।

एम.एड. के वायवा–वोज़ के लिए विशेषज्ञ, नोबल कॉलेज, आफ एजुकेशन डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

पढ़ने के लिए 'कक्ष', स्कूल नेतृत्व द्वारा पुस्तिका के विकास हेतु समर्थन

बीएड के वायवा–वोज़ के लिए विशेषज्ञ के रूप में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित छात्रों के लिए परीक्षाएं

त्रिपुरा और लक्षद्वीप, आर.एम.एस.ए. की वार्षिक कार्य योजना तैयार, मूल्यांकन रिपोर्ट

vU; 'kSf{kd vkSj 0;kolkf;d ;¨xnku

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन कोर्स में 34वां डिप्लोमा समन्वित

अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों, के प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण में पांचवें वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम में

भाग लिया और योगदान दिया, 4–8 नवम्बर, 2013

'शैक्षिक योजना और प्रबंधन में इंडोनेशिया के शिक्षा अधिकारियों की अध्ययन यात्रा', में भागीदारी और योगदान 13–30 नवम्बर, 2013

'मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रबंधित माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों के लिए संस्थान योजना' में आठवें वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया और योगदान दिया, 09–20 दिसम्बर, 2013

e¨uk lnoky

çdk'ku

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh

'शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दोंः एक नीति के परिप्रेक्ष्य', में 'शिक्षा के स्तर के पार एक अधिकार के रूप मेंः चुनौतियां, अवसर और रणनीतियां', अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 2014 वीवा समूह प्राइवेट लिमिटेड. नई दिल्ली, पृ.सं. 1429–1436.

iLrd@y[k leh{kk%

कक्षा (सं. रोनाल्ड ए बेघेटो और जेम्स सी कॉफ़मैन) में रचनात्मकता का पोषण, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2010 शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के जर्नल, वॉल्यूम. ग्गटप्, नंबर–2 अप्रैल, 2013, पृ. 217–219.

अमिता गोविंदा की पुस्तक 'द आर्ट ऑफ सेन्सिटिव पेरेन्टिंग' (पुस्तक महल, नई दिल्ली), की समीक्षा, पुस्तक समीक्षा, वॉल्यूम. 37, अंक–9 सितंबर, 2013, पृ. 27–28.

lfeukj@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

'बारहवीं पंचवर्षीय योजनाः सामाजिक क्षेत्र के लिए चुनौतियां और अवसर' विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद (आईसीआरआईईआर) और कोनराड– आदिनायर स्टिफटंग (कास), गुलमोहर हॉल, इंडिया हैबिटैट सेंटर द्वारा आयोजित, नई दिल्ली, 27 मई 2013

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), द्वारा सीआईईटी ऑडिटोरियम, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली में 30–31 जुलाई, 2013 तक संयुक्त रूप से आयोजित आईएएसई के सुदृढ़ीकरण पर कार्यशाला में भाग लिया

'स्कूल के शिक्षकों की कामकाजी दशा' पर राष्ट्रीय अध्ययन, न्यूपा, नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2013 की एक बैठक में भाग लिया।

'क्या प्रोत्साहन नीतियों से अनुसूचित जाति के बच्चों की स्कूल में भागीदारी बढ़ती है' शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत

अनिल बोर्डिया मेमोरियल नीति संगोष्ठी में शिक्षा और सामाजिक अधिकारिताः नीतियों और प्रथाओं विषय पर सम्मेलन? न्यूपा, नई दिल्ली, 16–17 दिसंबर, 2013

समीक्षा और स्कूल नेतृत्व, भारत पर्यावास केन्द्र, राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा आयोजित स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, की योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया, न्यूपा, 19–20 मार्च, 2014

vrjk"Vh;%

'इक्विटी, समावेशन और स्थिरता लोकतंत्र, शिक्षा और विकास' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, न्यूपा, कुतुब होटल, नई दिल्ली, मार्च 6–8, 2014

शिक्षा संकाय द्वारा आयोजितः चुनौतियां, अवसर और रणनीति स्तर के पार एक अधिकार के रूप में शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, 2014ः ''एक नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों'' पर शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत, यूनेस्को, नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, मार्च 10–11, 2014, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सहयोग से

dk;Z'kkyk,@lEesyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;¨tu

शिक्षा विभाग के सहयोग से न्यूपा द्वारा आयोजित डी. आई.ओ.एस., बी.एस.ए. और उत्तर प्रदेश के बी.ई.ओ.एस. के लिए ''शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए आयोजन दल के सदस्य, उत्तर

प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, 23–24 अप्रैल, 2013 (अध्यक्ष के रूप में दो सत्र भी समन्वित)

भूटान, के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायक कार्यक्रम समन्वयक, 5 मई–2 जून, 2013

मीडिया कार्यशाला, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, न्यूपा द्वारा आयोजित, 'आर स्कूल लीडर्स द मीसिंग लिंक इन क्वालिटी सम्प्रूवमेंट' में समन्वयन, 7 अगस्त 2013।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्षमता निर्माण में उन्मुखीकरण कार्यक्रम समनवित, न्यूपा, नई दिल्ली, 4–8 नवम्बर 2013।

शैक्षिक योजना और प्रबंधन, इंडोनेशिया के शिक्षा अधिकारियों की अध्ययन यात्रा के लिए सहायक कार्यक्रम समन्वयक, न्यूपा, 13–30 नवंबर, 2013

अल्पसंख्यक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, के प्रमुखों के लिए संस्थागत योजना में आठवां उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए सहायक कार्यक्रम समन्वयक, न्यूपा, 09–20 दिसम्बर, 2013।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण (डाइट) संस्थान, गुवाहाटी (असम), क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत योजना और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम समन्वयक, 22–24 जनवरी, 2014।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और निष्पादित

'एक बहुशिक्षण अग्रणी स्कूल प्रधान शिक्षकों के लिए एक व्यावहारिक गाइड' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल, जनवरी 2014 (डॉ रश्मि दीवान, एसोसिएट प्रोफेसर, न्यूपा के साथ संयुक्त रूप से विकसित)

lkoZtfud fudk;¨ d¨ ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

चंडीगढ़ राज्य के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, 5 जून, 2013 की बैठक में भाग लिया।

कोलम्बो प्लान पैनलबद्ध संस्थान के आईटीईसी/एससीएएपी/टीसीएस, विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली, 6 अगस्त 2013 की सह–क्रियात्मक बैठक में भाग लिया

गुणवत्ता समावेशी शिक्षा और विकेंद्रीकृत स्कूल प्रशासन, शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन, प्रदर्शन में अच्छा व्यवहार पर अध्ययन रिपोर्ट के लोकार्पण में भाग लिया; और इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के रूप में एक तकनीकी सहयोग कोष के अन्तर्गत आयोग)

संसाधन व्यक्ति, आईटीआई प्रधानाध्यापकों के लिए छह दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शिक्षण के तरीके पर दो सत्र, आईआईएफटी भवन, नई दिल्ली, 21 फरवरी 2014 को आयोजित

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) और मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा आयोजित भारत की पहलः नौकरियां, विकास और प्रभावी बुनियादी सेवाओं के लिए गरीबी से सशक्तिकरण मैक्किंज़े ग्लोबल इंस्टिट्यूट (एमजीएल) रिपोर्ट के लोकार्पण में भाग लिया इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 3 मार्च, 2014।

संसाधन व्यक्ति, आईटीआई प्रधानाध्यापकों के लिए छह दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शिक्षण के तरीके पर दो सत्र, आईआईएफटी भवन, नई दिल्ली, 4 मार्च 2014, को आयोजित।

अन्य शैक्षिक और व्यावसायिक योगदान शैक्षिक योजना और न्यूपा, नई दिल्ली, 30वें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा के लिए कार्यक्रम समन्वयक फरवरी–अप्रैल, 2013 (22 देशों से 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया)

U;ik d ckgj ç[;kr fudk;¨ dh lnL;rk

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी (सीईएसआई), दिल्ली

आजीवन सदस्य, शैक्षिक अनुसंधान के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन (एआईएईआर), भुवनेश्वर

स्कूल नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

l|dk;% jf'e nhoku ¼foHkkxk/;{k½] l|uhrk p|x] d';ih voLFkh] l|fHkrk th-oh- e|uu] ,u- e|fFkyh] J|;k frokjh

दो राष्ट्रीय स्तर दस्तावेजों अर्थात स्कूल नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन और पाठ्यचर्या की रूपरेखा और एक पुस्तिका, एनसीएसएल की प्रत्येक टीम के सदस्य से योगदान के साथ केंद्र की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में 2013–14 में प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, चार गतिविधियों सहित– पाठ्यक्रम और सामग्री विकास, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग और संस्था निर्माण, और अनुसंधान और विकास के साथ, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से एनसीएसएल द्वारा वर्ष के दौरान निम्नाकिंत कार्य किए गए:

1- ikB;Øe vkj lkexh fodkl

स्कूल नेतृत्व विकास, एनसीएसएल पर विकसित और मुद्रित कार्यक्रम रूपरेखा पाठ्यक्रम ढांचा और हस्तपुस्तिका

राष्ट्रीय शिक्षण कॉलेज और नेतृत्व (एनसीटीएल), यूकेआईईआरआई के सहयोग से विकसित पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक को प्रकाशित किया, स्कूल नेतृत्व विकास पायलट कार्यक्रम

स्कूल के नेतृत्व मानकों पर विकास (एनसीटीएल के साथ साझेदारी में) कार्यशाला, न्यूपा, 17–18 अप्रैल, 2013

कार्यशाला, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में मानक रूपरेखा पर चर्चा के लिए नव नियुक्त प्रधान शिक्षक के लिए क्षमता निर्माण कार्य कार्यक्रम की रूपरेखा (एनसीटीएल के साथ साझेदारी में) न्यूपा, 23–24 अप्रैल, 2013

स्कूल नेतृत्व और पाठ्यक्रम सामग्री विकास, 27–29 मई, 2013 के दौरान कार्यशाला, न्यूपा, नई दिल्ली

समीक्षा और वर्तमान एनसीटीएल (नॉटिंघम) पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला और स्कूल नेतृत्व का संशोधित स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, राजस्थान, 02–22 जून, 2013

समीक्षा और मौजूदा एनसीटीएल (नॉटिंघम) पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला और स्कूल के नेतृत्व का संशोधित स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, तमिलनाडु, 17–19 जून, 2013

समेकित पाठ्यक्रम और मानकों ढांचे के बंटवारे पर कार्यशाला, न्यूपा, 24–25 जून, 2013

राष्ट्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय संसाधन समूह, न्यूपा, 21–22 अक्टूबर, 2013, स्कूल के नेतृत्व पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण और सामग्री के लिए

2- {kerk fuek.k

उत्तर प्रदेश में संसाधन समूह का क्षमता निर्माण, 9–11 अक्टूबर, 2013

तमिलनाडु, 21–25 अक्टूबर, 2013 में मास्टर ट्रेनर के 5 दिवसीय क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण का प्रथम चरण यूकेआईईआरआई

तमिलनाडु, यूकेआईईआरआई, 19–21 दिसंबर, 2013 के दौरान मास्टर ट्रेनर के 3 दिवसीय क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण का दूसरा चरण

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 23–28 दिसम्बर, 2013 के दो ब्लॉकों में स्कूल प्रमुखों का क्षमता निर्माण

राजस्थान, यूकेआईईआरआई 6–10 जनवरी, 2014 में मास्टर ट्रेनर के 5 दिवसीय क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण का प्रथम चरण

गुजरात में स्कूल नेतृत्व विकास, 7–11 जनवरी, 2014 के दौरान हैंडबुक पर राज्य संसाधन समूह के उन्मुखीकरण पर कार्यशाला

तमिलनाडु, 8–10 जनवरी, 2014 और 27 फरवरी–1 मार्च, 2014 को स्कूल प्रमुखों की क्लस्टर आधारित क्षमता निर्माण

दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव, न्यूपा, 13–23 जनवरी, 2014 स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल के नेतृत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में स्कूल नेतृत्व विकास पर हैंडबुक पर राज्य संसाधन समूह के उन्मुखीकरण पर कार्यशाला, 29–31 जरवरी, 2014

राजस्थान, यूकेआईईआरआई, 30 जनवरी–1 फरवरी, 2014 के दौरान 3 दिवसीय क्षमता निर्माण और मास्टर ट्रेनर के कौशल निर्माण का दूसरा चरण।

आंध्र प्रदेश में स्कूल नेतृत्व विकास पर हैंडबुक पर राज्य संसाधन समूह के उन्मुखीकरण पर कार्यशाला, 11–13 फरवरी, 2014

मिजोरम में स्कूल नेतृत्व विकास पर हैंडबुक पर राज्य संसाधन समूह के उन्मुखीकरण पर कार्यशाला, फरवरी 12–14, 2014

राजस्थान में स्कूल प्रमुखों का क्लस्टर आधारित क्षमता निर्माण 27 फरवरी–2 मार्च, 2014,

राष्ट्रीय समीक्षा और योजना कार्यशाला, न्यूपा, 19–20 मार्च, 2014

3- uVofdx vkj lLFkk fuek.k%

स्कूल नेतृत्व पर राज्य परामर्श उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 29 जुलाई, 2013

स्कूल नेतृत्व पर राज्य परामर्श और गुजरात में विकास, 16 अगस्त 2013

स्कूल नेतृत्व पर राज्य परामर्श और आंध्र प्रदेश में विकास, 26 अगस्त 2013

स्कूल नेतृत्व पर राज्य परामर्श और केरल में विकास, 29 अगस्त, 2013

स्कूल नेतृत्व पर राज्य परामर्श और हिमाचल प्रदेश का विकास, 17 सितंबर, 2013

स्कूल के नेतृत्व विकास पर राज्य परामर्श और मिजोरम का विकास, 3 अक्टूबर, 2013

मिजोरम, एससीईआरटी, साझेदारी और पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण के लिए राज्य संसाधन समूह के साथ राज्य परामर्श और कार्यशाला, 3–5 अक्टूबर, 2013

स्कूल के नेतृत्व पर राज्य परामर्श और पश्चिम बंगाल में विकास, नवंबर, 22–23 2013

गुजरात, पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण और साझेदारी के लिए राज्य संसाधन समूह के साथ कार्यशाला, 22–23 नवंबर, 2013

पश्चिम बंगाल, एससीईआरटी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण और साझेदारी के लिए राज्य संसाधन समूह के साथ राज्य परामर्श और कार्यशाला

स्कूल के नेतृत्व पर राज्य परामर्श और छत्तीसगढ़ में विकास, 12–13 दिसंबर, 2013

छत्तीसगढ़, एससीईआरटी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भीकरण और साझेदारी के लिए राज्य संसाधन समूह के साथ कार्यशाला, 13–14 दिसंबर, 2013

कर्नाटक में स्कूल का नेतृत्व और विकास, जनवरी 8–9, 2014 के दौरान राज्य को परामर्श

4- vuqla/kku vkj fodkl%

प्रमुख अध्ययन ''स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सात अनुसंधान क्षेत्रों की रूपरेखा के अलावा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग।

केंद्र द्वारा की गई उपरोक्त चार गतिविधियों के अलावा, एनसीएसएल के संकाय साल में निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल रहे।

lqhrk pqx

vuqla/kku v/;;u

10 लाख से अधिक शहरों की मलिन बस्तियों, में स्कूली शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और प्रशिक्षण उपलब्धि पर अनुसंधान रिपोर्ट पूरी की।

lfeukj@lEesyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

अरुणाचल प्रदेश की स्कूल शिक्षा में ब्लॉक और जिला स्तर के प्रशासकों, 18–19 सितम्बर, 2013 के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया,

''कक्षा संपादन में गुणवत्ता – वार्षिक कार्य योजना के अधिगम आधार परिणाम'' पर एक कार्यशाला में भाग लिया, एडसिल, 10 जनवरी 2014

dk;Z'kkyk,¡@lEesyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;¨tu

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और टीएसजी के साथ समन्वय और समय समय पर विभिन्न मंचों पर एनसीएसएल में विकास पर प्रस्तुतीकरण किया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

2014–15 के लिए चयन राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास के लिए पी.ए.बी. बैठकों में भाग लिया

स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की समिति के सदस्य

संघर्ष क्षेत्र, में बच्चों की शिक्षा पर संचालन समिति के सदस्य, यूनिसेफ

d';ih voLFkh

lkoZtfud fudk;¨a d¨ ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

2014–2015 के लिए 18 चयनित राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास की पी.ए.बी. बैठकों में भागीदारी।

vU; 'kSf{kd vkSj 0;kolkf;d ;¨xnku

टीएसजी, एडसिल और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ एन.सी.एस.एल. के लिए कार्य योजना एवं बजट प्रारूप के लिए मंत्रालय के साथ विभिन्न बैठकों में योजना विकसित करने के लिए समन्वयन

lqfHkFkk th-oh- euu

çdk'ku

'k¨/k i=@yss[k@fVIi.kh

क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन कौशल शिक्षा प्रदान कर रहा है? भारत शिक्षा समीक्षा (अतिथि अनुच्छेद खंड), 2013

भारत, में ओ.डी.ई. टीचर ट्रेनिंग की चुनौतियों का सामना? एशियन जर्नल आफ डिस्टेन्स एजुकेशन वॉल्यूम. 11.2, 2013

,u- efFkyh

lxks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

सार्वजनिक प्रणाली, हैदराबाद, 24 अक्टूबर, 2013 को नवाचार के लिए केंद्र द्वारा आयोजित लोक प्रशासन में नवप्रवर्तन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में, ''आंध्र प्रदेश के लिए स्कूल नेतृत्व विकास'' पर एक रोड मैप शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत किया।

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

,u-oh- oxhZt ¼foHkkxk/;{k½

çdk'ku

आई.डब्ल्यू.जी.ई. से एक सारांशः फ्राम स्कूलिंग टू लर्निंग/यूनेस्को, 2013ः पेरिस.

हायर एजुकेशन इन एशियाः एक्सपैन्ड आऊट, एक्सपैडिंग उप–ग्रेजुएट एजुकेशन यूनिवर्सिटी बेसड् रिसर्च, यू.एन. यू./एलसिवियर 2014

अफ्रीका में उच्च शिक्षा के अभिशासन में सुधारः एक नीति फोरम की रिपोर्ट (जॉनसन इशेनगोमा और पास्कल होबा)। आईआईईपी/यूनेस्को और एएयू अकरा, 2013 का संयुक्त प्रकाशन।

डाइवरसीफिकेशन आफ पोस्ट सैकेण्डरी एजुकेशन : पेरिस : आईआईईपी/यूनेस्को 2014, आईआईईपी

''फोर ट्रेंड्स इन रिवाईविन्ग हायर एजुकेशन ग्लोबली'', एड्टेक, वॉल्यूम. सं.–3, 2014 पृ. 6–7.

ग्लोबलाईजेशन हायर एजुकेशन : चेन्जिंग ट्रेंड्स इन नाईट एजुकेशन विश्लेषणात्मक इंटरनेशनल पर रिपोर्टें, वॉल्यूम. 5 नंबर 1 दिसंबर, 2013, पृ. सं. 7–20

अफ्रीका में उच्च शिक्षा में सरकार और अभिशासन में सुधारष अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, 2013 शीत।

प्राइवेट हायर एजुकेशन : दि ग्लोबल सर्ज एंड इंडियन कर्न्सन भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट: शिक्षा में निजी क्षेत्र, लंदन और नई दिल्ली, रूटलेज (टेलर और फ्रांसिस), आईडीएफसी, 2013; पीपी. 145–156.

''गवर्नेंस रिफार्म्स इन अफ्रीकन हायर एजुकेशनः दि मीसिन्ग लिंक अफ्रीकी उच्च शिक्षा क्रॉनिकल, नंबर 3, मार्च 2013 (इंटरनेशनल उच्च शिक्षा केंद्र, बोस्टन, बोस्टन कॉलेज के लिए)।

jk"Vªh;%

'शैक्षिक योजना एवं प्रशासन' पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में ''शैक्षिक योजना'', बंगलौर, 7–8 जनवरी, 2014 पर प्रस्तुति

'उच्च शिक्षा में हाल के रुझान' पर राष्ट्रीय सम्मेलन, लोयोला कॉलेज, चेन्नई, 15–16 फरवरी, 2014 में मुख्य भाषण.

vUrjjk"Vªh;%

ब्रिटिश काउंसिल, मुंबई, द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई वार्ता में 'उच्च शिक्षा और रोजगार' पर प्रस्तुति 9–10 जनवरी, 2014।

'लोकतंत्र, शिक्षा, समता और स्थिरता से संबंधित विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, न्यूपा, 6–8 मार्च, 2014

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;¨xnku

सीपीआरएचई सलाहकार समिति, की पहली बैठक आयोजित, 4 फरवरी, 2014

सीपीआरएचई कार्यकारी समिति, की पहली बैठक आयोजित, 26 फ़रवरी 2014

उच्च शिक्षा में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, द्वारा आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषद के दो दिवसीय परामर्शदाताओं की बैठक, न्यूपा 25–26 मार्च, 2014

मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ

,l- bjQku gchc] ç¨Ql j

çdk'ku

इज भगत सिंह रिलेवन्ट टूडे? प्रगति, इ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट रिव्यू, मार्च 2013

(एड्सं. नूपुर दासगुप्ता और अमित भट्टाचार्य), कोलकाता 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहास विषय' पर 'आधुनिक विज्ञान और समकालीन इस्लाम में धार्मिक कट्टरपंथियों के साथ संलग्नता' 2014. पृ. सं. 92–120. फारगैटन इनहैरिटन्स आफ आज़ाद हिंदू, 22 फ़रवरी, 2014

lxk"Bh@lEeyu@dk;'kkyk e Hkkxhnkjh

jk"Vªh;%

'भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और चिकित्सा पर अध्ययनरू सामाजिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक आर्थिक

अनुसंधान अन्वेषण' पर एक संगोष्ठी में भाग लिया, आईआईटी, चेन्नई, 2 जनवरी 2014.

प्रगतिशील विचार के लिए फोरम द्वारा आयोजित ''जिहाद या इजतिहाद'' पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया, चेन्नई, 3 जनवरी, 2014

''सार्वभौमिक भाईचारे का इस्लामी संस्करण'' और इसके निहितार्थ पर व्याख्यान, 2014 प्रो हीरालाल गुप्ता व्याख्यान, लोयोला कॉलेज, चेन्नई, 14 फरवरी, 2014

vUrjjk"Vªh;%

आगन्तुक प्रोफेसर, विज्ञान और शिक्षा, ब्रिटेन, के इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर चार सार्वजनिक व्याख्यान दिए, अप्रैल–जून, 2013

dk;l'kkyk,@lEesyu@çf'k{k.k dk;Øe dk vk;¨tu

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, एनेक्सी, 'री–कालोनाइजिंग द माईन्ड' पर प्रोफेसर पीटर डिसूजा ने चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद व्याख्यान दिया, 11 नवम्बर, 2013

शिक्षक प्रबंधन और विकास पर राजीव गांधी फाउंडेशन

foeyk jkepæu] ç¨Qslj

अध्यापक प्रबंधन और विकास पर न्यास, जून 2013 को प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ गठित हुआ। जिसका काम एक सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित है, इसका मुख्य उद्देश्य, शिक्षक प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करने के लिए है और विकास और शिक्षक प्रबंधन और संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के साथ संवाद/विचार विमर्श आरंभ करने में यह प्रयासरत हैं।

çdk'ku

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh

वर्किंग पेपर 'एसेलटेटिंग प्रोग्रेस टू 2015–इंडिया' (ज़ान्थे एकरमैन के साथः सह लेखक)। वैश्विक शिक्षा पहली पहल और गुड प्लैनेट फाउंडेशन। वाशिंगटन डीसी. अमरीका, अप्रैल 2013

द सरप्राइजिंग हायर एजुकेशन आफ चिल्ड्रन्स एजुकेशन इन रुरल वेस्ट अफ्रीका : रिज़ल्ट्स फ्राम द सी.आर.ई.ओ. स्टडी इन गुयाना बिसाऊ (पीटर बूने, इलाफाजिया, कामेश्वरी, जांध्याला, चित्रालाजाअंती, सिमॉन जॉनसन, फिलिपा सिल्वा और झारगुआ झान के साथ सह–लेखक)। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो. कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, अप्रैल 2013

हमारे स्कूलों में एक दलित या आदिवासी बच्चे होने का क्या मतलब है:. छह राज्यों का गुणात्मक अध्ययन (तारामनी नाओरम के साथ सह–लेखक) का संश्लेषण इकॉनमिक एंड पालिटिकल वीकली वाल्यूम XLVIII नं. 2, नवंबर, 2013.

''गुणवत्तायुक्त समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन और विकेंद्रीकृत स्कूल प्रशासन'' पर अनुसंधान रिपोर्ट (ईआरयू रिसर्च टीम के साथ सह लेखक). यूरोपीय संघ, न्यूपा, नई दिल्ली, दिसंबर 2013

'इक्विटी और गुणवत्ताः भारत की स्कूल शिक्षा में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं' एनएमएमएल समसामयिक पत्र। पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन डवलपमेंट, न्यू सीरीज़ 23 नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली, जनवरी 2014

vu¡l/kku v/;;u

pkyw

नौ राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के काम की परिस्थितियों पर एक अध्ययन शुरू। झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश. इस परियोजना को नौ राज्यों में अनुसंधान भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अध्येता

,- eFk;w

çdk'ku

iLrd

लिटरेसी एंड एडलट एजुकेशन : सलेक्ट रीडिंग्स 2014, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली, (संयुक्त रूप से प्रो. जांध्याला बी.जी. तिलक के साथ संपादित) का चुनिंदा पाठ

'k¨/k i=@y[k@fVIi.kh%

'द राइट टू एजुकेशन आफ चिल्ड्रन आफ लेसर गॉड : नान फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया' (संयुक्त रूप से प्रो आर गोविंदा के साथ), प्रौढ़ शिक्षा, इंडियन जर्नल ऑफ एडलट एजुकेशन, वॉल्यूम 74, संख्या 3, जुलाई से सितंबर 2013, पीपी. 97–130

jk"Vh;%

''प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक अधिकारिताः भारतीय अनुभव'' पर अनिल बोर्डिया मेमोरियल 'शिक्षा और सामाजिक अधिकारिताः नीतियां और प्रथाएं', राष्ट्रीय संगोष्ठी में आलेख प्रस्तुत किया, न्यूपा, 16–17 दिसंबर, 2013

vrjk"Vh;%

तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''प्रौढ़ शिक्षा के साथ भारत के संबंधों'' पर (सी.ई.एस.आई.), कोलकाता, 28–30 दिसंबर, 2013 को आलेख प्रस्तुत किया

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'लोकतंत्र, शिक्षा और विकासः समावेशन, इक्विटी और स्थिरता से संबंधित मुद्दे', न्यूपा में पॉलिटिक्स आफ स्कूल एजुकेशन : देयर एक्सक्लूज़न, इन इक्विटी एंड अन–ससटेनबिलिटी प्रोपेनसिटीज़' पर (संयुक्त रूप से प्रो. आर. गोविंदा के साथ) आलेख प्रस्तुत, 6–8 मार्च, 2014

vU; 'kf{kd vkj 0;kolkf;d ;¨xnku

परियोजना प्रभारी, न्यूपा डिजिटल अभिलेखागार शिक्षा दस्तावेज़, (न्यूपा के एक विस्तारित चेहरे के रूप में) एक पोर्टल के तहत शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों और क्षेत्रों की नीति से संबंधित शिक्षा दस्तावेजों के ई संस्करण प्रदान करता है।

jRuk ,e lqn'ku

lxk"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

jk"Vh;%

'इनेबलिंग इक्वालिटी : गर्ल्स एजुकेशन, सोशल नार्मस एंड कम्यूनिटी इंटरवेंशन्स' पर आलेख प्रस्तुत

'नीतियों और प्रथाओंः शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण' पर अनिल बोर्डिया मेमोरियल सेमिनार में प्रस्तुत, न्यूपा, नई दिल्ली, दिसंबर 16–17, 2013

vrjk"Vh;%

दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसएएस), सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, 'निर्धारकों, आयाम और गतिशीलता भारतीय रोजगार चुनौती' पर गोलमेज सम्मेलनः 'एम्प्लायमेंट–रिसपोन्सिव एजुकेशन एंड द इनफॉरमल इकॉनमी : कांटेक्स्ट एंड चैलेन्जेस' 'विषय पर आलेख प्रस्तुत, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विभाग सिडनी विश्वविद्यालय, आईसीएएस, सिंगापुर, 25–26 फरवरी, 2014

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

न्यूपा परिषद् के सदस्य

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

v/;{k

1. डा. एम.एम. पल्लम राजू
   माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री
   भारत सरकार,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

mik/;{k

2. प्रो. आर गोविंदा
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली –110016

inu lnL;

3. सचिव
   भारत सरकार
   उच्च शिक्षा विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   नई दिल्ली–110001

4. सचिव
   भारत सरकार
   विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   नई दिल्ली–110001

5. अध्यक्ष
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   नई दिल्ली–110002

6. निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
   नई दिल्ली–110016

7. वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   भारत सरकार
   नई दिल्ली–110001

U;ik ifj"kn dk v/;{k }kjk ifjØeokj eukuhr jkT; ifrfufek ¼ikp {k=k l s ,d&,d lnL;½

8. सचिव, (विद्यालय शिक्षा)
   तमिलनाडु सरकार
   सचिवालय
   फोर्ट सेंट जॉर्ज, गिन्डी
   चेन्नई–600009

9. सचिव (उच्च शिक्षा)
   गुजरात सरकार
   ब्लॉक नं. 5, सातवीं मंजिल
   न्यू सचिवालय कॉम्प्लेक्स
   गांधीनगर–382010

10. सचिव (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा)
    दिल्ली सरकार
    मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा
    दिल्ली–110034

11. आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा)
नागालैंड सरकार
सिविल सचिवालय, कोहिमा–797001
नागालैंड

12 सचिव (स्कूल शिक्षा)
छत्तीसगढ़ सरकार
डीकेएस भवन, मंत्रालय
रायपुर–469001
छत्तीसगढ़

i[;kr f'k{kkfon

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

13. श्री राजेन्द्र एस. पवार
अध्यक्ष, एनआईआईटी लि.
सैक्टर 32, प्लाट नं. 85
गुड़गांव (हरियाणा)

14. प्रो. दीपक नैयर
पूर्व कुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय
एफ–5, फ्रैण्ड्स कॉलोनी (पश्चिम)
नई दिल्ली–110065

15. प्रो. पंकज चन्द्रा
निदेशक
भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर
बनेरघाटा रोड
बंगलौर–560076

U;kik lkdk;

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

16. प्रो. जांध्याला बी.जी. तिलक
अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त विभाग
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

17. श्री बसवराज स्वामी *सचिव*
कुलसचिव
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट-II

प्रबंधन बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

1. प्रो. आर. गोविंदा, *अध्यक्ष*
   कुलपति
   न्यूपा, नई दिल्ली – 110016

lnL;

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

2. प्रो. फरीदा खान
   अध्यक्ष
   शिक्षा विभाग
   शैक्षिक अध्ययन जामिया मिल्लिया इस्लामिया
   विश्वविद्यालय
   जामिया नगर, नई दिल्ली–110025

3. प्रो. एम. आनन्दकृष्णन
   अध्यक्ष, आईआईटी कानपुर
   नं. 8/15, पांचवां मेन रोड,
   मदन अपार्टमेंट,
   कस्तूरीबाई नगर, अडयर चेन्नई–600020

4. प्रो. पीटर रोनॉल्ड डिसूजा
   निदेशक
   अन्तर्राष्ट्रीय मानव विकास केन्द्र
   29, राजपुर रोड,
   दिल्ली

vU; lnL;

5. श्री अमित खरे, आईएएस
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

6. प्रो. जांध्याल्या बी.जी. तिलक,
   अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

7. प्रो. के. सुजाता
   शैक्षिक प्रशासन
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

8. डा. वाई. जोसेफिन
   सह–प्रोफेसर
   शैक्षिक प्रशासनक विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

9. श्री बसवराज स्वामी, *सचिव*
   कुलसचिव
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट-III

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

1. प्रो. आर. गोविंदा, *अध्यक्ष*
   कुलपति *(पदेन)*
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली–110016

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित सदस्य)

2. डा. बी.के. महापात्रा
   कुलसचिव
   श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
   नई महरौली रोड
   नई दिल्ली–110067

3. श्री एन यू सिदि्दकी
   पूर्व वित्त अधिकारी
   जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
   जामिया नगर
   नई दिल्ली–110025

ek-l-fo-e=ky; dk ifrfuf/k

4. वित्तीय सलाहकार
   मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

vU; lnL;

5. प्रो. एन.डी. माथुर,
   अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
   सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान
   किशनगढ़, अजमेर
   राजस्थान

6. श्री बसवराज स्वामी *विशेष आमंत्रिती*
   कुलसचिव
   न्यूपा
   नई दिल्ली – 110016

7. श्रीमती उषा त्यागराजन, *सचिव*
   वित्त अधिकारी
   न्यूपा
   नई दिल्ली–110016

अकादमिक परिषद के सदस्य

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

1. प्रो. आर. गोविंदा *अध्यक्ष*
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली – 110016

foHkkxk/;{k] U;ik

2. प्रो. जांध्याला बी.जी. तिलक
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

3. प्रो. के. सुजाता
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशासन विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

4. प्रो. (श्रीमती) नजमा अख्तर
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

5. प्रो. सुधांशु भूषण
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली – 110016

6. प्रो. अरुण. सी. मेहता
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली – 110016

7. प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक योजना विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली . 110016

8. प्रो. ए.के. सिंह
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शिक्षा–आधार विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

9. प्रो. नलिनी जुनेजा
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

fo[;kr f'k{kkfon

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

10. प्रो. एन. जयराम
    टाटा इस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज
    पोस्ट बॉक्स 8313, देवनार, मुंबई–400088

11. प्रो. एन.जे. कुरियन
मानव प्रोफेसर
समाज विकास परिषद, संघ रचना
53, लोधी इस्टेट
नई दिल्ली–110003

12. प्रो. गीता सेन
भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर
बनेरघाटा रोड,
बंगलौर–560076

¼dyifr] U;kl }kjk ukfer½

13. प्रो. सतीश देशपाण्डे
समाजशास्त्र विभाग
दिल्ली स्कूल आफ इकानमिक्स
दिल्ली विश्वविद्यालय

14. प्रो. एच. रामचन्द्रन
आई.सी.एस.एस.आर., राष्ट्रीय अध्येता
ई–1675, पालम विहार
गुड़गांव

15. प्रो. पी. बालकृष्णन, पूर्व निदेशक
विकास अध्ययन केन्द्र
प्रशान्त नगर के पास,
उल्लूर, त्रिवेन्द्रम–695011

U;kl lnL;

16. डा. रश्मि दीवान
प्रोफेसर
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

16. डा. आर.एस. त्यागी
सह–प्रोफेसर
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

17. श्री बसवराज स्वामी *सचिव*
कुलसचिव
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट-V

अध्ययन बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

1. प्रो. आर. गोविंदा, *अध्यक्ष*
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली

2. डीन
   न्यूपा, नई दिल्ली 110 016

foHkkxk/;{k] U;ik

3. प्रो. जांध्याला बी.जी. तिलक
   शैक्षिक वित्त विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली 110016

4. प्रो. के. सुजाता
   शैक्षिक प्रशासन विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली 110016

5. प्रो. (श्रीमती) नजमा अख्तर
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110016

6. प्रो. सुधांशु भूषण
   उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली 110016

7. प्रो. अरुण सी. मेहता
   शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली 110016

8. प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी
   शैक्षिक योजना विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली 110016

9. प्रो. नीलम सूद
   विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली 110016

10. प्रो. ए.के. सिंह
    शैक्षिक नीति विभाग
    न्यूपा, नई दिल्ली–110016

vU; U;ik ldk;

(कुलपति, न्यूपा द्वारा नामित)

11. प्रो. (श्रीमती) वीरा गुप्ता
    सह–प्रोफेसर
    न्यूपा, नई दिल्ली 110016

12. डा. आर.एस. त्यागी
    सह–प्रोफेसर
    न्यूपा, नई दिल्ली–110016

d|yifr] U;|ik }kjk lg;kftr fo'k"kK

13. प्रो. एम. आनन्दकृष्णन
नं. 8, पांचवा मेन रोड,
मदन अपार्टमेंट, द्वितीय तल
कस्तूरबा नगर, चेन्नई–600020

14. प्रो. सतेन्द्र कुमार
विभागाध्यक्ष
शिक्षा संकाय
एम एस विश्वविद्यालय, बड़ौदा
बड़ोदड़ा

15. श्री बसवराज स्वामी *सचिव*
कुलसचिव
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट-VI

संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ

(31 मार्च, 2014 के अनुसार)

d|yifr
प्रो. आर. गोविंदा

'kf{kd ;ktuk foHkkx
एस.एम.आई.ए. जैदी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
मोना खरे, प्रोफेसर
के. बिस्वाल, प्रोफेसर
एन.के. मोहंती, सहायक प्रोफेसर
सुमन नेगी, सहायक प्रोफेसर

'kf{kd i'kklu foHkkx
के. सुजाता, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
कुमार सुरेश, प्रोफेसर
विनीता सिरोही, सह–प्रोफेसर
आर.एस. त्यागी, सह–प्रोफेसर
मंजू नरूला, सहायक प्रोफेसर
वी. सुचरिता, सहायक प्रोफेसर

'kf{kd foÙk foHkkx
जांध्याला बी.जी. तिलक, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वाई. जोसेफिन, प्रोफेसर
पी. गीता रानी, सह–प्रोफेसर
वेटुकुरी पी.एस. राजू, सहायक प्रोफेसर

'kf{kd uhfr foHkkx
अविनाश के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वीरा गुप्ता, सह–प्रोफेसर
एस.के. मलिक, सहायक प्रोफेसर
नरेश कुमार, सहायक प्रोफेसर

fo|ky; vkj vukSipkfjd f'k{kk foHkkx
नलिनी जुनेजा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
नीलम सूद, प्रोफेसर
प्रणती पांडा, प्रोफेसर
रश्मि दीवान, प्रोफेसर
मधुमिता बंद्योपाध्याय, सह–प्रोफेसर
कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर

mPp vkj 0;kolkf;d f'k{kk foHkkx
सुधांशु भूषण, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
आरती श्रीवास्तव, सह–प्रोफेसर
नीरू स्नेही, सहायक प्रोफेसर
कौसर विजारत, सहायक प्रोफेसर
संगीता अंगोम, सहायक प्रोफेसर

'kf{kd izc/ku lwpuk iz.kkyh foHkkx
अरुण सी. मेहता, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
श्री ए.एन. रेड्डी, सहायक प्रोफेसर

'kf{kd izf'k{k.k ,o {kerk fodkl foHkkx
नज़मा अख्तर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
डा. बी.के. पंडा, प्रोफेसर
सविता कौशल, सहायक प्रोफेसर
मोना सेदवाल, सहायक प्रोफेसर

jk"Vh; fo|ky; urRo dsUn
रश्मि दीवान, प्रोफेसर तथा समन्वयक
सुनीता चुग, परियोजना सह–प्रोफेसर
एन. मैथिली, सहायक प्रोफेसर
सुविथा जी.वी., सहायक प्रोफेसर
श्रेया तिवारी, सहायक प्रोफेसर

jk"Vh; mPp f'k{kk uhfr vuqla/kku dsUn
एन.वी. वर्गीज, निदेशक

ekSykuk vcqy dyke vktkn ihB
एस. इरफान हबीब, प्रोफेसर

v/;kid izca/ku vkSj fodkl ij jktho xka/kh LFkkiuk ihB
विमला रामचन्द्रन, प्रोफेसर

jk"Vh; v/;srk
ए. मैथ्यू, प्रोफेसर
रत्ना मंगला सुदर्शन, प्रोफेसर

lykgdkj ¼vkbZ-,-vkbZ-bZ-ih-,- ifj;kstuk½
के. रामचन्द्रन, प्रोफेसर

iz'kklfud vkSj vdknfed lg;ksx

dqy lfpo
बसवराज स्वामी

lkekU; vkSj dkfeZd iz'kklu
जी. वीराबाहु, प्रशासनिक अधिकारी
जय प्रकाश धामी, अनुभाग अधिकारी
बी.आर. पहवा, अनुभाग अधिकारी (प्रभारी)

vdknfed iz'kklu
पी.पी. सक्सेना, अनुभाग अधिकारी

foÙk vkSj ys[kk
उषा त्यागराजन, वित्त अधिकारी
चंद्र प्रकाश, अनुभाग अधिकारी

izf'k{k.k d{k
पी.एन. त्यागी, प्रशिक्षण अधिकारी

izdk'ku ,dd
प्रमोद रावत, उप प्रकाशन अधिकारी

fganh d{k
डा. सुभाष शर्मा, हिंदी संपादक और सहायक हॉस्टल वार्डन

iqLrdky; vkSj iqys[ku dsUn
पूजा सिंह, पुस्तकालयाध्यक्षा
डी.एस. ठाकुर, प्रलेखन अधिकारी

dEI;wVj dsUn
श्री नवीन भाटिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनलिस्ट (प्रभारी)

VII

वार्षिक लेखा

2013-14

तुलन पत्र
31 मार्च 2014 के अनुसार

lex vkj ithxr fuf/k rFkk n;rk,	vu lph	31-03-2014 d vulkj	31-03-2013 d vulkj
पूंजीकृत निधि	1	19,83,25,068	16,56,76,185
पूंजीकृत जमा	2	4,65,126	3,81,110
चिन्हित/कल्याण निधि (जी.पी.एफ.)	3	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (विशिष्ट परियोजना)	4	2,68,02,043	2,05,37,975
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	5,96,57,702	5,26,09,553
;kx		**28,52,49,939**	**23,92,04,823**
ifjlifÙk;k			
अचल संपत्तियां	6	17,81,88,975	14,30,37,082
सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम	7	4,45,73,558	4,36,48,999
भविष्य निधि में निवेश	8	-	
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगियां	9	6,24,87,406	5,25,18,742
;kx		**28,52,49,939**	**23,92,04,823**
लेखा की महत्वपूर्ण नीतियां और लेखा पर टिप्पणियां	19	-	-
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियां	20		

ह./–	ह./–	ह./–
¼m"kk R;kxjktu½	¼clojkt Lokeh½	¼vkj- xkfonk½
वित्त अधिकारी	*कुलसचिव*	*कुलपति*

आय और व्यय लेखा
31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष

vk;	vulph	Pkkyw o"kZ	foxr o"kZ
अनुदान / उपादान	10	20,81,16,353	17,66,99,431
निवेश से आय	11	-	-
रायल्टी, प्रकाशन से आय	12	2,38,853	2,89,660
ब्याज से आय	13	34,06,180	19,58,580
अन्य आय	14	1,12,48,211	2,18,22,321
;ksx ¼v½		**22,30,09,597**	**20,07,69,992**
व्यय			
स्थापना व्यय	15	14,29,39,013	12,67,57,280
अन्य प्रशासनिक व्यय	16	8,83,03,927	9,83,30,603
प्रकाशन व्यय	17	15,03,220	16,31,289
परिसंपत्तियों की बिक्री में हानि	18	-	25,22,936
अवमूल्यन	6	94,98,201	70,56,667
;ksx ¼c½		**24,22,44,361**	**23,62,98,775**
जोड़कर : अतिरिक्त आय/व्यय		(1,92,34,764)	(3,55,28,783)

ह./–	ह./–	ह./–
¼m"kk R;kxjktu½	¼clojkt Lokeh½	¼vkj- xkfonk½
वित्त अधिकारी	*कुलसचिव*	*कुलपति*

तुलन पत्र का अनुसूचीबद्ध विवरण
31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष

अनुसूची 1
पूंजीकृत निधि

fooj.k	31-03-2014 d vu|lkj		31-03-2013 d vu|lkj	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	16,56,76,185		15,78,80,399	
वर्ष के दौरान जमा	1,87,85,636		2,10,62,059	
जमाः वर्ष के दौरान पूंजीकृत निर्माण	2,57,80,442		2,22,62,510	
जमाः पिछले वर्ष 2010–11 के पूंजीकृत को जोड़कर	73,17,569			
;kx		**21,75,59,832**		**20,12,04,968**
जमाः व्यय से अधिक आय	-		-	
घटाकरः आय से अधिक व्यय	1,92,34,764	1,92,34,764	3,55,28,783	3,55,28,783
o"kZ d vr e 'k"k		**19,83,25,068**		**16,56,76,185**

अनुसूची 2
पूंजीकृत आरक्षित निधि

fooj.k	31-03-2014 d vu|lkj		31-03-2013 d vu|lkj	
i t hd r nku fuf/k				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,81,110		3,74,886	
वर्ष में नई वृद्धि	84,016		6,224	
;kx		**4,65,126**		**3,81,110**

अनुसूची 3
चिन्हित/कल्याण निधि

fooj.k	31-03-2014 d vu|lkj		31-03-2013 d vu|lkj	
¼d½ th-ih-,Q-				
अ) अर्थ शेष	-		-	
ब) निधि (जी.पी.एफ., सी.पी.एफ.) में वृद्धि	-		-	
;kx ¼v½ $ ¼c½	-		-	
स) निधि का उद्देश्यों हेतु प्रयोग (निकासी)	-		-	
fuoy 'k"k	-		-	

अनुसूची 4
विशिष्ट परियोजनाएं

fooj.k	31-03-2014 d vu|lkj		31-03-2013 d vu|lkj	
परियोजना के लिये विशिष्ट अनुदान				
(अ) निधि का रोकड़ जमा	2,05,37,975		3,95,78,837	
(ब) निधि/ब्याज/विविध प्राप्तियों में वर्ष के दौरान वृद्धि	4,14,99,960		2,25,98,830	
;kx ¼v½ $ ¼c½		6,20,37,935		6,21,77,667
(स) निधि क`उद्देश्यों हेतु प्रयोग (निकासी) निवल शेष	3,52,35,892		4,16,39,692	
fuoy 'k"k		2,68,02,043		2,05,37,975

अनुसूची 5
अन्य देयताएं तथा प्रावधान

fooj.k	31-03-2014 d vu|lkj		31-03-2013 d vu|lkj	
orZeku ns;rk,a				
1. सुरक्षा जमा	4,91,883		4,54,993	
2. जर्नल शुल्क (अग्रिम)	1,49,846		1,54,560	
3. सी.पी.एफ. (देय)	15,973		-	
4. प्रावधान :– ग्रेच्यूटी	90,00,000		80,00,000	
– अवकाश वेतन	50,00,000		40,00,000	
– पेंशन	4,50,00,000		4,00,00,000	
;kx		5,96,57,702		5,26,09,553

अनुसूची 6

अचल परिसंपत्तियां

fooj.k	voeY;u nj	ifjlifÙk [kM				voeY;u	ifjlifÙk [kM
		vr'k"k	o"kZ dk nkSjku of} 2013&14	o"kZ dk nkSjku lek;kstu /kVkdj 31-03-14	ykxr eY;kdu 31-03-14	o"kZ dk nkSjku voeY;u 2013&14	vr'k"k 31-03-2014
A vpy ifjlifÙk							
1 भूमि	0%	2,17,215	20,90,677	-	23,07,892	-	23,07,892
2 भवन	2%	9,59,80,683	3,30,98,011	-	12,90,78,694	25,81,574	12,64,97,120
3 वाहन	10%	12,26,482	-	-	12,26,482	1,22,648	11,03,834
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	1,11,70,726	11,25,118	-	1,22,95,844	9,22,188	1,13,73,656
5 कंप्यूटर / सहायक सामाग्री	20%	25,61,002	19,82,795	-	45,43,797	9,08,759	36,35,038
6 कंप्यूटर साफटवेयर	40%	-	6,35,369	-	6,35,369	2,54,148	3,81,221
7 फर्नीचर, फिक्सर और फिटिंग	7.5%	59,62,501	6,52,565	-	66,15,066	4,96,130	61,18,936
8 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	30,34,472	29,81,886	-	60,16,358	6,01,636	54,14,722
9 जर्नल	10%	1,40,08,706	72,44,469	-	2,12,53,175	21,25,318	1,91,27,856
10 ई–जर्नल	40%	15,57,727	21,56,773	-	37,14,500	14,85,800	22,28,700
;kx ¼v½		13,57,19,513	5,19,67,663	-	18,76,87,177	94,98,201	17,81,88,975
11 जारी कार्य (सीविल)		56,25,013	-	56,25,013	-	-	-
12 जारी कार्य (वीधुत)		16,92,556	-	16,92,556	-	-	-
;kx ¼c½		73,17,569	-	73,17,569	-	-	-
;kx ¼v&c½		14,30,37,082	5,19,67,663	73,17,569	18,76,87,177	94,98,201	17,81,88,975

अनुसूची 7
सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम

fooj.k	31-03-2014 d vulkj		31-03-2013 d vulkj	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4,36,48,999		4,64,30,015	
वर्ष के दौरान जमा (सिविल/इलैक्ट्रिकल विभाग)	2,40,39,027		2,83,53,512	
वर्ष के दौरान निर्माण पूंजीकृत (सिविल)	(1,63,36,484)		(2,22,62,510)	
वर्ष के दौरान निर्माण पूंजीकृत (इलैक्ट्रिकल)	(64,67,150)		-	
वर्ष के दौरान ए.आर.एम.ओ. प्रभार (सिविल)	-		(50,71,692)	
वर्ष के दौरान ए.आर.एम.ओ. प्रभार (इलैक्ट्रिकल)	(3,10,834)		(27,16,914)	
वर्ष के दौरान जारी कार्य	-	4,45,73,558	(10,83,412)	4,36,48,999
;kx		**4,45,73,558**		**4,36,48,999**

अनुसूची 8
चिन्हित / कल्याण निधि में निवेश

fooj.k	31-03-2014 d vulkj	31-03-2013 d vulkj	
th-ih-,Q- l			
1. एफ.डी.आर./राष्ट्रीयकृत बैंकों के विशेष निवेश/डाकखाना सावधि जमा / आर.बी.आई. बॉण्ड		-	
;kx			-

अनुसूची 9

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

fooj.k	31-03-2014 dk vuqlkj		31-03-2013 dk vuqlkj	
¼v½- orZeku ifjlEifÙk;k				
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया (10137881320)	1,11,70,481		58,75,225	
2. सिंडीकेट बैंक (योजना) 91392010001112	30,79,571		95,76,067	
3. सिंडीकेट बैंक (परियोजना) 91392010001092	2,68,02,043		2,05,37,975	
4. सिंडीकेट बैंक (हॉस्टल) 91392015365	3,16,534		3,04,243	
5. कैनरा बैंक 25536	2,02,29,377		1,51,74,304	
6. डाक टिकट हस्तगत	48,709	6,16,46,715	98,562	5,15,66,376
;ksx ¼v½		**6,16,46,715**		**5,15,66,376**
¼c½- _.k] vfxze rFkk vU; ifjlEifÙk;k				
1- _.k @ LVkQ%				
त्योहार अग्रिम	1,10,625		88,500	
स्कूटर अग्रिम	19,965		36,845	
भवन निर्माण अग्रिम	64,950		86,550	
कंप्यूटर अग्रिम	34,500		54,000	
मोटर कार अग्रिम	1,20,000		1,56,000	
th-,l-,y-vkb-,l-	**2,280**	**3,52,320**	**440**	**4,22,335**
2- udn ;k oLrq dk :i esa olwyh ;ksX; ij'kfx;k vkj vU; /kujkf'k				
क). सुरक्षा जमा	98,298		98,298	
ख). ऋण और अग्रिम पर ब्याज	92,768		1,65,340	
ग). प्रकाशन हस्तगत	2,97,305	4,88,371	2,66,393	5,30,031
;ksx ¼c½		**8,40,691**		**9,52,366**
;ksx ¼v½ $ ¼c½		**6,24,87,406**		**5,25,18,742**

वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का अनुसूचीबद्ध विवरण

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 10

अनुदान / सब्सिडी (गैर वसूलीयोग्य अनुदान तथा सहायता और प्राप्त सब्सिडी)

	fooj.k	pkyw o"kZ		foxr o"kZ	
	Ekkuo lalk/ku fodkl e=ky; Hkkjr ljdkj ls izkIr vuqnku				
1)	;kstukrj	14,15,00,000		10,70,44,000	
	घटाकर: पूंजीकृत	-		(36,04,791)	
	;kx	**14,15,00,000**	14,15,00,000	**10,34,39,209**	**10,34,39,209**
2)	;kstuk	11,85,00,000		11,29,80,000	
	पूंजीकृत घटाकर	(1,87,85,636)		(1,74,57,268)	
	वर्ष 2013–14 का भवन पूंजीकृत घटाकर	(3,30,98,011)		(2,22,62,510)	
	;kx	**6,66,16,353**	6,66,16,353	**7,32,60,222**	**7,32,60,222**
			20,81,16,353		**17,66,99,431**

अनुसूची 11

निवेश से आय

	fooj.k	pkyw o"kZ	foxr o"kZ
1)	ब्याज प्राप्ति	-	-
2)	पी.एफ. जमा खाते पर ब्याज	-	-
3)	वर्ष के दौरान वास्तविक आय	-	-
4)	घटाकर: पिछले वर्ष का ब्याज	-	-
	;kx	-	-

अनुसूची 12

रायल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

	fooj.k	pkyw o"kZ		foxr o"kZ	
1)	रायल्टी से आय		29,183		61,022
2)	प्रकाशन से आय	2,04,956		2,53,968	
3)	पिछले वर्ष की सदस्यता शुल्क	1,54,560		1,29,230	
4)	घटाकर: जर्नल सदस्यता शुल्क अग्रिम	(1,49,846)	2,09,670	(1,54,560)	2,28,638
	;kx		**2,38,853**		**2,89,660**

अनुसूची 13
ब्याज से आय

	fooj.k	pkyw o"kZ		foxr o"kZ	
1)	बचत बैंक खाते पर ब्याज (योजनेतर)	5,97,003		7,70,613	
	बचत बैंक खाते पर ब्याज (योजना)	23,00,806		10,42,825	
	बचत बैंक खाते पर ब्याज (हॉस्टल)	12,292		10,290	
	बचत बैंक खाते पर ब्याज (केनरा बैंक)	4,85,920	33,96,021	-	18,23,728
2)	कर्मचारी ऋण पेशगी पर ब्याज	82,731		4,22,933	
3)	वास्तविक ब्याज	92,768		1,65,340	
4)	घटाकरः पिछले वर्ष का वास्तविक ब्याज	(1,65,340)	10,159	(4,53,421)	1,34,852
	;kx		**34,06,180**		**19,58,580**

अनुसूची 14
विविध आय

	fooj.k	pkyw o"kZ		foxr o"kZ	
1)	विविध आय				
	अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, जल प्रभार, विवरणिका की बिक्री, टेंडर फार्म, विविध प्राप्तियां	13,99,970		11,14,490	
2)	हॉस्टल किराया प्राप्तियां	30,47,880		46,57,171	
3)	अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान	20,22,209		7,75,033	
4)	विद्यार्थी शुल्क	2,09,000		1,14,300	
5)	विविध परियोजनाओं से प्राप्त ऊपरी प्रभार	45,69,152	1,12,48,211	1,51,61,327	2,18,22,321
	;kx		**1,12,48,211**		**2,18,22,321**

अनुसूची 15
स्थापना व्यय

fooj.k	pky o"k			foxr o"k		
	;kturj	;ktuk	;kx	;kturj	;ktuk	;kx
वेतन	4,19,94,616	20,97,210	4,40,91,826	4,17,59,888	25,70,587	4,43,30,475
बोनस और भत्ते तथा ओ.टी.ए.	5,14,49,174	21,73,883	5,36,23,057	4,27,45,981	26,27,088	4,53,73,069
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	37,87,276	-	37,87,276	28,92,739	-	28,92,739
वर्दी	42,040	87,427	1,29,467	14,443	28,672	43,115
अवकाश यात्राा रियायत (एलटीसी)	13,72,038	-	13,72,038	14,28,664	-	14,28,664
पेंशन	2,92,13,686	-	2,92,13,686	2,30,60,348	-	2,30,60,348
ग्रेच्युटी	48,21,025	-	48,21,025	46,03,853	-	46,03,853
अवकाश वेतन	35,18,446	-	35,18,446	33,11,690	-	33,11,690
नई पेंशन योजना	11,58,586	-	11,58,586	8,60,697	-	8,60,697
भविष्य निधि/ सी.पी.एस./एन. पी.एस. पर ब्याज	3,47,626	-	3,47,626	-	-	-
यात्राा भत्ता	75,482	-	75,482	1,20,221	-	1,20,221
शिक्षा शुल्क	8,00,498	-	8,00,498	7,32,409	-	7,32,409
;kx	**13,85,80,493**	**43,58,520**	**14,29,39,013**	**12,15,30,933**	**52,26,347**	**12,67,57,280**

अनुसूची 15 अ
प्रावधानों का आकलन

fooj.k	i'ku	xP;Vh	vodk'k oru
jkdM ckdh	4,00,00,000	80,00,000	40,00,000
घटाकरः वर्ष 2013–14 के दौरान वास्तविक भुगतान	2,42,13,686	38,21,025	25,18,446
31.3.2014 को उपलब्ध शेष	1,57,86,314	41,78,975	14,81,554
31.3.2014 को प्रावधान	4,50,00,000	90,00,000	50,00,000
o"k 2013&14 d fy; ikо/kku	**2,92,13,686**	**48,21,025**	**35,18,446**

अनुसूची 16

अन्य प्रशासनिक व्यय

	fooj.k	pkyw o"kZ			foxr o"kZ		
		;kstukrj	;kstuk	;kx	;kstukrj	;kstuk	;kx
v	vk/kkj lajpuk						
1	किराया/दर/टैक्स	3,69,819	-	3,69,819	3,87,289	4,21,470	8,08,759
2	बिजली/जल प्रभार	88,01,509	31,920	88,33,429	64,62,668	6,94,620	71,57,288
3	सुरक्षा प्रभार	24,115	4,90,803	5,14,918	6,39,487	1,23,845	7,63,332
4	बीमा	18,565	32,395	50,960	60,527	-	60,527
c	lapkj						
1	डाक तथा तार	-	4,86,526	4,86,526	-	3,12,247	3,12,247
2	टेलीफोन तथा फैक्स	8,83,556	89,767	9,73,323	9,55,717	1,03,997	10,59,714
l	vdknfed laLFkkuksa dk vuqnku				-	84,511	84,511
1	विज्ञापन प्रभार	-	22,61,842	22,61,842	-	22,67,311	22,67,311
2	कानूनी प्रभार	72,800	32,800	1,05,600	2,66,000	17,400	2,83,400
n	vU;						
1	अखबार प्रभार	1,25,018	15,228	1,40,246	1,01,836	22,165	1,24,001
2	पोषाहार प्रभार	-	37,65,462	37,65,462	-	27,84,041	27,84,041
3	कार्यक्रम प्रभार	-	42,41,720	42,41,720	-	38,14,000	38,14,000
4	पेट्रोल/तेल/ल्यूब्रीकैन्ट प्रभार	5,74,989	-	5,74,989	4,68,396	-	4,68,396
5	स्टेशनरी प्रभार	-	19,65,503	19,65,503	-	11,74,026	11,74,026
6	लेखा शुल्क	33,350	-	33,350	1,37,385	-	1,37,385
7	बागवानी प्रभार	-	82,994	82,994	-	24,985	24,985
8	फोटोकॉपी प्रभार	-	5,22,015	5,22,015	-	4,60,835	4,60,835
9	संविदा प्रभार	-	10,02,182	10,02,182	-	8,81,513	8,81,513
10	हाऊस कीपिंग प्रभार	9,78,260	17,64,945	27,43,205	9,59,636	9,81,034	19,40,670
11	विविध भुगतान	2,53,167	4,10,921	6,64,088	1,78,301	7,14,796	8,93,097
12	टैक्सी प्रभार	-	2,49,951	2,49,951			
13	कोर्स शुल्क/प्रशिक्षण	-	1,70,750	1,70,750	-	-	-
14	लेखन	-	-	-	-	15,726	15,726

fooj.k	pkyw o"kZ			foxr o"kZ		
	;ktukrj	;ktuk	;kx	;ktukrj	;ktuk	;kx
y ejEer rFkk j[k&j[kko						
1 वाहनों का रख–रखाव	2,04,913	-	2,04,913	1,19,974	-	1,19,974
2 उपकरणों का रख–रखाव	-	33,14,493	33,14,493	-	18,74,665	18,74,665
3 फर्नीचर तथा फिक्चर का रख–रखाव	-	11,58,217	11,58,217	-	51,113	51,113
4 भवन रख–रखाव	-	6,40,130	6,40,130	-	34,59,333	34,59,333
5 सिविल प्रभार (एआरएमओ)	-	-	-		50,71,692	50,71,692
6 विद्युत प्रभार (एआरएमओ)	-	3,10,834	3,10,834		27,16,914	27,16,914
;kx ¼1½	**1,23,40,061**	**2,30,41,398**	**3,53,81,459**	**1,07,37,216**	**2,80,72,239**	**3,88,09,455**
vdknfed@'kks/k 0;;	;ktukrj	;ktuk	;kx	;ktukrj	;ktuk	;kx
अ) छात्रावृत्ति/किताब और योजना अनुदान	-	2,86,678	2,86,678	-	2,76,817	2,76,817
ब) संकाय/स्टाफ को यात्रा भत्ता	-	47,95,519	47,95,519	-	31,22,169	31,22,169
स) भागीदारों को यात्रा भत्ता	-	88,20,207	88,20,207	-	63,36,637	63,36,637
द) संसाधन व्यक्तियों को मानदेय	-	6,48,987	6,48,987	-	4,55,876	4,55,876
;kx ¼2½	-	**1,45,51,391**	**1,45,51,391**	-	**1,01,91,499**	**1,01,91,499**
vdknfed@'kks/k 0;;	;ktukrj	;ktuk	;kx	;ktukrj	;ktuk	;kx
i) विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन	-	1,86,41,133	1,86,41,133	-	2,59,60,526	2,59,60,526
ii) एम.फिल./पी–एच.डी. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	-	59,43,204	59,43,204	-	75,47,308	75,47,308
iii) गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान	-	53,19,967	53,19,967	-	1,24,35,937	1,24,35,937
iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	84,66,773	84,66,773	-	33,85,878	33,85,878
योग (3)	-	3,83,71,077	3,83,71,077	-	4,93,29,649	4,93,29,649
;kx ¼1$2$3½			**8,83,03,927**			**9,83,30,603**

अनुसूची 17

प्रकाशन व्यय

fooj.k	pkyw o"kZ		foxr o"kZ	
प्रकाशन पर व्यय (मुद्रण/जिल्द पर खर्च)	15,34,132		16,44,207	
पिछले वर्ष के स्टाक को जोड़कर	2,66,393		2,53,475	
हस्तगत किताबों का भंडार घटाकर	(2,97,305)		(2,66,393)	
;kx		**15,03,220**		**16,31,289**

अनुसूची 18

परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि

fooj.k	31-03-2014 dh vuqlkj		foxr o"kZ	
ytj dh vuqlkj eY; ¼ekVj lkbfdy½			29,151	
okLrfod eY; ?kVkdj			(4,600)	24,551
कार्यालय उपकरण (कंप्यूटर, अन्य बिजली के उपकरण जैसे ए.सी., वाटर कूलर इत्यादि) 01.04.2011 के मूल्य			26,84,720	
okLrfod eY; ?kVkdj			(5,52,399)	21,32,321
फर्नीचर, फिक्सर और फिटिंग, आदि के 01.04.2011 का मूल्य			3,91,524	
वास्तविक मूल्य घटाकर			(25,460)	3,66,064
;kx				**25,22,936**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

अनुसूची 19

लेखा की महत्वपूर्ण नीतियां

1- Yk[kk fuekZ.k d vk/kkj

1.1. ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखा तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्य पद्धति के बारे में उल्लेख न हो और आमतौर पर लेखा की विधि वास्तविक गणना पर आधारित है।

2- jktLo dh ekU;rk

2.1 विद्यार्थियों की फीस, टेंडर प्रपत्रों तथा प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री, प्रकाशन बिक्री, रायल्टी तथा बचत बैंक खाता और अर्जित आय की वास्तविक आधार पर गणना की जाती है।

2.3 छात्राावास किराया से आय की वास्तविक आधार पर लेखा गणना की जाती है

3- vpy ifjlaifÙk;k

3.1 अचल परिसंपत्तियों को प्राप्ति लागत जैसे ढुलाई भाड़ा, शुल्क और कम प्राप्ति संबंधी आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों की लागत, स्थापित करने तथा उसे प्रयोग करने में आने वाली लागत के साथ लेखा में वर्णित किया जाता है।

3.2 उपहार में प्राप्त पुस्तकों की कीमत का पुस्तक में मुद्रित मूल्य के आधर पर निर्धारित किया जाता है। उपहार में प्राप्त जिन पुस्तकों मे मूल्य पुस्तक में मुद्रित नहीं होते, उनका मूल्यांकन के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

3.3 अचल परिसंपत्तियों की कीमत समुचित अवमूल्यन को घटाकर किया जाता है।

3.4 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स (ई–जर्नल) को पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग रखा जाता है। क्योंकि ऑन–लाईन सुविधा होने के कारण सीमित लाभ की संभावना होती है। यद्यपि ई–जर्नल ठोस रूप में नहीं हैं। व्यय की लागत शैक्षणिक ओर शोध कार्य से जुड़े स्टाफ द्वारा स्थाई एवं सतत ज्ञान के रूपों में प्राप्त लाभों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

3.5 कंप्यूटर और सहायक सामग्री को अर्जित साफ्टवेयर के व्यय से अलग किया गया है। क्योंकि यह कोई ठोस वस्तु नहीं होती और इसकी लुप्तशीलता की दर अपेक्षाकृत उच्च होती है। यद्यपि व्यय पूंजीकृत करने पर साफ्टवेयर की लागत रु. 15,000/– अधिक पाई गई

3.6 राशि रु. 73,17,569/– जारी कार्य के अंतर्गत दिखाया गया है जबकि वह पहले ही पूरा हो चुका था। अतः इसे संबंधित परिसंपत्ति शीर्ष में प्रस्तुत कर दिया गया है।

4- voeY;u

4.2 अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन आयकर अधिनियम 1961 में निर्देशित दर के अनुसार सीधे तौर पर कर दिया जाताा है।

1.	भूमि	0%
2.	भवन	2%
3.	कार्यालय उपकरण	7.5%
4.	कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	20%
5.	फर्नीचर फिक्सर और फिटिंग्स	7.5%
6.	वाहन	10%
7.	पुस्तकालय पुस्तकें और जर्नल	10%
8.	ई–जर्नल	40%
9.	कंप्यूटर साफ्टवेयर	40%

4.2 ई–जर्नल का अवमूल्यन दर प्रतिशत 40% है जबकि पुस्तकालय की पुस्तकों का अवमूल्यन दर 10% है क्योंकि जर्नल सीमित अवधि के लिये प्रयोग के लिये सुलभ कराए जाते हैं।

4.3 कंप्यूटर साफ्टवेयर का अवमूल्यन दर 40% है जबकि कंप्यूटर और सहायक सामग्री का अवमूल्यन दर 20% है।

4.4 अवमूल्यन प्राप्ति की तिथि के बजाए कुल परिसंपत्तियों (वर्ष के दौरान शामिल की गई सभी परिसंपत्तियों सहित) के आधार पर अवमूल्यन प्रदर्शित किया जाता है।

4.5 जब कोई परिसंपित्त पूर्णतः अवमूल्यित कर दी जाती है तब तुलन पत्रा में उसका अपक्षय मूल्य रु. 1.00 रखा जाता है। उसके बाद उसका पुनः अवमूल्यन नहीं किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष शामिल परिसंपत्तियों की मान्य अवमूल्यन दर के आधार पर परिसंपत्ति शीर्ष के अंतर्गत उसकी गणना की जाती है

5- LVkd

5.1 स्टेशनरी, रसायनों तथा स्टोर के अन्य सामान की खरीद पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

6- lsokfuoÙk ykHk

6.1 विश्वविद्यालय के जिन कर्मचारियों की सेवाओं को विश्वविद्यालय सेवा में समाविष्ट कर लिया जाता है, उनके पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन तथा उपदान के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित अवधान लेखा में जमा कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कर्मचारियों से प्राप्त पेंशन योगदान को भी पेंशन लेखा प्रावधान के अंतर्गत जमा कर दिया जाता है।

6.2 सेवानिवृत्त लाभों के प्रावधान, जैसे– पेंशन, उपदान और अवकाश नगदी को अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है न कि वास्तविक गणना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

7- ,e-fQy- vkSj ih&,p-Mh- fo|kfFk;ksa dks Nk=ofÙk

7.1 एम.फिल. और पी.एच.डी. के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से निधि प्राप्त होती है और इसे राजस्व व्यय माना जाता है।

8- fpfdRlk ;kxnku

8.1 न्यूपा की चिकित्सा योजना के अनुसार चिकित्सा योगदान प्राप्त हुआ जिसे गैर–योजना खाता में जमा किया गया क्योंकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति गैर योजना खाता से किया जाता है।

9- ljdkjh vuqnku

9.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार से वर्ष 2012–13 के दौरान कुल अनुदान राशि रु. 2200.24 लाख (योजना 1129.80 लाख रुपए और गैर योजना मद में 1070. 44 लाख रुपए प्राप्त हुए)

9.2 पूंजीगत व्यय (वास्तविक आधार पर) में अधिकतम उपयोग के लिए सरकारी अनुदान को पूंजीगत निधि में स्थानांतरित किया गया।

9.3 राजस्व व्यय (वास्तविक आधार पर) को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदान को वर्ष की आय का अधिकतम उपयोग के रूप में माना गया।

9.4 अनुप्रयुक्त अनुदान को आगामी वर्ष के लिए ले जाया गया और उसे तुलनपत्र में देयताएं के रूप में प्रस्तुत किया गया।

10- xSj ljdkjh lxBuk dk vuqnku

10.1 गैर सरकारी संगठनों के अनुदान/वित्तीय सहायता प्रयोजन के लिये है इसलिए इसे समान योजना खाता के अंतर्गत माना जाता है

11- ik;kftr ifj;ktuk,

11.1 पहले से जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में, प्रायोजनों से प्राप्त धनराशि 'चालू देयताएं और प्रावधान–चालू देयताएं–अन्य देयताएं, शीर्ष के अंतर्गत जमा कर दिया जाता है। ऐसे परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को आवंटित शीर्ष प्रभार/प्रशासनिक प्रभार और देयताएं लेखा से निकाल लिया जाता है। परियोजनाओं के ऊपरी प्रभार को परियोजना प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाता है। परियोजनाओं से वसूले अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार केनरा बैंक बचत खाता सं. 25536 में जमा करा दिया जाता है।

अनुसूची 20

आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियां

1- vuqnku

1.1 वर्ष 2013–14 के दौरान कुल अनुदान रु. 2,600.00 लाख (योजना– 1,185.00 लाख और गैर–योजना 1,415.00) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.2 वर्ष 2012–13 के लिए तदर्थ बोनस 3,21,218/– अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को भुगतान किया गया।

2- pkyw ns;rk,a vkSj izko/kku

2.1 आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई आयकर योग्य आन नहीं है इसलिए आयकर का प्रावधान आवश्यक नहीं है।

2.2 कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के समय देय भुगतान योग्य देयताएं और सम्मुचयित अवकाश नगदी संबंधी देयताएं का प्रावधान अनुमान के आधार पर किया जाता है।

3- vpy ifjlaifÙk;k

3.1 अचल परिसंपत्तियों केवल योजनागत अनुदान से निर्मित की जाती है।

3.2 वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों को और परिसंपत्तियों के अवमूल्यन का अनुसूची 6 में प्रस्तुत किया गया है।

3.3 अनुसूची 6 में प्रस्तुत अचल परिसंपत्तियों में उन परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है जो प्रायोजित परियोजना निधि से खरीदी जाती हैं और विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं।

4- pkyw ifjlaifÙk;k] _.k vkSj isf'kfx;k

4.1 प्रबंधन की राय के अनुसार चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगियां वास्तविक मूल्य के आधार पर प्रदर्शित हैं जिन्हें तुलनपत्र में कुलराशि के रूप में दिखाया गया है।

4.2 बचत बैंक खाताओं में शेष राशि का विवरण अनुसूची में प्रस्तुत किया गया है।

5- Hkfo"; fuf/k [kkrk vkSj ubZ isa'ku ;kstuk [kkrk

5.1 भविष्य निधि खाते और नई पेंशन योजना खाते सदस्यों के हैं न कि विश्वविद्यालय के, इसलिए इन खातों को विश्वविद्यालय के लेखे से अलग रखा गया है। यद्यपि वर्ष 2012–13 की प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा (वास्तविक आधार पर) और भविष्य निधि लेखा के साथ–साथ नई पेंशन योजना का तुलन पत्र विश्वविद्यालय लेखे के साथ संलग्न किए गए हैं।

6. वर्ष 2013–14 में उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्य रु. 4,65,126/– (पूर्व में रु. 3,81,110/–) था। उपहार में प्राप्त पुस्तकों का अवमूल्यन मूल्य भी दिखाया गया है।

7. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के अंक साथ–साथ दिखाए गए हैं।

8. अंतिक योग के अंकों को निकटवर्ती पूर्णांक रुपये में दिखाया गया है।

9. 31 मार्च, 2014 के तुलन–पत्र और आय तथा व्यय लेखा में एक अभिन्न अंग के रूप में अनुसूची 1–20 को संलग्न किया गया है।

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र
(योजना एवं योजनेत्तर)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त
(वर्ष 2013–14 के लिए)

ikfIr ;k	;k tuk	;k turj	Hkqxrku	;k tuk	;k turj
अर्थशेष	95,76,067	58,75,225	राजस्व व्यय	8,17,29,012	14,39,20,554
मा.सं.वि. मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	11,85,00,000	14,15,00,000	पूंजीगत व्यय/सी.पी. डब्ल्यू.डी. में जमा	4,55,68,290	-
बैंक से बचत खातों पर प्राप्त ब्याज	23,00,806	5,97,003	सुरक्षा जमा/चिकित्सा अग्रिम/वसूली योग्य अग्रिम/जी.एस.एल. आई.सी	-	2,65,750
विविध प्राप्तियां (छात्रावास किराया, लाइसेंस शुल्क जल प्रभार, वसूली योग्य अग्रिम)	-	73,84,557	कुल व्यय	**12,72,97,302**	**14,41,86,304**
			अंतशेष	**30,79,571**	**1,11,70,481**
;kx	**13,03,76,873**	**15,53,56,785**	;kx	**13,03,76,873**	**15,53,56,785**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. का तुलन पत्र

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तिय वर्ष

v{k; fuf/k@iw thxr fuf/k rFkk ns;rk,	31-03-2014 d vuqlkj	31-03-2013 d vuqlkj
चिन्हित / कल्याण निधि (सी.पी.एफ./ जी.पी.एफ.)	11,90,01,273	10,54,73,629
;kx	**11,90,01,273**	**10,54,73,629**
ifjlEifÙk;k		
भविष्य निधि निवेश	11,08,10,209	10,21,18,728
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	44,44,370	22,56,312
निवेश पर ब्याज प्रोद्भूत पर देय नहीं	37,46,694	10,98,589
;kx	**11,90,01,273**	**10,54,73,629**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की आय तथा व्यय लेखा

1.4.2013 से 31.3.2014 तक

vk;	2013-14	2012-13	0;;	2013-14	2012-13
जी.पी.एफ. खाते में हस्तांतरण	71,04,092	87,61,767	जी.पी.एफ. पर अदा किया गया ब्याज	87,96,521	71,32,603
सरकारी अंशदान प्राप्त योजनेतर खाता 1320	3,47,626	-	सी.पी.एफ. पर अदा किया गया ब्याज	25,001	4,11,631
प्रोद्भूत ब्याज	87,87,527	61,39,422	नियोक्ता अंशदान सी. पी.एफ. अभिदाता को देय	62,088	1,45,482
घटाकरः पिछले वर्ष का प्रोद्भूत बयाज	(61,39,422)	(55,12,292)	नियोक्ता अंशदान पर ब्याज सी.पी.एफ. अभिदाता को देय	23,766	1,46,681
			व्यय से अधिक आय (ब्याज जमा में स्थानांतरित)	11,92,447	15,52,500
;kx	**1,00,99,823**	**93,88,897**	;kx	**1,00,99,823**	**93,88,897**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼c lojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की आय तथा व्यय लेखा

1.4.2013 से 31.3.2014 तक

th-ih-,Q-@lh-ih-,Q- vuqlph	31-03-2014 dk vuqlkj		31-03-2013 dk vuqlkj	
रोकड़ बाकी	10,54,73,629		8,71,53,705	
प्राप्त अंशदान (जी.पी.एफ./सी.पी.एफ.)	1,81,88,630		1,96,47,140	
सी.पी.एफ. पर नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	88,21,522		75,44,234	
नियोक्ता अंशदान अभिदाता को देय	62,088		1,45,482	
सी पी एफ नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	23,766		1,46,681	
प्राप्त ब्याज जमा (व्यय से अधिक आय)	11,92,447		15,52,500	
	13,37,62,082		**11,61,89,742**	
घटाकरः निकासी	1,47,60,809	11,90,01,273	1,07,16,113	10,54,73,629
;kx		**11,90,01,273**		**10,54,73,629**
भविष्य निधि में निवेश		11,08,10,209		10,21,18,728
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि		44,44,370		22,56,312
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज पर देय नहीं		37,46,694		10,98,589
;kx		**11,90,01,273**		**10,54,73,629**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की प्राप्ति तथा भुगतान

1.4.2013 से 31.3.2014 तक

ikfIr ;k	2013-14	2012-13	Hkqxrku	2013-14	2012-13
अर्थ शेष	22,56,312	22,57,982	जी.पी.एफ. अग्रिम/निकासी	1,47,60,809	98,08,971
जी.पी.एफ. अंशदान और प्राप्तियां	1,81,22,630	1,92,88,640	सी.पी.एफ. निकासी	-	9,07,142
जी.पी.एफ. अंशदान और प्राप्तियां	66,000	3,58,500	निवेश	3,28,85,945	5,11,94,464
एफ.डी. नकदीकरण	2,41,94,464	3,35,00,000			
निवेश पर ब्याज जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. पर बैंक ब्याज	71,04,092	87,61,767			
प्राप्त सरकारी अंशदान योजनेतर खाता 1320	3,47,626		अंतशेष	44,44,370	22,56,312
;kx	**5,20,91,124**	**6,41,66,889**	;kx	**5,20,91,124**	**6,41,66,889**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

नई पेंशन योजना लेखा

31 मार्च 2014 के अनुसार तुलन–पत्र

n;rk,a	31-03-2014 dk vuqlkj	31-03-2013 dk vuqlkj
चिहिनत/कल्याण निधि (एन.पी.एस.)	1,73,427	51,03,026
;ksx	1,73,427	51,03,026
ifjlaifÙk;ka		
निवेश	-	33,50,000
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	12,832	17,53,026
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज, पर देय नहीं	1,60,595	-
न्यूपा लेखा से प्राप्य राशि	-	-
;ksx	**1,73,427**	**51,03,026**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

नई पेंशन योजना लेखा
आय तथा व्यय लेखा
1.4.2013 से 31.3.2014 तक

vk;	31-03-2014 d vuqlkj	31-03-2013 d vuqlkj
योजनेत्तर लेखा से प्राप्त ब्याज	-	-
एन.पी.एस. बचत खाते से प्राप्त ब्याज	36,719	39,009
एन.पी.एस. निधि निवेश से प्राप्त ब्याज	3,36,453	53,265
प्रोद्भूत ब्याज	-	-
;ksx	**3,73,172**	**92,275**
व्यय		
एन.पी.एस. अंशदाता के खाते में जमा ब्याज	-	-
व्यय से अधिक आय जमा ब्याज में स्थानांतरित	3,73,172	92,275
;ksx	**3,73,172**	**92,275**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

नई पेंशन योजना लेखा

1.04.2013 जव 31.03.2014 के लिये एनपीएस अनुसूची

vu|lph	31-03-2014 dh vu|lkj	31-03-2013 dh vu|lkj
पिछले वर्ष का अर्थशेष	51,03,026	32,51,791
प्राप्त कर्मचारी अंशदान	11,58,586	9,39,195
प्राप्त नियोक्ता अंशदान	11,58,586	9,39,195
एन.पी.एस. अंशदान पर ब्याज	3,36,453	53,265
घटाकरः प्रोद्भूत ब्याज (2012–13)	1,60,595	(85,705)
बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	36,719	39,009
घटाकरः बैंक प्रभार	-	(55)
घटाकरः निकासी	(5,85,076)	(33,670)
घटाकारः एन.पी.एस. निधि कर्मचारी को स्थानांतरित	(71,95,462)	-
;kx	**1,73,427**	**51,03,026**
निवेश	-	33,50,000
वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम इत्यादि	12,832	17,53,026
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज पर देय नहीं	1,60,595	-
बैंक प्रभार	-	-
;kx	**1,73,427**	**51,03,026**

ह./–	ह./–	ह./–
¼m"kk R;kxjktu½	¼clojkt Lokeh½	¼vkj- xkfonk½
वित्त अधिकारी	*कुलसचिव*	*कुलपति*

नई पेंशन स्कीम का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

1.4.2013 से 31.3.2014 को समाप्त वित्तिय वर्ष

ikfIr ;k	2013-14	2012-13	Hkqxrku	2013-14	2012-13
अर्थशेष	17,53,026	5,16,031	एन.पी.एस. निकासी	-	33,670
कर्मचारी अंशदान	11,58,586	9,39,195	निवेश 2013–14	-	12,50,000
नियोक्ता अंशदान	11,58,586	9,39,195	बैंक प्रभार	-	-
एफ.डी. नकदीकरण	33,50,000	5,50,000	निकासी (कर्मचारी खाता)	71,95,462	-
एन.पी.एस. निधि निवेश से प्राप्त ब्याज	36,719	53,265	शीर्ष प्रभार–स्थानातरण शीर्ष खाता (केनरा बैंक)	5,85,076	-
एन.पी.एस. निधि बचत खाते से प्राप्त ब्याज	3,36,453	39,009	अंत शेष	12,832	17,53,026
;kx	**77,93,370**	**30,36,696**	;kx	**77,93,370**	**30,36,696**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼c l ojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

ikfIr ;k	pkyw o"kZ 2013&14		foxr o"kZ 2012&13	
अर्थशेष				
बैंक रोकड़ बाकी (बचत खाता बैंक) डाक टिकट	3,60,87,829.03		8,81,62,296.09	
छात्रावास खाता	3,04,242.86		2,93,953.12	
केनरा बैंक	1,51,74,304.05		1,51,61,327.05	
;kx		5,15,66,375.94		**10,36,17,576.26**
I. भारत सरकार, मा.सं.वि. मंत्राालय से प्राप्त अनुदान (योजना)	11,85,00,000.00		11,29,80,000.00	
II. भारत सरकार, मा.सं.वि. मंत्राालय से प्राप्त अनुदान (योजनेत्तर)	14,15,00,000.00		10,70,44,000.00	
III. अन्य स्रोतों से विशिष्ट अनुदान	4,14,99,960.17		2,25,98,830.21	
;kx		30,14,99,960.17		**24,26,22,830.21**
III. बचत खाता से आय				
बचत खाता ब्याज (योजना)	23,00,805.80		10,42,824.80	
बचत खाता ब्याज (योजनेतर)	5,97,003.00		7,70,613.00	
बचत खाता ब्याज (केनरा बैंक)	4,85,920.00		10,289.74	
;kx	**33,83,728.80**	33,83,728.80	**18,23,727.54**	**18,23,727.54**
IV. प्राप्त ब्याज				
अग्रिम पर ब्याज	82,731.00		4,22,933.00	
;kx	**82,731.00**	82,731.00	**4,22,933.00**	**4,22,933.00**
V. अन्य आय				
रायल्टी	29,183.47		61,021.71	
प्रकाशनों की बिक्री	2,04,956.00		2,53,968.00	
अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री	-		5,82,399.00	
हॉस्टल किराया	30,47,880.00		46,57,171.00	
हॉस्टल टेलीफोन बूथ	12,291.39		-	
;kx	**32,94,310.86**	32,94,310.86	**55,54,559.71**	**55,54,559.71**

प्रशासन विश्वविद्यालय

अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

ikfIr;k	pky o"k 2013&14			foxr o"k 2012&13		
1. व्यय						
अ. स्थापना व्यय						
	;kturj	;ktuk	;kx	;kturj	;ktuk	;kx
अ) वेतन तथा भत्ते						
i) अधिकारियों का वेतन	2,81,22,276.00	20,97,210.00		2,78,34,680.00	24,35,387.00	
ii) स्थापना वेतन	1,38,72,340.00	-		1,39,25,208.00	1,35,200.00	
;kx	**4,19,94,616.00**	**20,97,210.00**	**4,40,91,826.00**	**4,17,59,888.00**	**25,70,587.00**	**4,43,30,475.00**
ब) भत्ते तथा बोनस						
i) भत्ते तथा मानदेय	5,10,48,987.00	21,73,883.00		4,24,11,175.00	26,27,088.00	
ii) समयोपरि भत्ता	78,969.00	-		78,904.00	-	
iii) बोनस	3,21,218.00	-		2,55,902.00	-	
iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	37,87,276.00	-		28,92,739.00	-	
;kx	**5,52,36,450.00**	**21,73,883.00**	**5,74,10,333.00**	**4,56,38,720.00**	**26,27,088.00**	**4,82,65,808.00**
2. अन्य भुगतान						
i) अवकाश यात्रा छुट	13,72,038.00	-		14,28,664.00	-	
ii) नई पेंशन योजना (सरकारी अंशदान)	11,58,586.00	-		8,60,697.00	-	
iii) पी.एफ./एन.पी.एस. पर व्याज कर्मचारियों को भुगतान	3,47,626.00	-		-	-	
iv) पेंशन	2,42,13,686.00	-		2,21,64,201.00	-	
v) ग्रेच्युटी	38,21,025.00					
vi) अवकाश वेतन	25,18,446.00	-		28,11,690.00	-	
vii) ट्यूशन फीस	8,00,498.00	-		7,32,409.00	-	
viii) यात्रा भत्ता	75,482.00	-		1,20,221.00	-	
ix) वर्दी	42,040.00	87,427.00		14,443.00	28,672.00	
;kx	**3,43,49,427.00**	**87,427.00**	**3,44,36,854.00**	**2,81,32,325.00**	**28,672.00**	**2,81,60,997.00**

ikfIr ;k	pkyw o"k 2013&14		foxr o"k 2012&13	
VI. अन्य प्राप्तियां				
लाईसेन्स शुल्क	1,85,594.00		2,74,947.00	
अन्य प्रभार	6,096.00		5,079.00	
विद्यार्थी फीस	2,09,000.00		1,14,300.00	
विविध प्राप्तियां	2,78,259.00		2,16,665.00	
विवरणिका की बिक्री	66,100.00		8,900.00	
टेंडर फार्म की बिक्री	36,100.00		26,500.00	
स्टाफ कार का प्रयोग	2,696.00		-	
दाखिला फीस – चिकित्सा प्रतिपूर्ति पेंशनभोगी	5,92,800.00		-	
चिकित्सा स्कीम में अंशदान	2,32,325.00		-	
देय राशि – सीपीएफ	15,973.00		-	
केनरा बैंक – प्रशासनिक उपरिनिधि	4569152.46		-	
;kx	**61,94,095.46**	61,94,095.46	**6,46,391.00**	**6,46,391.00**
VII. स्टाफ से प्राप्त ऋण/अग्रिम				
त्योहार पेशगी	1,57,875.00		1,50,675.00	
कार पेशगी	36,000.00		35,980.00	
स्कूटर पेशगी	46,880.00		23,330.00	
भवन निर्माण अग्रिम	21,600.00		69,800.00	
कम्प्यूटर अग्रिम	19,500.00		34,000.00	
चिकित्सा अग्रिम	-		80,000.00	
अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान	20,22,209.00		7,75,033.00	
प्रतिभूति जमा	90,800.00		5,73,775.00	
;kx	**23,94,864.00**	23,94,864.00	**17,42,593.00**	**17,42,593.00**

Hkxrku	pkyw o"k 2013&14			foxr o"k 2012&13		
III. अन्य प्रशासनिक व्यय						
विज्ञापन प्रभार	-	22,61,842.00		-	22,67,311.00	
कैटरिंग प्रभार	-	37,65,462.00		-	27,84,041.00	
प्रकाशन/मुद्रण प्रभार	-	15,34,132.00		-	16,44,207.00	
पोस्ट तथा टेलीग्राम प्रभार	-	4,86,526.00		-	3,12,247.00	
पेट्रोल/ऑयल/ल्यूब्रीकेन्ट प्रभार	5,74,989.00	-		4,68,396.00	-	
स्टेशनरी प्रभार	-	19,65,503.00		-	11,74,026.00	
लेखा शुल्क	33,350.00	-		1,37,385.00	-	
कानूनी व्यय	72,800.00	32,800.00		2,66,000.00	17,400.00	
स्टाफ कार का रख–रखाव	2,04,913.00	-		1,19,974.00	-	
डपकरणों का रख–रखाव	-	33,14,493.00		-	18,74,665.00	
फर्नीचर एवं साजो–सामान की मरम्मत	-	11,58,217.00		-	51,113.00	
संस्था भवन/हास्टल का रख–रखाव	-	6,40,130.00		-	34,59,333.00	
कार्यक्रम व्यय	-	42,41,720.00		-	38,14,000.00	
टेलीफोन प्रभार	8,83,556.00	89,767.00		9,55,717.00	1,03,997.00	
जल/विद्युत प्रभार	88,01,509.00	31,920.00		64,62,668.00	6,94,620.00	
किराया/दर/कर	3,69,819.00	-		3,87,289.00	4,21,470.00	
बागवानी प्रभार	-	82,994.00		-	24,985.00	
समाचार पत्र प्रभार	1,25,018.00	15,228.00		1,01,836.00	22,165.00	
बीमा	18,565.00	32,395.00		60,527.00	-	
विविध व्यय	2,53,167.00	4,10,921.28		1,78,301.00	7,14,796.34	
सुरक्षा व्यय	24,115.00	4,90,803.00		6,39,487.00	1,23,845.00	
फोटोकॉपी प्रभार	-	5,22,015.00		-	4,60,835.00	
दिहाड़ी प्रभार	-	10,02,182.00		-	8,81,513.00	
हाउसकीपिंग	9,78,260.00	17,64,945.00		9,59,636.00	9,81,034.00	
कार प्रभार	-	2,49,951.00		-	-	
कोर्स फीस एवं प्रशिक्षण फीस	-	1,70,750.00		-	-	
;kx	**1,23,40,061.00**	**2,42,64,696.28**	**3,66,04,757.28**	**1,07,37,216.00**	**2,18,27,603.34**	**3,25,64,819.34**

ikfIr;k	pkyw o"kZ 2013&14	foxr o"kZ 2012&13

Hkxrku	pkyw o"k 2013&14			foxr o"k 2012&13		
IV. अन्य व्यय (अकादमिक)						
छात्रवृत्ति, पुस्तकें तथा परियोजना अनुदान	-	2,86,678.00		-	2,76,817.00	
संकाय को यात्रा भत्ता	-	47,95,519.00		-	31,22,169.00	
भागीदारों को यात्रा भत्ता	-	88,20,207.00		-	63,36,637.00	
संसाधन व्यक्ति को मानदेय	-	6,48,987.00		-	4,55,876.00	
अकादमिक संस्थानों की सदस्यता	-	-		-	84,511.00	
;kx	-	**1,45,51,391.00**	1,45,51,391.00	-	**1,02,76,010.00**	**1,02,76,010.00**
V. अचल परिसंपत्ति पर निवेश तथा पूजींगत जारी कार्य						
फर्नीचर एवं साज–सामान	-	6,52,565.00		-	34,84,980.00	
अन्य कार्यालय उपकरण	-	11,25,118.00		-	67,59,980.00	
जर्नल की खरीद	-	72,44,469.00		36,04,791.00	33,58,354.00	
ई–जर्नल की खरीद	-	21,56,772.63		-	22,52,835.39	
पुस्तकालय की पुस्तकें	-	28,97,870.00		-	10,37,665.00	
कम्प्यूटर तथा साज–सामान	-	19,82,795.00		-	5,63,454.00	
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	-	6,35,369.00				
भूमि	-	20,90,677.00				
कार्यालय भवन	-	29,76,808.00				
;kx	-	**2,17,62,443.63**	2,17,62,443.63	**36,04,791.00**	**1,74,57,268.39**	**2,10,62,059.39**
VI. सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम						
भवन (सिविल / इलैक्ट्रिकल) पूजींगत / ए.आर.एम. ओ.		2,27,57,208.00		-	-	
भवन (पूंजीगत) इलैक्ट्रीकल		12,81,819.00		-	2,83,53,512.00	
;kx	-	**2,40,39,027.00**	2,40,39,027.00		**2,83,53,512.00**	**2,83,53,512.00**

ikfIr;k	pkyw o"kZ 2013&14	foxr o"kZ 2012&13

Hkqxrku		pkyw o"kZ 2013&14			foxr o"kZ 2012&13	
VII. विद्यार्थी प्रकोष्ठ						
एम.फिल. छात्रों की अध्येतता / वृत्ति	-	59,43,204.00		-	75,47,308.00	
VIII. एन.जी.ओ. को अनुदान	-	53,19,967.00		-	1,24,35,937.00	
IX. संस्थान अनुसंधान अध्ययन				-		
व्यय	-	1,86,41,133.00		-	2,59,60,526.00	
;kx	-	**2,99,04,304.00**	2,99,04,304.00		**45943771.00**	**4,59,43,771.00**
X. उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	-	84,66,773.00		-	33,85,878.00	
;kx	-	**84,66,773.00**	84,66,773.00		**33,85,878.00**	**33,85,878.00**
XI. विभिन्न विशिष्ट परियोजनाओं के लिये निर्धारित निधि का भुगतान						
राजस्व व्यय		3,52,35,892.00		-	4,16,39,692.05	
;kx	-	**3,52,35,892.00**	3,52,35,892.00		**4,16,39,692.05**	**4,16,39,692.05**
XII. अन्य भुगतान						
त्योहार अग्रिम	1,80,000.00	-		1,23,750.00		
स्कूटर अग्रिम	30,000.00	-		30,000.00		
कार अग्रिम	-	-		1,80,000.00		
भवन निर्माण अग्रिम	-	-		-		
कम्प्यूटर अग्रिम	-	-		-		
प्रतिभूति (वापिस)	53,910.00	-		-		
विभिन्न लेनदार	-	-		5,31,050.00		
जी.पी.एफ. अग्रिम तथा निकासी	-	-		15,973.00		
;kx	**2,63,910.00**	-	263910.00	**8,80,773.00**	-	**8,80,773.00**

ikfIr ;k	pkyw o"k 2013&14		foxr o"k 2012&13	
VIII. प्रेषित धन				
आयकर (वेतन से)	1,27,03,188.00		98,38,389.00	
पी.एफ. अंशदान और अग्रिम से वसूली	1,75,38,630.00		1,71,81,240.00	
पी.एफ. अंशदान/प्रतिनियुक्ति स्टाफ की वसूली	97,000.00		2,25,000.00	
सामूहिक बीमा लिंक बचत योजना	1,09,260.00		96,344.00	
स्टाफ की एल.आई.सी.	3,23,714.00		3,20,294.00	
सोसायटी वसूली	22,00,418.00		19,38,597.00	
आयकर (पार्टी)	6,17,059.00		4,25,873.00	
नई पेंशन स्कीम (टीयर–1)	11,62,366.00		8,60,697.00	
स्टाफ की एल.आई.सी. (प्रतिनियुक्ति)	1,368.00		7,368.00	
;kx	**3,47,53,003.00**	**3,47,53,003.00**	**3,08,93,802.00**	**3,08,93,802.00**
egk ;kx		**40,31,69,069.23**		**38,73,24,412.72**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

Hkqxrku	pkyw o"k 2013&14			foxr o"k 2012&13		
XIII. धन प्रेषित						
आयकर (वेतन	1,27,03,188.00			98,38,389.00		
पी.एफ. अंशदान तथा अग्रिम की वापसी	1,75,38,630.00			1,71,81,240.00		
पी.एफ. अंशदान / प्रति नियुक्ति स्टाफ वसूली	97,000.00			2,25,000.00		
सामूहिक बचत लिंक बीमा योजना	1,11,100.00			96,784.00		
स्टाफ की एल.आई.सी.	3,23,714.00			3,20,294.00		
सोसायटी वसूली	22,00,418.00			19,38,597.00		
आयकर (पार्टी)	6,17,059.00			4,25,873.00		
नई पेंशन स्कीम (टीयर–1)	11,62,366.00			8,60,697.00		
स्वयं की एल.आई.सी. (प्रतिनियुक्ति)	1,368.00			7,368.00		
;kx		-	**3,47,54,843.00**		-	**3,08,94,242.00**	**3,08,94,242.00**
अंतशेष						
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (10137881320)	1,11,70,481.40			58,75,224.93		
सिंडीकेट बैंक (91392010001112)	30,79,570.64			95,76,066.75		
सिंडीकेट बैंक (91392010001092)	2,68,02,043.52			2,05,37,975.35		
केनरा बैंक (25536)	2,02,29,376.51			1,51,74,304.05		
हॉस्टल खाता (91392015365)	3,16,534.25			3,04,242.86		
डाक टिकट हस्तगत	48,709.00			98,562.00		
;kx	**6,16,46,715.32**	-	**6,16,46,715.32**	**5,15,66,375.94**		**5,15,66,375.94**
egk ;kx			**40,31,69,069.23**			**38,73,24,412.72**

ह./–
¼clojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

सौंपे गये कार्यक्रमों का लेखा प्रपत्र

31 मार्च 2014 के अनुसार

Ø- l-	dk;Øe@v/;;u dk uke	vFk'k"k	ikfIr;k	;kx	0;;	'k"k
1	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2013	-15,68,380.00	55,80,330.00	40,11,950.00	62,86,736.00	-22,74,786.00
2	डाईस की स्थापना और संचालन (यूनीसेफ़) डा. ए.सी. मेहता	8,01,086.00	44,14,913.00	52,15,999.00	37,35,760.00	14,80,239.00
3	सर्व शिक्षा अभियान पर परियोजना (मा.सं वि. मंत्रालय)	10,64,362.00	1,05,949.00	11,70,311.00	11,25,300.00	45,011.00
4	ससेक्स विश्वविद्यालय के सहयोगात्मक परियोजना के संदर्भ में भारत में प्राथमिक शिक्षा (क्रिएट) डा. आर. गोविंदा)	22,593.26	-	22,593.26	20,568.00	2,025.26
5	स्कूल प्राचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2006 (डा. आर.एस. त्यागी)	20,37,727.00	-	20,37,727.00	-	20,37,727.00
6	14 राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन तथा निरीक्षण के संबंध में वी.ई.सी./डी.टी.ए./एस. एम.डी.सी./ स्थानीय शहरी निकायों की भूमिका पर एडसील अध्ययन	11,95,425.00	-	11,95,425.00	1,30,565.00	10,64,860.00
7	माध्यमिक शिक्षा सूचना प्रणाली प्रबंधन (सेमिस) मा.सं.वि. मंत्रालय	38,91,123.00	-	38,91,123.00	7,16,442.00	31,74,681.00
8	यूनेस्को संविदा सं. 4500084591 माध्यमिक शिक्षा नीति तथा प्रबंधन (डा. प्रणती पांडा)	1,58,411.00	-	1,58,411.00	-	1,58,411.00
9	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (यू.जी.सी. सहयोग) भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता का मुद्दा (डा. सुधांशु भूषण)	53,250.00	-	53,250.00	-	53,250.00
10	बुरूण्डी में भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (दक्षिण अफ्रीका)	25,64,658.00	-	25,64,658.00	-	25,64,658.00
11	एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के चुनिंदा विकासशील देशों में कार्य सूचना आधार स्कूल (डा. विनीता सिरोही)	69,995.00	-	69,995.00	-	69,995.00

Ø-l-	dk;Øe@v/;;u dk uke	vFk'k"k	izkfIr;k	;kx	0;;	'k"k
12	विश्व की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था में त्वरित उच्च शिक्षा विस्तार का संभावित आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव (डा. जे.बी.जी. तिलक)	5,15,281.00	-	5,15,281.00	-	5,15,281.00
13	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (एडसिल) डा. के सुजाता	3,62,399.00	5,00,000.00	8,62,399.00	6,45,959.00	2,16,440.00
14	शिक्षा–दक्षिण एशिया (डा. मोहन्ती/ डा. जैदी)	74,647.00	0.00	74,647.00	45,766.00	28,881.00
15	महात्मा गांधी शान्ति शिक्षा संस्थान (मगीप)	11,29,163.00		11,29,163.00	3,32,705.00	7,96,458.00
16	नेतृत्व कार्यक्रम (मा.सं.वि. मंत्रालय) डा. रश्मि दीवान	26,63,814.00	1,60,86,000.00	1,87,49,814.00	1,37,13,550.00	50,36,264.00
17	आर.एम. तथा भारत में सैनिक स्कूल (डा. प्रमिला मेनन)	4,26,291.00	-	4,26,291.00	24,102.00	4,02,189.00
18	आई.एस.एस.टी. परियोजना – डा. वी. रामचंद्रन	2,13,240.00	1,82,160.00	3,95,400.00	3,50,100.00	45,300.00
19	दक्षिण एशिया 4 देश – भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान (यूनिसेफ)	5,39,501.00	-	5,39,501.00	61,333.00	4,78,168.00
20	अध्यापक विकास और प्रबंधन पर राजीव गांधी स्थापना पीठ	-	45,00,000.00	45,00,000.00	41,83,611.00	3,16,389.00
21	डीईओ– किंगडम आफ भूटान परियोजना	-	44,96,976.00	44,96,976.00	18,46,937.00	26,50,039.00
22	निगम अनुसंधान केन्द्र (यूजीसी)	-	35,00,000.00	35,00,000.00	11,49,951.00	23,50,049.00
23	राष्ट्रीय अध्येयता (आईसीएसएसआर)	-	3,60,000.00	3,60,000.00	2,90,000.00	70,000.00
24	इंडोनेशिया कार्यक्रम	-	9,87,504.81	9,87,504.81	3,52,588.00	6,34,916.81
25	प्रशासनिक उपरिव्यय प्रभाग/बचत खाता पर ब्याज	43,23,389.09	7,86,127.36	51,09,516.45	2,23,919.00	48,85,597.45
	egk;kx	**2,05,37,975.35**	**4,14,99,960.17**	**6,20,37,935.52**	**3,52,35,892.00**	**2,68,02,043.52**

ह./–
¼m"kk R;kxjkt u½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼c lojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xkfonk½
कुलपति

मुख्य लेखा 2013-14

शेष परीक्षण (1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक)

fooj.k	vFk 'k"k		gLrkUrj.k		vr 'k"k	
			fudklh	tek		
iathxr y[kk	**16,60,57,259.49**	**Cr**	1,92,34,764.00	7,12,02,427.00	21,80,24,958.49	Cr
जोड़कर / अधिक आय / व्यय				1,92,34,764.00	1,92,34,764.00	Cr
पूंजीगत निधि	16,56,76,185.15	Cr	1,92,34,764.00	5,18,83,647.00	19,83,25,068.15	Cr
परिसंपत्ति निधि दान	3,81,110.34	Cr		84,016.00	4,65,126.34	Cr
pkyw nk;rk,a	**7,31,47,088.35**	**Cr**	**24,48,39,329.00**	**25,81,49,706.17**	**8,64,57,465.52**	**Cr**
राशि लेनदार				15,973.00	15,973.00	Cr
राशि लेनदार – सी.पी.एफ.				15,973.00	15,973.00	Cr
बिलों से कटौती			6,17,059.00	6,17,059.00		
ठेकेदार से आयकर – योजना			4,65,921.00	4,65,921.00		
ठेकेदार से आयकर – परियोजना			1,19,152.00	1,19,152.00		
ठेकेदार से आयकर – योजनेतर			31,986.00	31,986.00		
वेतन से कटौती	440.00	Dr	3,41,37,784.00	3,41,35,944.00	2,280.00	Dr
जी.पी.एफ. अंशदान (प्रतिनियोक्ता)			97,000.00	97,000.00		
जी.पी.एफ. अंशदान तथा वसूली			1,75,38,630.00	1,75,38,630.00		
सामूहिक बीमा योजना	440.00	Dr	1,11,100.00	1,09,260.00	2,280.00	Dr
जी.एस.एल.आई.सी. (प्रतिनियोक्ता)			1,368.00	1,368.00		
आयकर (वेतन) – योजनेत्तर			1,10,73,971.00	1,10,73,971.00		
आयकर (वेतन) – योजना			9,21,423.00	9,21,423.00		
आयकर (वेतन) – परियोजना			7,07,794.00	7,07,794.00		
एल.आई.सी.			3,23,714.00	3,23,714.00		
नई पेंशन स्कीम की वसूली			11,62,366.00	11,62,366.00		
सोसायटी वसूली			22,00,418.00	22,00,418.00		
विशिष्ट परियोजना	2,05,37,975.35	Cr	4,57,25,965.00	5,19,90,033.17	2,68,02,043.52	Cr
प्रावधान	5,20,00,000.00	Cr		70,00,000.00	5,90,00,000.00	Cr
प्रावधान – ग्रेच्युटी	80,00,000.00	Cr		10,00,000.00	90,00,000.00	Cr
प्रावधान – अवकाश वेतन	40,00,000.00	Cr		10,00,000.00	50,00,000.00	Cr

fooj.k	vFk 'k"k		gLrkUrj.k		vUr 'k"k	
			fudkl h	tek		
प्रावधान – पेंशन	4,00,00,000.00	Cr		50,00,000.00	4,50,00,000.00	Cr
भुगतान बदले में			1,50,051.00	1,50,051.00		
प्रतिभूति जमा योजना	4,54,993.00	Cr	53,910.00	90,800.00	4,91,883.00	Cr
जर्नल की सदस्यता (अग्रिम)	1,54,560.00	Cr	1,54,560.00	1,49,846.00	1,49,846.00	Cr
निधि हस्तांतरण – योजना			3,15,00,000.00	3,15,00,000.00		
निधि हस्तांतरण – केनरा बैंक खाता			3,35,00,000.00	3,35,00,000.00		
निधि हस्तांतरण – योजनेत्तर			7,55,00,000.00	7,55,00,000.00		
परियोजना खाते से हस्तांतरण अनुदान			2,35,00,000.00	2,35,00,000.00		
vpy lifUk;k	**14,30,37,082.90**	**Dr**	**5,41,35,653.63**	**1,89,83,761.00**	**17,81,88,975.53**	**Dr**
1027 – जर्नल की खरीद	36,15,306.00	Dr	11,380.00	11,380.00	36,15,306.00	Dr
2025 – फर्नीचर और साजो–सामान	59,62,501.34	Dr	6,52,565.00	4,96,130.00	61,18,936.34	Dr
2026 – अन्य कार्यालय उपकरण	1,11,70,725.82	Dr	32,81,729.00	30,78,799.00	1,13,73,655.82	Dr
2027 – पुस्तकालयों की पुस्तकें	30,34,471.95	Dr	29,81,886.00	6,01,636.00	54,14,721.95	Dr
2028 – कंप्यूटर तथा अन्य सामग्री	25,61,001.90	Dr	19,82,795.00	9,08,759.00	36,35,037.90	Dr
2029 – जर्नल की खरीद	1,03,93,399.95	Dr	72,44,469.00	21,25,318.00	1,55,12,550.95	Dr
2030 – ई–जर्नल की खरीद	15,57,726.99	Dr	21,56,772.63	14,85,800.00	22,28,699.62	Dr
2055 – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर			6,35,369.00	2,54,148.00	3,81,221.00	Dr
भूमि	2,17,215.03	Dr	20,90,677.00		23,07,892.03	Dr
कार्यालय भवन	9,59,80,682.99	Dr	3,30,98,011.00	25,81,574.00	12,64,97,119.99	Dr
स्टाफ कार खरीद	12,26,481.93	Dr		1,22,648.00	11,03,833.93	Dr
कार्य जारी – सिविल	56,25,013.00	Dr		56,25,013.00		
कार्य जारी – इलैक्ट्रिकल	16,92,556.00	Dr		16,92,556.00		
or'eku ifjlifUk;k	**9,61,67,300.94**	**Dr**	**57,39,90,720.32**	**56,30,99,336.91**	**10,70,58,684.35**	**Dr**
स्टाफ को अग्रिम			2,22,94,772.00	2,22,94,772.00		
2033 – विविध अग्रिम (यात्रा भत्ता/अन्य)			2,15,86,250.00	2,15,86,250.00		
अग्रदाय – योजना			10,000.00	10,000.00		
चिकित्सा अग्रिम			6,98,522.00	6,98,522.00		
आय प्रोद्भूत	1,65,340.00	Dr	92,768.00	1,65,340.00	92,768.00	Dr
ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज प्रोद्भूत	1,65,340.00	Dr	92,768.00	1,65,340.00	92,768.00	Dr

fooj.k	vFk 'k"k		gLrkUrj.k		vr 'k"k
			fudklh	tek	
वसूली योग्य – स्टाफ	4,21,895.00	Dr	2,10,000.00	2,81,855.00	3,50,040.00 Dr
कार अग्रिम	1,56,000.00	Dr		36,000.00	1,20,000.00 Dr
कंप्यूटर अग्रिम	54,000.00	Dr		19,500.00	34,500.00 Dr
त्योहार अग्रिम	88,500.00	Dr	1,80,000.00	1,57,875.00	1,10,625.00 Dr
भवन निर्माण अग्रिम	86,550.00	Dr		21,600.00	64,950.00 Dr
स्कूटर अग्रिम	36,845.00	Dr	30,000.00	46,880.00	19,965.00 Dr
जमा (परिसंपत्तियां)	4,36,48,999.00	Dr	2,40,39,027.00	2,31,14,468.00	4,45,73,558.00 Dr
सी.पी.डब्ल्यू.डी. को जमा–सिविल/इलैक्ट्रिकल	4,36,48,999.00	Dr	2,40,39,027.00	2,31,14,468.00	4,45,73,558.00 Dr
विविध देनदार	98,298.00	Dr			98,298.00 Dr
बैंक खाते	5,14,67,813.94	Dr	52,70,08,139.32	51,68,77,946.91	6,15,98,006.35 Dr
1000–एस.बी.आई.–10137881320–योजनेतर	58,75,224.93	Dr	25,05,10,457.47	24,52,15,201.00	1,11,70,481.40 Dr
2000–सिंडीकेट बैंक–91–1112–योजना	95,76,066.75	Dr	16,78,76,591.80	17,43,73,087.91	30,79,570.64 Dr
3000–सिंडीकेट बैंक 91–1092–परियोजना	2,05,37,975.35	Dr	7,00,53,726.17	6,37,89,658.00	2,68,02,043.52 Dr
6000 – हॉस्टल खाता	3,04,242.86	Dr	12,291.42		3,16,534.28 Dr
8000 – केनरा बैंक	1,51,74,304.05	Dr	3,85,55,072.46	3,35,00,000.00	2,02,29,376.51 Dr
हस्तगत डाक टिकट	98,562.00	Dr	48,709.00	98,562.00	48,709.00 Dr
हस्तगत – प्रकाशन	2,66,393.00	Dr	2,97,305.00	2,66,393.00	2,97,305.00 Dr
viR;{k vk;			**5,22,09,072.00**	**27,52,18,669.15**	**22,30,09,597.15 Cr**
प्राप्तियां – योजनेत्तर			3,25,425.00	14,93,50,499.47	14,90,25,074.47 Cr
पेंशन भोगी चिकित्सा दाखिला फीस				5,92,800.00	5,92,800.00 Cr
स्वास्थ्य योजना अंशदान (सीजीएचएस)			4,725.00	2,37,050.00	2,32,325.00 Cr
मा.सं.वि. मंत्रालय से प्राप्त अनुदान–योजनेतर				14,15,00,000.00	14,15,00,000.00 Cr
छात्रावास किराया				30,47,880.00	30,47,880.00 Cr
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज			1,65,340.00	1,75,499.00	10,159.00 Cr
बचत खाता पर ब्याज				5,97,003.00	5,97,003.00 Cr
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान				20,22,209.00	20,22,209.00 Cr
विविध प्राप्तियां				2,78,259.00	2,78,259.00 Cr
लाइसेंस शुल्क की वसूली			2,940.00	1,88,534.00	1,85,594.00 Cr
जल प्रभार की वसूली			574.00	6,670.00	6,096.00 Cr
रायल्टी				29,183.47	29,183.47 Cr

fooj.k	vFk 'k"k	gLrkUrj.k		vr 'k"k
		fudklh	tek	
विवरणिका की बिक्री			66,100.00	66,100.00 Cr
प्रकाशन की बिक्री		1,49,846.00	3,59,516.00	2,09,670.00 Cr
टेंडर फार्म की बिक्री		2,000.00	38,100.00	36,100.00 Cr
छात्र शुल्क			2,09,000.00	2,09,000.00 Cr
स्टाफ़ कार का प्रयोग			2,696.00	2,696.00 Cr
प्राप्तियां – योजना		5,18,83,647.00	12,08,00,805.80	6,89,17,158.80 Cr
मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुदान – योजना		5,18,83,647.00	11,85,00,000.00	6,66,16,353.00 Cr
बचत खाता पर ब्याज – योजना			23,00,805.80	23,00,805.80 Cr
8001 – प्राप्तियां प्रशासनिक ऊपरी निधि			45,69,152.46	45,69,152.46 Cr
बचत खाता से ब्याज – केनरा बैंक			4,85,920.00	4,85,920.00 Cr
प्राप्तियां – हॉस्टल टेलीफोन बूथ			12,291.42	12,291.42 Cr
viR;{k O;;		**28,85,21,523.28**	**4,62,77,162.00**	**24,22,44,361.28 Dr**
योजनेत्तर – व्यय		18,21,29,636.00	3,12,09,082.00	15,09,20,554.00 Dr
स्थापना व्यय – योजनेत्तर		16,97,19,032.00	3,11,38,539.00	13,85,80,493.00 Dr
1001 – अधिकारियों को वेतन		2,81,22,276.00		2,81,22,276.00 Dr
1002 – स्थापना को वेतन		1,38,72,340.00		1,38,72,340.00 Dr
1003 – वेतन – भत्ता		5,14,26,205.00	3,77,218.00	5,10,48,987.00 Dr
1004 – समयोपरि भत्ता		78,969.00		78,969.00 Dr
1005 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति		37,87,276.00		37,87,276.00 Dr
1006 – अवकाश यात्राा रियायत		15,58,786.00	1,86,748.00	13,72,038.00 Dr
1007 – बोनस		3,21,218.00		3,21,218.00 Dr
1008 – अंशदाता के पी.एफ. पर ब्याज		3,47,626.00		3,47,626.00 Dr
1009 – वर्दी		55,690.00	13,650.00	42,040.00 Dr
1010 – नई पेंशन योजना (सरकारी अंश)		11,62,366.00	3,780.00	11,58,586.00 Dr
1011 – ग्रेच्यूटी		38,25,011.00	38,25,011.00	
1012 – पेंशन		2,42,13,686.00	2,42,13,686.00	
1013 – अवकाश		25,18,446.00	25,18,446.00	
1014 – यात्रा भत्ता		75,482.00		75,482.00 Dr
1016 – शिक्षण शुल्क		8,00,498.00		8,00498.00 Dr
प्रावधानों के लिये व्यय – ग्रेच्युटी		48,21,025.00		48,21,025.00 Dr

fooj.k	vFk 'ks"k	gLrkUrj.k		vr 'ks"k
		fudklh	tek	
प्रावधानों के लिये व्यय – अवकाश वेतन		35,18,446.00		35,18,446.00 Dr
प्रावधानों के लिये व्यय – पेंशन		2,92,13,686.00		2,92,13,686.00 Dr
कार्यालय व्यय – योजनेतर		1,24,10,604.00	70,543.00	1,23,40,061.00 Dr
1021 – लेखा परीक्षा शुल्क		33,350.00		33,350.00 Dr
1022 – कानूनी व्यय		72,800.00		72,800.00 Dr
1023 – बीमा		18,565.00		18,565.00 Dr
1024 – स्टाफ कार की मरम्मत		2,38,713.00	33,800.00	2,04,913.00 Dr
1025 – समाचार पत्र प्रभार		1,25,018.00		1,25,018.00 Dr
1026 – पेट्रोल ऑयल तथा ल्यूब्रीकेंट्स		5,74,989.00		5,74,989.00 Dr
1028 – दर/किराया तथा टैक्स		3,69,819.00		3,69,819.00 Dr
1029 – टेलीफोन प्रभार		8,89,213.00	5,657.00	8,83,556.00 Dr
1030 – जल प्रभार		3,23,915.00	3,000.00	3,20,915.00 Dr
1031 – विद्युत प्रभार		84,94,320.00	13,726.00	84,80,594.00 Dr
1032 – विविध आकस्मिकताएं		2,67,527.00	14,360.00	2,53,167.00 Dr
1035 – हाऊसकीपिंग प्रभार		9,78,260.00		9,78,260.00 Dr
1036 – सुरक्षा प्रभार		24,115.00		24,115.00 Dr
;kstuk & 0;;		**10,63,91,887.28**	**1,50,68,080.00**	**9,13,23,807.28 Dr**
1- LFkkiuk 0;;&;kstuk		47,91,199.00	4,32,679.00	43,58,520.00 Dr
2001 – अधिकारियों का वेतन		20,97,210.00		20,97,210.00 Dr
2003 – भत्ते तथा मानदेय		26,06,562.00	4,32,679.00	21,73,883.00 Dr
2004 – वर्दी		87,427.00		87,427.00 Dr
2- dk;kZy; 0;; & ;kstuk		89,22,377.28	1,26,229.00	87,96,148.28 Dr
2011 – टेलीफोन / टेलीग्राम प्रभार		89,767.00		89,767.00 Dr
2016 – बागवानी		82,994.00		82,994.00 Dr
2017 – बीमा		32,395.00		32,395.00 Dr
2018 – कानूनी व्यय		32,800.00		32,800.00 Dr
2019 – उपकरणों का रख–रखाव		33,14,493.00		33,14,493.00 Dr
2020 – भवन का रख–रखाव/हॉस्टल		6,40,130.00		6,40,130.00 Dr
2021 – समाचार पत्र प्रभार		15,228.00		15,228.00 Dr
2022 – जल तथा विद्युत प्रभार		35,170.00	3,250.00	31,920.00 Dr

fooj.k	vFk 'ks"k	gLrkUrj.k fudklh	gLrkUrj.k tek	vUr 'ks"k
2024 – अन्य विविध प्रशासनिक व्यय		5,33,900.28	1,22,979.00	4,10,921.28 Dr
2031 – हाऊस कीपिंग सेवाएं		17,64,945.00		17,64,945.00 Dr
2035 – सुरक्षा व्यय		4,90,803.00		4,90,803.00 Dr
2038 – टैक्सी प्रभार		2,49,951.00		2,49,951.00 Dr
2040 – फर्नीचर तथा फिक्चर रख–रखाव		11,58,217.00		11,58,217.00 Dr
2043 – विद्युत रख–रखाव – ए.आर.एम.ओ.		3,10,834.00		3,10,834.00 Dr
2054 – पाठ्क्रम शुल्क/प्रशिक्षण		1,70,750.00		1,70,750.00 Dr
3- vdknfed 0;; & ;ktuk		3,78,50,140.00	75,50,279.00	3,02,99,861.00 Dr
2005 – विज्ञापन		22,61,842.00		22,61,842.00 Dr
2006 – पोषाहार प्रभार		37,65,462.00		37,65,462.00 Dr
2007 – मुद्रण प्रभार		18,00,525.00	2,97,305.00	15,03,220.00 Dr
2008 – पोस्टेज तथा टेलीग्राम		5,54,764.00	68,238.00	4,86,526.00 Dr
2009 – स्टेशनरी / स्टोर मद		19,66,570.00	1,067.00	19,65,503.00 Dr
2010 – छात्रवृत्ति, पुस्तकें तथा परियोजना (डेपा)		2,95,278.00	8,600.00	2,86,678.00 Dr
2012 – अकादमिक कार्यक्रम व्यय		61,59,614.00	19,17,894.00	42,41,720.00 Dr
2013 – संकाय को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता		71,47,483.00	23,51,964.00	47,95,519.00 Dr
2014 – भागीदारों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता		1,17,14,418.00	28,94,211.00	88,20,207.00 Dr
2015 – संसाधन व्यक्तियों को मानदेय		6,51,987.00	3,000.00	6,48,987.00 Dr
2036 फोटोकॉपी प्रभार		5,22,015.00		5,22,015.00 Dr
2037 – दिहाड़ी प्रभार		10,10,182.00	8,000.00	10,02,182.00 Dr
4- fo'ofo|ky; v/;;u@,u-th-vks- ;ktuk		3,58,08,697.00	59,04,393.00	2,99,04,304.00 Dr
2041 – एम.फिल./पी.एच.डी. छात्रों को अध्येतावृत्ति		75,18,804.00	15,75,600.00	59,43,204.00 Dr
2051 – एन.जी.ओ. को अनुदान		57,19,967.00	4,00,000.00	53,19,967.00 Dr
2061 – केब कमिटी		2,56,152.00		2,56,152.00 Dr
2064 – स्कूल शिक्षा में पहुंच, भागीदारी तथा अधिगम		44,667.00		44,667.00 Dr
2065 – मॉडल शिक्षा कोड की तैयारी		6,59,277.00		6,59,277.00 Dr
2069 – योजना के विकास हेतु प्रस्ताव		1,61,602.00		1,61,602.00 Dr

fooj.k	vFk 'k"k	gLrkUrj.k		vr 'k"k
		fudklh	tek	
2070 – शिक्षा के सामाजिक आयाम का केस अध्ययन		2,67,295.00	20,000.00	2,47,295.00 Dr
2071 – अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण		25,81,110.00	7,98,698.00	17,82,412.00 Dr
2075 – पारिवारिक प्रशिक्षण स्कूल – डा. रश्मि		1,75,278.00		1,75,278.00 Dr
2077 – व्यावसायिक मार्गदर्शन – डा. विनिता		2,88,973.00	1,00,000.00	1,88,973.00 Dr
2979 – हू गोस् टू स्कूल? एन अनालिसिस ऑफ एम्पिरिकल		4,67,859.00		4,67,859.00 Dr
2080 – विद्यालय गुणवत्ता का पुनरीक्षण – डा. मधुमिता		2,12,137.00		2,12,137.00 Dr
2081 – सहायता अनुदान अध्ययन		14,23,710.00		14,23,710.00 Dr
2083 – डी.ई.ओ. तथा बी.ई.ओ. क्षमता निर्माण सम्मेलन		93,65,142.00	29,76,762.00	63,88,380.00 Dr
2084 – शैक्षिक दस्तावेजों का डिज़िटल भंडारण (डा. मैथ्यू)		11,32,360.00		11,32,360.00 Dr
2085 – प्रकाशन एकक की योजनाएं (पी. रावत)		1,20,000.00		1,20,000.00 Dr
2086 – राष्ट्रीय साधन – मेरिट छात्रवृत्ति		3,25,577.00		3,25,577.00 Dr
2087 – बच्चों की भागीदारी पर सुधार लाने पर कार्यशाला		3,61,742.00		3,61,742.00 Dr
2088 – विदेशी बोर्ड का अध्ययन – प्रणती पांडा		3,21,668.00		3,21,668.00 Dr
2089 – 1000 स्कूल परियोजना		92,300.00	30,000.00	62,300.00 Dr
2090 – भारतीय उच्च शिक्षा की स्वापत्तता		1,37,333.00		1,37,333.00 Dr
2091 – शैक्षिक प्रशासन में राष्ट्रीय नवाचार		1,45,333.00		1,45,333.00 Dr
2092 – बच्चों की शिक्षा का महत्वपूर्ण मूल्यांकन		1,25,717.00		1,25,717.00 Dr
2093 – निजी फ्रेंचाइजी पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले		1,05,600.00		1,05,600.00 Dr
2095 – तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण – आर.एस. त्यागी		4,57,969.00	3,333.00	4,54,636.00 Dr
2096 – लड़कियों को राष्ट्रीय योजना – डा. वी.पी.एस. राजू		74,837.00		74,837.00 Dr
2097 – शैक्षिक ऋण का मूल्यांकन – डा. गीता रानी		60,645.00		60,645.00 Dr

fooj.k	vFk 'ks"k	gLrkUrj.k		vUr 'ks"k
		fudklh	tek	
2098 – डीडी सेकेण्डरी एजूकेशन रमसा – डा. जैदी		7,286.00		7,286.00 Dr
2099 – विद्यालय प्रमुख का कार्य – डा. रश्मि दीवान		37,286.00		37,286.00 Dr
2100 – म.प्र. और बिहार में प्रा.शि. प्रबंधन – प्रो. कुमार		7,286.00		7,286.00 Dr
2101 – अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार – डा. मधुमिता		31,53,785.00		31,53,785.00 Dr
5- mÙkj&iwohZ {ks=		95,21,273.00	10,54,500.00	84,66,773.00 Dr
2052 – उत्तर–पूर्वी क्षेत्र		95,21,273.00	10,54,500.00	84,66,773.00 Dr
8- voewY;u		94,98,201.00		94,98,201.00 Dr
अवमूल्यन – भवन		25,81,574.00		25,81,574.00 Dr
अवमूल्यन – कंप्यूटर		9,08,759.00		9,08,759.00 Dr
अवमूल्यन – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		2,54,148.00		2,54,148.00 Dr
अवमूल्यन – ई–जर्नल		14,85,800.00		14,85,800.00 Dr
अवमूल्यन – फर्नीचर		4,96,130.00		4,96,130.00 Dr
अवमूल्यन – जर्नल		21,25,318.00		21,25,318.00 Dr
अवमूल्यन – पुस्तकालय की पुस्तकें		6,01,636.00		6,01,636.00 Dr
अवमूल्यन – कार्यालय उपकरण		9,22,188.00		9,22,188.00 Dr
अवमूल्यन – गाड़ियां		1,22,648.00		1,22,648.00 Dr
egk;ksx		**1,23,29,31,062.23**	**1,23,29,31,062.23**	

ह./–
¼m"kk R;kxjktu½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼c lojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼vkj- xksfoUnk½
कुलपति

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लेखे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2014 के तुलन–पत्र की एवं 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखाओं, प्राप्ति और भुगतान लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा कर ली है। हमें वर्ष 2015–16 तक की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण के व्यवहार्य से एकरूपता, लेखाकरण के मानदंडों और पारदर्शिता के मानकों इत्यादि के संबंध में लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। निरीक्षण रिपोर्टों/नि.म.ले. की अतिरिक्त रिपोर्टों के द्वारा विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियामक) के अनुसार वित्तीय संचालन और कार्य निष्पादन सहित कार्यदक्षता संबंधी पक्षों इत्यादि पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती है।

3. हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के अधिक यथार्थ विवरणों से युक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना तथा लेखा परीक्षा का निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण के सिद्धांतों, महत्वपूर्ण आकलनों की समीक्षा के साथ–साथ प्रस्तुत किए गए संपूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर प्रतिवेदन करते हैं कि –

   (i) लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

   (ii) तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सही प्रकार से तैयार किए गए हैं तथा लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(iii) हमारी राय के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय ने समुचित रूप से लेखा पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया है जो कि ऐसी पुस्तिकाओं की जांच–पड़ताल से पता चलता है।

(iv) हम पुनः प्रतिवेदन करते हैं कि :

v- r|yu i=

v-1 pky nk;rk,a vkj iko/kku ¼fo'k"k ifj;kstuk½& #- 268-02 yk[k ¼vu|lph&4½

इस मद में ऋणात्मक जमा राशि रु. 22.75 लाख दिखायी गयी है। इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट परियोजनाओं और साथ ही चालू परिसंपत्तियों में देयताओं का कम आकलन किया गया।

v-2 ubl is'ku ;kstuk

v-2-1 ifjlifÙk& #- 1-73 yk[k

नई पेंशन योजना के तुलन पत्र की परिसंपत्तियों और देयताएं में वास्तविक निवेश पर रु. 1.61 लाख का वास्तविक ब्याज दिखाया गया है। परन्तु नई पेंशन योजना के तुलनपत्र की परिसंपत्तियां और देयताएं में नहीं दिखाया जाना था क्योंकि वर्ष 2013–14 में कोई निवेश नहीं किया गया था। इसके कारण नई पेंशन योजना के तुलनपत्र में परिसंपत्तियां और देयताएं में रु. 1.61 लाख अधिक प्रदर्शित हुआ।

c- lkekU;

न्यूपा ने स्वीकृति पत्र और प्रबंधन बोर्ड में बताए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं जैसे– एनईआर, जनजातीय उपयोजना, अ.ज.जा. के लिये विशेष घटक योजना के लिए अलग लेखे नहीं तैयार किए। अतः अलग लेखों के अभाव के कारण लेखा परीक्षा इन निधियों के उपयोग को सत्यापित नहीं कर सकती।

l- lgk;rk vuqnku

विश्वविद्यालय ने मार्च 2014 में रु. 2600. 00 लाख (योजना में 1170.00 लाख, योजना (एनईआर)ः रु. 15.00 लाख और योजनेतर में रु. 1415.00 लाख) का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसमें से रु. 38.72 लाख (योजना) मार्च 2014 में प्राप्त हुआ। न्यूपा ने कुल रु. 102.82 लाख की प्राप्तियां (योजना रु. 23.01 लाख और योजनेतर में रु. 79. 81 लाख) अर्जित की। विश्वविद्यालय ने रु. 2714.84 लाख (योजना में रु. 1188. 30 लाख, (इन.ई.आर.) रु. 84.67 लाख तथा योजनेत्तर में रु 1441.87 लाख) का उपयोग किया। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पूर्व वर्ष की शेष अनुदान राशि से की गई।

विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान मा.सं. वि. मंत्रालय से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए रु. 161.92 लाख का अनुदान प्राप्त किया और इन परियोजनाओं में रु. 87.48 लाख रोकड़ जमा था। कुल राशि रु. 249.40 लाख में से रु. 158.88 लाख रुपये वर्ष के दौरान व्यय किए गए और 31 मार्च, 2014 को रु. 90.52 लाख शेष पाया गया।

n- प्रबंधन पत्र : लेखा से संबंधित जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें दूर करने हेतु पृथक रूप से प्रबंधन पत्र के द्वारा कुलपति, न्यूपा के संज्ञान में लाया गया है।

(v) आगे के अनुच्छेदों में टिप्पणी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस लेखा रिपोर्ट में तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के विवरण लेखा पुस्तिका के अनुसार है।

(vi) हमारे विचार से और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित वित्तीय विवरण जो लेखाकरण की नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां के अधीन माने गये हैं, उपर्युक्त महत्वपूर्ण विवरणों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नित भाग में प्रस्तुत अन्य दूसरी सामग्री आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं:

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च 2014 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के तुलन पत्र की स्थिति से संबंधित हैं।

(ब) जहाँ तक यह इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आय तथा व्यय लेखे से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक तथा महानिदेशक, लेखापरीक्षा की ओर से और कृते

g-@&
egkfun'kd] y[kk ijh{kk
dUnh; 0;;

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.10.2014

y[kk ijh{kk fjikVZ dk vuqyXud

1. vkarfjd y[kk ijh{kk 0;oLFkk dh i;kIrrk

   - न्यूपा द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की जा रही है।

2. vkarfjd fu;a=.k 0;oLFkk dh i;kIrrk

   y[kk ijh{kk ijk

   - 2000–01 से 2013–14 तक की अवधि के दौरान 33 लेखा परीक्षा पैरा के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

3. laifÙk;ksa dk Hkkfrd fujh{k.k

   - 31.03.2014 वर्ष के लिये भूमि का भौतिक निरीक्षण किया गया था।
   - 31.03.2012 तक फर्नीचरों और फिक्सरों का भौतिक निरीक्षण किया गया था।
   - कंप्यूटर और सहायक सामग्रियों का जून 2012 तक भौतिक निरीक्षण किया गया था। कुछ सामान अप्राप्य मिले मगर उसकी जांच के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई।
   - पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक निरीक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाता है और जुलाई 2012 तक यह निरीक्षण किया गया है। 45 पुस्तकें अप्राप्य पाई गईं जिनकी लागत रु. 1028+8 डालर है। मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4. bUVjh dh Hkkfrd tkp

   - स्टेशनरी, प्रकाशन तथा उपभोग वस्तुओं की भौतिक जांच वर्ष 2011–12 तक कर ली गई है। कोई कमी की रिपार्ट नहीं की गई।

5. lkafofèkd Hkqxrku esa fu;fer rk

   लेखा के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2014 तक पिछले छः महीने से कोई भी सांविधिक देयता का भुगतान बाकी नहीं था।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

jk"Vªh; 'kf{kd ;kstuk ,oa iz'kklu fo'ofo|ky;

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016

EPABX Nos.: 91-011-26544800, 26565600 | Fax: 91-011-26853041, 26865180

email: nuepa@nuepa.org | URL: http://www.nuepa.org www.nuepaeduplan.nic.in